लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

सं० 20, मंगलवार, 19 मार्च, 1974/28 फाल्गुन 1895 (शक)
No. 20, Tuesday, March 19, 1974/Phalguna 28,1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
341.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में उच्च जिम्मेदारियों का पालन करने से इंकार करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन में कटौती	Deduction of Wages of Asstt. Station Masters who Refused to Carry out Higher Responsibilities (Northeast Frontier Railway) ..	1-3
342.	गोकाक टाउन हो कर जाने वाली मिराज लौंडा प्रस्तावित बड़ी लाइन	Proposed *Miraj* Londa Broad Gauge Line *Via* Gokak Town	3-4
343.	भारतीय पत्तनों पर आने वाले जहाजों द्वारा भट्टी तेल (फारनेस आयल) का उपयोग किया जाना	Furnace Oil Used by Ships Calling at Indian ports	4
344.	कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Calcutta Electric Supply Corporation	5-7
345.	हड़तालों और धीमे काम करने से रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Strike and Go slow Tactics	7-8
357.	सरकार द्वारा मंजूर की गई लोको कर्मचारयों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा	Gist of Demands of Loco Staff Accepted by Government	8-13
346.	उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चनाव खर्च की निर्धारित सीमा का पुनरीक्षण और संशोधन करनेके लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to Review and Revise the Prescribed Limits of Election Expenses to be incurred by Candidates.	13-15

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

347.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच वार्ता	Talks Between Employees and Management of O & NGC ..	1

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
348.	भारतीय रेलवे से टिकट चेकिंग स्टाफ को रनिंग स्टाफ का दर्जा देना	Treatment of Checking Staff as Running Staff on Indian Railway..	16
349.	मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in M. P. ..	16-17
350.	हावड़ा की मार्टिन बर्न रेलवे को अपने हाथ में लेने के लिये पश्चिम बंगाल का अनुरोध	West Bengal Government's request for Take over of Martin Burn Railway in Howrah.	17
351.	डीजल रेल इंजनों का निर्माण बंद किया जाना	Stoppage of Production of Diesel Locomotives	17
352.	उद्योग को भट्टी तेल वितरित करने के लिये समिति	Committee for Distribution of Furnace Oil to Industry	17-18
353.	आल इंडिया रेलवे इम्पालाइज कान्फेडरेशन द्वारा नियमानुसार काम करने का निर्णय	Decision to work to Rule by All India Railway Employees Confederation	18-19
354.	यूनियन कार्बाइड को कुछ वस्तुएं बनाने के लिए रियायतें	Concession to Union Carbide for Manufacture of Certain items ..	19
356.	बदरपुर बिजली घर के "वैगन ट्रैलर" का गिर जाना	Collapse of wagon trailer of Badarpur Power House	19-20
358.	महाराष्ट्र में कृष्ण बेसिन में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति	Clearance of Medium Irrigation Projects in Krishna Basin in Maharashtra	20-21
359.	मुरादाबाद के निकट रेल दुर्घटना	Train Accident Near Moradabad ..	21
360.	कर्नाटक में काली नदी पन बिजली परियोजना और कावेरी परियोजना के लिये पृथक पृथक प्रावधान	Separate Provision for Kalinadi Hydro Electric Project and Cauvery Project in Karnataka.. ..	21
361.	श्रीनगर, कश्मीर में तेल की खोज	Oil Exploration in Srinagar, Kashmir..	22
362.	नासिक में रेलवे उपकरण संयंत्र	Railway Equipment Plant at Nasik..	22
363.	अतिरिक्त कच्चे तेल का परिशोधन	Refining of Additional Crude Oil ..	22-23
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
3579.	मध्य रेलवे में मजदूर यूनियनें	Trade Unions in Central Railway ..	23
3580.	गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड	Golcha Properties Limited	23-24
3581.	ट्रेफिक एकाउंट्स आफिस, अजमेर, तथा दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के फॉरेन ट्रैफिक एकाउंट्स आफिस में कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की वापस अदायगी	Medical Reimbursement to Staff of Traffic Accounts Office, Ajmer and FTA, Western Railway at Delhi	24

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3582.	कलकत्ता में ग्राहकों द्वारा पैट्रोल-विक्रेताओं के पास धनराशि जमा कराया जाना	Depositing Money by Customers with Petrol Dealers in Calcutta	24-25
3583.	पश्चिम रेलवे के फॉरेन ट्रैफिक एकाउंट्स आफिस, दिल्ली के कर्मचारियों के लिए 24 क्वार्टरों का निर्माण	Construction of 24 Quarters for Staff of FTA Office, Delhi (Western Railway)	25
3584.	अति प्रवीण बढ़ई ग्रेड दो, अजमेर वर्कशाप (पश्चिम रेलवे) के पद के लिए, व्यावसायिक परीक्षण के बारे में अभ्यावेदन संबंधी निर्णय	Decision on Representation regarding Trade Test for post of Highly Skilled Carpenters Grade II, Workshop, Ajmer (Western Railway)	25
3585.	बम्बई (पश्चिम रेलवे) में टी० आई० ए० एस० की नियुक्ति पर हुआ व्यय	Expenditure on posting of TIAS at Bombay (Western Railway) ..	26
3586.	औषधों के मूल्यों के बारे में अनुमोदनार्थ आवेदन-पत्र	Applications Pending Approval to prices of Drugs	26
3587.	प्रस्तावित लोको शेड को कज्जाकुट्टम के किसी अन्य स्थान पर ले जाना	Shifting of proposed Loco Shed from Kazhakuttam to some other place ..	27
3588.	रेलवे सुरक्षा बल संघ का मांग-पत्र	Charter of Demands by Railway Protection Force Association ..	27-28
3589.	एर्नाकुलम में पुराने सामान के शेड क्षेत्र की भूमि के समर्पण के लिए केरल सरकार का अनुरोध	Kerala Government's request for Surrender of old goods sheds Land at Ernakulam	28
3590.	भारत में तेल की खोज में लगे हुए विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts engaged in Oil Exploration in India	28
3591.	रेलवे कर्मचारियों को खेती के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of Land for cultivation to Railway Employees	29
3592.	रूसी तेल-विशेषज्ञों द्वारा जम्मू-क्षेत्र में तेल कूप की खुदाई	Drilling Oil in Jammu Region by Russian Oil Experts	29
3593.	औषध फर्मों द्वारा अनुमति पत्र के अधीन बनाई गई वस्तुओं के आंकड़ों को रखना	Maintaining Data of Items produced by Drug Firms under Permission Letter	29-30
3594.	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में कार्य कर रहे हिन्दी कर्मचारी	Hindi Staff working in Ministry of Irrigation and Power	30
3595.	तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा औषध फर्मों के विविधीकरण कार्यक्रम का अनुमोदन	Approval of Diversification Programme of Drug Firms by DGTD ..	30

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3596.	मध्य प्रदेश में टिमरनी स्टेशन (मध्य रेलवे) पर इमारती लकड़ी का जमा हो जाना	Timber Stocks piled up at Timarni Station in Madhya Pradesh (Central Railway)	31
3597.	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई	Irrigation of Land in U. P. and M. P.	31
3598.	मध्य प्रदेश के सीधी जिले में तापीय विद्युत् केन्द्र की स्थापना	Setting up of Thermal Power Station in Sidhi District, M. P.	31
3599.	ताप्ती नदी पर एक बाँध के निर्माण के बारे में समझौता	Agreement re : construction of a Dam on River Tapti	31-32
3600.	मध्य रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Temporary Employees on Central Railway ..	32
3601.	पश्चिमी रेलवे में हड़ताल के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हुई रेलवे सम्पत्ति	Railway Property Lost due to strike on Western Railway ..	32
3602.	गत वर्ष उत्तर रेलवे में पंजीकृत की गई अपराध की घटनायें	Crimes on Northern Railway Registered during the Last Year ..	32
3603.	लोकों कर्मचारियों की हड़तालों वाले डिवीजनों के नाम	Names of Divisions where Loco Employees strike occurred	32-33
3604.	तेल का खर्च कम करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश	Directive to State Government to Economise use of oil	33
3606.	पैट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के कारण माल परिवहन में बाधा	Disruption in Transportation of goods due to increase in Prices of Petroleum	33-34
3607.	बसरा, ईराक में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए भारतीय सहायता	Indian Assistance for Setting up of a Refinery at Basra in Iraq ..	34
3608.	अमान में तेल परिशोधन शाला की स्थापना के लिए भारतीय सहायता	Indian Assistance for setting up of Refinery in Oman	34-35
3609.	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार	Improvement in service condition of judges of Supreme Court and High Court	35
3610.	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा ऊर्जा संकट पर बैंगकॉक में आयोजित सम्मेलन	Conference convened by FCAFE on Energy Crisis at Bangkok	35-36
3611.	डीजल कृषि पम्प सैटों को विद्युत् पम्प सैटों में बदलना	Conversion of Diesel Agricultural Pump sets to Power	36

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
3612.	26 प्रतिशत से कम विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को लाइसेंस दिया दिया जाना	Issue of Licences to Firms with less than 26 per cent foreign equity	36-37
3613.	राष्ट्रपति शासन के पश्चात् गुजरात को कोयले की सप्लाई	Coal supply to Gujarat after President's Rule	37
3614.	राजस्थान में 'राक फास्फेट' का खनन	Mining of Rock Phosphate in Rajasthan	37-38
3615.	तटवर्ती जहाज रानी के लिए तेल की सप्लाई	Supply of Oil for Coastal shipping ..	38
3616.	दिल्ली में तीसरा बड़ा स्टेशन	Third big station for Delhi ..	38-39
3617.	कच्चे माल की कमी के कारण रसायन उद्योगों के उत्पादन में कमी	Decline in production of Chemical industries for want of raw material ..	39-40
3618	पेट्रोलियम रसायनों की जमाखोरी, अपमिश्रण और चोरबाजारी	Hoarding, adulteration and black-marketing of petroleum chemicals ..	40
3619.	पैट्रोल, डीजल और अशोधित तेल का आयात	Import of petrol, Diesel and Crude Oil	40-41
3620.	तापीय संयंत्र का दलखोला से मुर्शिदाबाद को स्थानान्तरित किया जाना	Shifting of location of Thermal Plant from Dalkhola to Murshidabad ..	41
3621.	गैर-सरकारी क्षेत्र के 100 सबसे बड़े उपक्रमों की परिसम्पत्तियां	Assets of 100 top most private sector undertakings	41
3622	तेल की कीमत में वृद्धि का कोल्हापुर के डीजल तेल उद्योग पर प्रभाव	Impact of increase in price of oil on diesel oil industry in Kolhapur ..	42
3623.	अशोधित तेल के मूल्य पर भारत का इराक और कुवैत के साथ समझौता	India's agreements with Iraq and Kuwait on price of Crude oil ..	42
3624.	50 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक पूंजी निवेश वाले उपक्रम	Undertakings with Capital investment of Rs. 50 crores and above ..	42
3625.	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरि और मणिपुर की विधान सभाओं के चुनावों पर व्यय	Expenditure on elections to Legislative Assemblies of Uttar Pradesh, Orissa, Pondicherry and Manipur	43
3626.	सरकारी क्षेत्र के एककों को कोयला पहुंचाने के लिए वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons for Transfer of Coal to Public Sector Units	43
3627.	दुर्गापुर में तापीय विद्युत् केन्द्र का विस्तार	Extension of Thermal Power Station in Durgapur	43-44
3628.	पोलिएस्टर रेशों और धागों के लिए डी० एम० टी० का उत्पादन	Production of DMT for Polyester Fibres and Yarns	44

अता० प्र० स० U. S. Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3629.	लिक्विड नाइट्रोजन वाश प्लांट के लिए ब्रिटेन की एक फर्म तथा भारतीय उर्वरक निगम के बीच करार	Agreement between FCI and a U.K. firm for liquid nitrogen wash plant	44-46
3630.	फर्टिलाइजर एसोसिएशन ग्राफ इंडिया द्वारा सरकार और उद्योग के बीच ग्रायोजित की गई बैठक	Meeting organised by Fertiliser Association of India Between Government and Industry.. ..	44-46
3631.	सहायक स्टेशन मास्टरों की ऊंचे संवर्ग में पदोन्नति की समेकित प्रणाली (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)	Unified system of promotion of Asstt. Station Master to higher grade (Northeast Frontier Railway) ..	46
3632.	ग्रखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) की ग्रोर से ग्रभ्यावेदन	Representation for All India Station Masters' Association (Northeast Frontier Railway)	46-47
3633.	ईंधन सहित सामान पर खर्च में मितव्ययता	Economy in expenditure on Stores in cluding Fuel	47-48
3634.	प्रत्येक राज्य में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर रेलवे लाइन की लम्बाई	Length of Railway lines in each State per one lakh persons	48
3635.	भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिए ग्रमरीकी सहायता	US Assistance for setting up of fertilizer plants in India..	48-49
3636.	ग्रोज़ बेकर्ट साबू लिमिटेड, नई दिल्ली	Groz Beckert Saboo Limited, New Delhi	49-50
3637.	कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बातचीत	Negotiations for supply of Crude Oil	51
3638.	ग्रौषधि ग्रौर भेषज उद्योग के विकास संबंधी समिति	Committee on growth of Drugs and Pharmaceutical Industry	51
3639.	हिन्दी में विधि की पुस्तकें	Law Books in Hindi	51-52
3640.	विगत छः महीनों में हुई बिना-टिकट यात्रा	Ticketless Travelling during the last six months	52
3641.	चोरी के आरोप में दोषी पाए गए सुरक्षा दल के कर्मचारी	Security Force Personnel found guilty on charge of stealing ..	52
3642.	कचनारा फ्लैग स्टेशन (पश्चिम रेलवे) को पूरे स्टेशन में परिवर्तित करना	Conversion of Kachnara Flag Station (Western Railway) into a full fledged Station	52
3643.	मंदसौर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर यात्री शेड का विस्तार करने ग्रौर तृतीय श्रेणी प्रतीक्षालय की ग्रोर जाने हेतु दो फाटकों की व्यवस्था करने की मांग	Demand for the expansion of passenger Shed and for providing two Gates to Third Class Waiting Room at Mandsaur Station (Western Railway	52-53

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3644.	1973-74 में लोकों कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Loco Employees on strike in 1973-74	53
3645.	उच्च शक्ति वाले बिजली के रेल-इंजन	High powered Electrical Locomotives	53
3646.	राजस्थान में सुमेर तलिया के स्थान पर तेल के लिए छिद्रण कार्य का स्थगित किया जाना	Suspension of Oil Drilling at Summer Talia in Rajasthan	53-54
3647.	फरक्का बांध से नीचे की ओर गंगा के किनारे पर भू- क्षरण से बचाव के लिए निर्माण-कार्य	Construction of Anti Erosion Protective Measures on the Bank of Ganga Down Stream Farakka Barrage	54-55
3748.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फरक्का बांध से नीचे की ओर गंगा के किनारे पर भू-क्षरण से बचाव हेतु निर्माण कार्यों के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial assistance sought by West Bengal for Anti Erosion Protective Measures on the Bank of Ganga Down Stream, Farakka Barrage ..	55
3649.	झामरकोटरा क्षेत्र में राक-फास्फेट निक्षेपों के विकास के लिये समिति	Committee for Development of Rock-Phosphate Deposits in Jhamarkotra Area	55-56
3650.	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और मणिपुर की विधान सभाओं के चुनाव	Election to Legislative Assemblies of Uttar Pradesh, Orissa, Pondicherry and Manipur	56
3651.	दक्षिण मध्य रेलवे में मिराज-सांगली और मिराज-नान्द्रे रेल मार्गों के साथ रेलवे भूमि की खरीद	Railway land along Miraj Sangli and Miraj Nandre Links on South Central Railway	57
3652.	कोल्हापुर और पुने के बीच 312 अप और 311 डाउन गाड़ियों को पुनः चालू करना	Re : Introduction of 312 UP and 311 311 Down Trains between Kolhapur and Pune	57-58
3653.	सांगली और कोल्हापुर के बीच यात्री गाड़ियों को पुनः शुरु करने की मांग	Demand to Restart Passenger Trains between Sangli and Kolhapur ..	58
3654.	क्विलोन जंक्शन (दक्षिण रेलवे) का विकास करने संबंधी योजना	Scheme to develop Quilon Junction (Southern Railway)	58
3655.	कल्लाडा सिंचाई परियोजना	Kailada Irrigation Project ..	59
3656.	बिजली की सप्लाई बार-बार बंद करने का कलकत्ता जल सप्लाई व्यवस्था पर प्रभाव	Effect of Load Shedding on Calcutta Water Supply System	59
3657.	पिछले पांच महीनों के दौरान रेल-दुर्घटनायें	Train Accidents during the Last Five Months	59-60

अता० प्र० सं० U. S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3658.	पांचवीं योजना के पहले वर्ष में आंध्र प्रदेश के लिये बड़ी सिंचाई योजनायें	Major Irrigation Schemes for Andhra Pradesh for First Year of Fifth Plan	60
3659.	न्यू. सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी दवारा वाराणसी में अमोनिया यूरिया उद्योग समूह की स्थापना के लिये अनुमति मांगना	Permission sought by New Central Jute Mills Company to set up Ammonia Urea Complex at Varanasi	61
3660.	दक्षिण रेलवे में कोयले की कमी के कारण डीजल से रेलगाड़ियां चलाना	Dieselisation of Trains due to Shortage of Coal on Southern Railway	61
3661.	तेल की खोज के लिये आयल इंडिया तथा ईराक के बीच करार	Agreement between Oil India and Iraq for Oil Exploration	61-62
3662.	सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि करना	Raise in Minimum Pension Amount of All Categories of Railway Employees	62
3663.	गुजरात में बिजली का संकट	Power Shortage in Gujarat	62
3664.	अहमदाबाद और गांधी नगर के बीच ब्रॉड गेज लाईन	Broad Gauge Line between Ahmedabad and Gandhinagar ..	63
3665.	रेलवे संचालन के विभिन्न एककों में नियुक्त नमित्तिक कर्मचारी	Casual Labour Employed in various Units of Railways Operations ..	63-64
3666.	उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियरों द्वारा हड़ताल	Strike by Junior Engineers in U. P.	64
3667.	तेल शोधन कारखानों को कच्चे तेल की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Crude Oil supply to Refineries	64-65
3668.	भारतीय रेलों में विद्युत् विभाग में टी० एल० आई० बिजली घरों और हैड लाइट अनुभागों में कुशल कारीगरों की नियुक्ति के लिये निर्धारित मापदंड	Prescribed Yardstick for Artisan Staff in TLIs, Power Houses and Head Light in Electrical Department on Indian Railways	65
3669.	रेलवे अस्पताल, दानपुर (पश्चिमी रेलवे) के टी० बी० वार्ड में मेडिकल कर्मचारियों को टी० बी० भत्ते की अदायगी	Payment of T B. Allowance to Medical Staff in T.B. Ward, Railway Hospital, Danapur (Eastern Railway)	65-66
3670.	विद्युत् संयंत्रों को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Power Plants ..	66
3671.	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, समस्तीपुर की मांगे स्वीकार करना	Acceptance of Demands of North Eastern Railway Mazdoor Union Samastipur	66-67

अता०प्र०सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3672.	खजौली तथा जयनगर स्टेशनों के मध्य कोरैया को और कमतौल तथा जोगी आडा के मध्य मरैथा को 'हाल्ट स्टेशन' बनाना	Opening of Halts at Korhaiya between Khajauli and Jayanagar Stations and at Muraitha between Kamtaul and Jogiara	67
3673.	चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव	Proposal to convene a meeting of Political Parties by the Election Commission	67-68
3674.	इन्दौर-महू ब्राड गेज लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Indore Mhow Broad Gauge Line	68
3675.	गंगा-कावेरी लिंक परियोजना के कार्य में प्रगति	Progress regarding Ganga-Cauvery Link Project	68
3676.	मचेरला-सिकन्दराबाद रेल लाइन के निर्माण पर लागत और उसका पूरा होना	Cost and Completion of Macherla-Secunderabad Railway Line ..	68-69
3677.	पश्चिम बंगाल विधान सभा के उप-चुनाव के बारे में प्राप्त हुई शिकायतें	Complaints received in regard to by-election to West Bengal Assembly:	69
3678.	बड़े जलाशयों में गाद जमा होने की आशंका	Station threat to Major Reservoirs:	70
3679.	राजधानी में रिंग रेलवे का निर्माण	Construction of Ring Railway in the Capital	70
3680.	बम्बई और कलकत्ता में भूमिगत रेल व्यवस्था के संबंध में हुई प्रगति	Progress made on Provision of Tube Railway System in Bombay and Calcutta	70-71
3681.	हिमाचल प्रदेश की पनबिजली क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Assessment of Hydel Potential of Himachal Pradesh ..	71
3682	उत्तर राज्यों के कृषि फार्मों में बिजली की कमी	Shortage of Power in Agricultural Farms in Northern States	72
3683.	कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of Provision of Companies Law	72-73
3684.	विदेशी कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का लागू किया जाना	Application of Foreign Exchange Regulation Act to Foreign Companies	73
3685.	माल-डिब्बों का उत्पादन करने संबंधी नीति का पुनरीक्षण	Revision of Policy regarding production of Wagons	73
3686.	भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट का दिया जाना	False submission of Monthly Report by Supervisory Staff of P.F. Section DAO New Delhi (Northern Railway)	74

अता०प्र०सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3687.	साहिबाबाद, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे बुकिंग क्लर्कों को उनकी देय राशियों की अदायगी न करना	Non-payment of dues to Booking Clerks working at Sahibabad Delhi Division (Northern Railway)	74
3688.	वाणिज्यिक शाखा, प्रभागीय कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे आफिस क्लर्कों का स्थानान्तरण	Transfer of Office Clerks working in commercial Branch, Divisional Office, New Delhi (Northern Railway)	74-75
3689.	प्रभागीय लेखा-अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के उप-प्रभारी कर्मचारियों का निलंम्बित किया जाना	Suspension of Sub Heads of DAO New Delhi (Northern Railway) ..	75
3690.	नेपाल को पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई	Supply of Petroleum Products to Nepal	75-76
3691.	केरल में पहले से चली आ रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि	Rise in Cost of Continuing Irrigation Projects in Kerala	76-77
3692.	केरल में विद्युत् क्षमता के लिये खोज	Exploration of Power Potential in Kerala	77
3693.	विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of kerosene oil to various States	77-78
3694.	वर्ष 1972-73 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनायें	Schemes sanctioned by REC during 1972-73	78
3695.	तापीय बिजली घरों द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of Power by Thermal Stations	78-79
3696.	कोचीन और बरौनी तेल शोधक कारखानों के लिये ईराक से अशोधित तेल की सप्लाई स्थगित होना	Suspension of supply of Crudeoil from Iraq for Cochin and Barauni Refineries.	79
3697.	वर्ष 1971–72, 1972-73 और 1973-74 में हड़ताल करने वाले रेलवे कर्मचारियों के वर्ग	Categories of Railway Employees resorted to strikes, during 1971-72, 1972-73 and 1973-74	79-80
3698.	देश में तेल का उत्पादन	Indigenous production of oil	81
3699.	महाराष्ट्र की पनबिजली परियोजनाओं की मंजूरी	Clearance of Hydraulic Electricity Projects in Maharashtra	81
3700.	आयात किये जा रहे रसायनों का देश में ही निर्माण	Indigenous manufacturer of Chemicals which are being imported	81-83

अता०प्र०सं० U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3701.	पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे के वैगन निरीक्षकों और स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल	Strike by Wagon Examiners and Station Masters of North-Eastern and South-Eastern-Railway ..	83
3702.	नंगल में गोविन्दसागर बांध में गाद जमना	Siltage in Gobind Sagar Dam at Nangal	83
3703.	बीकानेर, जोधपुर, फ़िरोजपुर, लखनऊ, तथा इलाहाबाद डिवीजनों में स्टेशनों पर चीजों के लिये जारी किये गये लाइसेंस	Vending licences issued for stations in Bikaner, Jodhpur, Ferozepur, Lucknow and Allahabad Divisions:	84
3704.	रामपुरा, दिल्ली को रेलवे हाल्ट बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make a Railway halt at Rampura Delhi	84-85
3705.	कोचीन तथा मद्रास तेल शोधक कारखानों द्वारा ऊंची दरों पर अशोधित तेल की वसूली	Procurement of crude oil at higher rates by Cochin and Madras Refineries	85
3706.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन	Amendment to Hindu Marriage Act, 1955	85-86
3707.	नेपाल को डीजल की सप्लाई	Supply of Diesel to Nepal	86
3709.	15 दिसम्बर, 1973 को बारूद से रेलवे पुल उड़ाने का प्रयास	Attempt made to Dynamite Railway bridge on 15th December, 1973..	86
3710.	समस्तीपुर डिवीजन उत्तर बिहार में गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains in Samastipur Division	87
3711.	कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए रुस्तम क्रूड का उपयोग	Using Rustam Crude for Cochin Refinery	87
3712.	भारतीय तेल निगम के कोयाली तेल शोधक कारखाने में बेंजीन टालयुईन का उत्पादन बढ़ाना	Increasing production of Benzene toluene at Koyali Refinery of IOC	87-88
3713.	चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तेल शोधन क्षमता के लक्ष्य	Targets of Refining capacity during Fouth and Fifth Plans	88
3714.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Oil and Natural Gas Commission	88-89
3715.	मोदपुर और सिन्हान (पश्चिम रेलवे) के बीच माल डिब्बों का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Wagons between Modpur and Sinhan (Western Railway)	89
3716.	कालटेक्स द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for increase in price of Crude oil by Caltex	89

अता०प्र०सं० U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3717.	बरवाडीह और चिरमिरी रेलवे लाइन का निर्माण / Construction of Barwadih Chirmiri Railway line	89-90
3718.	डाल्टनगंज और दिल्ली के बीच देहरी अथवा चोपान से होकर सीधी गाड़ी / Direct train between Dalton Ganj and Delhi *via* Dehri or Chopan	90
3719.	कानपुर रेलवे स्टेशन पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों की स्थिति के बारे में प्राप्त शिकायतें / Complaints received against the condition of Bogies of Mail and Express Trains at Kanpur Railway Station	90
3720.	उप-नगरीय टिकटों के कारण रेलवे को हानि / Loss to Railways due to Suburban Season Tickets	90-91
3721.	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट पर राज्यों से प्राप्त टिप्पणी / Comments from States on the Krishna Water Disputes Tribunal award ..	91
3722.	गोदावरी जल विवाद के बारे में कृष्णा जल न्यायाधिकरण / Krishna Water Tribunal for Godavari Waters Dispute	91-92
3723.	रावी और व्यास नदियों के जल के बटवारे के बारे में समाधान / Solution regarding sharing of Ravi and Beas Waters	92
3724.	हिंगिर रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाई गई गोली से हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने संबंधी समझौते को क्रियान्वित न करना / Non-implementation of Agreement regarding compensation to victims of firing opened by Railway Protection Force at Hingir Railway Station (S.E. Railway) ..	92-93
3725.	वाराणसी स्थित उत्तर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास तथा मकान किराया सहायता दिया जाना / Facility of Accommodation and House Rent Assistance to Officers and staff of Northern Railway at Varanasi	93
3726.	बड़ौदा पेस्ट एण्ड टेलकम पाउडर-कालगेट कैरीज लूट शीर्षक से समाचार / News item captioned Tooth Paste and Telcum Powder—Colgate Carries Loot	93-94
3727.	बड़ौदा के फ्रेंच वैल वाटर पम्पिंग सिस्टम के टूट जाने की जांच करने वाली समिति का प्रतिवेदन / Report of Committee on collapse of french well water Pumping system of Baroda	94
3728.	विदेशी औषध फर्मों से लाभ संबंधी विवरणों का प्राप्त होना / Receipt of profitability returns from Foreign Drug Firms	94-95
3729.	आन्दोलनों के कारण जनवरी 1971 से अब तक रेल विभाग को हानि / Loss to Railways since January, 1971 due to agitations	95-96
3730.	राजस्थान में उर्वरक कारखानों की स्थापना / Setting up of Fertilizer Factories in Rajasthan	96

अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3731.	राष्ट्रीय सिंचाई संबंधी नीति	National Irrigation Policy	96
3732.	रेलगाड़ियों में जुआ	Gambling in trains ..	96-97
3733.	पांचवी योजना में बिहार में बिजली की कमी	Power shortage in Bihar in Fifth Plan	97-98
3734.	वर्ष 1973 में लोकों कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने की शर्तें	Terms on which strike of Loccmen was settled in 1973	98-99
3735	पहली जनवरी, 1974 से रेल किरायों में सामान्य वृद्धि	General Rise in Railway Fares from Ist January, 1974	99
3736.	पैट्रोल पम्पों के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil through Petrol Pumps	99-100
3737.	राष्ट्रीय परियोजना के रूप में राजस्थान नहर	Rajasthan Canal as a National Project	100-101
3738.	कैडबरी फ्राई (इंडिया)	Cadbury Fry (India)	101-102
3739.	बिजली-सप्लाई की दरों में समानता	Uniformity in Rates of Power Supply	102
3740.	जीवन रक्षक औषधियों में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in Life Saving Drugs	102-103
3741.	डीजल के अभाव में रेल गाड़ियां भाप के इंजनों से चलाना	Use of Steam Engines for Running Trains due to shortage of Diesel Oil	103
3742.	वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोगों के पास मामले	Cases with the MRTP Commission during 1970-71, 1971-72, 1972-73 and 1973-74.	103
3743.	मैसर्ज मे एण्ड बेकर से अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने का प्रस्ताव	Proposal from M/s May and Baker to Reduce its Foreign Equity ..	104
3744.	औषधि फर्मों को 'प्राडक्ट-मिक्स' की अनुमति	Permission to allow product Mix to Drug Firms	104
3745.	औषधि फर्मों को कच्चे माल के आयात की अनुमति	Permission to Drug firms for import of Raw Materials	104-105
3746.	पश्चिम बंगाल को सिंचाई के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal for Irrigation	105
3747.	पश्चिम बंगाल में विद्युत् प्रजनन	Generation of Power in West Bengal for Irrigation	105
3748.	पश्चिम बंगाल में तेल के लिये छिद्रण स्थान	Places for Oil Drilling in West Bengal	105-106
3749.	औषधि फर्मों द्वारा रक्षित खपत के लिए औषधि निर्माण	Production of Drugs for Captive Consumption by Drug Firms ..	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3750.	औषधि निर्माता फर्मों के निर्यात-व्यापार का अध्ययन	Study of the Export Performance by Drug Manufacturing Firms. ..	107
3751.	दक्षिण रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों का स्थायी रूप से खपाया जाना	Permanent Absorption of Casual Labour on Southern Railway ..	107
3752.	गुजरात में वाणिज्यिक स्तर पर तेल का उत्पादन	Production of Oil in Gujarat at Commercial Level	107-108
3753.	औषधि निर्माता फर्मों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय को मासिक विवरणियां भेजना	Submission of Monthly Returns by Drug Firms to DGTD	108
3754.	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के अधीन औषधि फर्मों को अनुमति-पत्र जारी करना	Issue of permission letters to Drugs Firms under the Industrial (Development and Regulations) Act, 1951	109
3755.	विधान सभा और लोक सभा के उपचुनाव	By elections to Vidhan Sabha and Lok Sabha	109-110
3756.	वर्ष 1973 में आरक्षित अथवा अनारक्षित किये जाने वाले विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्र	Vidhan Sabha Constituencies which were Reserved or Dereserved in 1973	110
3757.	उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में विरोधी दलों द्वारा कांग्रेस की चुनाव सभाओं में कथित विघ्न डालने की शिकायतें	Complaints Alleging Disturbance of Election Meetings of Congress Party by Opposition Parties in U. P. and Orissa	110-111
3758.	उर्वरकों की विश्वव्यापी भारी कमी की आशंका	Fear of Acute World Fertilizer Crisis	111
3759.	बदरपुर तापीय बिजली घर में एक जैनेरेटर चालू करना	Commissioning of a Generator at Badarpur Thermal Power Station ..	111
3760.	काठघर की रेल दुर्घटना के 20 मृतकों का बिना शिनाखत दाह संस्कार	Cremation of 20 Victims of Train Accident at Kathghar without Identification	112
3761.	अंकलेश्वर और दूसरे तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन में कमी	Decline in Oil Production at Ankleshwar and other Oil Fields	112
3762.	कोयली तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाना	Increasing Production capacity of Koyali Refinery	112-113
3763.	केरल में बिना चौकीदार वाले रेल-फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना	Manning of Railway Crossings in Kerala	113
3764.	मालाबार एक्सप्रैस के परापननगडी में रुकने संबंधी मांग	Demand to stop the Malabar Express at Parappanangadi	113
3765.	केरल में घाटे पर चल रही रेलगाड़ियां	Railways Running in Loss in Kerala	113-114
3766.	1/2 मंगलौर-मद्रास मेल गाड़ियों का डीजलीकरण	Dieselisation of 1/2 Mangalore-Madras Mails	114

अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3767.	केरल में वैगन उपलब्ध न किए जाने के कारण उद्योगों को हुई हानि	Loss to Industries due to Non-Availability of Wagons in Kerala ..	114
3768.	डीजलीकरण के कारण रेलवे की संचालन कार्यकुशलता	Operational Efficiency of Railways due to dieselisation	115
3769.	उत्तर प्रदेश में विद्यमान मीटर लाइनों को बड़ी और दोहरी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre-Gauge to Broad Gauge and Doubling of Existing Lines	115-116
3770.	पश्चिम बंगाल में दामोदार नदी के निचले क्षेत्रों से गाद निकालने के काम के लिये धन का अभाव	Shortage of Funds for Desilting Work of Lower Breaches of Damodar River in West Bengal	116-117
3771.	पश्चिम बंगाल में अजय नदी योजना का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Ajoy River Scheme in W. Bengal	117-118
3772.	राजामुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) के दूसरे रेल पुल का काम पूरा हो जाना	Completion of Second Railway Bridge at Rajahmundry (Andhra Pradesh)	118
3773.	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में "ट्रैक" नवीकरण का लक्ष्य	Target for Track Renewals during 1971-72 and 1972-73	118-119
3774.	वर्ष 1973-74 के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिए दिया गया मुआवजा	Compensation paid on account of accidents during 1973-74	119
3775.	वर्ष 1973-74 में हड़तालों और दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि को पूरा किया जाना	Recoupment of Losses due to Strikes and Accidents during 1973-74 ..	119
3776.	स्वर्णरेखा परियोजना का पुनरीक्षण	Revision of Subarnarekha Project ..	120
3777.	रेलवे में काम कर रहे स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters in Service of Railways	120-121
3778.	ज्वार-भाटीय तंरगों से बिजली बनाना	Generation of Power from Tidal Waves	121
	अतारांकित प्रश्न संख्या 921 दिनांक 26 फरवरी, 1974 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting answer to U.S.Q. No. 921 dated 26-2-1974	121
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	122
	उत्तर प्रदेश बिहार तथा अन्य राज्यों में गन्ना उत्पादकों के लिए निर्धारित गन्ने के न्यूतनम मूल्य का भुगतान न किये जाने का कथित समाचार	Reported non-payment of the Minimum cane price to cane-growers in U. P. Bihar and other States ..	122-125
	श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	.. 122-123
	श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	.. 123-125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव—प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दिया जाना	Motion for Adjournment—Leave to move not grated	125-126
पटना में गोली चलना	Firing in Patna ..	126-127
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ..	127-129
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377	129
महाराष्ट्र सरकार द्वारा समुद्री भराव की भूमि को बेचने का कथित समाचार	Reported Sale of land underlying territorial waters by Maharashtra Government	129
सामान्य बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा	General Budget, 1974-75—General Discussion	129-145
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar ..	129
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	129-130
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richariya ..	130-131
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar ..	131-133
डा० कैलाश	Dr. Kailas ..	133-134
श्री धरणीधर दास	Shri Dharnidhar Das	134-135
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	135
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	135-136
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi ..	136-137
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi ..	137-138
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli ..	138-139
श्री तुला राम	Shri Tula Ram ..	139
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy ..	139-140
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	140
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	140-145
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1974-75—पारित	Demands for Grants on Account (General) 1974-75—passed ..	145-149
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1974-75	Demands for Grants (Railways), 1974-75	149-217
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya ..	213-214
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani ..	214-215
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey ..	215-216
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	216-217
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder ..	217
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	217

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 19 मार्च, 1974/28 फाल्गुन, 1895 (शक)
Tuesday, March 19, 1974/Phalguna 28, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में उच्च जिम्मेदारियों का पालन करने से इंकार करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन में कटौती

*341. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उन सहायक स्टेशन मास्टरों को वेतन में कटौती करने के बारे में कोई अनुदेश जारी किए हैं जो उपस्थित तो थे लेकिन जिन्होंने बिना आनुपातिक लाभ के उच्च जिम्मेदारियों का पालन करने से इंकार कर दिया था; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे प्रशासन ने लगभग 300 स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की मजूरी काटने के आदेश दिए हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) . जी नहीं। लेकिन जिन कर्मचारियों ने आदेश के अनुसार स्टेशनों का कार्यभार नहीं सम्हाला, उन्हें 'काम नहीं, वेतन नहीं' के सिद्धान्त पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे मैनुएल और सेवा नियमों के अनुसार ऊंचे वेतनमान में किसी प्रतिनियुक्ति को स्वीकार करना कर्मचारी के लिए

ऐच्छिक है अथवा अनिवार्य । दूसरे, क्या यह भी सच है कि रेलवे मैनुएल तथा सेवा नियमों के अनुसार इन सभी अवकाश रिक्तियों को न्यूनतम रखने के सम्बन्ध के पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यदि हां, तो पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में ऊंचे दायित्वों के पद कितने समय से खाली पड़े हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वर्तमान नियमों के अनुसार 250-280 रुपए के वेतनमान में स्टेशन-मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरोंके छुट्टी रिजर्व 130/150-240 रुपए के सहायक स्टेशन मास्टरोंके वेतन-मान के होते हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, इस श्रेणी में छुट्टी रिजर्व की यह उच्चतम प्रतिशतता है । यह लगभग 30 प्रतिशत है । परन्तु कठिनाई यह है कि ये उस समय निम्न स्तर के वेतनमानों में कार्य कर रहे होते हैं जब इन्हें सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतनमानों में कार्य करना होता है । जब आवश्य-कता होती है तो वे उच्च पदों पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते । इसी कारण वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करते हैं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने साधारण सा प्रश्न पूछा था कि क्या किसी ऊंचे वेतनमान में प्रतिनियुक्ति स्वीकार करना ऐच्छिक है अथवा अनिवार्य ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह अनिवार्य है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या आप जोनल रेलवेज में भी, चाहे वह पूर्व रेलवे हो, चाहे उत्तर रेलवे अथवा दक्षिण रेलवे, स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के सेवा संवर्ग के संबंध में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है ? जहां तक मुझे पता है, पूर्व रेलवे में रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पृथक नियमों का पालन किया जा रहा है । कठिनाई केवल यह पैदा होती है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे प्राधिकारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । क्या यह सही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम सभी जोनों पर लागू होते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हम कुछ छुट्टी रिजर्व पदों के ग्रेड बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that the Station Masters and Assistant Station Masters of N. F. Railway were assured by the Divisional Authorities that there will not be any deduction from their wages and their other demands will be considered sympathetically, if so, whether it is a fact that the authorities did not fulfil their assurances and consequently, the Station Masters and Assistant Station Masters have to regret to 'work to Rule' and other agitations?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I am not aware of any such assurance.

Shri Ramavatar Shastri : May I know as to why the agitation is going on there? Agitation is still there and as a result of that running of trains is being obstructed. May I know the steps government propose to take to ease the situation?

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं आपको जानकारी दे रहे हैं ।
श्री गोस्वामी ।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया है कि ऊंचे पद पर काम करना कर्मचारी के लिए अनिवार्य है यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है । जब कोई विकल्प नहीं रह जाता और यह अनिवार्य है तब "काम नहीं दाम नहीं" सिद्धान्त की तरह यह सिद्धान्त भी बनाया जाना चाहिए कि वेतन कार्य के अनुसार दिया जाए । यदि किसी कर्मचारी से ऊंचे वेतनमान में कार्य करने के लिए कहा जाता है तब क्या उस कर्मचारी को ऊंचे वेतनमान में वेतन दिया जाएगा ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उसे ऊंचे वेतनमान में वेतन दिया जाता है।

गोकाक टाऊन होकर जाने वाली मिराज-लोंडा प्रस्तावित बड़ी लाइन

*342. **श्री पी० आर० शिनाया**
श्री एस०बी० पाटिल } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोकाक टाऊन होकर जाने वाली मिराज-लोंडा बड़ी लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कौर (ख) मिराज-लोंडा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण दल इस लाइन को गोकाक शहर के रास्ते से निकालने के प्रस्ताव की भी जांच कर रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने और उनकी जांच कर लिए जाने के बाद ही अंतिम निर्णय किया जा सकता है।

श्री पी० आर० शिनाय : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि गोकाक होते हुए प्रस्तावित बड़ी लाइन पर विचार किया जा रहा है, और मुझे आशा है कि अन्त में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण किया जा रहा है वह प्राथमिक सर्वेक्षण है अथवा अन्तिम और यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह अन्तिम सर्वेक्षण है। इसे पूरा होने में तीन महीने लगेंगे।

श्री पी० आर० शिनाय : बंगलौर से उत्तर भारत के लिए केवल मद्रास होकर जाने वाली लाइन को छोड़कर और कोई बड़ी लाइन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मिराज-लौंडा लाइन को दक्षिण में बंगलौर तक, पूर्व में हास्पेट तक, तथा पश्चिम में गोआ तक बढ़ाया जाएगा और क्या इन लाइनों का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मिराज-लौंडा, गोआ-हास्पेट तथा लौंडा-हास्पेट लाइनों का सर्वेक्षण कराया गया है।

श्री पी० आर० शिनाय : बंगलौर के बारे में क्या विचार है ?

मुहम्मद शफी कुरेशी : इस लाइन का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले सर्वेक्षण के बारे में पूछा अब आप विस्तार के बारे में भी पूछ रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस लाइन से पश्चिम भारत होकर उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच सम्पर्क स्थापित होता है क्या मंत्रालय पांचवीं योजना अवधि में इस परियोजना को क्रियान्वित करना चाहता है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जा सकता है।

Shri Jagannath Rao Joshi : I had asked a question during the session period last year and the reply was the same as is today. Secondly, the hon. Minister said that it will take three months time but now six months have passed. Therefore, I would like to know as to why some importan

stations like Gokak are being excluded while converting this Line into broad gauge? What is the criteria adopted regarding laying of new lines? The criteria adopted by the Britishers was 'Quick movement of the Military and today the criteria is public facilities. Would this line not be laid until people resort to 'Gheraos and certain other agitations? Why the people of Gokak are being deprived by the facility?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Shri Joshi is resorting to what he has said but nothing will come out of that. I have said that we are considering the matter regarding Gokak line. This line will cost more than three crores of rupees. even then survey is being conducted.

भारतीय पत्तनों पर आने वाले जहाजों द्वारा भट्टी तेल (फरनेस आयल) का उपयोग किया जाना

*343. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों पर तेल भरने के लिए आने वाले बंकर हंगरी जहाज देश के कीमती और सीमित भट्टी तेल (फरनेस आयल) को ले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी नहीं।

(ख) (i) निकटवर्ती बन्दरगाहों पर प्रचलित मूल्यों के तुलनात्मक स्तर तक लाने के लिए बंकर मूल्यों में उचित ढंग से वृद्धि की गई है।

(ii) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर, जहाजों को केवल उतना ही बंकर जितना कि उन्हें अगली बन्दरगाह तक ले जाने के लिए पर्याप्त हो, सप्लाई के प्रबन्ध किए गए हैं।

Shri Shrikishan Modi : What are the rates decided for the supply of furnace-oil to foreign ships and what is the reaction of foreign companies in this regard? May I know whether our ships will also suffer the same inconveniences while passing through other country's ports?

श्री देवकांत बरुआ : विदेशों ने अपने पत्तनों में मूल्य बढ़ा दिए हैं और इन्हें अशोधित के मूल्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय दरों के स्तर पर ले आया गया है। अतः हमने भी उसी स्तर तक मूल्य बढ़ा दिए हैं। जो कठिनाइयां दूसरे देश के जहाजों को हमारे पत्तनों में होंगी वही कठिनाइयां दूसरे देशों के पत्तनों में भट्टी तेल के संबंध में हमारे जहाजों को भी होंगी।

Shri Shrikishan Modi : How much foreign exchange will be earned from the supply of furnace oil at increased rates to foreign ships in Indian Ports? Will there be any additional income in this way and if so, the amount thereof. May I know whether the additional money collected in this way is proposed to be spent on oil resources, if so, the details thereof?

Shri D. K. Barooah : There is no earning of foreign exchange because the furnace oil is supplied at the rates the crude is purchased. But it is seen that the oil companies will have an additional income of 16 crores annually but there is no scope of additional foreign exchange in that. These oil companies have been asked to keep this amount under "Cost and Foreight Adjustment Accounts".

कलकत्ता विद्युत् सम्भरण निगम को अपने नियंत्रण में लेना

*344. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को तत्काल अपने नियंत्रण में लेने के लिए उनके मंत्रालय की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : छपे एक समाचार के अनुसार भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को, जो ब्रिटिश एकाधिकारवादी कंपनी है, अपने हाथ में लेने पर निर्णय न करने की सलाह दी है और पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने इसे तुरन्त अपने हाथ में लेना चाहा था परन्तु केन्द्र ने अभी प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। तीसरे यह निगम केवल कुछ क्षमता का ही उपयोग कर रहा है और इसकी मशीनें बहुत पुरानी हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि :

"प्राइवेट लाइसेंस प्राप्त उपक्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने संबंधी अध्यादेश जारी करने संबंधी कुछ प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार ने भेजे हैं और वे विचाराधीन हैं"!

अतः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अद्यतन स्थिति क्या है और इस आवश्यक क्षेत्र में क्यों एक विदेशी एकाधिकारवादी कंपनी को चलने की अनुमति दी गई है और प्रतिवर्ष भारी लाभ विदेश भेजने दिए जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वास्तव में राज्य सरकार ने हमें बताया है कि वह उक्त निगम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती·····।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह समाचार पत्रों में छपा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ठीक है। परन्तु मैं अधिकृत सूत्र से बता रहा हूं। राज्य सरकार ने हमें यही सूचना भेजी है। हो सकता है कि यह पुराना उपक्रम हो परन्तु मोटे तौर पर यह सुचारु ढंग से काम कर रहा है। मेरे पास संगत आंकड़े हैं और मैं कह सकता हूं कि यह निगम काफी अच्छा काम कर रहा है। जहां तक प्रबन्ध के सरकारीकरण संबंधी अध्यादेश की बात है राज्य सरकार ने जो सुझाव दिया था वह इसी निगम के संबंध में नहीं था––यही बात मैं स्पष्ट करना चाहता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जहां तक मुझे पता है, क्योंकि विद्युत् उत्पादन आवश्यक मामला है,इसलिए औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार इसे सरकारी क्षेत्र में ही होना चाहिए कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम भारतीय पूंजी से चल रहा है और सरकार से 675 लाख का ऋण लिया हुआ है, इसके अलावा ऋण पत्र 750 लाख के हैं और उपभोक्ताओं की जमा राशि 443 लाख है। इस प्रकार कुल भारतीय पूंजी 1868 लाख है। साथ ही साधारण शेयर भारतीयों के 54.24 प्रतिशत हैं। वे सरकारी क्षेत्र की बिजली खरीदते हैं अर्थात् 6.25 पैसे प्रति यूनिट की दर पर दामोदर घाटी निगम से बिजली खरीद कर तिगुने दामों पर कलकत्ता में जनता और सरकारी अधिकारियों को वे बेच रहे हैं और इस प्रकार कलकत्ता विद्युत् प्रदाय अधिनियम के अनुसार अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं और यह क्रम कई वर्षों से चल रहा है।

फिर क्यों सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में इस ब्रिटिश कंपनी को इस प्रकार बनाए रखना चाहती है। जिसका अपना कोई योगदान नहीं है क्योंकि डी० वी० सी० से 6.25 पैसे पर बिजली लेकर वह कम्पनी कलकत्ता में 19 पैसे पर बेच रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इसके राष्ट्रीयकरण में क्या बाधा है ? अपने प्रश्नों का मैं स्पष्ट और ठीक-ठीक उत्तर चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनका प्रश्न यह है कि विद्युत अधिनियम के अनुसार वह उचित लाभ के अधिक लाभ कमाते हैं। उन्होंने पहले भी लिखा था और उसके उत्तर में कुछ जानकारी दी गई थी। उसी के अनुसार कंपनी ने वर्ष 1951 तथा 1952 और वर्ष 1963-64, 1964-65 तथा 1967-68 में उचित लाभ जितना ही शुद्ध लाभ कमाया। 1953 और 1-1-56 से 31-3-56 तक के लिए शुद्ध लाभ उचित लाभ से 16.6 प्रतिशत (22.5 लाख रुपये) और 26.8 प्रतिशत (47.5 लाख रुपये) और यह विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के तब के उपबन्धानुसार सीमा के अन्दर ही था। पूरे वर्ष का शुद्ध लाभ उचित लाभ से कम ही था। इस कंपनी को 1951 से 1972-73 तक की अवधि में कुल मिला कर 5.54 करोड़ का घाटा हुआ बताया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ..... (**व्यवधान**)

श्री ए० के० एम० इसहाक : प्रश्न के स्थान पर उन्होंने लम्बा भाषण दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि डी० वी० सी० से कैसे इतनी सस्ती बिजली लेकर तिगुने दामों पर बेची जाती है जबकि सरकार को घाटा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के बारे में है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सदस्य महोदय ने मुझे उस कम्पनी का वक़ील बताया है। जिसपर मुझे गंभीर आपत्ति है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनको धन उपयोक्ताओं और बैंकों से मिलता है। आपको डी० वी० सी० की बिजली किस दर पर मिलती है। आप शतप्रतिशत कंपनी के वकील हैं इसीलिए तो आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री ए०के०एम० इसहाक : बिजली प्रदाय निगम द्वारा कितनी बिजली पैदा की जाती है और क्या बिजली उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : पहले उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कह तो दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : वह तो कंपनी के सरकारीकरण के संबंध में था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनके प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में निगम ने गत तीन वर्षों में पैदा की गई और खरीदी गई बिजली के आंकड़े ये हैं :

वर्ष	शुद्ध उत्पादन	खरीदी गई बिजली (दस लाख यूनिटों में)
1970-71	1,555	1,289
1971-72	1,618	1,360
1972-73	1,733	1,046

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे मे मुझे विस्तार के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। यदि वह आया होता तो राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के माध्यम से ही आता।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी: कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनी है, जिसने हमारी जनता का शोषण किया है और गत कुछ वर्षों में काफी धन कमाया है और क्योंकि सकार ने काफी राज्यों में अनेक गैर-सरकरी कंपनियों का सरकारीकरण कर दिया है, अतः क्या हमारे राज्य में भी क्या सरकार इस कंपनी के उपकरणों से सज्जित एककों का सरकारीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्या कोई निश्चित नीति है या कोई भेद है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें नीति का कोई प्रश्न नहीं है, यदि राज्य सरकार इसका सरकारीकरण करना चाहे, तो हम उस प्रस्ताव पर अवश्य विचार करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या गत 6-8 मास में इस कम्पनी ने उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरें बढ़ाने का प्रयास किया है और क्या राज्य सरकार और अन्य औद्योगिक तथा इस कंपनी में इस पर मतभेद है ? यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कलकत्ता विद्युत प्रदाय कंपनी इस दर में वृद्धि पर जोर देती रही है और उन्होंने यह अनुरोध पश्चिम बंगाल सरकार से किया भी है और मेरे विचार में विचार करने के बाद राज्य सरकार ने उसे नहीं माना है। अतः दरों में वृद्धि नहीं हुई है।

हड़तालों और धीमे काम करने से रेलवे को हानि

*345. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में लोको कर्मचारियों की, विशेषकर लोकोमैन की, हड़तालों और धीरे काम करने के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) सरकार का भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लगभग 21 करोड़ रुपये। कर्मचारियों की सभी कोटियों की युक्तियुक्त मांगों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान सामूहिक समझौता तंत्र की विभिन्न श्रेणियों—स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के माध्यम से किया जाता है जो एक लम्बे समय से संवैधानिक रूप से एवं सोद्देश्य काम कर रहे हैं। फिर, गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों सहित किसी भी स्रोत से प्राप्त अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जब शिकायतों को खुले आम सामने रखने और उन्हें दूर करने के लिए इतनी गुंजाइश है तो गैर कानूनी हड़तालों या 'नियमानुसार काम' 'संरक्षापरक कार्य' जैसे आन्दोलनों के एकाएक चल पड़ने के लिए वास्तव में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

(2) भारत रक्षा नियम, 1971 का प्रयोग करते हुए 21-11-73 को जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत 26-11-73 से छः महीने की अवधि के लिए रेल सेवाओं में हड़ताल का निषेध है। नियमों के उपबन्ध के अनुसार इन आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय है।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए जो रेल कर्मचारी गैर कानूनी हड़तालों का आश्रय लेते हैं, उन्हें दण्ड दिया जा सकता है।

(4) हड़तालों और आंदोलनों के लिए भड़काने वाले तत्वों को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धान्त लागू करने का विनिश्चय किया गया है।

(5) अनुशासनहीनता के सभी मामलों पर दृढ़ता के साथ कार्रवाई की जायगी।

(6) शिकायत समाधान तंत्र एवं कार्यान्वयन कक्ष को उपयुक्त रूप से दृढ़ बनाया जा रहा है।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, question no. 357 can also be taken up simultaneously as it is a similar question.

Mr. Speaker : They are not quite similar. If members are interested in tha t we can rush through and cover that also.

Shri Naval Kishore Sharma : As per the Statement Railway Strikes in the country have resulted in a loss of 21 crores of rupees, but I think this is not correct because the loss of production and inconvenience to the public would amount to much more. In the context of strikes posing a serious threat to the nation, I want to know the position in regard to the person arrested under D. I. R.? Also whether some persons mentioned in item 3 of the Statement have been punished or prosecuted under the Industrial Disputes Act, 1947? Also, the effect of the steps taken by Government in this regard and whether the situation in regard to the Strike has imposed?

Mr. Speaker : Shri Vajpayee ji, your question relates to locomotion and it is different one.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is true that apart from the loss of traffic on Railways to the extent of Rs. 21 crores, the loss to Railways is much more and might be many crores of rupees and so far this loss is estimated at 80 crores. So far there have been five major strikes and the strike of loco-running-staff was the biggest and some persons were arrested in that connection under D. I. R. but they were promised to be released later as per an agreement and Minister's assurance in the House. Therefore, no one is under arrest under D. I. R. at present. Prosecution was on against same but for the sake of better relations, these cases were also withdrawn. It is true that we were not as strict as we ought to have been, but in future we have decided to be more strict on the principle of 'no work no pay' and action would be taken for sobotaging the Railways.

Mr. Speaker : You have brought in locomen also. You have mentioned question No. 357 as well. Let us now take up both of them together.

सरकार द्वारा मंजूर की गई लोको कर्मचारियों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा

*357. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1973 के दौरान लोको कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी राजस्व की हानि हुई और कितने जन-दिवसों का नुक्सान हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा मंजूर की गई लोको संगचल कर्मचारियों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख), एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिसम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप रेलों को 2.24 लाख जन-दिन और राजस्व में 6.11 करोड़ रुपये की हानि हुई।

जिस आश्वासन के आधार पर दिसम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली और इस संबंध में जो कार्रवाई की गई, वह इस प्रकार है :—

(1) किसी को परेशान करने अथवा दण्ड देने की कार्रवाई नहीं की जायेगी। यह स्वीकार कर लिया गया है कि केवल ट्रेड यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों के कारण किसी को परेशान करने अथवा दण्ड देने की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(2) लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति (मोहम्मद शफी कुरेशी समिति) की तुरन्त बैठक हो। तदनुसार एसोसिएशन की पूर्ववर्ती और वर्तमान शिकायतों पर विचार करने के लिए 28 दिसम्बर, 1973 को 11.00 बजे पूर्वाह्न एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने भी भाग लिया।

(3) सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया जाये और वारंट और सम्बन्धित मामले वापस ले लिये जायें। हिंसा और तोड़-फोड़ के मामलों को छोड़कर बाकी सब मामलों में इसे स्वीकार कर लिया गया है।

(4) 10 घंटा ड्यूटी को कार्यान्वित किया जाये। यह स्वीकार किया गया कि 10 घंटा ड्यूटी को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया पर 28 दिसम्बर, 1973 की बैठक में रेल मंत्री और श्रम मंत्री द्वारा आगे विचार किया जायेगा। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि ड्यूटी की अवधि को चरणबद्ध रूप में घटाकर 10 घंटे कर दिया जायेगा।

Shri Nawal Kishore Sharma : He has stated in the statement "further representation coming from any source including unrecognised unions are given due consideration and appropriate action is taken in each case. Then I would request him to refer to item (6) which reads thus :

"The grievances redressing machinery and implementation cell is being suitably strengthened.

But unrecognised unions always complain that the Railway Board and their high officials do not pay any attention towards their complaints. The Presidents of most of their unions are M.Ps. I would like to know whether it is a fact that the Railway Board and the General Manager do not send replies to the letters of the Members of Parliament on the plea that this matter is related to staff. In case it is true then I want to ask whether steps would be taken to remove the legitimate grievances of the workers.

It has been stated in item No. 6 that "The grievances redressal machinery and implementation cell is being suitably strengthened." What steps have been taken in this regard. The reply given by the hon'ble Minister is vague. Will he please elaborate?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It has repeatedly been explained that there are two recognised unions in the Railways with whom negotiations take place and which are valid. Besides there are seven hundred unions in the Railways and if each one is recognised then a difficult situation would arise. In spite of all this, if an unrecognised union is represented by a Member of Parliament and if he places grievances of the employees before the Railway Ministry as a Member of Parliament, then a suitable reply is sent to the hon'ble Member. Recently there was an agitation by Guards. Hon'ble Member Shri Yadav represented them. We discussed the matter with him. We have given instruction at divisional and zonal levels that the complaints of Cabin and shop level should be heard and possibly disposed of even if unrecognised unions lodge such complaints.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is contradiction in the replies given by the hon'ble Minister. In reply to the question of Shri Sharma he has said that there was a loss of Rs. 21 crores. But in reply to my question he has said :

> "The number of man-days lost and the extent of loss of revenue suffered by the Railway as a result of locomen's strike in the month of December, 1973 are 2·24 lakhs and 6·11 crores respectively.

I want to know the correct figures.

Mr. Speaker : His question was general one, whereas yours was specific.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Sharma's question was also related to locomen. I would like to know the number of sittings of the Qureshi Committee which was set up to go into the complaints of locomen and the number of issues which have been disposed of and whether it is a fact that the Railway Minister has agreed to include the representatives of Guards in the Qureshi Committee?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Guards have not been included in that Committee. Shaimaji had asked the number of strikes in 1973 in which locomen took part and the total loss as a result thereof? There were 75 strikes upto the month of December and the strike by locomen was one of them. Shri Vajpayee wanted to know the loss as a result of strike by locomen in the month of December. As a result of this strike there was a loss of rupees six crores The total loss is Rs. 21 crores and rather more. The Committee which was formed under my Chairmanship, has held more than twelve meetings and all the issues except one have been settled. This is regarding implementation of 10 hour duty programme. We have fixed next meeting for 3rd April to examine this issue. Thereafter a decision will be taken after investigating the matter on the spot in four divisions that whether it is possible to implement this programme in three years period or loss them that? All of the issues have been settled.

Shri Atal Bihari Vajpayee : When the Guards resorted to 'work to rule' agitation, a Lok Sabha Member Shri Ishwar Choudhury accompanied some guards to see the Divisional Manager of Danapur at Gaya Stations. But Shri Gulati, the Divisional Manager said "I am not prepared to talk to any bloody M.P." I have already confirmed this incidence. I would like to know whether Railway officials will be allowed to behave like this with Members of Parliament.

Shri Ramavatar Shastri : The services of such officers should be terminated. There are many complaints about this type of behaviour of Railway Officials.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जनसंघ के नेता ने जो बात अभी कही है, यदि वह सच है तो मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि उस अधिकारी को तत्काल मुअत्तिल कर दिया जायेगा। हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि उप-मंत्री उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे जिसने एक संसद सदस्य के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। मंत्रियों के लिये कुछ भी विशेषण लगाये जायें परन्तु हम नहीं चाहते कि हमारे लिये इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री भी संसद सदस्य होते हैं । हम संसद सदस्यों को 'ब्लडी एम० पी०' कहे जाने की अनुमति नहीं दे सकते ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If the incidence to which Shri Vajpayee has drawn attention of the House is true, it is really a deplorable one. I assure the House that I would certainly give more weight to the session given by the Member of the House and if this is true, the concerned officer would be dealt with firmly.

Shri R. P. Yadav : It has been observed in the past that the Government takes steps only when the workers resort to 'strikes', 'go slow' or 'work to rule' agitations. But they incur huge losses by them. I want to know whether some method will be evolved by which legitimate demands are met before such agitations take place so that Railways may not incur losses?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If some issue is raised which is in accordance with the rules and proper notice is given, the examineee it thoroughly.

Shri Nathu Ram Ahirwar : Recently Guards resorted to 'work to rule' as a result of which Government had to incur losses. I would like to know whether the work was being done against the rules hitherto, if so, whether steps would be taken to amend the rules so that the work could be carried on efficiently.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : 'Work to rules' is a new type of agitation, which does not find its place in any book or legislation. It is just an excuse not to work. When they do not want to work, they resort to 'work to rule'.

श्री समर मुखर्जी : क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों ने जो आन्दोलन किया था उसमें उनकी मुख्य मांग 'बातचीत करने का अधिकार' थी । क्या लोको कर्मचारियों की एसोसिएशन को स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि उन्हें यह अधिकार दिया जायेगा और इसी आश्वासन के आधार पर हड़ताल समाप्त की गई थी, मंत्री महोदय द्वारा अब दिये गये वक्तव्य से पता चलता है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था और एसोसिएशन को संसद सदस्यों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : लोको कर्मचारियों के संसद सदस्यों के माध्यम से बातचीत करने में कोई रुकावट नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने कोई आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उनकी मांगों में एक मांग यह भी थी कि उन्हें बातचीत करने का अधिकार मिलना चाहिये अर्थात् उन्हें संघ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये । मंत्रालय ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है ।

Shri R. S. Pandey : The hon'ble Minister has stated that there were 75 strikes in 1973 as a result thereof there was a loss of Rs. 80 crores. I feel that 1973 was a year of strikes for the Railways. The hon'ble Minister has said that Government have not taken any stern action so far but they will take stringent measures if failure. It is stronger that Government has been tolerating so much indiscipline. I want to know whether Government would evolve any scheme under which demands of the workers may be accepted before hand if they are legitimate ones so that strikes could be averted? Besides, there should be a true for five years so that movement of Railways could take place without any hinderance, if so the details of such scheme?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have already stated that there are two recognised unions in Railways *viz.*, A.I.R.F. and N.F.I.R. All these issues, which are raised by category unions, are taken up by these recognised unions. There is a regular permanent negotiating machinery wherein all such issues are examined. But unfortunately category unions want to raise some issues which have already been taken up by recognised unions.

Shri Ram Singh Bhai : I would like to know whether strikes in Railways take place before the submission of demands or after the submission of demands?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Both the things can happen, but generally we do not have any prior information and work is stopped before hand.

Shri Madhu Limaye : Whether Railway Ministry wants that departmental strikes should take place so that they may not have to face the situation in which the six main demands submitted by the Railway Federation or the Action Committee and large scale strike of Railways may not take place? I want to know whether this is the intention of the hon'ble Minister?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : No, Sir. This is not our intention.

श्री था किरूतिनन : क्या यह सच है कि मद्रास में जनरल मैनेजर के कार्यालय के सामने इन लोकोमैनों की रिले भूख-हड़ताल जारी है; यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं। 10 घण्टे की ड्यूटी के बारे में यहां सभा में आश्वासन दिया गया था कि उसे क्रियान्वित किया जायेगा, जहां तक अन्य मांगों का सवाल है, कुरेशी समिति को उनकी जांच करने को कहा गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुरेशी समिति ने उन मांगों की जांच कर ली है यदि हां, तो इस बारे में कितने निर्णय किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत संबंधित नहीं है। परन्तु यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी हो और वह देना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री था किरूतिनन : मद्रास में लोकोमैन रिले भूख हड़ताल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न वर्ष 1973 में रेलवे को हुई हानि के बारे में है और आप आज जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। यदि आप सूचना दें तो वह आपको जानकारी दे देगें।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या इन हड़तालों का एक कारण यह नहीं है कि फेडरेशन के अन्तर्गत ये तथाकथित मान्यता प्राप्त संघ वस्तुतः अधिक रेलवे विभागों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार "एक रेलवे में एक संघ" की प्रणाली आरंभ करने जा रही है जिसका गठन गुप्त मतदान के आधार पर हो? क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने एक गैर-पंजीकृत संघ को मान्यता दे रखी है जबकि उसी नाम के एक अन्य पंजीकृत संघ को मान्यता नहीं दी गई है और इस गैर-कानूनी कार्यवाही के कारण उपद्रव तथा हड़तालें हो रही हैं?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम एक उद्योग के लिये एक संघ रखने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु जैसा कि प्रश्न है आज हमने दो संघों को मान्यता दे रखी है और वे कर्मचारियों तथा उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम गुप्त मतदान द्वारा एक संघ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : आप ने एक गैर-पंजीकृत संघ को मान्यता दी है जोकि गैर-कानूनी बात है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने ऐसे किसी संघ को मान्यता नहीं दी है।

उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन खर्च की निर्धारित सीमा का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने के लिए की गई कार्यवाही :

*346. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि तथा रुपये के मूल्य में हो रही गिरावट के कारण अब किसी भी उम्मीदवार के लिए, निर्धारित निर्वाचन खर्च से किसी संसदीय अथवा विधान सभा का निर्वाचन लड़ना सम्भव नहीं रहा; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन खर्च की निर्धारित सीमा का वास्तविक व्यय के आधार पर पुनरीक्षण करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). निर्वाचन-व्ययों की विहित परिसीमाओं का पुनरीक्षण किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये परिसीमाएं, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर जनवरी, 1971 में बढ़ाई गई थीं और जब कभी भी इनके बढ़ाए जाने के लिए पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा, नियमों में संशोधन करके ऐसा किया जा सकेगा।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का अभिप्राय सरकार से यह जानना था कि क्या सरकार यह समझती है कि किसी उम्मीदवार के लिये निर्धारित व्यय-सीमा के भीतर कोई संसदीय अथवा विधान सभायी चुनाव लड़ पाना संभव है और सरकार का उत्तर है 'हां'।

सरकार के अपने कहने के अनुसार सिर्फ पिछले वर्ष ही मूल्यों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1961 के बाद रुपये के मूल्य में 36 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। गैसोलीन के मूल्यों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मेरा प्रश्न यह है। क्या सरकार इन तथ्यों से इन्कार करती है या वह यह समझती है कि इस के बावजूद भी इस व्यय-सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री एच० आर० गोखले : सरकार इस बारे में इतनी सख्त नहीं है। नियमों के अधीन अपनी सीमा का निर्धारण चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाता है। परिवर्तित परिस्थितियों में, यदि इस मामले को चुनाव आयोग के पास सलाह के लिए भेजा जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : चुनाव कानून में संशोधन के लिये एक संयुक्त समिति है और इसने कुछ सिफारिशें की थीं। कुछ सिफारिशों में विशेष समिति आदि के गठन की भी बात शामिल थी। इस बारे में सरकार का क्या मूल्यांकन है, क्या इन में से कुछ सिफारिशों को

क्रियान्वित किया जायेगा। तब तक क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उम्मीदवारों को अपने स्थानों से त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि उन्हें चुनाव संबंधी व्यय-सीमा का पालन करना पड़ता है जिनका कि आज की स्थिति में वस्तुतः कोई औचित्य है?

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार से, ये प्रश्न संबंधित नहीं हैं। माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग संयुक्त समिति की कुछ सिफारिशों से संबंधित था। संयुक्त समिति ने विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की हैं। प्रश्न से संबद्ध चुनाव-व्यय की सीमा का जहां तक संबंध है संयुक्त समिति ने एक विशेष उप-समिति की नियुक्ति की थी। अब दो पहलुओं पर विचार हो रहा है। एक पहलू यह था कि क्या निर्धारित सीमा में कोई परिवर्तन किया जाये। संयुक्त समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यह दृष्टिकोण बनाना तो संभव नहीं है कि कोई सीमा ही न रखी जाये। इसलिये सरकार इस बारे में तो विचार नहीं कर सकती कि व्यय-सीमा को समाप्त ही कर दिया जाये। उन्होंने और भी कई सिफ़ारिशें की थीं जिनपर सरकार विचार कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मैं इस मामले को चुनाव आयोग की सलाह के लिये भेजने को सहमत हूं।

Shri M. C. Daga : In view of the recommendations made by the Joint-Committee does the hon. Minister wish that the law enacted should not be implemented or in that case would he accept the following recommendation:

In keeping with the Committee's view, five copies of electoral bills instead of two shall be supplied free of charge to every recognised political party.

Whether all these recommendations in Para 17·16 of the Report will be implemented or not?

The Joint Committee has recommended that either the concerned political party should furnish the accounts of the expenses of their candidate or the candidate himself should make that available what is your view in this regard?

श्री एच० आर० गोखले : उसने अवश्य ही कई सिफारिशें की थीं। उदाहरणार्थ, उसने यह सिफारिश की थी कि चुनावों के समय पर्चियों को भेजने के लिये डाक सुविधायें दी जानी चाहियें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह भी सिफारिश थी कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को कुछ चुनाव सूचियां उपलब्ध कराई जानी चाहियें। ऐसी बात नहीं है कि सरकार इन सिफ़ारिशों पर विचार ही करने को तैयार नहीं है। उन पर विचार किया जा रहा है। परन्तु उनमें से कुछ सिफ़ारिशों को मान लेने से भारी खर्चा पड़ेगा। मैं इस के उदाहरणार्थ कुछ आंकड़े देता हूं। केवल एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में ही डाक द्वारा पहचान पर्चियां वितरित करने पर 1,10,934 रुपये खर्च आता है। वर्ष 1971 में मतदाताओं की संख्या 28 करोड़ से अधिक थी और लोक सभा में चुने जाने वाले स्थान 519 थे। वर्ष 1976 में मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हो जायेगी लगभग 30 करोड़ हो जायेगी, और पहचान पर्चियों को बांटने का खर्च, डाक दरें बढ़ने के बाद, प्रति चुनाव क्षेत्र 1,15,000 रुपये हो जायेगा। इसलिये यहां यह सिफारिश आकर्षक लगी थी वहां राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार करना संभव नहीं था। परन्तु चुनाव सूचियों तथा वितरणार्थ छपी हुई पर्चियों की सप्लाई के प्रश्न विचाराधीन हैं। शायद मैं गलती पर भी हूं। मगर हाल ही में उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में छपी हुई पर्चियां बांटी गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं ने कहा था कि शायद मैं गलती पर भी हूं मुझे ऐसा पता लगा है। मैं इसकी पुष्टि करूंगा।

श्री पीलू मोदी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि जहां तक मतदाता-पर्चियों का संबंध है यदि किसी स्थान के लिये आठ या पांच उम्मीदवार हैं, तो प्रत्येक को ऐसा करना पड़ेगा चाहे वह डाक-पर्ची हो या कोई अन्य हो। यदि सरकार प्रत्येक मतदाता को पहचान-पत्र देती--एक प्रकार का स्थायी पहचान-पत्र तो यह केवल एक ही बार करना पड़ता और पांच या आठ उम्मीदवारों को हर बार वही प्रक्रिया या वही खर्च नहीं करना पड़ता। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय धन की दृष्टि से, यदि सरकार बस एक ही बार ऐसा कर देती तो कितना धन बच सकता था ?

श्री एच० आर० गोखले : यह भी उसी समस्या का एक अंग है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। संयुक्त प्रवर समिति ने इस पर भी विचार किया था। बिना चित्र के मतदाता को पहचान-पत्र देना .....

श्री पीलू मोदी : चित्र सहित।

श्री एच० आर० गोखले : इस विभिन्न बातों पर विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि इस का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि यह पहचान पत्र का अर्थ मतदाता द्वारा स्वयं को उस सूची में मतदाता सिद्ध करना जिसमें उसका नाम दर्ज है। इस पर बहुत लागत आयेगी और इसको व्यवहार्य नहीं माना गया।

श्री पिलू मोदी : लागत तो पांच गुना होगी। मैं ने खर्च का वास्तविक हिसाब लगाया है यदि सभी उम्मीदवारों का खर्च जोड़ दिया जाये तो लागत 2 1/2 करोड़ रुपये होगी जबकि सरकार को तो केवल एक ही बार खर्च करना पड़ेगा वह चाहे जो भी हो।

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय के विचारार्थ एक अच्छा सुझाव है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि समिति की सिफारिशों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस संदर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ऐसी सीमायें अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी हैं और क्या सरकार ने इस बारे में अध्ययन किया है कि क्या इन सीमाओं का अन्य लोकतांत्रिक देशों में पालन किया जाता है, यदि हां, तो यह कैसे सुनिश्चय किया जाता है कि उनका पालन किया जाता है ?

श्री एच० आर० गोखले : कुछ अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी इस से संबंधित स्थिति का संयुक्त प्रवर समिति ने अध्ययन किया था। अधिकांश देशों में ये सीमायें नियत हैं और वहां इन व्यय सीमाओं का उल्लंघन होने पर चुनाव-याचिकायें दर्ज करने की प्रणाली भी है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Election Commissioner has also recommended that besides those of undividing candidates accounts of political parties should also be maintained. Have the Government explained that recommendation, and would they ask the Election Commissioner to formulate some concrete proposal in this regard ?

श्री एच० आर० गोखले : चुनाव आयोग की सिफ़ारिशों तथा संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद चुनाव कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच वार्ता

*347. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की मांगों का निर्णय करने के लिये 27 फरवरी, 1974 को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच दूसरी बार बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलिय म और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : **(क)** और **(ख)**, उन के वेतन तथा भत्तों आदि में वृद्धि किये जाने के संबंध में अधिकारियों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस के प्रबन्धको तथा "वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारी संघ' और 'अधिकारी संघ' के प्रतिनिधियों के बीच 27 फरवरी, 1974 को तीसरी बार बातचीत हुई थी । इस विचार-विमर्श के आधार पर, आधिकारियों की कुछ श्रेणीयों के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक प्रस्ताव भेजा है । यह प्रस्ताव सरकार के पास 13 मार्च 1974 को पहुंचा था और इसकी जांच की जा रही है । अधिकारियों की शेष कुछ श्रेणियों की मांगों पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अभी विचार किया जा रहा है ।

Treatment of Checking S taff as Running Saff on Indian Railways

*348. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the difficulties and needs of the checking staff of Indian Railways;

(b) if so. whether Government are considering the question of treating the checking staff as running staff and providing necessary insurance facilities to them, and

(c) if so, the time by which this will be done and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes Sir. The Government are aware of the difficulties and needs of all categories of staff on Indian Railways including Ticket Checking Staff.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Electrification of Villages in M. P.

*349. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages in Madhya Pradesh which were electrified during the financial year 1972-73;

(b) the number of villages which are proposed to be electrified by the end of 1973-74; and

(c) the time by which the programme of electrification of all the villages in Madhya Pradesh will be completed?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a) 1146 villages.

(b) & (c) : There are 70414 villages in Madhya Paradesh. 10278 villages have been electrified upto 31-12-1973. The total is likely to reach 10700 by 31-3-1974. The provision in the 5th Plan will help in further electrification of 9000 villages. While the remaining villages will be progressively electrified during the subsequent Plans, it is not possible to indicate the date by which electrification of all the villages in Madhya Pradesh will be completed.

हावड़ा की मार्टिन बर्न रेलवे को अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध

*350. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा की मार्टिन बर्न रेलवे को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) विगत में इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए थे लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन जीर्ण शीर्ण लाइट रेलों का परिचालन नितान्त अलाभप्रद था । फिर भी, पश्चिम बंगाल सरकार से विचार-विमर्श करने के पश्चात यह विनिश्चय किया गया है कि मार्टिन बर्न रेलों को अपने हाथ में लेने की अपेक्षा उस क्षेत्र में बड़े ओमान की लाइनों का निर्माण किया जाय ।

Stoppage of Production of Diesel Locomotives

*351. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have stopped production of diesel locomotives; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

उद्योग को भट्टी तेल वितरित करने के लिये समिति

*352. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग को भट्टी तेल आवंटित करने के लिये कोई कसौटी निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त प्रयोज के लिये कोई समिति गठित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं के सभी वर्गों को, उन की निर्धारित मांग अथवा 1973 की वास्तविक खपत, इन में से जो भी हो, की तुलना में, भट्टी के तेल की सप्लाई में इस समय एक सार 10 प्रतिशत दक्षता कटोती की जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) तकनीकी विकास के सचिव एवं महानिदेशक समिति के चेयरमैन हैं और इस के अतिरिक्त इस में रेल मंत्रालय, इस्पात तथा खान मंत्रालय, केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के प्रतिनिधि और इस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल है। डी० जी० टी० डी० के औद्योगिक सलाहकार इस के सदस्य-सचिव हैं। यह समिति, और बातों के साथ साथ, औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में अवरोध किये वगैर देश में भट्टी के तेल की खपत में यथाशीघ्र कमी करने के उपायों की सिफारिश करेगी; उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को भट्टी के तेल के आवंटन के लिये प्राथमिकताए निर्धारित करेगी ; भट्टी के तेल पर आधारित औद्योगिक यूनिटों के नये प्रतिवेदनों की जांच करेगी; उन उद्योगों जो प्रौद्योगिकी तथ्यों पर भट्टी के तेल के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, को कोयले की उपलब्धि तथा सप्लाई की प्रगति पर निगरानी और भट्टी के तेल के प्रयोग तथा ईंधन दक्षता में वचत के बारे में की गई प्रगति का ध्यान रखेगी।

आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कान्फेडरेशन द्वारा नियमानुसार काम करने का निर्णय

*353. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी से 17 फरवरी, 1974 तक मद्रास में हुई आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कान्फेडरेशन की बैठक में लिये गये इस निर्णय की और आकर्षित किया गया है कि यदि कान्फेडरेशन की न्यूनतम मांगें स्वीकार नहीं की जातीं तो वे 15 अप्रैल, से नियमानुसार काम करना आरम्भ कर देंगे और 16 मई, 1974 से सब कार्य करना बन्द कर देंगे ;

(ख) उक्त कान्फेडरेशन की अधिकारिता क्या है और जोनल अथवा कार्मिक आधार पर यह रेलवे कर्मचारियों के किन बार्गों का प्रतिनिधित्व करता है; और

(ग) क्या सरकार को कान्फ्रेडरेशन से कोई अभ्यावेदन अथवा मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कान्फेडरेशन मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है कि निम्नलिखित 15 कौटिवार संघ इसकी संघटक इकाई हैं :—

1. भारतीय रेलवे लोको यांत्रिक कर्मचारी संघ ।
2. अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ।
4. अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी संघ ।
4. अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संघ ।

5. भारतीय रेलवे टिकट जांच कर्मचारी संघ ।
6. अखिल भारतीय रेलवे लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ।
7. भारतीय रेलवे सिगनल एवं दूर-संचार कर्मचारी संघ ।
8. अखिल भारतीय गार्ड परिषद ।
9. अखिल भारतीय गाड़ी लिपिक संघ ।
10. अखिल भारतीय रेलवे लेखा कर्मचारी संघ ।
11. अखिल भारतीय सवारी डिबा एवं माल डिब्बा कर्मचारी परिषद् ।
12. अखिल भारतीय रेलवे चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी संघ ।
13. अखिल भारतीय गाड़ी नियंत्रक संघ ।
14. अखिल भारतीय रेलवे आशु लिपिक संघ ।
15. अखिल भारतीय रेलवे ड्राइंग कर्मचारी संघ ।

(ग) जी हां ।

यूनियन कार्बाइड को कुछ वस्तुएं बनाने के लिये रियायतें

*354. **श्री मधु लिमये :** क्या **पट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड को कुछ वस्तुएं बनाने के लिए क्या रियायतें दी गई हैं ; और

(ख) देशी निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नावाज खां) : (क) उन वस्तुओं, जो पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के क्षेताधिकार में हैं, के बारे में मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड को कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई हैं। लेकिन उपयुक्त तथा सामायिक पौधा-सरंक्षण आवरण की व्यवस्था करने की दृष्टि से कीटनाशी दबाइयों के बारे में सूत्रयोग के लिये अपेक्षित तकनीकी सामग्रियों के लिये तदर्थ आयात की इजाजत दी जाती है। इस प्रकार का तदर्थ आयात उद्योग के दोनों भारतीय तथा विदेशी क्षेत्रों को उपलब्ध है और पौधा-संरक्षण तथा जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ साथ कीटनाशी उद्योग के शीध्र तथा विनियमित विकास के लिये रूपांकित किये जाते हैं।

(ख) इस बारे में सरकार की नीति का उल्लेख औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा निकाले गये प्रकाशन "गाइडलाइन्ज फार इंडस्ट्रीज-1973-74" में किया गया है।

Collapse of Wagon Trailer of Badarpur Power House

*356. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(*a*) whether the wagon trailer of Badarpur Power House, which was installed only some months back, has collapsed in February, 1974;

(*b*) if so, the results of the enquiry made in this regard by Government; and

(*c*) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C Pant) : (*a*) The Cradle of the Wagon tippler (and not trailer) at Badarpur Power House got displaced from the foundation on 21st February, 1974.

(*b*) & (*c*) : A Committee of experts has been appointed to enquire into the matter. The report of the Committee is awaited.

महाराष्ट्र में कृष्णा बेसिन में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

*358. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कृष्णा बेसिन में ऐसी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं तथा उनके स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी स्वीकृति नहीं मिली है ;

(ख) क्या उन्होंने इन परियोजनाओं को, तथा विशेषकर ओरलवाड़ी और सिद्धेवाड़ी परियोजनाओं को, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का पंचाट मिलने पर, शीघ्र ही स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कृष्णा जल विवाद के कारण स्वीकृति के लिए निलंबित पड़ी हैं :—

परियोजना का नाम	स्थल
खंडाला . . .	उस्मानाबाद जिले के तुल्जापुर तालुका में
पानगांव हिंगनी . . .	शोलापुर जिले के बर्शी तालुका में
बाजारे	पूना जिले के पुरंधर तालुका में
भंडार्दी	उस्मानबाद जिले के भूम तालुका में
येरलवादी	सतारा जिले के खटाऊ तालुका में
हाजिज हिंगनी . . .	शोलापुर जिले के वर्शी तालुका में
सिना	अहमदनगर जिले के कारजात तालुका में
सिद्देवादी	सांगली जिले के तासगांव तालुका में
उलुप . . .	उस्मानाबाद जिले के भूम तालुका में
गुडावले	कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ तालुका में

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय 24 दिसम्बर, 1973 को दे दिया। राज्य सरकार से उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नई परियोजनाओं का न्यायाधिकरण के निर्णय

के प्रकाश में पुनरीक्षण करने तथा जहां भी आवश्यक हो संशोधित परियोजनाओं तथा अद्यतन प्राक्कलनों को भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों ने स्कीमों में यथा आवश्यक संशोधन कर लिए हैं तथा उनको अब केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच की जा रही है ; और जांच पुरी हो जाने के उपरांत स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जाएगी।

मुरादाबाद के निकट रेल दुर्घटना

*359. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1974 को मुरादाबाद के निकट काठघर पर हुई रेल दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या वह मुआवजा जिसको देने का उन्होंने बचन दिया था, हताहतों अथवा उनके परिवारों को अदा कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) **और** (ख) यह दुर्घटना 21-2-74 को हुई थी। रेल संरक्षा के अपर आयुक्त उत्तरी सर्किल, लखनऊ, इस दुर्घटना की सांविधिक जांच कर रहे हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) यदि कोई कर्मचारी उत्तरदायी पाया गया तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

(घ) दावा आयुक्त के विनिश्चय के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाना है। मुआवजे के दावों का निर्धारणकरने के निमित्त एक तदर्थ दावा आयुक्त को नियुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया है।

कर्नाटक में कालीनदी पनबिजली परियोजना और कावेरी परियोजना के लिए पृथक पृथक प्रावधान

*360. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कर्नाटक राज्य में कालीनदी पनबिजली परियोजना और कावेरी परियोजना के लिए पृथक-पृथक प्रावधान करना मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कर्नाटक के लिए 1974-75 की वार्षिक योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कावेरी बेसिन में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अभी तक योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्रीनगर, कश्मीर में तेल की खोज

*361. श्री एम० एस० संजीवीराव
श्री भागीरथ भंवर } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में श्रीनगर तथा अन्य स्थानों में तेल की खोज करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) व्यधन के लिये चार स्थान चुन लिये गये हैं । वे जम्मू तथा काश्मीर के श्रीनगर जिले के रायथान तथा चतरगांव तथा बारूमूला जिले के पत्तन में हैं ।

नासकि में रेलवे उपकरण संयंत्र

*362. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री राम साहय पान्डें } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नासिक में एक रेलवे उपकरण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) उक्त संयंत्र में उत्पादन कब से आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस संयंत्र की स्थापना पर प्रारम्भिक खर्च लगभग तीन वर्षों से अधिक की अवधि में 9.38 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो पूंजी खाते में डाला जायेगा ।

(ग) नियमित रूप से उत्पादन दिसम्बर, 1976 से शुरू होने की आशा है ।

Refining of Additional Crude

*363. **Shri Chandra Bhalmani Tewari** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether five lakh tonnes of crude is available annually in the new wells of Assam and Nagaland;

(*b*) the steps proposed to be taken by Government to arrange refining thereof; and

(*c*) the reasons for delay in arranging for refining when the country is facing oil crisis ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Barooah) : (*a*) The present production from ONGC's fields in Assam is about 4 lakh tonnes per annum. An additional production of slightly over 5 lakh tonnes per year can be expected from ONGC wells in Assam in about 2 to 3 years.

(*b*) & (*c*) The present output of about 4 lakh tonnes is being refined at the Barauni refinery. Further, the Bongaigaon refinery is expected to go on stream during the second quarter of 1976. Steps have been taken to suitably enlarge the capacity of the oil pipeline so that the availability of extra crude will coincide with the Bongaigaon refinery going on stream.

Trade Unions in Central Railway

3579. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of trade unions functioning in the Central Railway and the number among them of those which are recognised giving particulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : There are three Unions functioning on the Central Railway, out of which two are recognised, salient particulars of which are given below :—

Name	Whether recognised or not	Whether to affiliated any All India organisation.	Membersip as on 13-12-1973
1	2	3	4
National Railway Mazdoor Union (Head Office)	Recognised	All India Railwaymen's Federation.	75908
Central Railway Mazdoor Sangh	Recognised	National Federation of Indian Railwaymen.	64934

गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड

3580. **श्री विश्वनाथ झुझुंनवाला : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य :** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गोलचा प्रापर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक के पास कुल कितनी धनराशि जमा हैं;

(ख) क्या आस्थगित भुगतान के आधार पर आय-कर के भुगतान के मामले को सुलझाने तथा जमा धनराशि को ऋणदाताओं के बीच वितरित करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है और ऋणदाताओं को और आगे किस्तें कब दी जायेंगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) महोदय का ध्यान दिनांक 3-4-1973 के लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5704 विशेषत: उसके भाग (क) में दिये गये बचन को पूर्ण किये जाने में, सभापटल पर प्रस्तुत विवरणपत्र, पर जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 26-3-1973 तक सरकारी समापक द्वारा 77,01,591 रु० की राशि प्राप्त की गई थी, आकर्षित किया जाता है।

(ख) ध्यान दिनांक 20-11-1973 को उत्तरित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1206 विशेषत: भाग (ग) तथा (घ) जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आयकर विभाग के साथ समझौते का निष्पादन, राजस्थान उच्च न्यायालय में, परिसमापन में होने वाली कम्पनी के कुछ जमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत समझौते की व्यवस्था योजना की विषयवस्तु है, पर आकर्षित किया जाता है। तिसपर कम्पनी का आयकर देनदारियों के लिए उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का मामला है।

(ग) पूर्वोक्त कार्यवाहियां अभी भी अनिर्णीत हैं और सरकारी समापक द्वारा आगे लाभांश के वितरण का मामला न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला है, जैसा कि ऊपर संदर्भित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1206 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

ट्रैफिक, एकाउंट्स आफिस, अजमेर, तथा दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के फोरेन ट्रेफिक एकाउंट्स आफिस में कर्मचारियों को चिकित्सा-व्यय की वापस अदायगी

3581. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्थित ट्रेफिक एकाउंट्स आफिस तथा दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के फोरेन ट्रेफिक एकाउंट्स आफिस के उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1971 के बाद चिकित्सा व्यय की वापस अदायगी के लिये आवेदन किया ; और

(ख) यदि हां, तो दो वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भी उन्हें उक्त भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31

(ख) 11 मामलों में चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य सीमा तक मंजूर कर दी गयी है। 2 मामले नियमों के अन्तर्गत नहीं आते थे इसलिए, उनकी प्रतिपूर्ति मंजूर नहीं की गयी। 18 मामलों की जांच की जा रही है और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए कद उठाये जा रहे हैं।

कलकत्ता में ग्राहकों द्वारा पेट्रोल-विक्रेताओं के पास धनराशि जमा कराया जाना

3582. **श्री डी० वी० चन्द्र गोडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता में पेट्रोलिय विक्रेताओं ने अपने मासिक ग्राहकों से कहा है कि वे अपना प्रतिदिन का ईंधन प्राप्त करने के लिये उनके पास तुरन्त ही पर्याप्त धनराशि जमा करादें और फिर उस राशि में उनके मासिक बिल की राशि को समायोजित कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि यदि सभी मासिक ग्राहक काफ़ी बड़ी धनराशि विक्रेताओं के पास जमा करा देंगे तो विक्रेताओं के पास बिना ब्याज दिये बहुत बड़ी धनराशि जमा हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) जी, हां । दिसम्बर 1973 से डीलरों ने नकद या उधार विक्रय कार्य जमा राशि के आधार पर करना आरंभ कर दिया है । उधार ग्राहकों को 45 से 60 दिन के उपभोग के बराबर अग्रिम धन राशि जमा करनी होती है । इस संबंध में वित्तीय उलझनों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। उधार बिक्री की शर्तों को डीलरों तथा ग्राहकों के ऊपर छोड़ दिया गया है जो उधार की इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं ।

पश्चिम रेलवे के फारिन, ट्रैफिक एकाउंट्स आफिस, दिल्ली के कर्मचारियों के लिए 24 क्वार्टरों का निर्माण

3583. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के फारिन ट्रैफिक एकाउंट्स अफिस के कर्मचारियों के लिय 24 क्वार्टरों के निर्माण को निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजरी दे दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा क्वार्टरों के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी (कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यालयेत्तर इमारतों के निर्माण पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध के हटते ही इनका निर्माण शुरू कर दिया जायेगा ।

अति प्रवीण बढ़ई ग्रेड-II, अजमेर वर्कशाप (पश्चिम रेलवे) के पद के लिए व्यावसायिक परीक्षण के बारे में अभ्यावेदन संबंधी निर्णय

3584. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री अति प्रवीण बढ़ई ग्रेड-II, अजमेर (पश्चिम रेलवे) के पद के लिए व्यावसायिक परीक्षण के बारे में अभ्यावेदन विषयक 31 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1213 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी (कुरेशी) : संलग्न विवरण में अपेक्षित सूचना दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6471/74]

बम्बई (पश्चिम रेलवे) में टी० आई० ए० एस० की नियुक्ति पर हुआ व्यय

3585. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई (पश्चिम रेलवे) में स्थायी रूप से नियुक्त टी० आई० ए० एस० की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद अनेक आर० टी० आई० ए० एस० प्रत्येक माह बंबई में प्रति-नियुक्ति पर भेजे जाते हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और 1971-72 और 1972-73 के वर्षों के दौरान उनके बम्बई में ठहरने के लिए उन्हें दी गई यात्रा भत्ते की कुल राशि कितनी है : और

(ग) इस आवर्ती व्यय को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । बम्बई में प्रति माह औसतन दो या तीन आर० टी० आई० ए० प्रतिनियुक्त किये जाते हैं।

(ख) बम्बई क्षेत्र में छुट्टी लेने, टी० आई० ए० को विशेष कार्य आदि पर प्रतिनियुक्त करने के फलस्वरूप काम बकाया रह जाता है । अतः बम्बई क्षेत्र में रिलीविंग टी० आई० ए० की प्रतिनियुक्ति करना अपरिहार्य हो जाता है । जितनी रकम का भुगतान किया गया वह इस प्रकार है :—

1971-72	8,121 रुपये ।
1972-73	11,356 रुपये ।

(ग) आर० टी० आई० ए० के यात्रा भत्ते पर होने वाला खर्च अपरिहार्य है।

ओषधों के मूल्यों के बारे में अनुमोदनार्थ आवेदन-पत्र

3586. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन औषधों के मूल्यों के बारे में अनुमोदनार्थ पड़े आवेदन-पत्रों सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) 10 फरवरी, 1974 तक ऐसे कितने आवेदन-पत्र अनुमोदनार्थ पड़े हैं; और

(ग) 20 नवम्बर, 1973 तक प्राप्त (एक) एक महीने से कम अवधि; (दो) एक से दो महीने तक की अवधि; तथा (तीन) दो से तीन महीने तक की अवधि से निर्णयाधीन पड़े आवेदनों का विवरण क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नावज खां) : (क) 14-3-74 को इस प्रकार के 1,608 आवेदन पत्र निलम्बित थे ।

(ख) 1,277

(ग) (i)	एक माह से कम अवधि के . .	395
(ii)	1-2 माह की अवधि के .	411
(iii)	2-3 माह की अवधि के . .	279
(iv)	3 माह से अधिक अवधि के .	613
	योग	1,698

प्रस्तावित लोक शेड को कज्जा कुट्टम से किसी अन्य स्थान पर ले जाना

3587. **श्री वयावार रवि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने कज्जा-कुट्टम में बनाये जाने वाले प्रस्तावित लोको शेड को अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस शेड को कज्जा कुट्टम में बनाने का है जहां रेलवे के कब्जे में भूमि का विशाल क्षेत्र है ?

रेल मंत्रालय में रेल मंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) से (ग) कोल्लम में एक रेल इंजन शेड पहले से ही मौजूद है जिससे रेलवे की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं; और कज्जा-कुट्टम में दूसरा रेल इंजन शेड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे सुरक्षा बल संघ का मांग-पत्र

3588 . **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरझा बल संघ ने सरकार को कोई मांग-पत्र पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हाँ । क्षेत्रीय रेलों की रेलवे सुरक्षा दल की कुछ मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों ने ज्ञापन दिये हैं जिनमें उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं ।

(ख) ये मांगें मुख्यत: निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) केन्द्रीय सूरक्षा दल के समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में रेलवे सुरझा दल के कार्मिकों के वेतनमानों में असमानता ।

(ii) रेलवे सुरक्षा दल के लिये रात्रि ड्यूटी भत्ता ।

(iii) धुलाई भत्ता ।

(iv) आपातकाल में भोजन भत्ता।

(v) आवधिक स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध।

(vi) रेलवे सुरक्षा दल की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों की सुविधाएं।

(vii) 1973 के संशोधित रेलवे सुरक्षा दल नियम 21(8) का निवर्तन।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार के श्रेणी IV, III और II के कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को मौटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। इस दल की ओर से आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदनों सहित सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आयोग ने रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतनमानों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों और अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है।

एर्नाकुलम में पुराने सामान के शैड क्षेत्र की भूमि के समर्पण के लिए केरल सरकार का अनुरोध

3589. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मत्स्य उद्योग समूह की स्थापना के लिये एर्नाकुलम स्थित पुराने सामान शेड के क्षेत्र में से कुछ भूमि छोड़ देने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य सरकार ने मत्स्य उद्योग समूह की स्थापना के लिये एरणाकुलम माल गोदाम क्षेत्र की दक्षिण पश्चिम दिशा में 3.62 एकड़ रेलवे भूमि छोड़ देने का अनुरोध किया था। चूंकि माल गोदाम सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार हेतु यही उपलब्ध स्थान सुविधाजनक है। अतः इसे राज्य सरकार को अन्तरित करने की स्वीकृति नहीं दी गयी थी।

भारत में तेल की खोज में लगे हुए विदेशी विशेषज्ञ

3590. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय तेल की खोज में लगे हुए किन-किन देशों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, और

(ख) उनके नियत कार्य की शर्तें क्या हैं और वे कितनी अवधि के लिये भारत में आए हुए हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

Allotment of Land for cultivation to Railways' Employees.

3591. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has prepared a scheme to allot land to Railway employees for cultivation;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) whether land is not similarly being allotted to the employees working in other Ministries?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) Surplus cultivable railway land between stations is handed over to the State Governments for 'Grow More Food' purposes with a request that, while licensing the said land, preference may be given to the actual tillers of land who may be landless, with an over-riding prioritybeing given to the casual labour who have worked on Railways for a minimum period of three years. Where State Governments decline to take over surplus railway land it is licenced to the adjacent owners/ cultivators agricultural graduates, or any other applicant. The surplus railway lands in station yards and railway colonies are, however, licensed to the Railway employees/Railwaymen's Co-operative Farming Societies.

(c) Railway land in station yards and colonies under part (b) is not allotted to employees working in other Ministries.

Drilling Oil in Jammu Region by Russian Oil Experts

3592. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a team of Russian oil experts are engaged in the work of drilling oil in Jammu region; and

(b) if so, the broad features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

औषध फर्मों द्वारा अनुमति पत्र के अधीन बनाई गयी वस्तुओं के आंकड़ों को रखना

3593. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी वस्तु के लिये, जिसके निर्माण की अनुमति उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दी गई थी, औषध निर्माताओं के लिये आंकड़े रखना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार अनुमति/अनापति पत्रों के लिये कोई आंकड़े रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनुमति/अनापति पत्रों के अधीन निर्माण कार्यक्रमों में 'नई वस्तुओं' को शामिल नहीं किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) से (ग) : औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 में आंकड़ों के अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । तथापि इसके लाइसेंसिंग एवं अन्य नीतियों के प्रशासन की सुविधाओं के लिए

सरकार ने अब अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी औद्योगिक स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आंकड़े को रखना प्रारम्भ कर दिया है अनुमति तथा अनापति पत्रों के ब्यौरों के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे गये थे । अनुमति/अनापति पत्र लाइसेंसिंग कमेटी के निर्णय के आधार पर जारी किये जाते थे, कि वर्तमान उपक्रमों द्वारा एक अतिरिक्त मद उत्पादन नयी वस्तु का निर्माण नहीं माना जावेगा बशर्ते कि अतिरिक्त मद अनुसूची के उसी शीर्ष के अन्तर्गत आता हो और नये ट्रेड मार्क अथवा पेटेन्ट का प्रयोग न हुआ हो ।

Hindi Staff Working in Ministry of Irrigation and Power

3594. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9534 on the 8th May, 1973 regarding Hindi Staff working in the Ministry of Irrigation and Power and state :

(a) whether the recruitment rules for the Hindi Translators have since been finalised;

(b) if so, whether the appointments of the Translators working for the last four to five years have been regularised; and

(c) if not, the reasons for delay in confirming these Translators ?

The Minister of Irrigation & Power (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Steps are being taken to fill the posts of Hindi Translators on a regular basis in accordance with the provisions of the Recruitment Rules. The persons holding these posts on deputation basis will also be considered along with other eligible employees.

तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा औषध फर्मों के विविधीकरण कार्यक्रम का अनुमोदन

3595. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले प्रचलित छूट आदेशों के अधीन यह निर्धारित किया गया था कि औषध निर्माता फर्मों द्वारा कुछ विवरण देने के बाद विविधीकरण कार्यक्रम के ब्यौरे तकनीकी विकास महानिदेशालय से अनुमोदित कराये जायेंगे ;

(ख) क्या विविधीकरण उत्पादों के निर्माण से पहले अथवा इसके बाद यह अनुमोदिन आवश्यक था; और

(ग) यह अनुमोदन वैकल्पिक था अथवा अनिवार्य था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अक्तूबर, 1966 में जारी किए गए आदेशों, जिनमें बिना किसी लाइसेंस के विविधीकरण के लिये अनुमति दी गई थी, औद्योगिक उपक्रमों को अपने संशोधित निर्माण व कार्यक्रम और निर्माण किए जाने वाली नई प्रस्तावित वस्तुओं और उनके द्वारा सम्मिलित की गई यदि कोई हो तो, लघु सन्तुलन उपकरण का प्रकार और उसके मूल्य के सम्बन्ध में की सूचना तकनीकी विकास महानिदेशालय या अन्य उजित तकनीकी प्राधिकारी को देनी थी और तकनीकी विकास महानिदेशालय से कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Timber Stocks filled up at Timarni Station in Madhya Pradesh (Central Railway)

3596. Shri G. C. Dixit. Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that timber stocks worth lakhs of rupees have piled up at Timarni Station of Madhya Pradesh on Central Railway due to non-availability of wagons ;

(b) the action taken by Government for providing wagons immediately; and

(c) if no action has been taken, the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) : No. During the period from November 1973 to February 1974, 114 wagons were loaded with timber at Timarni Station as compared to 49 wagons loaded during the corresponding period of 1972-73.

(c) Does not arise.

Irrigation of Land in U. P. and M. P.

3597. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the percentage of irrigated agricultural land in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh at present; and

(b) the action being taken by Government for improving irrigation facilities in Madhya Pradesh ?

The Minister of Irrigation & Power (Shri K. C. Pant) : (a) & (b): At present, the irrigation in Uttar Pradesh is about 34% of the gross cropped area. This includes extensive areas where the irrigation is of a protective nature and water allowances are inadequate. Further, large areas under bundies are also included in the reported irrigated figures.

The irrigation in Madhya Pradesh at present is about 10% of the cropped area. Irrigation has been given high priority in the Fifth Plan Programmes of the State and the percentage is expected to increase to about 14·5% by the end of the Fifth Plan.

Setting up of Thermal Power Station in Sidhi District, M. P.

3598. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a Russian Team surveyed the Singrauli Coal area in Sidhi District of Madhy-Pradesh in December, 1973 and affirmed the possibility of setting up of a thermal power station there; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : Yes, Sir. A Russian Team surveyed the Singrauli coal field area in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The experts will prepare a feasibility report for integrated development of coal production for industries and power generation. On receipt of the feasibility report, further action will be taken.

Agreement Re: Construction of a Dam on River Tapti

3599. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached between the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra in regard to the construction of a dam on Tapti river;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether the construction work on this dam has been started and if so, the progress made in this regard; and

(d) if not, the time by which the construction work is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : In May, 1969, an agreement was reached between the State Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra in regard to the Upper Tapi Project (Stage II). The agreement provided that the Government of Mahrashtra may proceed with the preparation of the detailed project report for a storage at Kheria-Gutighat and that the Government of Madhya Pradesh would conduct further investigations, regarding the utilisation of water in the Madhya Pradesh territory, and that if necessary the scheme would be modified to provide for increased irrigation in Madhya Pradesh.

(c) & (d) : The Government of Maharashtra have recently sent the project report and estimates for the scheme which is proposed to be implemented as a joint venture of the two States. These are under technical examination in the Central Water and Power Commission.

Confirmation of Temporary Employees on Central Railway

3600. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees in Central Railway at present who are still temporary even after having served for more than 5 years; and

(b) the steps proposed to be taken by Government regarding confirmation of these temporary employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 2329.

(b) A special drive has been instituted for conversion of temporary posts into permanent ones wherever justified and for confirmation of the eligible staff against such posts.

Railway Property lost due to Strike on Western Railway

3601. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the value of Railway property lost by the Western Railway during the last two years on account of Railway employees' strikes and other political agitations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : About 8·53 lakhs.

Crimes on Northern Railway registered during the last Year

3602. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of crimes in running trains on the Northern Railway registered during the last one year;

(b) the total number of persons arrested in this connection ; and

(c) the number of persons prosecuted and convicted, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) : A statement is attached.

[Placed in Library. See No. LT. 6472/74].

Names of Divisions where Loco Employees strike occurred

3603. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the Divisions of Railways in which Loco-employees observed strikes during the last one year;

(b) the number of days for which each of these strikes lasted;

(c) the estimated loss suffered by Government as a result thereof; and

(d) the number of Railway employees removed from service, if any during these strikes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) All Divisions of Northern, North Eastern, Northeast Frontier, Southern and South Eastern Railways and Jhansi, Jabalpur and Bhusawal Divisions of Central Railway, Vijayawada and Hubli Divisions of South Central Railway and Asansol Division of Eastern Railway and Baroda, Ratlam, Jaipur, Kota and Ajmer Divisions of Western Railway were affected by the strikes of Loco Running Staff during the last one year.

(b) There were three main strikes of Loco Running Staff during last one year, the dates of which are given below :—

May Strike—2-5-73 to 31-5-73.

August Strike—1-8-73 to 12-8-73

December Strike—26-11-73 to 24-12-73.

(c) The loss suffered due to strikes and agitations by the Loco Running Staff in 1973 is estimated to be Rs. 21 crores.

(d) No employee was removed from service for mere participation in these strikes.

तेल का खर्च कम करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश

3604. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से तेल के खर्च में कमी करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो आदेश कब जारी किये गये थे ;

(ग) क्या आदेश जारी किये जाने के पश्चात् मितव्ययिता उपायों तथा वास्तव में की गई मितव्ययिता के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) 17 नवम्बर, 1973 को इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) तब से मितव्ययिता करने वाले राज्यों से कोई विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि गत वर्ष के अनुरूप महीनों की तुलना में, देश में, कुल मोटर स्पिरिट की बिक्री नवम्बर, 1973 में 19.2 प्रतिशत, दिसम्बर, 1973 में 19.9 प्रतिशत और जनवरी, 1974 में 23.8 प्रतिशत तक कम हुई।

पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के कारण माल परिवहन में बाधा

3606. **श्री एम० एम० जोज़फ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में 1 मार्च, 1974 को घोषित भारी वृद्धि से माल को राजधानी लाने तथा ले जाने में बाधा पड़ने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को बिगड़ने से बचाने हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) और (ख) माल के यातायात की प्रणाली अधिकतर हाई स्पीड डीजल आयल पर निर्भर करती है। आयातित अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि अनिवार्य हो गई और डीजल आयल सहित उत्पादों के मूल्य को 2 मार्च, 1974 से संशोधित किया गया था। तथापि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करते हुए हाई स्पीड डीजल आयल के मामले में वृद्धि कम से कम की गई है। डीजल आयल के मूल्यों में हाल की वद्धि के परिणामस्वरूप नई दिल्ली से तथा नई दिल्ली तक माल के यातायात के विच्छेद होने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

बसरा, ईराक में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये भारतीय सहायता

3607. **श्री लम्बोदर बलियार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसरा में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये ईराक की सहायता हेतु कुछ इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को वहां भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ईराक में उनके ठहरने की अवधि क्या होगी और वे किन-किन शर्तों पर वहां जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) ईराक नेशनल आयल कम्पनी (आई० एन० ओ० सी०) को बहुत से इंजीनियरों तथा तकनीशनों की सेवाओं की आवश्यकता है। उनके कहने पर, निर्धारित अहर्रताएं प्राप्त उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगवाये गये थे और आई० एन० ओ० सी० के एक दल ने बहुत से उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया है। इसके परिणामस्वरूप, तेल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से भारतीय इजीनियरों तथा तकनीशियनों को व्यक्तिगत ठेके पर अथवा ईराक के प्राधिकारियों एवं भारत में संबंधित संस्थाओं के बीच हुये करारों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर ईराक जाने की संभावना है। ईराक में उनके ठहरने की अवधि तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें ईराक के अधिकारियों तथा व्यक्ति की अहर्रताओं एवं अनुभव पर निर्भर करेंगी।

अमान में तेल परिशोधन शाला की स्थापना के लिए भारतीय सहायता

3608. **श्री लम्बोदर बलियार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमान में तेल परिशोधन शाला की स्थापना करने में उस देश की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ इंजीनियरों एवं तकनीशियनों को भी इस संबंध में अमान भेजा जायेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) विश्व कच्चे तेल की पूर्ति स्थिति में हाल में परिवर्तन के संदर्भ में कुछ खाड़ी देशों

के साथ सहयोग से संयुक्त शोधनशालाओं की स्थापना की संभावनाओं की छानबीन की जा रही है। ग्रमान के बारे में प्रस्ताव बहुत ग्रारम्भिक ग्रवस्था में है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार

3609. **श्री आर० पी० उलगनस्वी**
श्री पी० जी० मावलंकर } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय ग्रौर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; ग्रौर यदि हां, तो इस बारे में मुख्य सुझाव क्या हैं; ग्रौर

(ख) उन सुझावों को कार्यरूप देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ग्रथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ग्रौर (ख) : सामान्य धारणा है कि उच्चतम न्यायालय ग्रौर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें ग्राकर्षक नहीं हैं, जिसके कारण बाँर के योग्य सदस्य न्यायाधीश का पद स्वीकार नहीं करते हैं। ग्रतः सरकार स्वयं ग्रपनी ग्रोर से इस बात पर विचार कर रही है कि उनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। किन्हीं भी विनिर्दिष्ट प्रस्तावों को ग्रभी ग्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा ऊर्जा संकट पर बंगकोक में आयोजित सम्मेलन

3610. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए ग्रार्थिक ग्रायोग द्वारा वर्तमान ऊर्जा संकट के बारे में फरवरी, 1974 में बंगकोक में ग्रायोजित किये गये सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये; ग्रौर

(ग) उक्त सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) ग्रौर (ग) [सम्मेलन] में ईकाँफे क्षेत्र तथा संयुक्त राष्ट्र देशों के सदस्यों [एवं सम्बन्धित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुग्रा :—

(i) क्षेत्र के देशों में उर्जा स्थिति की समीक्षा।

(ii) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उर्जा संकट का प्रभाव ।

(iii) उर्जा संकट के प्रभाव को कम करने के उपाय जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहायता भी सम्मिलित है ।

सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया किन्तु एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे 27 मार्च से 8 अप्रैल, 1974 को होने वाले ईकॉफे के 30वें वार्षिक अधिवेशन में विचार किया जाना है ।

डीज़ल कृषि पम्प सैटों को विद्युत् पम्प सैटों में बदलना

3611. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सिंजाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डीज़ल कृषि पम्प सैटों को विद्युत् पम्प सैटों में बदलने के बारे में रज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, नहीं । बहरहाल, ईंधन की वर्तमान कमी के संदर्भ में योजना आयोग ने डीज़ल पम्पों की संख्या, उनके विद्युत् से चलाए जाने वाले पम्पों में परिवर्तन की संभाव्यता और इस परिवर्तन के लिए अनुमानित लागत आने के संबंध में सूचना एकत्र करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया है । यह सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

26 प्रतिशत से कम विदेशी साम्य पूजी वाली फर्मों को लाईसेंस दिया जाना

3612. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से कम विदेशी साम्य पूंजी वाली कितनी फर्मों को 15 अगस्त 1973 के बाद बिना किसी शर्त के 'फार्मुलेशनों' के मूलत: निर्माण के लिये औद्योगिक लाईसेंस दिये गये;

(ख) इस प्रकार दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों को इस प्रकार के कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(घ) ऐसे लाइसेंसों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) 15-8-73 से 28 फरवरी 1974 की अवधि के दौरान उन कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए गए थे जिनके पास मूल निर्माण हेतु किसी शर्त के बिना सूत्रयोग के लिए 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी है । केवल सूत्रयोगों के लिए उसी अवधि के दौरान 27 प्रतिशत से कम विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों को दिए गए लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लाइसेंस संख्या तथा तिथि	निर्माण के विषय	क्षमता प्रतिशतता
1.	बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि०	एल/22/481/73-केम. III दिनांक 10-9-73	क्लोराविट कैपसूल	50 बोतल
2.	रपताकोस ब्रेत तथा कम्पनी लि० (सी० ओ० वी०)	एल/22/485/72-केम. III दिनांक 22-9-73	1. अमीनोसिल इलिक्सिर (300 एम 1)	56770 बोतलें
			2. इयूपेपटाइन इलिक्सिर	85290 बोतलें
			3. होवित सिरप	87461 बोतलें
			4. कितेमेमिन सं० गोलियां	05,18,360
			5. कटेमेसिन सं० इंज (1 एम 1)	15,528
			6. डिगीरोसिन सं० आर० वी० गोलियां	5 लाख

राष्ट्रपति शासन के पश्चात् गुजरात को कोयले की सप्लाई

3613. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय गुजरात राज्य को कोयले की सप्लाई युद्ध स्तर पर की जा रही है; और

(ख) राष्ट्रपति शासन के पश्चात् राज्य को कुल कितना कोयला आवंटन किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। संचलन सामान्य गति से हो रहा है।

(ख) 9 फरवरी से 28 फरवरी तक गुजरात को विभिन्न प्रकार के कोयले/कोक के कुल 7960 माल डिब्बे आवंटित किये गये।

राजस्थान में राक फास्फेट का खनन

3614. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राक फास्फेट के खनन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह समिति कब तक बना दी जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) से (ग) राजस्थान में झमारकोत्रा क्षेत्र में राक फास्फेट के विकास के सम्बन्ध में तकनीकी तथा अन्य पहलुओं की जांच के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। समिति के निम्नलिखित प्रचारार्थ विषय हैं :--

(i) विदेशी परामर्शदात्री फर्म द्वारा तैयार किये गये सम्भाव्य अध्ययन का मूल्यांकन करना तथा लगे हुए समस्त तकनीकी पहलुओं की जांच करना तथा झमारकोत्रा राक फास्फेट भंडारों के शीघ्र एवं एकीकृत विकास के सम्बन्ध में उठाये जाने वाले अतिरिक्त उपायों को बताना; और

(ii) लगी हुई निवेश की सीमा तथा वित्त पोषण की पद्धति को ध्यान में रखते हुए भण्डारों के विकास के सम्बन्ध में अति उपयुक्त संगठित संरचना का सुझाव देना।

समिति के शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की आशा है।

Supply of Oil for Coastal Shipping

3615. Shri Onkar Lal Berwa
Shri C. K. Jaffer Sharief } : Will the Minister of **Petroleum and Chemi cals** be pleased to state :

(a) whether oil will be supplied for coastal shipping on concessional rates i.e. rates as prevailing upto the 12th December, 1973;

(b) if so, the way it will be done;

(c) the loss Government is likely to incur as a result thereof; and

(d) time by which the oil is likely to be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) Effective from 13-12-1973 and subsequently with effect from 16-12-1973, the price of bunker fuels at Indian ports had to be increased substantively to curb the excessive off take of bunker fuels by Inter-national vessels at Indian ports. all vessesl permitted by Director General (Shipping) to carry coastal cargo and/or passengers and performing coastal voyages between Indian ports, excepting vessels on single or consecutive voyage charter basis are exempt from the aforesaid increases of 13-12-1973 and 16-12-1973.

(c) There is no loss to Government on this account.

(d) The coastal ships take fuel when required by them.

दिल्ली में तीसरा बड़ा स्टेशन

3616. श्री ए० के० एम० इसहाक
श्री अटल बिहारी बाजपेयी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वर्तमान रेलवे स्टशनों पर भीड़-भाड़ को समाप्त करने के लियें राजधानी में तीसरे बड़े रेलवे स्टशन के लिये स्थान के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये विकसित किये जाने वाले स्टेशन का नाम क्या है; और

(ग) यह स्टेशन कब तक चालू हो जायगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे माल की कमी के कारण रसायन उद्योगों के उत्पादन में कमी

3617. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित तथा स्वदेशी पैट्रो-रसायन कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण रसायन उद्योगों के उत्पादन में हाल में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित मात्रा में आयातित तथा स्वदेशी पेट्रो-रसायन कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वर्ष 1973 में पेट्रोकैमिकल फीड स्टाक पर आधारित निम्नलिखित मुख्य आर्गनिक कैमिकलों के उत्पादन में वर्ष 1972 की तुलना में पैट्रोकैमिकल के कच्चे माल की कमी के कारण कमी दिखलाई दी है :—

उत्पादन मी० टनों में

उत्पादन का नाम	1972	1973
1. एसिटिलीन ब्लैक	5112	5013
2. ऐसेटेनिलाइड फ्लेक	1847	1171
3. ऐनिलाइन	3857	1871
4. ब्यूटाडाईन	6337	6117
5. क्लीरो एथिलीन	6251	4787
6. एथिलीन ग्लाइकोल	6223	1383
7. फार्मल डीहाइड	30141	26000 (स्थापित)
8. मेटा अमिनी फीनोल	328	248
9. अक्स एसिड	922	711
10. आर्गेनिक पैरोक्साइड	41	35
11. पेन्टाएरिथी टोन	594	560 (स्थापित)
12. रबर कैमिकल्स	4632	4200 (स्थापित)

(ख) आयातित कच्चे माल की प्राप्ति करने और अत्याधिक देशज उत्पादन के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए सब सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

पैट्रोलियम रसायनों की जमाखोरी, अपमिश्रण और चोरबाजारी

3618. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1972 और 1973 के दौरान पैट्रोलियम रसायनों की जमाखोरी, अपमिश्रण तथा चोरबाजारी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये सरकार द्वारा इस अवधि में राज्यवार क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस प्रकार के अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया तथा प्रत्येक मामले में क्या दण्ड दिया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (ग): पैट्रो-रसायन उत्पादों पर कोई सांविधिक मूल्य एवं वितरण नियंत्रण नहीं है। केवल संश्लिष्ट रबड़ जिसका उत्पादन एलकोहल पर आधारित होता है, के मूल्य पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के एक आदेश के अन्तर्गत सांविधिक नियंत्रण है। वर्ष 1972 और 1973 के दौरान सरकार के सामने संश्लिष्ट रबड़ की जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट का कोई मामला नहीं आया है। पैट्रोलियम उत्पाद के सम्बन्ध में बढ़िया किस्म के मिट्टी तेल, लाइट डीजल तेल के मूल्यों का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। राज्य सरकारों को इन आदेशों के अन्तर्गत अपराधियों से निपटने के लिए अधिकार दिये गये हैं और भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध से इन आदेशों के अन्तर्गत दिये गये दण्डों एवं की गई कार्यवाही के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पैट्रोल, डीजल और अशोधित तेल का आयात

3619. **श्री शंकर राव सावंत:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में फरवरी, 1974 के अन्त तक भारत को कितना-कितना पैट्रोल, डीजल तथा अशोधित तेल आयात करना पड़ा;

(ख) इसमें से (1) ईराम, (2) अरब देश, (3) सोवियत रूस, (4) यूगोस्लाविया तथा (5) अन्य देशों से कितनी मात्रा प्राप्त होने की सम्भावना है तथा किन मूल्यों पर; और

(ग) 1974-75 के दौरान देश में कोयले से कितना पैट्रोल निकाले जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) पैट्रोल का कुछ समय से आयात नहीं किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में कच्चे तेल के आयात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा मिलियन मीटरी टनों में
1972	12.31
1973	13.38 (अस्थाई)

पिछले दो वर्षों के दौरान आयात किये गये डीजल की मात्रा के बारे में बताना जन हित में नहीं है।

(ख) इस समय इस बात को सही-सही बताना संभव नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित देशों में से प्रत्येक से कच्चे तेल का कितना और किस मूल्य पर आयात, यदि हुआ तो, किया जायेगा।

(ग) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति और योजना आयोग द्वारा अब तक किये गये अन्वेषी अध्ययनों के आधार पर कोयले से तेल का उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में संभाव्य अध्ययन करने के लिये एक दल की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया है। जब तक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती, 1974-75 के दौरान देश में कोयले से निकाले जाने वाले तेल की अनुमानित मात्रा के बारे में ब्यौरे तैयार करना संभव नहीं है।

तापीय संयंत्र का दलखोला से मुर्शिदाबाद को स्थानान्तरित किया जाना

3620. **श्री राम भगत पासवान**
श्री प्रबोध चन्द्र } : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित तापीय संयंत्र की स्थापना दलखोला के स्थान पर मुर्शिदाबाद में करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्रीय सैक्टर में एक ताप विद्युत् केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए प्रस्ताव को डलखोला की अपेक्षा मर्शिदाबाद जिले में फरक्का में स्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है क्योंकि फरक्का में कोयले की कम ढुलाई और शीतक जल की भरपूर सप्लाई की सुविधाएं हैं। डलखोला में एक ताप विद्युत् की स्थापना का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के 100 सबसे बड़े उपक्रमों की परिसम्पत्तियां

3621. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र के 100 सबसे बड़े उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनकी कुल परिसम्पत्तियां कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

तेल की कीमत में वृद्धि का कोल्हापुर के डीजल तेल उद्योग पर प्रभाव

3622. **श्री निवालकर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण कोल्हापुर के डीजल तेल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) : कोल्हापुर में डीजल आयल निर्माण करने वाला कोई उद्योग नहीं है। लाइट और हाई स्पीड डीजल आयल सहित पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि आयातित अशोधित तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप अनिवार्य हो गई है। मूल्य वृद्धियां देश भर में लागू हैं।

अशोधित तेल के मूल्य पर भारत का ईराक और कुवैत के साथ समझौता

3623. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, ईराक और कुवैत की सरकारों में अशोधित तेल के मूल्य और उन देशों में तेल शोधक कारखाने और पैट्रो-रसायनिक उद्योग लगाने के लिए संयक्त सहयोग व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और और (ख) : ईराक और कुवैत के साथ द्विपक्षीय प्रबन्धों पर बातचीत की जा रही है। इस अवस्था में इसका विवरण देना जनहित में ठीक नहीं है।

50 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक पूंजी-निवेश वाले उपक्रम

3624. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 50 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक पंजी-निवेश वाले उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक उपक्रम में सरकार के कितने-कितने शेयर हैं; और

(ग) अपने वित्तीय हितों पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें सुप्रशासित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

Expenditure on Election to Legislative Assemblies of Uttar Pradesh, Orissa, Pondicherry and Manipur.

3625. Shri Ramavtar Shastri
Shri Chhatrapati Ambesh } : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state the amouont of expenditure incurred by Government on elections to Legislative Assemblies of Uttar Pradesh, Orissa, Pondicherry and Manipur, separately.

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी क्षेत्र के एककों को कोयला पहुंचाने के लिये वैगनों की सप्लाई

3626. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों को कोयला पहुंचाने के लिए वैगनों की सप्लाई के कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को परिवहन के अन्य साधनों से कोयले की सप्लाई प्राप्त करने के लिए कोई निदेश दिए हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) इस्पात संयत्रों और बिजली घरों जैसी सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के लिए कोयले के संचलन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता;

(ग) रेल मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है ।

दुर्गापुर में तापीय विद्युत् केन्द्र का विस्तार

3627. **श्री ई० वी० विखे पाटिल**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दुर्गापुर में पांचवीं योजना के दौरान क्रियान्वित हेतु तापीय विद्युत् केन्द्र के विस्तार की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी; और

(ग) उन सलाहकारों के क्या नाम हैं जिन्होंने उक्त विचार योजना संबंधी संभाव्यति-प्रतिवेदन तैयार किया है और इस संभाव्यता प्रतिवेदन को तैयार करने तथा सलाहकार-सेवाएं देने के लिए कितनी राशि की अदायगी की गई है अथवा देना तय हुआ है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल राज्य प्राधिकारियों ने 110 मेघावाट क्षमता की एक और यूनिट लगाकर दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के ताप विद्युत् केन्द्र की विद्यत् जनन क्षमता बढ़ाने हेतु एक व्यव-हार्यता रिपोर्ट तैयार करवा ली है। परियोजना पर 31.5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । इसे अभी योजना आयोग ने स्वीकृत नहीं किया है ।

यह सूचित किया गया है कि व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार, मैसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेन्ट्स, कलकत्ता को 25,000 रुपये का भुगतान किया गया था। परियोजना के कार्यान्वियन के लिए सलाहकारी सेवाएं देने के लिए अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

पालिस्टर रेशों और धागों के लिये डी० एम० टी० का उत्पादन

3628. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी० एम० टी० का स्टाक समाप्त होने वाला है जिससे पालिस्टर रेशों और धागों के उत्पादन के लिये खतरा पैदा हो गया है;

(ख) वर्ष 1974 में कितना आयात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या कुछ तकनीकी खराबियों और एक विदेशी तकनीशन के छुट्टी अथवा अन्य शिकायतों के बारे में विवाद के कारण इण्डोपेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन के बड़ोदा संयंत्र में महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) यह विभिन्न विचारों, जैसे आई० पी० सी० एल० के संयंत्र के उत्पादन में प्रगति, विदेशी मुद्रा देना तथा विश्व बाजार में डी० एम० टी० की उपलब्धता, पर निर्भर करेगी।

(ग) पेराजाइलीन संयंत्र के प्रोपेन प्रसीतन कम्प्रैसर के कार्यकरण में खराबी आने के कारण संयंत्र महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं कर सका। किसी विदेशी तकनीशियनों के साथ किसी विषय पर कोई विवाद नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लिक्विड नाइट्रोजन वाश प्लांट के लिए ब्रिटेन की एक फर्म तथा भारतीय उर्वरक निगम के बीच करार

3629. **श्री पुरुषोत्तम काकेडकर**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाजा नंगल उर्वरक कारखाने को विस्तार के लिये एक लिक्विड नाइट्रोजन वाश प्लांट तथा एक एयर सेपरेशन प्लांट के बारे में भारतीय उर्वरक निगम ने दिसम्बर, 1973 में ब्रिटेन की एक फर्म के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो करार का मुख्य क्या है;

(ग) यूरिया बनाने के लिये संयंत्रों की क्षमता क्या होगी; और

(घ) क्या परियोजना के लिए आई० डी० ए० ने कोई राशि मंजूर की है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) संविदा का कुल मूल्य निम्न प्रकार है :—

	स्टर्लिंग पौंड	डी० एम०	एस० डब्ल्यू० फ्रैंक
(i) एयर सेपरेशन वाश प्लांट	7,19,352	3,62,000	14,000
(ii) लीक्विड नाइट्रोजन प्लांट	2,57,684	—	—
जहाज तक नि:शुल्क संविदा मूल्य	9,77,036	3,62,000	14,000
(iii) डिजाइन, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवा शुल्क	1,83,565	—	—
कुल संविदा मूल्य :	11,60,601	3,62,000	14,000

(ग) 1000 मीटरी टन प्रति दिन।

(घ) जी हां। 58 मिलियन डालर।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा सरकार और उद्योग के बीच आयोजित की गई बैठक

3630. **श्री पी० वेंकट सुब्बया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इण्डिया ने हाल में सरकार तथा उद्योग के बीच नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बैठक में क्या सुझाव दिए गए ; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़खां) : (क) से (ग) : भारतीय उर्वरक संघ ने वर्तमान उर्वरक यूनिटों में अधिकतम उत्पादन करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए 29 जनवरी, 1974 को एक बैठक बुलाई थी और उन संयंत्रों, जिन में निकट भविष्य में उत्पादन शुरु किए जाने का कार्यक्रम है, को कार्यक्रम से पहले मुकम्मल करने के उपायों पर विचार करने के लिए दूसरी बैठक 23 फरवरी को बुलाई थी। इन बैठकों में, अन्य व्यक्तियों के अलावा सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बातों के साथ-साथ इन बैठकों में उठाए गए प्रश्न, उद्योग को कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई किए जाने, फालतू पुर्जों के आयात की पद्धतियों के सरल किए जाने, एक संयुक्त मोनिटोरिंग कक्ष की स्थापना किए जाने, उर्वरकों के उत्पादन के लिए बिजली की कटौतियां

किए जाने में छूट दिये जाने, कच्चे माल के प्रयोग में दक्षता और उद्योग द्वारा उच्च परिचालन संबंधी दक्षता प्राप्त किए जाने से संबन्धित थे। बैठक में उठाए गए विषयों को नोट कर लिया गया है और सरकार द्वारा तथा अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

सहायक स्टेशन मास्टरों की ऊंचे संवर्ग में पदोन्नति की समेकित प्रणाली (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे)

3631. **श्री बी० के० दास चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मालूम है कि प्रारम्भिक संवर्ग के सहायक स्टेशन मास्टरों की ऊंचे संवर्ग में पदोन्नति करने सम्बन्धी प्रणाली सभी रेलवे ज़ोनों में समान नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप विभिन्न रेलवे ज़ोनों में विषमतायें पैदा नहीं हुई हैं विशेषकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में जहां इस दोषपूर्ण प्रणाली के कारण संवर्ग बार छुट्टी रिज़र्व तथा वेतन-सुरक्षण संबंधी बहुमुखी समस्यायों पैदा हो गई हैं ; और

(ग) इन असंगतियों को दूर करने के लिए इन के मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) रेलवे बोर्ड द्वारा निश्चित सामान्य मार्ग-दर्शन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन प्रशासनिक आवश्यताओं के अनुरूप अराजपत्रित कर्मचारियों जिन में स्टेशन मास्टर भी शामिल हैं, की पदोन्नति सरणि निर्धारित करते हैं।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सहित रेलों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित पदोन्नति सरणियों में कोई असंगति नहीं है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों की कोटि में पद-क्रम के अनुसार छुट्टी आरक्षी पदों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) की ओर से अभ्यावेदन

3632. **श्री बी० के० दास चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, ने अपनी निम्नलिखित मांगों के लिए अभ्यावेदन दिया है :—

(i) स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के वर्गों में प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक वर्ग-वार छुट्टी रिज़र्व स्थानों की व्यवस्था ;

(ii) दोहरी लाईनों वाले स्टेशनों पर अलग-अलग स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था ;

(iii) विश्राम-गृहों की अनिवार्य व्यवस्था ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मांगों को पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां,।

(ख) (i) छुट्टी रिजर्व स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के ग्रेडवार पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ii) दोहरे आमान वाले स्टेशनों पर कार्य-भार के आधार पर यथेप्ट संख्या में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

(iii) क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजन के लिए स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को अनिवार्य कर्मचारी माना जाता है और जब क्वार्टर उपलब्ध होते हैं तो उन्हें तरजीह दी जाती है।

ईंधन सहित सामान पर खर्च में मितव्ययिता

3633. श्री श्रीकिशन मोदी
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए ईंधन सहित सामान पर खर्च में मितव्ययिता लाने के लिए रेलवे ने कोई कार्यवाही की है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर निगाह रखने के लिए सभी रेलवे में सामान सूची सैलों की स्थापना कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस कक्ष को रेलों पर ए० बी० सी० विश्लेषण के स्वीकृत सिद्धांतों पर लगातार भंडार सूचियों की निगरानी करने और स्थिति का विश्लेषण करने तथा उसे उच्चतम स्तर पर लाने के लिए उपयुक्त उपाय करने का काम सौंपा गया है। यह कक्ष खासतौर से इन मामलों की जांच करेगा :--

(i) अधिक मूल्य की सभी मदों की व्यवस्था करना,

(ii) आवश्यकता से अधिक स्टाक और पालतू वस्तुओं की शीघ्रतापूर्वक जानकारी देना और उनकी निकासी के लिए जल्द व्यवस्था करना,

(iii) युक्ति युक्तिकरण को शीघ्रता से क्रियान्वित करना और रेलों पर एकत्र भंडार की मदों के संबंध में विविधता में कमी करना,

(iv) भंडार लेखा के संगणकीकरण और भंडार सूची नियंत्रण की प्रगति में तेजी लाना, और

(v) रद्दी भंडार के निबटारे में तेजी लाना,

उपर्युक्त उपायों के अलावा, रेल उपमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी समिति गठित की गई है जिसमें कुछ गैर-सरकारी विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। यह समिति भारतीय रेलों पर भंडार कार्यविधि को सुप्रवादी बनाने और सामान प्रबंध के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Length of Railway Lines in Each State per one Lakh Persons

3634. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of Railways be pleased to state the length of Railway lines in each State per one lakh persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Route kilometres of Railway lines in each State per lakh of population are as follows :—

State	Route kilometres per lakh of population	State	Route kilometres per lakh of population
Andhra Pradesh	10·90	Tripura	0·77
Assam (including Mizoram)	14·67	Uttar Pradesh	9·67
		West Bengal	8·35
Bihar ..	9·53	*Union Territories*	
Gujarat	21·12	Andaman and Nicobar Islands	—
Haryana	13·95	Arunachal Pradesh	—
Himachal Pradesh ..	7·40		
Jammu & Kashmir	1·78	Chandigarh	4·28
Karnataka ..	9·58	Dadra and Nagar Haveli	—
Kerala	4·17	Delhi	4·16
Madhya Pradesh ..	13·82	Goa, Daman & Diu	9·21
Maharashtra ..	10·37	Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	—
Manipur	—		
Meghalaya	—	Pondicherry	5·72
Nagaland	1·74	All India	11·01
Orissa	8·55		
Punjab	15·75		

भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिये अमरीकी सहायता

3635. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के भूतपूर्व आर्थिक सलाहकार डा० रेमण्ड एवैल ने अभी हाल में भारत की यात्रा की थी और भारत की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सरकार के साथ विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहन वाज़ खां) : (क) और (ख) : भारतीय उर्वरक संगठन के द्वारा 70वें दशक में विश्व में उर्वरक समिति

"दी वरल्ड फर्टिलाइजर सिचुएशन इन दी सैवनटीज़" पर आयोजित विचार गोष्ठी के सम्बन्ध में डा० रेमण्ड एवैल ने भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान डा० एवैल ने शिष्टाचार के रूप में उर्वरक विषय के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। उनके द्वारा इस विचार विमर्श में न तो कोई विशेष प्रस्ताव रखा गया और न ही हमारे द्वारा कोई सहायता प्राप्त की गई।

ग्रोज़ बेकेर्ट साबू लिमिटेड, नई दिल्ली

3636. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रोज बेकेर्ट साबू लिमिटेड, नई दिल्ली" के निदेशक-बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस कम्पनी के मुख्य शेयर-धारियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के पास कितने मूल्य के तथा कितने शेयर हैं ;

(ग) इस कम्पनी का मुख्य व्यवसाय क्या है और इसकी कुल दत्त-पूंजी एवम् आस्तियों का मूल्य कितना है ;

(घ) क्या यह कम्पनी किसी बड़े व्यापार गृह/व्यापार-गृहों के नियंत्रण में हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ङ) क्या इस कम्पनी पर एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रतिक्रिया अपनाने का आरोप लगाया है ; और

(च) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का स्वरूप क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग). एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) मैसर्स ग्रोज बेकेर्ट साबू लिमिटेड, भारत से बाहर पंजीकृत विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक है। अतः किसी भारतीय व्यापारिक गृह द्वारा नियंत्रण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) तथा (च). जुलाई, 1972 में, रजिस्ट्रार निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष कम्पनी के विरुद्ध आरोप लगाते हुए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि कम्पनी प्रादेशिक प्रतिबन्धात्मक, एकमात्र व्यापार और पुनः विक्री मूल्य के रखरखाव में ग्रस्त निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं की अति भोगी है। जांच के पश्चात्, आयोग रजिस्ट्रार से सहमत हो गया और आदेश पारित किया कि कम्पनी इन प्रथाओं पर विराम लगाए और बन्द करे।

विवरण

31-3-1973 तक ग्रोज बेकेर्ट साबू लिमिटेड, के सम्बन्ध में ब्यौरे

1.	प्रदत्त पूंज	30.00 लाख रुपए (10 रु० प्रत्येक के 3,00,000 साम्य शेयर)
2.	कुल परिसम्पत्ति	92.67 लाख रुपए
3.	व्यापारिक गति विधियों की मुख्य रेखा	हौज़री और निटिंग मशीन का निर्माण
4.	निदेशक मडल	श्री ग्रोज बाल्थर, श्री कोर्यानिंग कुर्ट, श्री पीटर लेमको (प्रबन्ध निदेशक) श्री ताराचन्द साबू, श्री सूर्य प्रकाश मन्डेलिया श्री राजेन्द्र कुमार साबू (प्रबन्ध निदेशक)
5.	**प्रधान शेयरधारी :**	
	(1) ग्रोज बेकेर्ट इन्टरनेशनल एजेंसीज, स्विस (विदेशी/ स्वामित्वयी कम्पनी) .	1,80,000 शेयर
	(2) राजेन्द्र कुमार साबू .	23,214 शेयर
	(3) श्रीमती कल्याणी देवी मोदी	10,178 शेयर
	(4) श्रीमती इन्द्रमणी मन्डेलिया	10,176 शेयर
	(5) श्रीमती भगवति प्रसाद और श्रीमती सुमित्रादेवी मन्डेलिया	9,376 शेयर
	(6) श्री सूर्य प्रकाश और श्रीमती तारामणी मन्डेलिया	9,376 शेयर
	(7) साबू के उपमान सहित 16 शेयरधारी या श्री टी० सी० साबू के साथ संयुक्त धारी . .	40,500 शेयर
	(8) 14 अन्य शेयरधारी :	
	(क) मन्डेलिया के उपनाम के साथ 4	4,715
	(ख) मोदी उपनाम के साथ 2 .	4,822
	(ग) 3 अन्य	7,643
		17,180
	योग	3,00,000 शेयर

कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बात-चीत

3637. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देशों के साथ ईरान के साथ हुए करार के सिद्धान्तों पर भारत को कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में कोई बात-चीत हुई है अथवा हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य-2 बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) (क) और (ख) अशोधित तेल के आयात करने के लिए कुछ तेल उत्पादक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर बात चीत की जा रही है अथवा की गई है। इन व्यवस्थाओं का ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है।

औषध और भेषज उद्योग के विकास संबंधी समिति

363. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और भेषज उद्योग के विकास का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति अभी हाल ही में गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन किन परिस्थितियों के कारण किया गया ; और

(ग) उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उस के निर्देश-पद क्या हैं और उसकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : समिति का गठन किए जाने वाली परिस्थितियाँ उसकी संरचना, विचारार्थ विषय और समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि का उल्लेख दिनांक 5 मार्च 1974 को दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के उत्तर में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के संकल्प दिनांक 8 फरवरी 1974 में किया गया है।

Law Books in Hindi

3639. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of law books brought out in Hindi so far; and

(*b*) the total number of law books proposed to be brought out in Hindi in the next three years ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (*a*) No law text book in Hindi has been yet published by this Ministry. Two books however, in the press.

(*b*) No programme as such for publication during the next three years has been drawn up. But in pursuance of the schemes relating to the writing of original law books in Hindi and the translation of legal classics into Hindi, every effort will be made to publish as many books as possible during the said period.

Ticketless Travelling during the last six months

3640. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of passengers apprehended for travelling without tickets during the last six months, Railway-wise; and

(b) the amount recovered from them as fine?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) & (*b*): A statement is attached. (Placed in Library. See No. **L.T. 6473/74**)

Security Force Personnel found guilty on charges of stealing

3641. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether some officers and other ranks of the Security Force of the Railways have been found guilty on charges of theft of goods from the trains and abetment thereof; and

(*b*) if so, the broad outlines thereof and the action taken against the guilty persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) Yes. some officers and other ranks of the RPF have been found involved in cases of thefts and pilferages of booked consignments.

(*b*) A Statement is attached. (Placed in Library. See No. **L.T.64 74/74**)

Conversion of Kaohnara Flag Station (Western Railway) into a full fledged Station

3642. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether there has been a long-standing demand to convert Kachnara Flag station of Mandsaur District in Ratlam Division of Western Railway into a full-fledged station;

(*b*) whether a preliminary survey has already been made in this regard and if so, the outcome thereof; and

(*c*) the progress made so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) Yes.

(*b*) and (*c*) Yes. The survey revealed that conversion of Kachnara train halt into a full-fledged station was not financially justified. In view of this, the proposal for conversion was dropped.

Demand for the expansion of Passenger Shed and for providing two Gates to Third Class Waiting Room at Mandsaur Station (Western Railway)

3643. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether there is a long standing demand for the expansion of passenger shed at the platform and for providing two gates for entry towards third class waiting room at Mandsaur Railway station of Ratlam Division on Western Railway; and

(*b*) if so, the action taken so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) No. The existing platform shelter measuring 2100 sq. ft. and one exit and entry gate 10" wide are considered adequate for the present level of passenger traffic.

(*b*) Does not arise.

Loco Employees on Strike in 1973-74

3644. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of times loco employees went on strike in 1973 and 1974; and

(*b*) the loss of life and property suffered thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) Four times in general on different railways and on Northern six times.

(*b*) There was loss of property worth Rs. 1·87 lakhs but no loss of life as a result of these strikes on all the railways.

उच्च शक्ति वाले बिजली के रेल इंजन

3645. श्री डी० डी० देसाई
रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अनुसंधान विभाग ने देश में ही बने कल-पुर्जों में एक उच्च शक्ति वाले बिजली के रेल-इंजन का डिजाईन तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा एक रेल इंजन चितरंजन में निर्माणाधीन है ;

(ग) उच्च स्तर की कुशलता से चलने वाले रेल इंजनों का निर्माण करने की दिशा में अनुसंधान-गतिविधियों में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) देश में परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) अनुसंधान कार्य एक सतत प्रक्रिया है। रेल इंजनों में समय-समय पर सुधार किए जाते हैं।

(घ) प्रत्याशित यातायात को सम्भालने के उद्देश्य से रेलों के विकास कार्यक्रम में अतिरिक्त चल स्टाक की खरीद, लाइन क्षमता में वृद्धि और सिगनल तथा दूर संचार उपस्कर और कर्षण व्यवस्था आदि के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना अवधि में इस काम पर कुल 2,350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

राजस्थान में सुमेर तलिया के स्थान पर तेल के लिये छिद्रण क्रिया का स्थगित किया जाना

3646. श्री डी० डी० देसाई : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सुमेर तलिया के स्थान पर तेल का पता लगाने हेतु बहुत गहराई तक छिद्रण करने का काम 23 दिसम्बर 1973 को शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त छिद्रणकार्य फरवरी, 1974 में रोक दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ; और

(घ) अब तक कितना छिद्रणकार्य पूरा किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्मचारियों द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित पारी पद्धति (शिफ्ट सिस्टम) के अनुसार कार्य करने को स्वीकार न करने के कारण 14 जनवरी 1974 से 10 मार्च 1974 की अवधि के लिए व्यधन कार्य रुक गया था। कर्मचारियों ने 11 मार्च 1974 से व्यधन स्थल पर पुनः कार्य आरम्भ किया।

(घ) 13-1-1974 तक 296 मीटर गहरा कुआं खोदा जा चुका है।

फरक्का बांध के नीचे की ओर गंगा के किनारे पर भू-क्षरण से बचाव के लिए निर्माण कार्य

3647. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरक्का बांध से नीचे की ओर गंगा के दायें किनारे पर भू-क्षरण से बचाव के लिए निर्माण-कार्य करने संबंधी कोई योजना पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या इस भू-क्षरण को रोकने के लिए कोई उपाय किए हुए हैं जिस के कारण इस जिले के भरपूर आबादी वाले कई नगरों तथा असंख्य गांवों को बी० ए० के० लूप लाईन को रेल-पटरी को, राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 को तथा फरक्का बांध की जंगीपुर सहायक नहर को गंभीर खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या इस भू-क्षरण के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और गंगा बाढ़ आयोग द्वारा कोई जांच की गई है तथा क्या उन्हें इसके लिए किन्हीं विशिष्ट रसायनिक उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की अपनी जानकारी के अनुसार भू-क्षरण संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा के दक्षिण तट कटाव के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु 63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक स्कीम मार्च, 1973 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से केन्द्र को प्राप्त हुई थी। इस स्कीम को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में विस्तारपूर्वक जांच की गई है और यह पाया गया है कि स्कीम विस्तृत अन्वेषणों और माडल अध्ययनों पर आधारित नहीं थी। अतः राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि वे विस्तृत सर्वेक्षण और माडल अध्ययन करने के बाद एक व्यापक स्कीम तैयार करें।

कटाव समस्या को हल करने के लिए लघु कालीन तथा दीर्घकालीन दोनों बचाव उपायों पर अप्रैल, 1973 में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक में भी विचार-विमर्श हुआ था। जैसा कि उस समय निर्णय लिया गया था राज्य सरकार ने अधिक नाजुक क्षेत्रों में तत्काल कार्य क्रियान्वित कर दिए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना में किए जाने वाले माडल प्रयोगों के परिणामों के आधार पर दीर्घकालीन उपायों का आयोजन करना होगा। अभी माडल अध्ययन पूरे नहीं हुए हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कटाव को रोकने के लिए पिछले वर्ष किए गए तत्काल का उन विशेष क्षेत्रों में, जहां के लिए वे अभीष्ट थे, वाकयी प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फरक्का बांध से नीचे की ओर गंगा के किनारे पर भू-क्षरण से बचाव हेतु निर्माण कार्यों के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता

3648. श्री त्रिदिव चौधरी
श्री आर० एन० बर्मन } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के नीचे की ओर गंगा के दायें किनारे पर भू-क्षरण से बचाव के लिए निर्माण कार्यों पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहले कर लिए गए आपात खर्च को पूरा करने के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपए की योजना के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर, 1973 में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) कटाव-रोधी स्कीमें बाढ़ नियंत्रण सैक्टर में शामिल हैं जो राज्य योजना का भाग है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के के रूप में, विकास अथवा स्कीम के किसी विशिष्ट शीर्ष के साथ जोड़े बिना, दी जाती है। इस प्रकार से फरक्का के अनुप्रवाह में कटाव-रोधी कार्यों के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा की जानी है तदनुसार, राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

झामर कोटरा क्षेत्र में राक-फास्फेट निक्षेपों के विकास के लिये समिति

3649. श्री फतह सिंह राव गायकवाड: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर में झामरकोटरा क्षेत्र में राक-फास्फेट निक्षेपों के विकास के संबंध में तकनीकी पहलुओं की जांच करने के लिए गठित समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं? और

(ख) यह समिति संभवत: किस तारीख तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया गया है:—

1. सचिव, पैट्रोलियम तथा रसायन	अध्यक्ष
2. श्री एस० वेंकटारमन, सलाहकार (उर्वरक) पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	सदस्य
3. श्री जी० रामास्वामी, संयुक्त सचिव, खान विभाग	सदस्य
4. श्री एम० सत्यापाल, अपर सलाहकार (आई०एण्ड एम०) योजना आयोग नई दिल्ली	सदस्य
5. डा० वी० ए० आलतेकर, निदेशक, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर . . .	सदस्य
6. श्री आर० नरसिंह्न, उप सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग (व्यय) नई दिल्ली	सदस्य
7. श्री प्रताप नारायण संयुक्त निदेशक (योजना) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली .	सदस्य
8. श्री जी० के० आयंगर, प्रबन्धक (वाणिज्य) भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बंगलोर .	सदस्य
9. श्री नरेश चन्द्र, सचिव (उद्योग) राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
10. श्री एस० सुन्दर, उप सचिव, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	सदस्य-सचिव

(ख) समिति द्वारा शीघ्र कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है।

Election to Legislative Assemblies of Uttar Pradesh, Orissa, Pondicherry and Manipur

3650. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Ramavatar Shastri } : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(*a*) the total number of candidates, party-wise and independents who filed their nominations for the recent elections to the Legislative Assemblies of U. P., Orissa, Manipur and Pondicherry;

(*b*) the total number of candidates, party-wise whose Security deposits were forfeited; and

(*c*) the income accrued to Government as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (*a*) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दक्षिण-मध्य रेलवे में मिराज-सांगली और मिराज नान्डे रेल-मार्ग के साथ रेलवे भूमि की खरीद

3651. **श्री आप्पा सहिब गोट खिन्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे में मिराज-सांगली और मिराज-नान्डे रेल मार्गों के साथ रेलवे भूमि क्रय करनी चाही थी जो भूमि नई ब्राड गेज लाइन के चालू होने से रेलवे के पास फालतू हो गई थी ;

(ख) क्या राज्य सरकार को उक्त भूमि की आवश्यकता वर्तमान सांगली-मिराज सड़क को चौड़ा करने और मिराज तथा माधव नगर के बीच लिंक मार्ग बनाने के लिए थी और क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के मूल्य निर्धारण से रेलवे के प्रतिनिधि इस शर्त के साथ सहमत हो गए थे कि रेलवे बोर्ड की अन्तिम मंजूरी भी ली जाएगी ;

(ग) क्या बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दी जाएगी और भूमि का कब्जा कब तक दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया था कि सड़क को चौड़ा करने/नयी सड़क की व्यवस्था करने के लिए मिराज-सांगली और मिराज-नान्डे रेलवे लाइनों के साथ वाली भूमि की आवश्यकता है। राज्य सरकार और रेलवे के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक में भूमि के मूल्यांकन पर सहमति हो गयी थी। बोर्ड ने उसका अनुमोदन भी कर दिया था।

(ग) और (घ) : बोर्डद्वारा अनुमोदित सम्मत मूल्यांकन की सूचना स्वीकृति के लिए संभावत: राज्य सरकार को नवम्बर, 1973 में दे दी गयी थी। लेकिन राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने और सम्मत दरों पर भुगतान की भी व्यवस्था होने पर राज्य सरकार को भूमि सौंप दी जाएगी।

कोल्हापुर और पूने के बीच 312 अप और 311 डाउन गाड़ियों को पुन: चालू करना

3652. **श्री अण्णा साहि : गोट खिंड़े :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्हापुर और पूने के बीच चल रही 312 अप और 311 डाउन गाड़ियों को कब चालू किया गया था और इन्हें कब से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों को पुन: कब से चालू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). 311 डाउन/312 अप पुणें–कोल्हापुर एक्सप्रैस गाड़ियां जो 1-11-1973 से चलायी गयीं थीं, कोयले की कठिन स्थिति के कारण 23-12-73 को पुणें से और 22-12-73 को कोल्हापुर से रद्द करना

पड़ा। जैसे ही कोयले की स्थिति में सुधार होता है इन गाड़ियों को फिर से चलाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

सांगली और कोल्हापुर के बीच यात्री गाड़ियों को पुनः शुरु करने की मांग

3653. **श्री अण्णासाहिब गोटखिड़े :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाये जाने से दक्षिण मध्य रेलवे पर सांगली और कोल्हापुर के बीच यात्री गाड़ियां चलती थीं;

(ख) क्या लाइन परिवर्तन के बाद ये गाड़ियां रद्द की गई थीं;

(ग) क्या सांगली और कोल्हापुर के बीच यात्री गाड़ियों को पुनः शुरू किए जाने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां। चार जोड़ी स्थानीय गाड़ियां।

(ख) जी हां। लेकिन इन के स्थान पर, यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुणें और मिराज के बीच 3 जोड़ी गाड़ियों और मिराज और कोल्हापुर के बीच 4 जोड़ी शटल गाड़ियों के अलावा इस खण्ड पर तीन जोड़ी एक्सप्रैस गाड़ियां चल रही हैं।

(ग) और (घ). कोल्हापुर-मिराज स्थानीय गाड़ियों को सांगली तक चलाने के लिए किए गए अनुरोध पर विचार किया जा रहा है और जो भी कार्रवाही व्यावहारिक और उचित होगी की जाएगी।

क्विलोन जंक्शन (दक्षिण रेलवे) का विकास करने सम्बन्धी योजना

3654. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के क्विलोन जंक्शन रेलवे स्टेशन का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) एर्नाकुलम-तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल खण्ड की मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की योजना के अन्तर्गत अपेक्षित आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेशन की एक नई इमारत बनाने का विचार है।

(ग) आमान परिवर्तन का काम पहले से ही चल रहा है और प्रस्तावित स्टेशन की नयी इमारत के निर्माण का काम, 1975 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

कल्लाडा सिंचाई परियोजना

3655. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन्न:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कल्लाडा सिंचाई परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक पूरे हुए कार्य का विवरण क्या है और नवीनतम गणना के अनुसार इस परियोजना के विभिन्न चरणों के आरम्भ होने में समय-सारिणी क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : कल्लाडा सिंचाई परियोजना में पाराप्पर पर एक सिंचाई बांध तथा ओट्टक्कल पर, वाम और दक्षिण तट नहरों सहित एक पिक-अप वियर का निर्माण परिकल्पित है। पाराप्पर बांध पर कुछ पहुंचों में नींव की खुदाई और चिनाई का कार्य प्रगति पर है । ओट्टकल पर पिक-अप वियर, घर्षण स्लूइस के कार्य के कुछ भाग को छोड़ कर पूरा हो गया है। दक्षिण तट नहर पर कार्य शुरू किया गया है और यह विभिन्न पहुंचों में प्रगति पर है।

परियोजना के प्रथम चरण के जिसमें 22000 हैक्टेयर की सिंचाई के लिए सहायक नहर प्रणाली और ओट्टक्कल वियर शामिल हैं, पांचवीं योजना के दौरान पूर्ण होने की आशा है जबकि सम्पूर्ण परियोजना के छटी योजना में पूर्ण होने की संभावना है ।

बिजली की सप्लाई बार-बार बन्द करने का कलकत्ता जल-सप्लाई व्यवस्था पर प्रभाव

3656. **श्री राकेन सेन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई अनिर्धारित रूप से बार-बार बन्द करने का कलकत्ता जल-सप्लाई व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पिछले पांच महीनों के दौरान रेल दुर्घटनायें

3657. **श्री एम० एस० संजीवी राव**
श्री एस० एन० सिंह देव } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच महीनों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) रेलवे को कितनी क्षति हुई ;

(ग) कितने व्यक्ति हताहत हुए और दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई ;

(घ) क्या सभी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए कोई जांच की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक जांच का क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) भारत की सरकारी रेलों पर 1-9-1973 से 31-1-1974 तक की अवधि में टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 351 दुर्घटनाएं हुईं।

इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को जो क्षति पहुंची उसकी लागत का अनुमान लगभग 1,25,47,000 रुपए लगाया गया है।

इन दुर्घटनाओं में 62 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 291 व्यक्ति घायल हुए। 1-9-1973 से 31-1-1974 तक की अवधि में 54,081 रुपए की रकम मुआवजे के रूप में दी गई।

(घ) और (ङ) सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई है।

इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(i) रेल कर्मचारियों की गलती	190
(ii) रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों की गलती . .	57
(iii) रेलवे उपस्करों की खराबी	54
(iv) आकस्मिक . . .	21
(v) कारण ज्ञात न हो सका	6
(vi) कारण जिसका अन्तिम रूप से निर्णय अभी नहीं हुआ है .	23
जोड़	351

पांचवी योजना के पहले वर्ष में आन्ध्र प्रदेश के लिए बड़ी सिंचाई योजनाएं

3658. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में आन्ध्र प्रदेश के लिए कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) इन योजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : 1974-75 के लिए आंध्र प्रदेश की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी द्वारा वाराणसी में अमोनिया यूरिया उद्योग समूह की स्थापना के लिये अनुमति मांगना

3659. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री प्रबोध चन्द्र } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू सेन्ट्रल मिल्स कम्पनी ने वाराणसी में अमोनिया यूरिया उद्योग समूह की स्थापना के लिए अनुमति मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दक्षिण रेलवे में कोयले की कमी के कारण डीजल से रेलगाड़ियां चलाना

3660. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम सहाय पाण्डे } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की कमी के कारण दक्षिण रेलवे में अनेक गाड़ियों में डीजल से चलने वाले इंजन लगाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो डीजल से चलने वाले इंजन कितनी रेलगाड़ियों में लगाये जायेंगे।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : यात्री गाड़ियों का डीजलीकरण कई उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना, निर्धारित रफ्तार में वृद्धि करना आदि। यात्री गाड़ियों का डीजलीकरण डीजल रेल इंजनों, जिनकी आवश्यकता मुख्य रूप से आवश्यक माल यातायात की ढुलाई के लिए पड़ती है, की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखकर एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। अन्य बातें सामान्य होने पर, डीज़लीकरण के मामले में उन क्षेत्रों को तरजीह दी जाती है जो कोयला क्षेत्रों से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर स्थित हैं। तदनुसार 207/208 कर्नाटक एक्सप्रैस को 28-2-1974 से डीजल इंजन से चलाया जा रहा है। निकट भविष्य में दक्षिण रेलवे पर 101/102 मद्रास-रामेश्वरम एक्सप्रैस और 103/104 तिरुचिरापल्लि-तुत्तुकुडि एक्सप्रेस गाड़ियों को भी डीज़ल इंजनों से चलाने का विचार है।

Agreement between Oil India and Iraq for Oil Exploration

3661. Shri Shrikrishna Agarwal : Will the Minister of **Petrolcum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether under the agreement concluded with Iraq the experts of the Oil-India paid a visit to that country recently with the object of prospecting oil there;

(*b*) if so, the facts thereof; and

(*c*) the success expected in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum ad Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (*a*) to (*c*) : No agreement has been concluded with iraq by Oil India Limited. Presumably the reference is to the agreement concluded with Iraq by the ONGC on August 20, 1973.

The ONGC has already set up a project office in Iraq for conducting the operations in the area covered by the contract between the Commission and the Iraq National Oil Company (INOC). The Commissions personnel are already in Iraq for conducting seismic surveys in the contracted area which are expected to commence shortly. exploring for oil is a time consuming process and it is too early to comment on the success, if any that may be achieved.

सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि करना

3662. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन-राशि को बढ़ाकर 40 रुपये प्रति माह करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्तमान आदेशों के अधीन पेंशनीय कर्मचारियों को देय पेंशन की न्यूनतम रकम 40 रुपये मासिक है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में बिजली का संकट

3663. **श्री पी० के० मावलंकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद तथा गुजरात के अनेक अन्य नगरों और स्थानों में बिजली का भारी संकट है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या तत्काल कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र से, जहां कि एक यूनिट में दुबारा ईंधन लेने के लिए उसे काम से हटा लिया गया है तथा दूसरे को अनुरक्षण कार्यों के लिये शीघ्र ही कार्य से हटा लेने की संभावना है (जिसमें लगभग एक सप्ताह लगेगा) कम बिजली उपलब्ध होने के कारण बिजली सप्लाई में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । ये मार्च, 1974 तक लागू रहेंगे ।

राज्य में अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता को चालू करने में शीघ्रता लाई जा रही है । उकई जल विद्युत् केन्द्र में 75-75 मैगावाट की दो यूनिटों के अप्रैल, और जून, 1974 में चालू करने की संभावना है ।

अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच ब्राडगेज लाइन

3664. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच ब्राडगेज लाइन के निर्माण कार्य प्रगति पर है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उस मार्ग पर ब्राड-गेज लाइन पर आवागमन कब से आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना पर वास्तविक प्रगति 35 प्रतिशत से ऊपर हुई है। दिसम्बर, 1974 तक इस लाइन के पूरा हो जाने और माल यातायात के लिए खुल जाने की संभावना है और आशा है, सवारी यातायात के लिए यह लाइन मई, 1975 में खुल जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे संचालन के विभिन्न एककों में नियुक्त नैमित्त कर्मचारी

3665. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे संचालन के विभिन्न एककों में नैमित्तिक कर्मचारियों को काम पर रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा मोटे तौर पर उनकी श्रेणियां क्या हैं तथा वे किस प्रकार का कार्य करते हैं ?

(ग) ऐसे कितने नैमित्तिक कर्मचारी 5, 10, 15 और 20 वर्षों में से अधिक समय से काम पर हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों को स्थायी न करने के क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) नैमित्तिक मजदूरों को अधिकांश: सामयिक, छुटपुट और सविरामी ढंग के निर्माणकार्यों की अकुशल कोटियां तथा परियोजनाओं में काम पर लगाया जाता है। उनके काम की किस्म में गर्मी में गाड़ी में यात्रियों के लिये पानी की व्यवस्था, मानसून के समय रेल पथ पर गश्त लगाना, बाढ़ से क्षति ग्रस्त होने पर मरम्मत का काम शामिल है। उन्हें विशेष कामों जैसे मिट्टी बिछाने, फिर से स्लीपर बिछाने, फिर से लाइन बिछाने और इमारतों तथा पुलों आदि के निर्माण में भी काम पर लगाया जाता है । 31-3-73 को नैमित्तिक मजदूरों की संख्या 3,16,890 थी।

(ख) 17,048 मजदूर 5 से 10 वर्ष के बीच और 2773 मजदूर 10 वर्ष से अधिक समय के लिए नियोजित किये गये थे ।

(घ) जब कभी नियमित रिक्तियां होती हैं, छान-बीन समितियों द्वारा उपयुक्त पाये गये नैमित्तिक मजदूरों को नियुक्त करने पर विचार किया जाता है लेकिन, नियमित पदों पर आमलित करने की सम्भावना सीमित होती है ।

उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियरों द्वारा हड़ताल

3666. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री प्रसन्ना भाई मेहता } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में 22,000 जूनियर इंजीनियरों ने 10 जनवरी, 1974 से अनिश्चित काल को एवं आम हड़ताल कर रखी है ?

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की हड़ताल फैल रही है और यदि हां, तो इसका राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) हड़ताली इंजीनियरों की मांगों की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) उत्तर प्रदेश में सभी इंजीनियरिंग विभागों में काम कर रहे लगभग 15,000 जूनियर इंजीनियरों (राज्य बिजली बोर्ड समेत) में अधिकांश 10 जनवरी, 1974 से हड़ताल पर आए ।

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इस हड़ताल से अन्य राज्यों पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) इस मामले से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ही सक्षम है ।

तेल शोधन कारखानों को कच्चे तेल की अपर्याप्त सप्लाई

3667. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री के० मालन्ना } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल शोधन कारखाने कच्चे तेल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण अपनी क्षमता से बहुत कम क्षमता पर चल रहे हैं जिससे बहुत अधिक हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) . समस्त चार अन्तरदेशीय परिष्करणशालाएं देशज आशोधित तेल पर ही आधारित हैं जो असम और गुजरात के तेल क्षेत्रों से उनको सप्लाई किए जाने वाले देशज अशोधित तेल की सम्पूर्ण मात्रा का शोधन कर रही है। बरौनी परिष्करण शाला देशज असम अशोधित तेल के अतिरिक्त प्रति वर्ष 0·5 से 0. 6 मिलियन मीटरी टन आयातित अशोधित तेल का भी अब शोधन कर रही है।

पांच तटवर्ती परिष्करण शालाओं का जहां तक सम्बन्ध है, वे आयातित अशोधित पर आधारित है । अशोधित तेल की परिवहन व्यवस्था करने में कठिनाइयों सहित, तत्वों के संयोग के कारण कोचीन परिष्करणशाला अपनी क्षमता से कम कार्य कर रही है। इन कठिनाइयों पर उत्तरोत्तर काबू पाया जा रहा है।

भारतीय रेलों में विद्युत् विभाग में टी० एल० आई० बिजली घरों और हैड लाइट अनुभागों में कुशल कारीगरों की नियुक्ति के लिये निर्धारित मापदण्ड

3668. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में विद्युत् विभाग में टी० एल० आई० बिजली घरों और हैड लाइट अनुभागों में कुशल कारीगरों की नियुक्ति के संबंध में कोई मापदण्ड निर्धारित है;

(ख) क्या विद्युत विभाग में कुशल, अर्द्ध-कुशल कारीगरों के संवर्गों की दरों में कोई प्रतिशतता निर्धारित है;

(ग) क्या उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही कर्मचारी नियुक्त हैं और यदि हां, तो पूर्व रेलवे में विद्युत् विभाग में टी० एल० आई० बिजली-घरों और हैड लाइट अनुभागों में क्या प्रतिशतता है ; और

(घ) निर्धारित मापदण्ड की मुख्य बातें क्या हैं और पूर्व रेलवे में विद्युत विभाग में प्रत्येक अनुभाग में क्या प्रतिशतता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) रेलवे बोर्ड द्वारा कोई माप-दण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। रेलों ने मार्ग-दर्शन के लिए कुछ अपने सिद्धान्त निश्चित कर रखे हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी । ।

रेलवे अस्पताल, दानापुर (पश्चिम रेलवे) के टी० बी० वार्ड में मेडिकल कर्मचारियों को टी० वी० भत्ते की अदायगी

3669. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या रेल अस्पतालों के टी० बी० वार्ड में काम कर रहे मेडिकल कर्मचारियों को टी० बी० भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर रेलवे अस्पताल में टी० बी० वार्ड में काम कर रहे मैडिकल कर्मचारियों को पिछले कुछ सालों से टी० बी० भत्ते की अदायगी नहीं की जा रही है; और

(ग) क्या रेलवे अस्पतालों की शय्याओं से सम्बद्ध नर्सों, परिचारिकों और सफाई वालों के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केवल नर्सों के पदों के सृजन के लिए ही मापदण्ड निश्चित है, परिचरों और सफाई वालों के लिए नहीं ।

विद्युत् संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

3670. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले पर आधारित विद्युत् संयंत्र कोयले के अभाव के कारण बन्द होने की स्थिति में है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों में विद्युत उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) यद्यपि कुछ मामलों में कोयले के स्टाक का सामान्य स्तर, कुछ मामलों में तो यहां तक कि खपत के 1/2 दिन के स्तर तक नीचे चला गया था, सब मिलाकर, कोयले की अनुपलब्धता के कारण किसी विद्युत् केन्द्र को बन्द अथवा विद्युत् जनन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना पड़ा था।

(ख) और (ग) : जी, नहीं । बहरहाल, विद्युत् केन्द्रों के लिए कोयले की सप्लाई बनाए रखने हेतु खान विभाग एवं रेलवे मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं :—

1. विद्युत् केन्द्रों को कोयले के मासिक आवंटन का पुनरीक्षण करने हेतु खान विभाग में एक स्थायी सम्पर्क समिति का गठन किया गया है ।
2. विभिन्न विद्युत् केन्द्रों में कोयले की प्रतिदिन सप्लाई और भंडारों का पुनरीक्षण करने के लिये रेलवे मंत्रालय में एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है ।
3. ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयला ले जाने के लिए वैगनों के लदान का पुनरीक्षण करने हेतु कलकत्ता में एक संयुक्त एकक का सृजन किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, समस्तीपुर की मांगें स्वीकार करना

3671. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा 30 अक्तूबर, 1973 को समस्तीपुर में प्रदर्शन के सम्बन्ध में 27 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उत्तर में उल्लिखित मांगों में से कौन-कौन सी मांग स्वीकार कर ली गई है। कार्यान्वित कर दी गई है अथवा अस्वीकार कर दी गई है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6475/74) ।

खजौली तथा जयनगर स्टेशनों के मध्य कोरैया को और कमतौल तथा जोगीआडा के मध्य मरैथा को 'हाल्ट स्टेशन' बनाना

3672. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री खजौली तथा जयनगर स्टेशनों के मध्य कोरैया को और कमतौल तथा जोगीआड़ा के मध्य मरैथा को 'हाल्ट स्टेशन' बनाने के बारे में 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीज श्रमदान द्वारा मिट्टी आदि का कार्य पूरा हो गया है तथा क्या कोरैया में 'हाल्ट स्टेशन' चालू हो गया है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मई, 1973 के बाद मरैथा में 'हाल्ट स्टेशन' बनाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया है और इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां, मिट्टी का काम तो पूरा हो चुका है परन्तु अन्य निर्माण संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं । इन कार्यों के पूरा होते ही हाल्ट स्टेशन खोल दिया जायगा।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रस्ताव पर पुनः जांच कर ली गई है और अब रिपोर्ट रेल मंत्रालय के संवीक्षाधीन है।

Proposal to convene a meeting of Political Parties by the Election Commission

3673. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the Election Commission has not convened any meeting of the political parties since 1968;

(*b*) if so, the reasons therefor;

(*c*) whether the Jan Sangh President had requested the Election Commission to convene an immediate meeting of political parties in order to ensure peaceful elections to Uttar Pradesh and other State Legislature Assemblies; and

(*d*) if so, what action was taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (*a*) No conference of political parties has been convened by the Election Commission since 1968.

(*b*) The Conference of political parties in May, 1968, was convened for the purpose of ascertaining their views in regard to the provisions to be made in the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order issued on 31st August, 1968. No question of such general importance has arisen since then.

(*c*) No, Sir.

(*d*) Does not arise.

Survey of Indore-Mhow Broad Gauge Line

3674. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) whether survey of Indore-Mhow broad gauge line has been completed; and

(*b*) if so, salient features in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) Yes.

(*b*) The reconnaissance survey carried out for the extension of the broad gauge line from Indore to Mhow has shown that this 21·01 km. long line would cost Rs. 2·13 crores and yield a negative return in the 6th year after opening. After due examination of the report, this unremunerative project has been shelved.

गंगा-कावेरी-लिंक परियोजना के कार्य में प्रगति

3675. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
श्री श्याम सुन्दर महापात्र } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी लिंक परियोजना के कार्य में प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). विभिन्न नदी प्रणालियों को जोड़ने वाले सम्पर्कों को अभिज्ञात करने के लिए अपेक्षित विभिन्न उप-बेसिनों, बेसिनों, इलाकों और क्षेत्रों को कमियों तथा वेशियों के अध्ययन और उसके उपरांत और आवश्यक अन्वेषणों को पांचवीं योजना में शुरू करने का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि पांचवीं योजना की अवधि के दौरान इन अध्ययनों और अन्वेषणों के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। ये अध्ययन और अन्वेषण संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

मचरेला-सिकन्दराबाद रेल लाइन के निर्माण पर लागत और उसका पूरा होना

3676. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मचेरला-सिकन्दराबाद नई रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान उस पर क्या कार्य किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी और यह नई लाइन कितने समय में पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : नडिकुडे-वीवीनगर नई बड़ी लाइन परियोजना के पूरा हो जाने और माचेर्ला-गुंटूर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव हो जाने के बाद माचेर्ला और सिकन्दराबाद के बीच नई बड़ी लाइन स्थापित हो जायेगी। निर्माण के लिए इन दोनों परियोजनाओं को 1974-75 बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ग) अनुमान है कि इन परियोजनाओं पर 22.82 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तारीख 1-4-1979 है।

पश्चिमी बंगाल विधानसभा के उप-निर्वाचन के बारे में प्राप्त हुई शिकायतें

3677. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को, पश्चिम बंगाल के मायघाट निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के दौरान आतंकवाद, बूथों पर बलात् कब्जा करने और विरोधी उम्मीदवारों को हथियारों से धमकियां देने के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) क्या इन अनुचित उपायों के विरोध में समाजवादी दल के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया था; और

(ग) स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचनों पर रोक लगाने वाली इन अलोकतान्त्रिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :

(क) जी हां।

(ख) रिटर्निंग आफिसर को, समाजवादी दल से अपने अभ्यर्थी का नाम वापस ले लेने के निर्णय की लिखित प्रज्ञापना मतदान की तारीख को लगभग चार बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी।

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी, 1974 को सात प्रभावित मतदान केन्द्रों में फिर से मतदान कराने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही, आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से विधि और व्यवस्था बनाए रखने और निर्बाध और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचक आफिसर को घटनाओं की पूर्ण जांच करने के लिए भी निदेशित किया।

बड़े जलाशयों में गाद जमा होने की आशंका

3678. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा**
श्री राम सहाय पाण्डे } : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 22 बड़े जलाशयों में गाद के जमा हो जाने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : देश के कुछ जलाशयों में गाद की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए अब तक किए गए सर्वेक्षणों और अनुसंधानों से पता चला है कि गाद वास्तव में उम्मीद से ज्यादा पड़ रही है परन्तु इससे संचय जलाशय के सक्रिय अवधि पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहरहाल, जब तक गाद जमा होने की गति के संबंध में कोई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकलता, पर्यवेक्षणों को कई वर्षों तक चालू रखना पड़ेगा।

जलाशयों में गाद जमा होने की गति कम करने के लिए, केन्द्र द्वारा आयोजित कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 नदी घाटी परियोजनाओं के वाह क्षेत्रों में वाटरशेड प्रबंध तथा भू-संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं।

राजधानी में रिंग रेलवे का निर्माण

3679. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तेल स्थिति और दिल्ली में असन्तोषजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा को ध्यान में रखते हुए राजधानी में रिंग रेलवे के निर्माण में द्रुत गति लाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : दिल्ली में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली की व्यवस्था के लिए तकनीकी-एवं-आर्द्रिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण का काम विशेष रेलवे संगठन द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए योजना आयोग द्वारा गठित महानगर परिवहन दल ने पहले सिफारिश की थी। निर्माण कार्य का विस्तार और उसके कार्यक्रम के बारे में कोई विनिश्चय रेलवे दल की रिपोर्ट मिलने पर ही किया जायेगा।

बम्बई और कलकत्ता में भूमिगत रेल व्यवस्था के सम्बन्ध में हुई प्राप्ति

3680. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
श्री समर गुह } : क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कलकत्ता में भूमिगत रेल व्यवस्था के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के काम को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बम्बई

बम्बई नगर के लिए व्यापक द्रुत पारवहन योजना में उपनगरीय लाइनों की बगल में गोरेगांव से कुर्ला तक सतही रेलवे लाइन और फार्ट-मार्किट में समाप्त होने वाली थोड़ी दूरी की भूगत रेलवे शामिल है। अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण और विस्तृत योजना सम्बन्धी काम हो रहा है और आशा है यह 1974 में पूरा हो जायेगा। इस लाइन का निर्माण-कार्य शुरू करने के उद्देश्य से 1974-75 के बजट में 4.65 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस योजना में के 5 वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

इसके अलावा बान्द्रा के रास्ते कोलाबा से कुर्ला तक एक ट्यूब रेलवे बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और व्यवहारिकता अध्ययन किये जा रहे हैं।

कलकत्ता

कलकत्ता नगर के लिये टालीगंज से दमदम तक एक द्रुत पारवहन भूगत रेलवे लाइन की योजना बनायी गई है और 1972 में इसके निर्माण का जो काम शुरू किया गया था, उसमें प्रगति हो रही है। यह काम सोवियत रूस की सरकार की सहायता से किया जा रहा है। इस परियोजना को 1979 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

हिमाचल प्रदेश की पनबिजली क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण

3681. **श्री कमल मिश्र मधुकर**
श्री भान सिंह भोरा } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश की पनबिजली क्षमता का मूल्यांकन करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इससे ऊर्जा संकट किस हद तक दूर हो सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार राज्यों को जल विद्युत् शक्यता 5100 मैगावाट (सतत्) है जैसाकि नीचे दी गई है :—

यमुना बेसिन	120 मैगावाट
सतलुज बेसिन	2400 मैगावाट
ब्यास बेसिन	1320 मैगावाट
रावी बेसिन	630 मैगावाट
चनाव बेसिन	330 मैगावाट

विद्युत् शक्यता, यदि विकसित की गई, उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी सहायक होगी। 1500 मैगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली जल विद्युत् परियोजनाएं पहले ही राज्य में निर्माणाधीन हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जल विद्युत् विकास की योजना में उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

उत्तरी राज्यों के कृषि फार्मों में बिजली की कमी

3682. **श्री गजाधर माझी**
श्री के० मालन्ना } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेष रुप से उत्तरी राज्यों के कृषि फार्मों में बिजली की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में विद्युत् की उपलब्धता पूरी मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहरहाल, विद्युत् की उपलब्धता मात्रा में से कृषि उद्देश्यों के लिए विद्युत् सप्लाई करने को राज्यों द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। विद्युत्/ऊर्जा कटौतियां मुख्यतया गैर-कृषि भारों पर लगाई गई हैं तथा विद्युत् की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए भार स्टेगरिंग भी लागू की गई है।

क्षेत्र में ताप विद्युत् केन्द्रों में उत्पादन को अधिकतम करने के लिए तथा अंतयोजित प्रचालनों द्वारा उत्पादन तथा पारेषण सुविधाओं को अधिकतम करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। विद्युत् के अंतक्षेत्रीय विनिमय की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, रबी फसल के लिए ऊर्जा सप्लाई को बढ़ाने के उद्देश्य से इस मास में भाखड़ा से नंगल उर्वरक कारखाने की विद्युत् सप्लाई 124 मेगावाट से घटा कर 68 मैगावाट कर दी गई है।

कृषि की आवश्यक विद्युत् मांगों को इस प्रकार पूरा किया जा रहा है।

कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन

3683. **श्री नवल किशोर सिन्हा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री कम्पनी कानून के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के नामों संबंधी जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) देश में 36000 के लगभग कम्पनियाँ हैं और औसतन प्रत्येक वर्ष 2000 कम्पनियों के विरुद्ध 6000 अभियोग चलाए जाते हैं। उल्लंघन मुख्यत: सामान्य प्रकृति के हैं, जैसे तुलन-पत्र का प्रस्तुन न किया जाना, सांविधिक बैठकों को विलम्बित सम्पन्न करना, वार्षिक महासभा की बैठकें सम्पन्न न करना और सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत न करना। इन उल्लंघनों

के विषय में सांख्यिकीय आंकड़े कम्पनी अधिनियम के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट में, जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, दिये जाते हैं।

दो वर्ष की अवधि में चलाए गए अभियोगों के विषय में, कम्पनियों के नाम प्रत्येक मामले में उल्लंघन, की गई कार्यवाही, अनिर्णीत जांचों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना के संकलन में काफी समय और परिश्रम ग्रस्त होगा और इस विभाग के दृष्टान्त पर संसदीय कार्य विभाग ने 21 जनवरी, 1974 की इस विभाग को अपने वर्तमान रूप में वचन पूर्ण किये जाने से मुक्ति के लिए सरकारी वचनों की समिति से सम्पर्क किया है। समिति की प्रतिक्रियाएं अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

विदेशी कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का लागू किया जाना

3684. **श्री बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम प्रभावी होने से पहले कुछ विदेशी कम्पनियां ठेकेदारी अथवा उप-लाइसेंसिंग के काम में संलग्न थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन उन के बारे में अब क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

माल-डिब्बों का उत्पादन करने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

3685. **श्री बेकारिया**
श्री० डी० पी० जदेजा } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने माल डिब्बों का उत्पादन करने सम्बन्धी अपनी नीति में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने 500 माल डिब्बों के निर्माण के लिए अभी हाल में आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो किसे आदेश दिया गया है और उस की शर्तें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल में माल डिब्बों के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य-निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट का दिया जाना

3686. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या रेल मंत्री भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट के दिया जाने के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 3665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष दो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : बाकी के दो कर्मचारियों में से एक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उसके मामले में एक सेट पास और दो सेट पी० टी० ओ० बन्द कर दिये गये हैं। दूसरे कर्मचारी के मामले में अभी कार्यवाही चल रही है।

साहिबाबाद, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे बुकिंग क्लर्कों को उनकी देय राशियों की अदायगी न करना

3687. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिबाबाद, दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे पर इस समय काम कर रहे कुछ बुकिंग क्लर्कों को दिसम्बर, 1972 में उनकी बीमारी की अवधि के सम्बन्ध में उन्हें अभी तक उनकी देय राशि की अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की अदायगियों में जानबूझ कर विलम्ब करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मव शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक शाखा, प्रभागीय कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे आफिस क्लर्कों का स्थानान्तरण

3688. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक शाखा, प्रभागीय कार्यालय, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में काम कर रहे कुछ आफिस क्लर्कों (ग्रेड 130-300 रु०) (ए० एस०) को कुछ अज्ञात व्यक्तियों को शिकायत के आधार पर फरवरी, 1972 में मुख्यालय के रिफण्ड अनुभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को आरोपों का उत्तर देने के लिए कोई अवसर दिया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1972 के अनेक महीनों के छुट्टी वेतन की अदायगी इन कर्मचारियों को नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). प्रशासनिक आधार पर केवल एक क्लर्क का स्थानान्तरण किया गया था जो उसी अनुभाग में लगभग 6 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रभागीय लेखा-अधिकारी कार्यालय नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के उपप्रभारी कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना

3689. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभागीय लेखा-अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे कुछ उप-प्रभारी कर्मचारियों (ग्रेड 210–380 रु० (ए० एस०) को वर्ष 1973 में गम्भीर कदाचार के आरोप में निलम्बित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को बड़ा दण्ड देने के लिए कोई आरोप पत्र दिया गया है ;

(ग) क्या अनुशासन और अपील नियमों के अधीन किसी सांविधिक जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी हां, केवल एक।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) अभी जांच हो रही है।

नेपाल को पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

3690. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री जगन्नाथ मिश्र } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा नेपाल को कितनी मात्रा में पैट्रोलियम–उत्पाद सप्लाई किये जा रहे हैं और इस संबंध में हुए करार की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : 1973 के दौरान नेपाल को लगभग 73,000 मीटरी टन पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की गई थी।

एक नेपाली शिष्टमंडल ने फरवरी, 1974 में भारत का दौरा किया था तथा भारतीय शिष्ट-मण्डल से विचार-विमर्श किया था। इस बातचीत के दौरान नेपाल को पी० ओ० एल० उत्पादों की सप्लाई की मात्रा का पुनरीक्षण किया गया था। और बातों के साथ साथ, यह बात मान ली गई थी कि उन आवश्यकताओं, जिन के बारे में भारत ने नेपाल को सप्लाई करने की पहले ही जिम्मेवारी ली थी, से अधिक के लिये नेपाल तेल निगम तथा भारतीय तेल निगम पूरा पूरा सहयोग करेंगे ताकि पी० ओ० एल० मदों का नेपाल को आयात किया जाना सुविधाजनक बनाया जा सके। यह बात भी मान ली गई थी कि भारत देख-रेख, परिवहन, भंडार तथा शोधन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और नेपाल द्वारा अपेक्षित पी० ओ० एल० मदों के मिश्रण, उत्पाद विनिमय आधार पर की, नेपाल को सप्लाई करने से संबंधित उपयुक्त प्रबन्ध भी करेगा।

केरल में पहले से चली आ रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

3691. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
श्री वयालार रवि } :क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पहले से चली आ रही प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना को अनुमानित लागत में माल, भूमि और श्रमिक दरों में वृद्धि हो जाने के कारण बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इस बढ़ी हुई लागत की तुलना में केन्द्रीय सहायता में कितनी वृद्धि हुई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां

(ख) केरल में सात बृहत् संतत् सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति के समय मूल अनुमानित लागत तथा इस समय को अनुमानित लागत नीचे दी जाती है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृति के समय मूल अनुमानित लागत	वर्तमान अनुमानित लागत
1.	पैरियार पाटो	348.00	1650.00
2.	कल्लाड़ा . . .	1328.00	4500.00
3.	पम्बा .	383.13	1890.00
4.	कुटियाड़ी .	496.04	1520.00
5.	चित्तुरपुडा .	106.00	624.00
6.	कनहिरापुका . .	365.10	926.15
7.	पज्यासी	442.40	1462.00

सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्विति के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी सम्पूर्ण विकासात्मक योजनाओं में से की जाती है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष विकास सैक्टर अथवा परियोजना से संबंद्ध नहीं होती है।

केरल में विद्युत क्षमता के लिए खोज

3692. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**
श्री वयालार रवि } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में सस्ती जल विद्युत् शक्ति की उपलब्धता से दक्षिणी राज्यों में बिजली के संकट को कम करने में बड़ी सहायता मिली है और उस राज्य में जल विद्युत् क्षमता के और आगे विकास की काफी संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बिजली के किसी भावी संकट का सामना करने के लिए इस विद्युत् क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या विशेष उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) . जी, हां। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा किए गए जलवैज्ञानिक विद्युत् सर्वेक्षण के अनुसार केरल राज्य को जल विद्युत् शक्यता 925 मेगावाट संतत है जो कि 8100 मिलियन यूनिट प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन के समकक्ष है। इस शक्यता में से लगभग 300 मेगावाट संतत 621.5 मेगावाट को प्रतिष्ठापित क्षमता वाले विद्युत् केन्द्रों में विकसित की जा चुकी है। 975 मेगावाट को प्रतिष्ठापित क्षमता की और परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जोकि 320 मेगावाट को संतत शक्यता का उपयोग करेगी। 475 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की स्कीमों के अन्वेषण हो गए हैं तथा परियोजना रिपोर्टों की जांच की जा रही है जिसमें 216 मेगावाट शक्यता का समुपयोजन होगा।

राज्य में जल विद्युत् शक्यता के समुपयोजना में तेजी लाने की नीति है ताकि संसाधनों की उपलभ्यता के अन्दर-अन्दर बढ़ती हुई विद्युत्-मार्गों को पूरा किया जा सके।

विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3693. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में विभिन्न राज्यों को सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल का आंकड़े वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6476/74**]

(ख) से (घ). जल्दी पूरे किये जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में डीजल की मांग में अत्यधिक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम जून, 1974 तक यथा सम्भव उच्चतम सीमा तक मिट्टी के तेल के उपयोग में मितव्ययता करना आवश्यक है। डीजल तेल का उच्चतम सीमा तक उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में समस्त राज्यों को जनवरी में 15 प्रतिशत, फरवरी में 20 प्रतिशत तथा मार्च, 1974 में 15 प्रतिशत तक कम किया गया। इस प्रकार की कटौतियां जून, 1974 तक आवश्यक होंगी। पश्चिम बंगाल सहित समस्त राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उपलब्ध सप्लाई के समान वितरण को सुनिश्चित करें तथा उत्पाद की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने हेतु कदम उठायें।

वर्ष 1972-73 के दौरान ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा-स्वीकृत योजनाएं

3694. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री राम भगत पासवान } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1972-73 के दौरान 227 योजनाओं को मंजूरी दी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ग्राम विद्युत्करण निगम ने 1972-73 के वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की 200 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, पहले से विद्युतीकरण ग्रामों के समीपवर्ती हरिजन बस्तियों में विद्युत् के विस्तार के लिए भी 27 स्कीमें स्वीकृत की हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6477/74**]

तापीय बिजली घरों द्वारा बिजली की सप्लाई

3695. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तापीय बिजली घरों द्वारा बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत की वद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की सप्लाई में वृद्धि के बावजूद बिजली की कमी होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1973 के दौरान देश में ताप विद्युत् केन्द्रों से कुल ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त सीमा तक उतना ही था जितना कि 1972 में । विद्युत् की मांग में वृद्धि के कारण विद्युत् की कमी बनी हुई है।

कोचीन और बरौनी तेल शोधक कारखानों के लिए ईराक से अशोधित तेल की सप्लाई स्थगित होना

3696. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन, बरौनी, एस्सों तथा बर्मा सैल तेल शोधक कारखानों को सरकारी खाते में ईराक से होने वाली अशोधित तेल की सप्लाई स्थगित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में हड़ताल करने वाले रेलवे कर्मचारियों के वर्ग

3697. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में फरवरी के अन्त तक रेलवे कर्मचारियों के किन-किन वर्गों ने हड़ताल की थी;

(ख) प्रत्येक हड़ताल में कितने कर्मचारी शामिल हुए थे ;

(ग) इन हड़तालों में प्रत्येक हड़ताल के कारण रेलवे को कितना हानि उठानी पड़ी; और

(घ) भविष्य में इन हड़तालों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). रेलों पेर विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले आन्दोलनों की घटनाएं होती रहती है जिनसे कम या अधिक समय के लिए काम रुक जाता है। आमतौर पर 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में बड़ी हड़तालों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनमें शामिल कर्मचारियों में इंजन शैडों (अनुरक्षण) के कर्मचारी, इंजन कर्मचारी (भाप, डीजल या बिजली) सवारी और मालडिब्बा विभाग के कर्मचारी और पिछले दिनों कुछ स्टेशनमास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर, यार्ड कर्मचारी गार्ड और कुछ गैंगमैन भी थे।

काम रुक जाने की अधिकांश घटनाएं अल्प कालिक होती हैं और कुछ छोटी घटनाओं के परिणामस्वरूप हो जाती है। ऐसे मामलों में कर्मचारियों को ड्यूटी शुरू करने की अनुमति दे दी जाती है। किन्तु, बड़ी हड़तालों के मामले में जिसमें लम्बी अवधि तक काम रुका रहता है और उनमें शामिल व्यक्तियों की संख्या 100 से लेकर लगभग 22,000 तक थी जैसा कि अगस्त, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल में हुआ था। ऐसी बड़ी हड़तालों के कारण जितने जिन दिनों की हानि हुई थी उसकी गणना पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की गयी थी :—

1971-72	लगभग	1.24 लाख
1972-73	,,	1.12 लाख
1973-74 . .	अब तक	4.5 लाख

हड़तालों और आन्दोलनों के कारण रेलों को 1971 में 1.4 करोड़ रुपये और 1972 में 1.9 करोड़ रुपये की हानि हुई। 1973 में हड़तालों/आन्दोलनों और खासतौर से लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कुल मिलाकर लगभग 21 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय रेलों पर श्रमिक संबंध एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है और इस सन्दर्भ में मान्यताप्राप्त फैडरेशनों के तत्वावधान में श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ कई विशेष बैठकें बुलायी गयी जो लाभदायक सिद्ध हुई हैं। स्थायी वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र का जो पिछले दो दशकों से वैधानिक ढंग से काम करते रहे हैं, पहले की अपेक्षा अधिक लाभप्रद उपयोग किया जाना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, 4 फरवरी 1974 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें श्रमिक समस्याओं में रूचि रखने वाले कुछ संसद सदस्यों, केन्द्रीय श्रमिक संघों के नेताओं और मान्यताप्राप्त दो फैडरेशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक उद्योग में एक यूनियन की नीति सिद्धान्त रूप में मान ली गयी है।

देश में तेल का उत्पादन

3698. श्री शंकर राव सावंत : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1974 के अन्त तक गत तीन वर्षों के दौरान देश के अन्दर तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : वर्ष 1971, 1972, 1973, 1974, (1974 के फरवरी मास तक) के दौरान अशोधित तेल का देशीय उत्पादन निम्नलिखित रूप में हुआ।

(हजार लीटरी टनों में)

वर्ष	अशोधित तेल का उत्पादन
1971	7185
1972	7373
1973	7197
1974 (74 के फरवरी, मास तक)	1176*

*अनन्तिम (प्रेषण पर आधारित)

महाराष्ट्र की पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी

3699. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णाजल विवाद न्यायधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट के बाद महाराष्ट्र की किन-किन पनबिजली परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दी है ; और

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एसी कोई परियोजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयात किये जा रहे रसायनों का देश में ही निर्माण

3700. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से अब भी किन-किन रसायनों का आयात किया जा रहा है, और

(ख) उनका भारत में ही निर्माण करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उर्वरकों, कुछ विशिष्ट औषधों और औषधके मध्यवर्ती पदार्थों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण रसायनों का आयात किया जा रहा है जो नीचे दिए गए हैं ।

1. सोडा राख
2. काष्टिक सोडा
3. सोडा ब्लीचिंग पाउडर
4. सोडा वाइक्कामेट्स
5. पोटाशियम कार्बाइड
6. सोडियम हाइड्रो सल्फाइट
7. कैल्शियम कार्बाइड
8. मर्करी
9. फासफोरिक एसिड
10. म्यूरिएट आफ पोटाश (प्योर)
11. पोटाशियम क्लोराइड (वाणिज्यिक)
12. सोडियम नाइट्रैट (नेचुरल)

13. सोडियम नाइट्रेट (सिन्थेटिक)
14. सोडियम नाइट्रेट
15. हाइड्रोक्लोरिक एसिड
16. अमोनियम क्लोराइड
17. सोडियम डिक्रोमेट
18. सिन्थेटिक क्रायोलाइट
19. अल्यूमिनियम फलोराइड
20. प्रशीतक गैसें
21. पोटाशियम क्लोरट
22. कैल्शियम कार्बोनेट
23. हाड्रोजन पेरोक्साइड
24. एस० टी० पी० पी० (सोडियम ट्रिपोलाय फोसफेट)
25. काप्रोलैक्टग
26. डी० एम० टी०
27. ऐनिलीन
28. मेथनोल
29. एल० डी० पोलिथिलीन
30. एच० डी० पोलिथिलीन
31. पी० वी० सी०
32. मेलिक ऐन हाइड्राइड
33. पोलिग्रोपिलीन
34. ऐथिलीन ग्लायकोल
35. ऐलक्लि डोडाक्लि बैंजीन
36. फ्थालिक ऐन्डिड्राइड
37. सेलामाइन
38. मेन्टाक्राइथ्रिटोल
39. अमोनियम नाइट्रेट
40. फोसफोरस पेटोक्साइड

इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के कीटनाशी औषधियों का आयात भी किया जा रहा है जिसमें कृमिनाशी रबर, पतवार नाशी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेन्टों आदि का आयात भी शामिल है।

(ख) जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, स्वदेशीय उपलब्धता आवश्यकता की अपेक्षा कम हो जाती है और जहां तक संभव होता है, इस अन्तर को कम करने के लिए आयात किया जाता है। विद्यमान एककों में देशज उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए निरन्तर

प्रयास किए जा रहे है और नए संयंत्रों को शीघ्र आरम्भ कराने के लिए भी निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य समस्त रसायनों के लिए भी, जिनका अब भी कमी की सीमा तक आयात किया जा रहा है और जिनका देश में निर्माण किया जा सकता है उनके लिए नए/विकसित उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए/जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे के वैगन-निरीक्षकों और स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल

3701. श्री नरेन्द्र सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्व रेलवे के वैगन-निरीक्षकों और स्टेशन-मास्टरों ने अभी हाल में हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पूर्वोत्तर रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के कतिपय खण्डों के गाड़ी परीक्षकों और दक्षिण पूर्व रेलवे के कतिपय खण्डों के केवल स्टेशन मास्टरों ने बेहत्तर वेतनमान और सेवा की बेहतर शर्तों की मांग को मनवाने के उद्देश्य के नियमानुसार काम आन्दोलन शुरू कर दिया था।

नंगल में गोविन्द सागर बांध में गाद-जमना

3702. श्री मोहिन्दर सिंह गिल: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल में गोविन्द सागर बांध में आयोजकों द्वारा निर्माण के समय अनुमानित गति से अधिक गति से गाद जमा हो रही है और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में विद्युत् सप्लाई तथा सिंचाई सुविधाओं में गम्भीर रुकावट उत्पन्न होने की गम्भीर आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जलाशय के प्रथम पांच वर्षों में किए गए पर्यवेक्षणों से पता चला है कि गाद भरने की गति परियोजना रिपोर्ट में प्रत्याशित दर से कुछ अधिक है। बहरहाल, परवर्ती वर्षों से संबंधित पर्यवेक्षणों से पता चलता है कि गाद भरने की दर में कमी आ गई है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए उससे पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य भागों के लिए सिंचाई और बिजली सुविधाओं के लिए कोई खतरा नहीं है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गाद कम करने के लिए भू-संरक्षण उपाय बाद्य क्षेत्र में शुरू किए जा चुके है।

Vending licences issued for stations in Bikaner, Jodhpur, Ferozepur, Lucknow and Allahabad divisions

3703. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the number of Railway Stations in Bikaner, Jodhpur, Ferozepur, Delhi, Lucknow and Allahabad Divisions where new vendor and rehrie licences for tea, betls, bidi, milk curd sweets, puri and roti and licences for refreshment rooms have been granted during 1973;

(*b*) the number of licences out of them given to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(*c*) the number of all types of licencees whose licencees have been cancelled in the said Divisions indicating the reasons therefor; and

(*d*) the number of licencees whose licences have expired and got renewed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) 48.

(*b*) 5.

(*c*) 31. The reasons for cancellation of the contracts are as under :

(*i*) In 10 cases licences were not renewed as a result of recent policy decision that contracts will not be renewed in respect of catering/vending contractors who have completed 6 years tenure in the case of Refreshment Rooms and vending and 10 years tenure in the case of Restaurants and Restaurant cars.

(*ii*) In 5 cases licences were cancelled due to death of contractors.

(*iii*) In 4 cases licences were cancelled on account of subletting of contracts.

(*iv*) In 5 cases contracts cancelled on account of unsatisfactory service.

(*v*) One contract cancelled due to conviction of the contractor.

(*vi*) One contract cancelled due to absence of the contractor for 7 months.

(*vii*) In 2 cases the contractors resigned and in 3 cases contractors left the contracts of their own accord.

(*d*) 114.

रामपुरा, दिल्ली को रेलवे हाल्ट बनाने का प्रस्ताव

3704. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि त्रिनगर, दिल्ली के निवासियों को वाहन उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली और नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों में पहुंचने में भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का रामपुरा, दिल्ली में शकूरबस्ती और दया बस्ती के बीच रेलवे हाल्ट बनाने का विचार है जिससे वहां के निवासी अपने कार्य के स्थानों पर समय पर पहुंच सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : दया बस्ती और शकूरबस्ती स्टेशनों के बीच रामपुरा में एक नया रेलवे स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी। स्टेशन नहीं खोला जा सका क्योंकि जिस खण्ड पर यह बनेगा उसका उपयोग चरमसीमा तक हो रहा है और इस स्थिति में एक स्टेशन का खोला जाना परिचालनिक

दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा नीति के अनुसार नये स्टेशन तब तक नहीं खोले जाते जब तक कि नये स्टेशन से दोनों ओर के निकटतम स्टेशनों की दूरी कम से कम 5 कि० मी० न हो। इस मामले में दोनों ओर के स्टेशनों की दूरी 2 कि० मी० और 2.4 कि० मी० थी। यह भी रिपोर्ट मिली है कि इस क्षेत्र में अच्छी सड़क सेवाएं उपलब्ध हैं।

कोचीन तथा मद्रास तेल शोधक कारखानों द्वारा ऊंची दरों पर अशोधित तेल की वसूली

3705. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन तथा मद्रास तेल शोधक कारखानों में मध्य पूर्व के स्वतंत्र खरीदारों द्ववारा दिये गये मूल्यों में ऊंची दरों पर अशोधित तेल लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या इन तेल शोधक कारखानों को उचित मूल्य पर अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): कोचीन और मद्रास में शोधनशालाए अपने प्रदायकों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार निर्धारित मुल्यों पर कच्चे तेल का आयात कर रही है।

(ग) अन्य बातों के साथ साथ इन शोधनशालाएं को उचित मूल्यों पर कच्चे तेल की सप्लाई दिलाने को ध्यान में रखकर तेल उत्पादक देशों के साथ विपक्षीय संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन

3706. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक-पृथक्करण की अवधि घटाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में विधेयक के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधुरी) : (क) और (ख) : हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1क) के अधीन, कोई पक्ष और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात् विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन कर सकता है, यदि पुनर्मिलाप बिना दो वर्ष की न्यूनतम अवधि बीत गई हो । दो वर्ष की उक्त अवधि में कमी करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

(ग) इन पर और हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए अन्य अभ्यावेदनों पर साथ-साथ विचार किया जा रहा है और इस संबंध में विनिश्चय किए जाने से पूर्व कुछ और समय लगेगा ।

नेपाल को डीजल की सप्लाई

3707. **श्री राम कंवर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार नेपाल को कुल कितने डीजल तेल का निर्यात करती रही है;

(ख) क्या तेल संकट के कारण नेपाल को डीजल तेल के निर्यात में कटौती किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) नेपाल को निर्यात किए गए डीजल तेल की मात्रा निम्नलिखित है:—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)
1970	20,039
1971 . .	22,705
1972 . .	23,195
1973 (जनवरी से जून)	14,979

(ख) और (ग) देश की आवश्यकताओं की तुलना में नेपाल को निर्यात महत्वपूर्ण नहीं है । वे निर्यात ऐतिहातिक और परम्परागत कारणों से किए जाते हैं । अत: पूर्ति के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में नेपाल को यथा सम्भव सहायता देने का प्रस्ताव है ।

Attempt made to Dynamite Railway Bridge on 15th December, 1973

3709. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) Whether an attempt was made to dynamite Railway bridge No. 12 between Lotaphar and Chakradharpur Stations on Howrah-Bombay main line on the 15th December, 1973;

(b) if so, the loss suffered by Railways ; and

(*c*) the steps taken by Government to protect vital installations from anti-social elements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) On 15-12-73 at about 00·10 hours an explosion took place at Bridge No. 256 between outer and home signals of Lotapahar Railway Station on the Howrah-Nagpur main line of South Eastern Railway.

(*b*) Negligible.

(*c*) Vital installations/vulnerable points have been placed in various categories according to their vulnerability and importance. Those considered important are guarded both during normal times and during emergencies. The rest are guarded only during emergencies. The responsibility of protecting Railway track and Bridges has been placed on the Police Force of the concerned States.

Cancellation of Trains in Samastipur Division (U.P.)

3710. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(*a*) whether many trains had to be cancelled due to shortage of coal in the Samastipur Division of Railways in Uttar Bihar uptil the 23rd **February, 1974;**

(*b*) if so, the factors responsible for shortage of coal; and

(*c*) the scheme being formulated to ensure regular coal supply in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) On an average 22 pairs of passenger trains remained suspended daily during the period 1-1-74 to 23-2-74 due to shortage of coal.

(*b*) From November 1973 ownwards there has been a spate of staff agitations on the Railways including of the Loco Maintenance Staff followed by the Locomen Strike, in December, 1973, and Carriage and Wagon staff agitation in February which seriously affected coal loading. In the immediate past there was a guards, agitation which particularly affected coal loading in the Bengal and Bihar and Central India Coalfields.

(*c*) Given normal conditions of working it will be possible to ensure regular supplied and build up coal stocks.

कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए रुस्तम क्रूड का उपयोग

3711. श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री सी० जनार्दनन } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुस्तम क्रूड का कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए उपयोग किये जाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण तथा अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) :— अशोधित तेल की कठिन सप्लाई स्थिति को दृष्टिगत करते हुए इस देश में तेल शोधक के लिए रुस्तम अशोधित तेल में भारतीय शेयर को उपयोग करने का निश्चय किया गया है। 1974 में अशोधित तेल में भारतीय शेयर लगभग 0.52 मिलियन मीटरी टन है। इस परिष्करणशाला की क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अन्य अशोधित तेलों के अतिरिक्त रुस्तम अशोधित तेल का शोधन किया जा रहा है।

भारतीय तेल निगम के कोयाली तेल शोधक कारखाने में बेंजीनटांल्युईन का उत्पादन बढ़ाना

3712. श्री अरविन्द एम० पटेला
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के टालवीन कोयाली तेल शोधक कारखाने में बैंजीनटांल्युईन के अधिकतम उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या इसके उत्पादन से तेल शोधक कारखाने की हानि पूरी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) कोयाली परिष्करणशाला में अब बैंजीन की प्रतिवर्ष 33000 मीटरी टन की अधिकल्पित क्षमता के स्थान पर अब 45000 मीटरी टन का तथा टोल्यून की प्रतिवर्ष 14,000 मीटरी टन की अभिकल्पित क्षमता के विरुद्ध अब 17,000 मीटरी टन का उत्पादन हो सकता है।

(ग) परिष्करणशाला पहले से ही लाभ अर्जित कर रही है। बैंजीन उत्पादन की वृद्धि से परिष्करण-शाला के लाभ में और अधिक सुधार होने की आशा की जाती है।

चौथी और पांचवीं पंचवषीय योजना में तेल शोधन क्षमता के लक्ष्य

3713. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तेल शोधक क्षमता का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य प्राप्त किया, और

(ग) क्या सरकार का पैराफिन वैक्स, स्नेहकों और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा करने का विचार है जिससे देश इन उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) अशोधित तेल के तेजी से बढ़ने वाले मूल्यों तथा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि से विदेशी मुद्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की जाने वाली अनुकूलतम परिष्करण क्षमता अभी भी विचाराधीन है।

(ख) चौथी योजना के अन्त तक 25.25 मिलियन मीटरी टन की आयोजित क्षमता की तुलना में योजना अवधि के अन्त तक सम्भाव्य क्षमता की उपलब्धता 24.05 विलियन मीटरी टन है। इसमें गैर सरकारी परिष्करणशालाओं से उपलब्ध फालतू क्षमता भी सम्मिलित है।

(ग) जी हां।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

3714. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के बारे में इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है और निकट भविष्य में अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है। तब तक इसका ब्यौरा देना जनहित में ठीक नहीं है।

मोदपुर और सिन्हान (पश्चिम रेलवे) के बीच माल डिब्बों का पटरी के उतर जाना

3715. **श्री राम प्रकाश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 फरवरी, 1974 को पश्चिम रेलवे पर मोदपुर और सिन्हान के बीच कुछ माल डिब्बे पटरी से उतर गये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार माल डिब्बों के पटरी से उतरने का कारण यांत्रिक उपस्कर की खराबी था।

कालटेक्स द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग

3716. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटेक्स ने अशोधित तेल के मूल्य में और वृद्धि करने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) (क) और (ख) : कालटेक्स ने उनके द्वारा आयातित लिये गये लाइट इरानियन अशोधित तेल के मूल्य में जनवरी 1974 से वृद्धि करने को कहा है जिसका वह प्रतिबैरल 8.48 डालर से 8.97 डालर प्रति बैरल मूल्य पर आयात कर रहे थे। 16-2-1974 से कालटेक्स ने लाइट अरोवियन अशोधित तेल का आयात करना आरम्भ कर दिया। अस्थायी रूप में कालटेक्स द्वारा मांगा गया लाइट अरोवियन अशोधित तेल का मूल्य प्रति बैरल 8.35 डालर है जब कि 1-1-1974 से एस्सो द्वारा उसी प्रकार के अशोधित तेल के प्रतिबैरल का अस्थायी मूल्य 8.32 अमरीकी डालर मांगा गया था इन वृद्धियों का स्पष्ट कारणों की जानकारी कालटेक्स द्वारा अभी तक नहीं आरम्भ की गई है और उनका पता लगाया जा रहा है।

बरवाडीह और चिरमिरी रेलवे लाइन का निर्माण

3717. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरवाडीह और चिरमिरी रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) बरवाडीह और चिरमिरी के बीच एक रेलवे लाइन के निर्माण का काम 1947 में शुरु किया गया था, लेकिन बाद में अद्योपाय की कठिन स्थिति के कारण तथा यह पता चलने के कारण कि इस लाइन पर प्रत्याशित यातायात नहीं मिल पायेगा, काम रोक दिया गया । फिर भी, इस क्षेत्र में कोयला-खानों के विकास के साथ-साथ, इस लाइन के निर्माण के बारे में पुनर्विचार किया जायेगा ।

डाल्टनगंज और दिल्ली के बीच देहरी अथवा चौपान से होकर सीधी गाड़ी

3718. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देहरी अथवा चोपान से होकर डाल्टनगंज और दिल्ली के बीच सीधी रेल गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख): रास्ते में लाइन क्षमता सीमित होने और दिल्ली/नयी दिल्ली में पर्याप्त टर्मिनल सुविधायों के अभाव में इस समय डेहरी-ओन-सोन अथवा चौपन के रास्ते डाल्टनगंज और दिल्ली के बीच एक सीधी गाड़ी चलानी परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

कानपुर रेलवे स्टेशन पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों की स्थिति के बारे में प्राप्त शिकायतें

3719. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1974 के दौरान मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों की स्थिति के बारे में विशेषकर हावड़ा-दिल्ली मेल (हावड़ा मेल 11 अप) के संदर्भ में, कानपुर रेलवे स्टेशन पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) क्या उक्त शिकायतों के प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही की गई थी; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उप-नगरीय 'सीजन टिकटों,' के कारण रेलवे को हानि

3720. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उप-नगरीय 'सीजन टिकटों' के कारण रेलवे को अब तक कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) उक्त हानि को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उपनगरीय सीजन टिकटों से 1970-71 में 13.31 करोड़ रुपये, 1971-72 में 13.94 करोड़ रुपये और 1972-73 में 15.99 करोड़ रुपये की आमदनी हुई । चूंकि इस यातायात पर होने वाले व्यय का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता, इसलिए हानि के आंकड़े नहीं बताये जा सकते । फिर भी उपनगरीय सेवाओं से कुल मिलाकर 1970-71 और 1971-72 में लगभग 12 करोड़ रुपये प्रति वर्ष और 1972-73 में लगभग 13 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ख) 1-4-1974 से उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्रा के यात्री किरायों को बढ़ाने का प्रस्ताव है लेकिन सीजन टिकटों के किराये में वृद्धि नहीं की जायेगी ।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट पर राज्यों से प्राप्त टिप्पणी

3721. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट पर सम्बद्ध राज्यों में से कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 24 दिसम्बर, 1973 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्हें अभिज्ञात तथ्य तथा उन पर उनके निर्णय दिए हुए हैं । अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार, यदि किसी राज्य सरकार का यह मत हो कि निर्णय में निहित किसी भी बात की व्याख्या करने की आवश्यकता है अथवा किसी ऐसे मद्द पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिससे मूलतः न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा गया था, ऐसी स्थिति में निर्णय तीन महीने के अन्दर वह मामला पुनः न्यायाधिकरण को विचार के लिए भेजा जा सकता है । ऐसा मामला प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण जैसा उचित समझे वैसा स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन देते हुए और रिपोर्ट दे सकता है और ऐसे मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय तदनुसार संशोधित माना जाए ।

भारत सरकार को किसी भी राज्य से अब तक ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है ।

गोदावरी जल विवाद के बारे में कृष्णा जल न्यायाधिकरण

3722. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्ण जल विवाद के मामले में जांच करने वाला न्यायाधिकरण ही गोदावरी जल वितरण के प्रश्न के बारे में भी जांच कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने सेवा निवृत्त हुए अथवा सेवा निवृत्त होने वाले न्यायाधीशों के स्थान पर वर्तमान न्यायाधीशों का न्यायाधिकरण गठित करने तथा उनके पंचाट प्रस्तुत करने तक कार्य करते रहने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ग) क्या अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम में इस उद्देश्य से समुचित संशोधन किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं। कृष्णा विवाद और गोदावरी विवाद के लिए अलग-अलग न्यायाधिकारण हैं। इन दोनों न्यायाधिकरणों को अप्रैल, 1969 में स्थापित किया गया था परन्तु चूंकि ये जल-विवाद आपस में जुड़े हुए थे और इन विवादों में कुछ पक्ष सांझे थे, इसलिए दोनों न्यायाधिकरणों की सदस्यता भी वही रखी गई थी।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण अपना निर्णय दे चुका है। गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के सम्मुख राज्यों के सभी पक्षों की सुनवाई पूर्ण हो गई है और गवाहों में बहुत से कागजात दाखिल कर दिए गए हैं; न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय जल-विवाद अधिनियम, 1956, जिसे 1968 में संसद् द्वारा संशोधित किया गया था, के उपबंधों के अनुसार, कृष्णा और गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया गया था जो मनोनीत करते समय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के जज थे। न्यायाधिकरणों को सदस्यता के लिए वर्तमान उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

रावी और व्यास नदियों के जल के बंटवारे के बारे में समाधान

3723. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिसम्बर, 1973 में अन्तर्राज्य जल विवादों के समाधान के लिये कोई कार्यवाही की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के बारे में कोई समुचित समाधान निकाला गाया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास के जल के बटवारे के प्रश्न को हल करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं : बहरहाल, इस मामले पर आगे विचार-विमर्श किया जाना है।

हिंगिर रेलवे स्टशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा चलाई गई गोली से हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने संबंधी समझौते को क्रियान्वित न करना

3724. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हिंगिर रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 26 फरवरी, 1973 को चलाई गई गोली से हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने संबंधी समझौते को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन और संबंधित यूनियन नेताओं के बीच इस विषय पर हुए विचार-विमर्श की कार्रवाई के फलस्वरूप उन लोगों को रेल मंत्री कल्याण एवं राहत निधि सेन निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है जो 26-2-1973 को हिंगिर रेलवे स्टेशन पर हुई गोलीकांड में मारे गये थे/घायल हुए थे।

दो कर्मचारियों को जो मारे गये थे	प्रत्येक को 2,500 रुपये
एक कर्मचारी को जिसके सिर में गंभीर चोट आयी थी	1,500 रुपये
एक कर्मचारी को जिसकी बायीं बांह कट गयी थी	500 रुपयें
पांच कर्मचारियों को जिनको मामूली चोटें आयी थीं	प्रत्येक को 300 रुपये

इन मामलों में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है। क्या संबन्धित कर्मचारियों को कोई अन्य क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

वाराणसी स्थित उत्तर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास तथा मकान किराया सहायता दिया जाना

3725. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी स्थित उत्तर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये अब तक न तो आवास की सुविधा प्रदान की गई है और न ही उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आवास-स्थान की उपलब्धता को देखते हुए जहां तक सम्भव है, अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास स्थान दिया गया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, उन्हें स्वीकार्य मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"टूथ पेस्ट एण्ड टेलकम पाउडर कालगेट कैरीज लूट" शीर्षक से समाचार

3726. **श्री शशि भूषण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री "मिलियन्स इन टूथ पेस्ट एण्ड टेलकम पाउडर कालगेट कैरीज लूट" शीर्षक से समाचार के बारे में 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में जांच करने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने में आगे कितना समय लगने की सम्भावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) मामले का विधि कार्य विभाग के परामर्श से परीक्षण किया गया है और आगे कार्यवाही विचाराधीन है ।

बड़ौदा के फ्रेंच वैल वाटर पम्पिंग सिस्टम के टूट जाने की जांच करने वाली समिति का प्रतिवेदन

3727. **श्री शशि भूषण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महीसागर नदी पर बड़ौदा के फ्रेंच वैल वाटर पम्पिग सिस्टम के सितम्बर, 1973 में दो करोड़ रुपये के इस्पात और सीमेंट कंकरीट के गर्डर के टूटने के बारे में जांच करने के लिये बनाई गई समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : गुजरात सरकार से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

विदेशी औषध फर्मों से लाभ संबंधी विवरणों का प्राप्त होना

3728. **श्री शशि भूषण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री विदेशी औषध फर्मों से लाभ सम्बन्धी विवरणों के प्राप्त होने के बारे में 20 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभ सम्बन्धी विवरण इस बीच प्राप्त हो गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) 25% से अधिक विदेशी इक्विटी शेयर वाली 23 फर्मों से प्राप्त सूचना का विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण पत्र में यह देखा गया है कि (प्रपुंज और सूत्रयोगों के सम्बन्ध में मैसर्स रोशे प्रोडक्ट्स लि० को छोड़ कर) कुल बिक्री पर लाभ की प्रतिशतता निर्धारित सीमा के अन्दर थी ।

वर्ष 1972/1972-73 में विदेशी कंपनियों की कुल बिक्री का लाभ दिखाने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विदेशी इक्विटी शेयर की प्रतिशतता	बिक्री के लाभ की कुल प्रतिशतता	
			प्रपुंज और सूत्रयोग	केवल सूत्रयोग
1.	मर्क शार्प दोहमे इण्डिया लि०	60	11.00	8.00
2.	जर्मन रेमेडीस लि०	64.19	हानि	11.08
3.	रूसल फार्मास्युटिकल (I) लि०	66-2/3	8.52	8.52
4.	सैण्डोज इण्डिया लि०	60	8.97	9.05
5.	रोशे प्रोडक्टस लि०	89	16.64	13.39
6.	स्मिथ एण्ड नेफ्यू (इण्डिया) लि०	59.6	हानि	हानि
7.	बोइईगर नाल लि०	60.6	0.21	0.46
8.	ऐग्लो फ्रैंच ड्रग कं० लि०	80	11.70	11.70
9.	जी० डब्ल्यू० कार्मिक कं० (इण्डिया) लि०	100	हानि	हानि
10.	ईथनोर लि०	75	शून्य	12.70
11.	जान्सन एण्ड जॉसन लि०	75	शून्य	1.80
12.	वेयर इण्डिया लि०	57.45	12.21	8.30
13.	ब्यूरोग्स वैल्कम एण्ड कंपनी लि०	100	5.34	5.65
14.	इण्डियम शोरिंग लि०	88.7	14.01	12.60
15.	सी० ई० फुलफोर्ड (इण्डिया) लि०	100	—	हानि
16.	निकोलस (इण्डिया) लि०	100	शून्य	13.60
17.	सीबा (इण्डिया) लि०	65	10.71	7.60
18.	गलेक्सो लैबोरेटरीज लि०	75	10.36	5.47
19.	जिआफरी मैनर्स एण्ड कं० लि०	45	14.17	10.75
20.	यू० एन० आई०—यूसीवी (प्रा०) लि०	40	9.50	9.00
21.	सुहृद गेगी लि०	47.5	10.07	7.43
22.	वार्नर हिन्दुस्तान लि०	50	—	14.60
23.	रेलिस इण्डिया लि०	26.29	—	4.50

आन्दोलनों के कारण जनवरी, 1971 से अब तक रेल विभाग को हानि

3729. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के आन्दोलनों के कारण जनवरी, 1971 के पश्चात् भारतीय रेलवे को (जोनवार) कितनी-कितनी हानि हुई?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जायेगी ।

Setting up of Fertilizer Factories in Rajasthan

3730. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether the Central Government propose to set up fertilizer factories in Chittorgarh and Sikar Districts of Rajasthan; and

(*b*) whether pyrite is available in abundances at both these places ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) *and* (*b*) : Some studies have already been made on the feasibility of setting up a fertilizer complex in Rajasthan based on the locally available pyrites and rock phosphate in the State and further studies are underway. A decision in the matter along with the location of the project can be taken only after adequate firm data become available on the economic availability and exploitation of the aforesaid deposits.

About Pyrites deposits in the Suladipura area, a feasibility report prepared by Messrs RTZ of U.K. has been received and is being appraised.

National Irrigation Policy

3731. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(*a*) whether any national irrigation policy has been formulated in the country or the various States of the country formulate their own policies;

(*b*) whether small farmers are not deriving the same benefits from irrigation facilities as the big farmers; and

(*c*) whether the reason for this is the defective system of distribution of water ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (*a*) Irrigation is a State subject and the State Governments formulate the irrigation policies taking into consideration the special conditions and other factors obtaining in their States.

(*b*) and (*c*) : The systems of water distribution prevalent do not discriminate against the small farmers.

Gambling in trains

3732. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether some people, mostly Railway employees, indulge in gambling in trains;

(*b*) whether gambling is mostly indulged into near the seats of attendants; and

(c) if so, whether Government propose to conduct an inquiry into the matter and take remedial steps ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No case of gambling, in trains, has come to notice.

(b) and (c) : In view of (a) above, question does not arise.

पांचवीं योजना में बिहार में बिजली की कमी

3733. **श्री मधु लिमये**
श्री जनन्नाथ मिश्र } : क्या **सिंचाई और विद्युत्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) क्या इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के व्यय की आवश्यकता है;

(ग) योजना आयोग ने कितनी धनराशि मंजूर की और बिहार सरकार ने कितनी धनराशि का प्रस्ताव रखा; और

(घ) बिहार राज्य को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री **सिद्धेश्वर प्रसाद**) : (क) से (घ). पांचवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में विद्युत् की कमी की आशंका नहीं है। पांचवीं योजना के प्रारूप में 995 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करना परिकल्पित है जो कि 606 मैगावाट वर्तमान क्षमता के साथ पांचवीं योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। वर्तमान यूनिटों से अधिकतम विद्युत् उत्पादन करने के लिए तथा निर्माणाधीन नई यूनिटों को चालू करने में तेजी लाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत् क्षेत्र के लिए 435.36 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्ष 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने की शर्तें

3734. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के अन्तिम दिनों में लोको कर्मचारियों की हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त हुई;

(ख) क्या श्रम मंत्री ने लोको कर्मचारियों के नेताओं को गुप्त रूप से वचन दिया है कि उनकी एसोसियेशन को वस्तुत: और कानूनी मान्यता दी दे जायेगी; और

(ग) 10 घंटे के कार्यदिवस सम्बन्धी करार को क्रियान्वित करने के लिये रेलवे द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) लोकों कर्मचारियों के नेताओं को श्रम-मंत्री द्वारा दिये गये ऐसे किसी गोपनीय वायदे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ग) 29 नवम्बर, 1973 को रेल मंत्री द्वारा संसद में की गयी घोषणा के अनुसार डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए 10 घंटे काम का कार्यान्वयन 1 दिसम्बर, 73 को प्रारम्भ हुआ था और आशा है कि जैसे ही आवश्यक व्यावहारिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी और कार्मिकों को प्रशिक्षित कर दिया जायेगा वैसे ही अन्य गाड़ियों पर भी तीन वर्षों के समय में यह काम उत्तरोत्तर पूरा हो जायेगा। अधिकांश डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों तथा 50 सवारी गाड़ियों में यह व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 22 खंडों पर चुनी हुई माल गाड़ियों को 10 घंटा काम के अंतर्गत लाया गया है। आशा है कि बाकी कुछ डाक/एक्सप्रेस यात्री गाड़ियां 31 मार्च, 74 तक तथा शेष सवारी गाड़ियां 30 नवम्बर, 74 तक इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगी।

दिसम्बर, 1973 में लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस लिये जाने के बाद उनकी जिन मांगों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया, उनका सारांश इस प्रकार है :—

(1) किसी को परेशान करने अथवा दण्ड देने की कार्रवाई नहीं की जायेगी— यह स्वीकार कर लिया गया है कि केवल ट्रेड यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों के कारण किसी को परेशान करने अथवा दण्ड देने की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(2) लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति (मुहम्मद शफी कुरेशी समिति) की तुरंत बैठक हो—तदनुसार एसोसिएशन की पूर्ववर्ती और वर्तमान शिकायतों पर विचार करने के लिए 28 दिसम्बर 73 को 11.00 बजे पूर्वाह्न एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने भी भाग लिया।

(3) सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया जाये और वारंट और सम्बन्धित मामले वापस ले लिये जायें—हिंसा और तोड़-फोड़ के मामलों को छोड़कर बाकी सब मामलों में इसे स्वीकार कर लिया गया है।

(4) 10 घंटा ड्यूटी को कार्यान्वित किया जाये—यह स्वीकार किया गया कि 10 घंटा ड्यूटी को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया पर 28 दिसम्बर, 1973 की बैठक में रेल मंत्री और श्रम मंत्री द्वारा आगे विचार किया जायेगा। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि ड्यूटी की अवधि को चरणबद्ध रूप में घटाकर 10 घंटे कर दिया जायेगा।

पहली जनवरी, 1974 से रेल किरायों में सामान्य वृद्धि

3735. **श्री मधु लिमये :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली जनवरी, 1974 से रेल किरायों में सामान्य वृद्धि की गई है ।

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न श्रेणी के यात्रियों का कितना-कितना किराया बढ़ा;

(ग) क्या महानगरीय क्षेत्रों के 'सीजन टिकट' बनवाने वालों को इस बृद्धि से छूट दी गई है; दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल दुर्घटनाओं में ग्रस्त यात्रियों के प्रति रेलवे का दायित्व बढ़ जाने के कारण 1-1-1974 से सामान्य यात्री किराये के अलावा एक अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है ।

(ख) प्रति यात्री अतिरिक्त प्रभार तीसरे दर्जे में 5 पैसे, दूसरे दर्जे या वातानुकूल चेयर कार में दस पैसे, पहले दर्जे में पचास पैसे और वातानुकूल दर्जे में एक रुपया है ।

(ग) जी नहीं । मासिक सीजन टिकटधारियों पर लगाया गया अतिरिक्त प्रभार दूसरे और तीसरे दर्जे के प्रति टिकट पर 25 पैसे और पहले दर्जे के टिकट पर 1 रु० 50 पैसे है ।

(घ) सीजन टिकट पर यात्रा करने वालों को भी बढ़ी हुई दर पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा ।

पेट्रोल पम्पों के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण

3736. **श्री मधु लिमये**
श्री वी०एस० मूर्ति } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब से मिट्टी के तेल का वितरण पैट्रोल और डीजल पम्पों के मालिकों द्वारा किया जायगा,

(ख) क्या इससे डीलरों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल में मिलावट बढ़ जायेगी,

(ग) क्या इस मिलावट का पम्पों/डीलरों से पैट्रोल प्राप्त करने वाली कारों और टैक्सियों के इंजनों की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और

(घ) यदि हां, तो मिलावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जहाँ पर एच० एस० डी० तथा मिट्टी के तेल के मूल्य एक जैसे हैं, तेल कम्पनियों को मिट्टी के तेल के वितरण कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ चुने हुए पैट्रोल पम्पों की मार्फत मिट्टी के तेल की फुटकर बिक्री करने का परामर्श दिया गया है ।

(ख) पैट्रोल की मिट्टी के तेल के साथ मिलावट किये जाने की संभावना सीमित है और इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) मिट्टी के तेल की मिलावट पैट्रोल इंजनों पर बुरा प्रभाव डालेगी अतः मोटर चालकों द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है।

(घ) इस प्रकार की मिलावट को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) राज्य सरकारों को पैट्रोल पम्पों से बेचे जाने वाले पैट्रोल के नमूने की समय-समय पर जांच सुनिश्चित करने तथा अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्य-वाही करने का परामर्श दिया गया है।

(2) मिट्टी के तेल की पैट्रोल के साथ मिलावट का पता लगाने के लिये सरल परीक्षणों का प्रचार किया जा रहा है।

(3) तेल कम्पनियों को इस प्रकार के परीक्षण करने और मिलावट संबंधी शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) भारतीय पेट्रोलियम संस्था के परामर्श से मिट्टी के तेल का नीला रंग किये जाने से संबंधित योजना विचाराधीन है। इससे इस प्रकार की किसी मिलावट का दृष्टि से पता लगाना सुनिश्चित हो जायेगा।

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में राजस्थान नहर

3737. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के परियोजना अनुमानों में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उसके पास संसाधनों को कमी के कारण केन्द्रीय सरकार से राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में आरंभ किये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

सिंचाई और विद्युत्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्देश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान नहर की लागत जैसा कि 1970 में अनुमान लगाया गया था, 208 करोड़ रुपये थी। कीमतों के बढ़ने के कारण इसके अब और बढ़ जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान नहर समेत बृहत् सिंचाई परियोजनाओं को लेने के प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 1964 में विचार किया गया था और सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया था ये परियोजनाएं राज्य योजना के एक भाग के रूप में ही रहे। बहरहाल, परियोजना के महत्व को ध्यान में रखकर केन्द्र ने योजना परिव्ययों के अतिरिक्त, 15.17 करोड़ रुपयों को अब तक योजनेतर सहायता दी है।

कैडबरी फ्राई (इंडिया)

3738. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैण्ड की कैडबरी श्वैपैस लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कैडबरी फ्राई (इण्डिया) का मुख्य व्यापार क्या है ;

(ख) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में इस कम्पनी के कुल व्यापार, परिसम्पतियों तथा लाभ का मूल्य कितना रहा ;

(ग) इसका वर्तमान पूंजी-निवेश कितना है ;

(घ) 1970-71 तथा 1971-72 में इस कम्पनी ने कुल कितनी राशियों का प्रत्यावर्तन किया;

(ङ) क्या इस कम्पनी के विरुद्ध एकाधिकारिक तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं सम्बन्धी आरोपों की जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) कैडबरी स्विप्स लिमिटेड, यू०के० की पूर्ण रूप से स्वामित्वी सहायक, मैसर्स कैडवरी, फ्राई (इण्डिया) लिमिटेड, माल्टीकृत खाद्य, कोका उत्पाद पीने योग्य चाकलेट और चाकलेट मिठाई के उत्पादन के व्यापार में ग्रस्त है ।

(ख) 1 जनवरी, 1972 से 30 दिसम्बर, 1972 की वर्ष समाप्ति हेतु कम्पनी का कुल आवर्त्त, परिसम्पत्ति और लाभ निम्न प्रकार है :—

	कुल आवर्त रु०	परिसम्पत्ति	कर के पश्चात् विकास छूट लाभ रु०
1-1-72	6,96,03992	41661849	2379,651
30-12-72	7,77,90472	49463468	2593412

(ग) 100 रु० प्रत्येक के साम्य 12961 साम्य शेयरों सहित कम्पनी की वर्तमान प्रदत्त पूंजी 12,36,100 रु० है ।

(घ) कम्पनी द्वारा 1971 और 1972 के मध्य अपने समस्त लेखाओं पर कुल प्रेषण के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) तथा (च) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 44 के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यों की जांच का आदेश दिया गया था और अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो सरकार की परीक्षा के अन्तर्गत है ।

बिजली-सप्लाई की दरों में समानता

3739. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली सप्लाई की दरें समान बनाने में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उद्योगपतियों की अपेक्षा किसानों को सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) प्राय: सभी राज्यों में राज्य के प्रत्येक उपभोक्ताओं को प्रत्येक श्रेणी के लिए पहले से ही समान बिजली दरें हैं। बहरहाल, बिजली-उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की लागत में विविधता होने के कारण बिजली की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं। बृहत् क्षेत्रीय विद्युत् केन्द्रों से प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक समान दर संभव हो जाएंगी।

(ख) कृषकों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत् उद्योगपतियों को दी जाने वाली बिजली की अपेक्षा अधिक महंगी होती है। क्योंकि कृषि संबंधी भार मात्रा में कम होता है और इसके मौसमी किस्म के होने के कारण इसमें कम भार अनुपात पर सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, वे आमतौर से बिखरे हुए हैं और विद्युत् स्रोत से बहुत दूर स्थित होते हैं। ये तथ्य प्रचालन दक्षता को कम करते हैं और सप्लाई की लागत को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। इन प्रतिकूल तथ्यों के बावजूद कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों को अधिकतर राज्यों में लघु उद्योग उपभोक्ताओं की अपेक्षा प्राय: कम रखा गया है।

जीवन रक्षक औषधियों में आत्म निर्भरता

3740. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में जीवन रक्षक औषधियों के मामले में आत्म निर्भरता की स्थिति आ जाएगी, यदि नहीं, तो क्यों, और

(ख) देश में और अधिक औषधी निर्माण कारखाने लगाने के लिये आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) देश में प्रपुंज औषधी के वर्तमान वार्षिक देशीय उत्पादन का मूल्य 50 करोड़ रुपया है जिसमें पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक 200 करोड़ रुपये तक वद्धि करने का विचार है। सरकारी क्षेत्र में नये औषध एककों की स्थापना करने वर्तमान एककों का विस्तार करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने औषध उद्योग के संगठनों के साथ विचार विमर्श किये हैं जिससे गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों सहित आगे कदम उठायें।

Use of Steam Engines for Running Trains due to Shortage of Diesel Oil

3741. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether the Government have made arrangements to use steam engines for the running of trains due to shortage of diesel oil;

(*b*) if so, the names of the trains in which this arrangement has been made; and

(*c*) whether Government propose to resume the train services which are suspended at present by using steam engines?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*), (*b*) and (*c*) : No diesel hauled trains were suspended due to shortage of diesel oil. Therefore, the question of resumption of train services suspended due to shortage of diesel oil does not arise.

वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोगों के पास मामले ।

3742. **श्री रानेन सेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग ने कितने मामलों पर विचार किया और उनमें से कितने निपटाये गये : और

(ख) सरकार द्वारा उसे भेजे गये मामलों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) 1 जून, 1970 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि हेतु सूचना पहिले ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई आयोग की दो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों में सम्मिलित है । 1 जनवरी, 1973 से 15 मार्च 1974 तक की अवधि हेतु सूचना निम्न प्रकार है :—

धारा 21	1-1-73 से पूर्व 31 माह की अवधि में 21 के विरुद्ध 16 मामले
धारा 22	पूर्व अवधि में 5 के विरुद्ध 5 मामले ।
धारा 23	पूर्व अवधि में 6 के विरुद्ध 1 मामला
धारा 10	पूर्व अवधि में शून्य के विरुद्ध 45 मामले ।

आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है । 1-1-73 से 15-3-74 की अवधि में निपटाये गये मामलों की संख्या (उपक्रमों द्वारा वापिस लिये गये मामलों सहित) निम्न प्रकार है :—

धारा 21	10
धारा 22	5
धारा 23	3
धारा 10	2

(ख) उत्पादन नहीं होता ।

मैसर्ज मे एण्ड बैंकर से अपनी विदेशी ईक्विटी पूंजी कम करने का प्रस्ताव

3743. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मे एण्ड बैंकर में अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी कम करने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो कब और उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ख) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार उस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): मैसर्स मे एण्ड बैंकर लि० ने पहले एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें कम्पनी का भारतीय कम्पनी के रूप में परिवर्तन, 10 प्रतिशत की सीमा तक भारतीय पूंजी को सम्बद्ध करना; 15 वर्ष के लिए कुल बिक्री पर 7-1/2 प्रतिशत की रायल्टी का भुगतान आदि सम्मिलित है। उन्होंने 1973 में संशोधित प्रस्ताव पेश किये। संशोधित प्रस्तावों में, प्रपुंज औषधों एवं मध्यवर्ती पदार्थों, अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना एवं विदेशी साम्यपूंजी में 75 प्रतिशत की कमी सम्मिलित है।

ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा शीघ्र ही एक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

औषधी फर्मों को 'प्राडक्ट-मिक्स' की अनुमति

3744. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधी फर्मों को 'प्राडक्ट-मिक्स' की अनुमति देने संबंधी हिदायतें दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस अनुमति से प्रत्येक फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा का उपयोग बढ़ जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): अनेक औषध उत्पादक फर्में बहुत से औषध उत्पादों का निर्माण करती हैं। इस सम्बन्ध में स्वीकृतियां समय समय पर प्रभावी औद्योगिक लाइसेंसिग नीति की शर्तों के अन्तर्गत दी जाती हैं।

(ग) अपूर्ण आधार पर तकनीकी अधिकारियों तथा आयात नियंत्रण अधिकारियों द्वारा औषध उत्पादकों को कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दी गई है तथा विदेशी मुद्रा का बाहर जाना सम्बन्धित एककों के उत्पादन से सीधे सम्बन्धित है जिसमें आयातित कच्चा माल लगता है ।

औषधी फर्मों को कच्चे माल के आयात की अनुमति

3745. **श्री भालजी भाई परमार**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधी फर्मों को अनुमति/अनापति पत्रों में उल्लिखित औषधियों के लिये कच्चे माल के प्रत्यक्ष और परोक्ष आयात की अनुमति दी गई है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं। और

(ग) क्या अनुमति पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस माना गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) और (ख) : उपक्रमों को आयात व्यापार निमन्त्रण नीति के अनुसार कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दी

गई है। अनमति पत्रों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा कुछ सूत्रयोगों का निर्माण करने की स्वीकृति का उल्लेख है।

पश्चिम बंगाल को सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता

3746. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या सिंचाई और विद्युत्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, परियोजनावार पश्चिम बंगाल राज्य को सिंचाई के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत्त मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : चौथी योजना में राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समग्र रूप में दी जा रही है और यह किसी विशेष परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत प्रजनन

3747. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या सिंचाई और विद्युत्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से राज्य में अधिक विद्युत प्रजनन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के लिए निम्नलिखित विद्युत् उत्पादन स्कीमें स्वीकृत हुई हैं :—

स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1. बन्देल ताप केन्द्र विस्तार (1×200 मेगावाट)	200
2. कोलाघाट ताप-विद्युत् केन्द्र (3×200 मेगावाट)	600
3. जलढाका जल-विद्युत् स्कीम चरण-दो (2×4 मेगावाट)	8
4. रिन्चिगटन जल-विद्युत् स्कीम चरण-दो (2×1 मेगावाट)	2

संथाल डोह ताप-विद्युत् केन्द्र विस्तार (1×200 मेगावाट) दुर्गापुर कोक ओवन ताप केन्द्र विस्तार (1×200 मेगावाट) और दुर्गादुर परियोजना लिमिटेड विस्तार (1×110 मेगावाट) के लिए परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में तेल के लिए छिद्रण स्थान

3746. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में तेल के लिए छिद्रण हेतु कितने स्थानों पर समय-समय पर विचार किया गया,

(ख) क्या इन स्थानों पर छिद्रण का काम आरम्भ किया गया है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या करण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल तथा गैस के लिए अन्वेषण कुओं के व्यधन के विचार किए गए स्थान निम्नलिखित हैं :—

1. वक्कुलतला क्षेत्र, 24 परगना जिला

2. चेतन्यपुर क्षेत्र, मिदनापुर जिला

3. वोदरा क्षेत्र, 24 परगना जिला

5. गलसी क्षेत्र, वरदवान जिला ।

(ख) और (ग) कुछ क्षेत्रों में व्यधन के लिए प्रारंभिक कार्य हाथ में है । कुछ क्षेत्रों में और भूकम्नीय सर्वेक्षण कार्य की भी आवश्यकता है । अत: इन क्षेत्रों में अभी तक व्यधन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

औषधि फर्मों द्वारा रक्षित खपत के लिए औषधि निर्माण

3749. **श्री के० एस० चावड़ा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधी निर्माता फर्में कुछ 'बल्कि' औषधियां बना कर, उनका उपयोग केवल रक्षित खपत के लिए कर रही हैं और औषधियां बनाने वाले असम्बद्ध लोगों को उनकी सप्लाई नहीं कर रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को औषधी (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उन फर्मों को 'बल्कि' औषधियों का कुछ प्रतिशत भाग उक्त असम्बद्ध निर्माताओं की सप्लाई करने पर बाध्य करने की वांछनीय पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) यह सम्भव है कि प्रपुंज औषधों को उत्पादन करने वाली फर्में अपने प्रपुंज औषध उत्पादन को सम्पूर्ण रूप में कैप्टिव खपत के लिए उपयोग करते हों ।

(ख) प्राय: अब औद्योगिक लाइसेसों पर शर्तें लागू की जा रही हैं जिससे असम्बद्ध उत्पादकों को प्रपुंज औषध उत्पादन की निर्धारित प्रतिशत उपलब्ध की जा सके । तथापि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यवस्था में इस बात की आवश्यकता है कि इसके अधीन जारी किये जाने वाले आदेशों में उन निर्माताओं का उल्लेख होगा जिनको प्रपुंज औषधों का कोई भी निर्माता विशिष्ट प्रपुंज औषध बेच सके ।

औषधि निर्माता फर्मों के निर्यात व्यापार का अध्ययन

3750. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधी निर्माता फर्मों द्वारा विशेषकर 26 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी पूंजी वाली फर्मों द्वारा किये गये निर्यात व्यापार का कोई गहन अध्ययन किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसे अध्ययन करने की व्यवस्था करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किये गये निर्यात देश के सर्वाधिक हित में हैं या नहीं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) 26 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषध फर्मों द्वारा किये गये निर्यात् व्यौरों को अध्ययन हेतु एकत्र किया जा रहा है ।

दक्षिण रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों का स्थायी रूप से खपाया जाना

ज3751. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे तथा अन्य रेलवेज में तीन वर्ष से अधिक अवधि से काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक स्थायी रूप से नहीं खपाया गया है; और

(ख) उन्हें स्थायी रूप से कब तक खपाने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सभी रेलों में दैनिक मजदूरी और केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों पर नियुक्त कर्मचारियों की सख्या लगभग 39,000 है । दक्षिण रेलवे पर इनकी संख्या 8,000 है ।

(ख) जांच समितियों द्वारा जो नैमित्तिक श्रमिक उपयुक्त पाये जाते हैं, उन्हें नियमित पदों पर लगाने के बारे में जैसे-जैसे रिक्तियां होती हैं, पहले से ही विचार किया जा रहा है, लेकिन नियमित पदों पर उन्हें खपाने सम्भावनाएं सीमित होती हैं ।

Production of Oil in Gujarat at Commercial Level

3752. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(*a*) whether production of oil at commercial level has been started immediately in about 100 new oil wells in Gujarat in which prduction was so far beirg made only on experiment basis;

(*b*) if so, the quantity of oil being produced on experiment basis and the quantity of oil likely to be produced now; and

(*c*) the steps staken to boost up production and to develop the wells ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (*a*) and (*b*) : Of the about 100 new oil wells in North Gujarat fields about 25 wells are at present under trial production, giving a yield of about 350 tonnes of crude oil per day. The ONGC have drawn up a plan to put the remaining wells in this area on full production during the year 1974-75. During 1974-75 the production from the new wells is expected to yield an additional 1000-1200 tonnes per day.

(*c*) : The steps being taken to boost up production and to develop the new wells include implementation of a scheme known as 'Operation SOKOIL' which involves laying of a 57 km. pipeline, construction of a group gathering station etc. Besides this other steps being taken to boost up production are construction of isolated well-head installations, installation of Sucker Rod Pumps for artificial oil lifting and expansion of the existing installations and construction of new production installations etc.

औषधी निर्माता फर्मों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय को मासिक विवरणियां भेजना

3753. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : **क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि निर्माता फर्मों द्वारा तकनीकी विकास महानिर्देशालय को भेजी जाने वाली मासिक उत्पादन-विवरणियां केवल सांख्यकीय महत्व रखती हैं,

(ख) क्या उसमें प्रत्येक औषधी का नाम तथा मात्रा दी जाती है;

(ग) सरकार को यह कैसे पता चलाया है कि इनमें कोई नया उत्पाद शामिल किया गया है या नहीं, और

(घ) इन विवरणियों का सत्यापन करने के लिए सरकार क्या उपाय करती है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) से (घ) : सांख्यिकीय महत्व के लिये उनके प्रयोग के अतिरिक्त तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों पर लाए हुए औषध एककों द्वारा प्रस्तुत किए हुए उत्पादन के मासिक विवरणियां जांच के प्रयोग के लिए भी हैं :—

(i) संबंधित एककों के निष्पादन की तुलना में लाइसेंस युक्त क्षमता ;

(ii) क्षमता के प्रभावी उपयोग में बाधाएं और समस्याएं;

(iii) रिपोर्ट के समय कम्पनी के तैयार माल के स्टाक के आर्डर बुक करना,

(iv) रोजगार स्थिति और

(v) अत्यधिक उपयोग मूल विषयों के उत्पादन और नाम उत्पादन विवरणियों में प्रतिबिम्बित हैं ।

उत्पादन विवरणियों की तकनीकी विकास महानिदेशालय में विकास अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और ये तदनतर कच्चे माल आदि के लिए दिए जाने वाले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आवेदन-पत्र से संबद्ध किए जाते हैं जो इस स्तर पर सनदीलेखाकार द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। इस कार्यवाही में एककों द्वारा प्रस्तुत किए हुए मासिक विवरणों को भी ध्यान में रखा जाता है और अधिप्रमाणिकता की जाँच की जाती है ।

जहां प्रवत्तियों में अत्याधिक उपयोग दिखाया है, जहां कहीं अनिवार्य हुआ, तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा निरीक्षण दौरे आयोजित किए जाते हैं। सम्मिलित संस्था के विचार में मिश्रित प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर आवधिक आधार पर केवल चुनीदा जांच की जाती है ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औषधी फर्मों के अनुमति-पत्र जारी करना

3754. **श्री सोम चन्द सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार जिन औषधियों के लिए अनुमित/अनापति पत्र जारी किए जाते हैं उनमें "नई औषधी" की क्या परिभाषा है ;

(ख) क्या किसी नये उत्पाद के निर्माणार्थ औद्योगिक लाईसेंस/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण या विधिकरण के अन्तर्गत निर्माण के लिए अनुमति अपेक्षित है,

(ग) क्या औषधी निर्माता फर्मों के सम्बन्ध में कोई अपवाद किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के खण्ड 3 के उपखण्ड (डी०डी) को व्यवस्थाओं के अनुसार नये वस्तुओं, (न्यू आर्टिकल्स), जो औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में पंजीकृत हैं अथवा जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा अमुमति-पत्र दिए गए हैं, का अर्थ है :—

(i) उन मदों के अलावा जिनके अन्तर्गत साधारणतया वस्तुओं का निर्माण किया जाए या उस तिथि को जब पंजीकरण हो जाए या लाइसेंस जारी किए जाएं या स्वीकृति दी जाए, जिस तरह का भी मामला हो, के अतिरिक्त कोई भी वस्तु जो अधिनियम के पहले अनुसूची में आए।

(ii) कोई भी वस्तु जो ट्रेड एण्ड मरचन्डाइज मार्क्स एक्ट 1958 में अंकित हो या जो किसी भी पैटन्ट के अन्तर्गत आतीं हों यदि लाइसेंस अथवा अनुमति-पत्र को जारी किए जाने की पंजीकरण तिथि को, जैसा भी मामला हो, औद्योगिक उपक्रम ऐसे वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रही थी जिस पर ऐसा मार्क था अथवा जो उस पेटैन्ट के अन्तर्गत आती हो ।

(ख) से (घ) तक : उन वस्तुओं जो अधिसूचना सं० एस० ओ० 98 (ई०)/आई० डी० आर० ए०/29-बी०/73/1 दिनांक 16 फरवरी 1973 (जिसकी प्रति लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है) के अन्तर्गत आती हैं, जो कुछ शर्तों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस को प्राप्त करने की छूट देते हैं, के अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रमों को नई वस्तुओं के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना होता है।

विधान सभा और लोक सभा के उप-निर्वाचन

3755. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में होने वाले विधान सभा और लोक सभा के उप-निर्वाचनों की 1 मार्च 1974 तक संख्या कितनी थी ;

(ख) ये स्थान किन किन तारीखों को रिक्त हुए थे और इसके कारण क्या थे;

(ग) जो स्थान 6 महीने से अधिक समय से रिक्त पड़े हैं और जिनके लिए उप-निर्वाचन होने थे, उनको कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) ये उप-निर्वाचन किन तारीखों को करवाए जाएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6478/74]।

वर्ष 1973 में आरक्षित अथवा अनारक्षित किए जाने वाले विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्र

3756. **श्री नारायन चन्द पाराशर:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश में परिसीमन के परिणामस्वरूप आरक्षित किए गए विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों और उनके जिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) विधान सभा के लिए उन निर्वाचन क्षेत्रों और उनके जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें इस परिसीमन के परिणामस्वरूप अनारक्षित घोषित कर दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख): अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 6479/74]।

उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में विरोधी दलों द्वारा कांग्रेस की निर्वाचन सभाओं में विघ्न डालने का आरोप लगाने वाली शिकायतें

3757. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली हैं कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस की निर्वाचन सभाओं में सी० पी० आई० (एम०), जनसंघ, भाक्रांद और कांग्रेस (संगठन) जैसे दलों के समर्थकों और सदस्यों ने विघ्न डाले हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें राज्यवार प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है और आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह):

(क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश————4।

उड़ीसा————1।

(ग) और (घ) : उत्तर प्रदेश राज्य से तीन शिकायतों की प्रतियां संबंधित राज्य प्राधिकारियों को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई थीं। शेष शिकायत के बारे में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने साधारण निर्वाचन से पूर्व निर्बाध और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए विधि और व्यवस्था का बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु राज्य का विस्तृत दौरा किया था और आयुक्तों, कलक्टरों और ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था। उड़ीसा राज्य से प्राप्त शिकायत, उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को इन अनुदेशों के साथ कार्यवाही के लिए भेज दी गई थी कि निर्वाचन आयोग को इसके बारे में वापस रिपोर्ट की जाए। उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

उर्वरकों की विश्वव्यापी भारी कमी की आशंका

3758. **श्री नवल कशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगले वर्ष उर्वरकों की विश्व-व्यापी भारी कमी की आशंका के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संकट को देखते हुए और देश की उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, और

(ग) क्या सरकार देश की उर्वरकों की मांग पूरी करने के लिए परम्परागत खादों को लोकप्रिय बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

बदरपुर तापीय बिजलीघर में एक जेनेटर चालू करना

3759. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजलीघर में आगामी जुलाई में चालू होने वाले 100 मैगावाट के जेनेरेटर के चालू होने में विलम्ब होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) इसे निर्धारित समय पर चालू करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

काठघर की रेल दुर्घटना के 20 मृतकों का बिना शिनाख्त दाह संस्कार

3760. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री निहार लास्कर } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी 1974 की काठघर रेल दुर्घटना के 20 मृतकों की शिनाखत नहीं हो सकी ;

(ख) क्या उनका बिना-शिनाखत ही दाह संस्कार कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी उनकी संख्या 21 थी न कि 20।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि गंभीर चोटों के कारण मृत व्याक्तियों के चेहरे इतने विकृत हो गए थे कि वे पहचाने नहीं जा सके और किसी ने उनके शवों का दावा नहीं किया। इसलिए उनका अन्तिम संस्कार कर दिया गया । बाद में मृतकों के शरीर पर पाए गए सामानों और कपड़ों से 6 मृतक–5 पुरुष और 1 स्त्री की शिनाखत की जा सकी।

अंकलेश्वर और दूसरे तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन में कमी

3761. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री निहार लास्कर } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात में अंकलेश्वर में, जहां अब तक 30 लाख टन से अधिक तेल का उत्पादन हो रहा है, विकास की चरम सीमा आने वाली है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष वहां से तेल कम मात्रा में प्राप्त होने लगा है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : प्रत्येक तेल क्षेत्र की प्रारंम्भिक अवस्था में उत्पादन में वृद्धि दूसरी में उत्पादन में चरम सीमा पर और तीसरे में उत्पादन में कमी होती है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र काफी समय तक उत्पादन की चरम सीमा पर रहा है और हाल ही में उसके उत्पादन में कमी आने लगी है।

कोयली तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाना

3762. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुजरात कोयली तेलशोधक कारखाने की देश में पेट्रोलियम गैस की उत्पादन क्षमता बढ़ायी जा रही है यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) जी हां,। एल० पी० जी० के प्रति वर्ष 10,000 मीटरी टन की रुपांकित क्षमता की तुलना में कोयली परिष्करण-शाला का वर्तमान उत्पादन स्तर 65,000 मीटरी टन प्रति वर्ष 90,000 मीटरी टन तक और वृद्धि होने की आशा है।

तीसरे वायुमण्डलीय एकक (एटोमोस्फारिक यूनिट) तथा कैलिटिक रिफार्मिक एकक गैसों में एल० पी० जी० के उत्पादन (जिसकी परिकल्पना डिजाइन में नहीं की गयी है), भंडारण तथा सिलेंडर भरने की सुविधाओं में वृद्धि तथा टैंक वैगनों में एल० पी० जी० के प्रचुर मात्रा में परिवाहन सुविधाओं की व्यवस्था करके एल० पी० जी० के उत्पादन में वृद्धि की गयी है।

केरल में बिना चौकीदार वाले रेल-फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना

3763. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितने रेल फाटकों पर चौकीदार नहीं हैं: और

(ख) वहां कब तक चौकीदार नियुक्त कर दिये जायेंगे?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) दो सौ सत्रह।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने का काम राज्य सरकार सड़क प्राधिकारी के परामर्श से प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार रखने की कोई पक्की तारीख नहीं बतायी जा सकती।

मालाबार एक्सप्रैस के परापननगडी रुकने सम्बन्धी मांग

3764. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालबार एक्सप्रैस के परापननगडी रूकने के बारे में वहां की जनता की मांग के बारे में पता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) परापननगडी स्टेशन पर 29/30 मालबार एक्सप्रैस गाड़ी के ठहराए जाने का न तो यातायात की दृष्टि के कोई औचित्य है और न ही ऐसा करना भीड़-भाड़ वाली इन गाड़ियों को तेज रफ्तार वाली गाड़ियों बनाए रखने के हित में वांछनीय ही है।

केरल में घाटे पर चल रही रेलगाड़ियां

3765. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कौन-कौन सी रेल गाड़ियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या केरल के लिए अधिक रेल गाड़ियों की व्यवस्था करके घाटे को समाप्त करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन करने के लिए कम से कम सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों पर घाटे के बारे में सूचना राज्यवार नहीं, बल्कि रेलवे वार संकलित की जानी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

1/2 मंगलौर-मद्रास मेल गाड़ियों का डीज़लीकरण

3766. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1/2 मंगलौर-मद्रास मेल गाड़ियों का डीज़लीकरण करने का विचार है और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख): डीज़ल रेल इंजन मुख्यतः अनिवार्य माल यातायात की निकासी के लिए आपेक्षित हैं : अतः इनकी कुल उपलब्धता को देखते हुए एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर सवारी गाड़ियों का डीज़लीकरण किया जा रहा है। इस समय डीज़ल रेल की कमी के कारण सवारी गाड़ियों के डीज़लीकरण की गति धीमी कर दी गयी है। स्थिति में सुधार होते ही इस तरह की अन्य मांगों के साथ-साथ 1/2 मद्रास-मेंगलूर मेल गाड़ियों के डीज़लीकरण के संबंध में भी विचार किया जायेगा।

केरल में वैगन उपलब्ध न किए जाने के कारण उद्योगों को हुई हानि

3767. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्याप्त संख्या में रेलवे वैगन उपलब्ध न किये जाने के कारण केरल प्रदेश प्रदेश के उद्योगों को बहुत नुकसान पहुंचा है; और

(ख) वैगनों की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) केरल के विभिन्न उद्योगों की माल डिब्बों के संबंधित मांग अधिकाधिक पूरी की गयी है। लोको कर्मचारियों की हड़ताल कर्मचारियों और जनता द्वारा किये गये आन्दोलन, नागरिक उपद्रवों आदि के कारण जब कभी माल डिब्बों के अन्तर्रेलवे संचालन की विनियमित करना पड़ा तो उस समय कभी-कभार माल डिब्बों की सप्लाई में देरी हुयी।

(ख) ब्लाक स्पेशल गाड़ियों के रूप में माल डिब्बों की सप्लाई करने के लिये एक विशेष प्रबंध किये गये हैं।

डीजलीकरण के कारण रेलवे की संचालन कार्यकुशलता

3768. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजलीकरण के बाद से रेलवे को संचालन कार्यकुशलता बढ़ रही है?

(ख) यदि हां, तो क्या संचालन कार्य-कुशलता बढ़ जाने के कारण यात्रियों को कम किराए और माल-भाड़े तथा अधिक सुविधाओं के रूप में कोई लाभ पहुंच सका है?

(ग) क्या रेलवे डीजलीकरण से लागत लाभ संबंधी कोई विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) रेलों की समग्र परिचालन कुशलता आंकने का कोई एकमात्र सूचक नहीं है। लेकिन जब से डीजल और बिजली रेल इंजन जैसे कर्षण के आधुनिक साधनों का उपयोग होने लगा है तब से इंजन के उपयोग के विभिन्न सूचकांकों अर्थात लाइन पर प्रति इंजन दिन किलोमीटर गाड़ियों के भार उपयोग में लाइन पर प्रति मालगाडी इंजन दिन शुद्ध मीटरिक टन किलोमीटर और प्रति इंजन घंटा शुद्ध-मीटरिक टन-किलोमीटरों में काफी सुधार हुआ है।

(ख) डीज़ल कर्षण सहित आधुनिक कर्षण के फलस्वरूप उन्नत परिचालन कुशलता के जो लाभ प्राप्त हुए हैं उनके चलते ही रेलों के लिए निवेष की तेजी से बढ़ती हुयी लागत अर्थात कर्मचारियों की लागत और भण्डार तथा समान जिसमें ईंधन भी शामिल है, की लागत का प्रभाव बहुत हद तक सहन करना संभव हो सका है और किराये तथा भाड़े की दरों में केवल न्यूनतम वृद्धि की गयी है। इससे रेल उपयोगकर्ताओं को भी लाभ हुआ है। जहां तक यात्रियों के लिये सुविधाओं का प्रश्न है डीज़ल कर्षित सवारी गाड़ियों की औसत गति उनमें लगाये जाने वाले डिब्बों की संख्या में वृद्धि हुई है इससे अधिक स्थान की व्यवस्था हो गयी और यात्रा के दौरान सफाई के साथ-साथ यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विद्यमान मीटर लाइनों को बड़ी और दोहरी लाइनों में बदलना

3769. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह सिन्हा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश में नयी रेलवे लाइनें बिछाने अथवा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने अथवा विद्यमान लाइनों को दोहरी बनाने का काम आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबंध में क्या संभाव्यता अध्ययन किया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, जैसा नीचे बताया गया है;

(1) बाराबंकी से समस्तीपुर तक मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन

(2) जहां पहले शहादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे चलती थी, उस क्षेत्र में बड़ी लाइन का निर्माण।

(3) छितौनी से वगहा तक उखाड़ी गयी मीटरी लाइन को फिर से बिछाना

(4) डलमऊ से दरियापुर तक उखाड़ी गयी लाइन को फिर से बिछाना।

(5) मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़े आमान की रेलवे लाइन का निर्माण।

(6) निम्नलिखित खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाना :—

(i) करोंदा-धौरा

(ii) बयाना-मथुरा

(iii) माताटीला-बसई

(iv) गाजियाबाद-मुरादनगर

(v) मेरठ सिटी-दौराला, और

(v) नागल-सहारनपुर

(ख) जी हां व्यावहारिक अध्ययनों से ऊपर (क) में उल्लिखित योजनाओं वाले पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता उनके विकास का पता लगा है।

पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के निचले क्षेत्रों से गाद निकालने के काम के लिए धन का अभाव

3770. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के निचले क्षेत्रों में गाद निकालने का काम जो केन्द्रीय मंत्रालय के रहने पर आरंभ किया गया था, धन के अभाव के कारण बीच में ही रोक दिया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बर्दवान जिले (पश्चिम बंगाल) में बेगुआ हना में नदी को मुख्य धार के विभाजन स्थल से लेकर हावड़ा जिले में हुगली नदी में उसके संगम स्टाल तक पुन: चालू करने की योजना को क्रियान्वित करने का वचन और जो उसके लिए आवश्यक धन राशि दी थी एवं क्या यह काम पहले ही आरंभ किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : निम्न दामोदर सुधार स्कीम का चरण एक 6.82 करोड़ रूपए को अनुमानित लागत पर अप्रैल, 1971 में योजना आयोग द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया था। इस स्कीम में अपता चैनल (निम्न दामोदर नदी की पुरानी धारा) और इसको कुछ सहायक नालियों

की खुदायी, मदरिया तथा डाकलिया खाल्स के वोग एक सम्पर्क चैनल, अमता चैनल पर मुहाना जलकपाट का निर्माण और वर्तमान पुलों जलकपाटों आदि का निर्माण तथा पुनः रूपण शामिल है। इस स्कीम पर कार्य 1971-72 से आरंभ किया गया था और इसके मार्च 1975 तक पूरे होने की संभावना है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अमता चैनल की खुदायी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और वृहत्त क्षेत्रों में जल निकास अवरोध में सुधार हुआ है। डकातिया तथा मडारिया खाल्स के बीच चैनल तथा बहुत सी चिनायो योजनाओं पर कार्य प्रगति कर रहा है। मुहाने जलकपाट पर कार्य के लिए प्रबंध भी किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल में पांच प्राथमिकता बाढ़ नियंत्रण स्कीमों, जिनमें निम्न दामोदर सुधार स्कीम शामिल थी, का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान 11 करोड़ रुपए को विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गयी थी। सभी प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए 1972-73 के दौरान 3 करोड़ रुपए और 1973-74 के दौरान 8 करोड़ रुपए की धन राशि दी गयी।

पश्चिम बंगाल में अजय नदी योजना का क्रियान्वित किया जाना

3771. **श्री सरोज मुखर्जी:** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिकितिया में जलाशय बनाने के लिए अजय नदी योजना केन्द्रीय सरकार से आवश्यक मंजूरी न मिलने के कारण अनिमित पड़ी है?

(ख) क्या तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आश्वासन दिये जाने के बाबजूद पश्चिम बंगाल में अजय नदी के बहाव को मोड़ने की योजना को क्रियान्वित में पड़ने वाली वाधाओं पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय रूप से तथा अन्य प्रकार से राज्य सरकार को सहायता करेगी, अजय योजना ठप्प कर दी गयी है और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग): सोकितिया में जलाशय के लिए कोई स्कीम पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। वहरहाल, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 20.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सोकतिया के लगभग $7\frac{1}{2}$, मील अनुप्रवाह में बिहार में तोलावोनो पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव किया है। दूसरी ओर बिहार सरकार को सोकेतिया पर एक वराज बनाने की स्कीम है।

इन प्रस्तावों में अन्तर्राजीय पहलू निहित हैं और उनके हल होने पर ही कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने अगस्त, 1972 में इस मामले का तथा उन अन्य मामलों का जिनके बारे में उनमें मदभेद है, विस्तृत अध्ययन करने तथा तदोपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक बिहार पश्चिम

बंगाल नदी अध्ययन दल गठित किया था जिनमें दोनों राज्य के अधिकारी सम्मिलित थे। दल ने अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल और बिहार ने मंत्रियों को विचार करने तथा अन्तिम निर्णय लेने के लिए अगस्त, 1973 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट पर अभी तक उनके द्वारा निर्णय नही लिया गया है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री ने भी दोनों मुख्य मंत्रियों को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

राजामुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) में दूसरे रेल पुल का काम पूरा हो जाना

3772. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में राजामुन्दरी में दूसरा रेल पुल कब तक तैयार हो जायगा; और

(ख) यदि इसमें विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) दिसम्बर, 1974 तक पुल को यात्री यातायात के लिए खोल दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) काम को पूरा होने में विलम्ब का कारण यह है कि गार्डरों के लिए आपेक्षित इस्पात उपलब्ध नहीं हुआ 1972 में हार्डिग ब्रिज को फिर से चालू करने के लिए 300 के दो स्पेन बंगला देश भेज दिये गये थे।

वर्ष 1971-72 और 1972-73 में "ट्रैक" नवीकरण का लक्ष्य

3773. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में ट्रैक नवीकरण के क्या लक्ष्य थे: और

(ख) ये लक्ष्य कहां तक प्राप्त हो सके हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए रेल पथ के नवीकरण के लक्ष्य इस प्रकार थे:—

	रेल पथ किलोमीटर में			
	1971-72		1972-73	
	मुख्य	अनुषंगी	मुख्य	अनुषंगी
पूरे रेल पथ का नवीकरण .	960	307	15,34	3,78
रेल पटरियों का नवीकरण .	393	1,44	4,29	3,73
स्लीपरों का नवीकरण .	842	80	10,87	2,37

(ख) वर्ष 1971-72 और 1982-73 में रेल पथ के नवीकरण के लक्ष्यों में उपलब्धि इस प्रकार रही:—

रेल पथ किलोमीटर में

	1971-72		1972-73	
	मुख्य	अनुषंगी	मुख्य	अनुषंगी
पूरे रेल पथ का नवीकरण	590	295	810	238
रेल पटरियों का नवीकरण	376	28	478	113
स्लीपरों का नवीकरण	583	31	760	63

वर्ष 1973-74 के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिए दिया गया मुआवजा

3774. **श्री एम० सी० सामन्त:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: वर्ष 1973-74 में हुयी मुख्य रेल दुर्घटनाओं के कारण क्षतपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : वर्ष 1973-74 की अवधि में अब तक कुल 1,89,200 रुपए 81 पैसे की रकम मुआवज़ा के रूप में दी जा चुकी है। इसमें मुआवज़े के रूप में जितनी राशि का भुगतान 1973-74 के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिये किया गया उसके आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1973-74 में हड़तालों और दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि को पूरा किया जाना

3775. **श्री एस० सी० सामन्त:** :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 में हुई हड़तालों और दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए रेलवे का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) रेलवे में हुई हड़तालों के कारण, जिनमें प्रयोक्ताओं का कोई हाथ नहीं था, व्यक्तियों संगठनों व्यापार गृहों, सरकारी उपक्रमों सहित सरकार को हानि अथवा क्षति की ज़िम्मेदारी रेलवे द्वारा अपने ऊपर न लिये जाने का क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) रेलवे राजस्व की अब तक की हुई हानि को पूरा करना संभव नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 12 दिन बाद समाप्त हो जायगा;

(ख) जिस किस्म की हानियों और क्षतियों का उल्लेख किया गया है रेल उनके लिए उत्तरदायी नहीं है।

स्वर्ण रेखा परियोजना का पुनरीक्षण

3776. **श्री समर गुह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए स्वर्णरेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का पुनरीक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) नयी परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसको क्रियान्वित करने का क्या कार्यक्रम है ; और

(घ) क्या गत वर्ष स्वर्ण रेखा को बाढ़ से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनता को हुई हानि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार परियोजना को फिर से तैयार करने और उसकी क्रियान्विति संबंधी काम को पूरा करने को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) अगस्त, 1972 में एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार करने हेतु सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित स्वर्णरेखा की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1970 में उड़ीसा तथा पश्चमी वंगाल को सरकारों द्वारा तैयार की गयी स्वर्णरेखा को बाढ़ों के प्रति सुरक्षा की स्कीमों का संशोधन किया जाना है। समिति द्वारा संस्तावित स्कीम में बिहार सरकार द्वारा तैयार की गयी स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना में सम्मिलित चंदिल पर बांध में बाढ़-संचय बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा तटबंधों का निर्माण तथा उडीसा में खालजोरो तथा चित्ताई नालों के निकास में सुधार करना सम्मिलित है।

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर संशोधन स्कीमों को बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ? उनसे उसे शीघ्र अंतिम रूप में देने के लिए अनुरोध किया गया है।

रेलवे में काम कर रहे स्वतंत्रता सेनानी

3777. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या रेलवे में अनेक स्वतंत्रता सेनानी काम कर रहे हैं ?

(ख) क्या उनमें से अधिकांश ने देर से सेवा आरंभ की थी और वे पूरी अवधि तक सेवा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं।

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों ने स्वतंत्रता सेनानी सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि बढ़ाए जाने का लाभ दिया है ;

(घ) क्या रेलवे भी अपने कर्मचारियों को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया इस प्रकार का लाभ देगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है और रेलवे के स्वतंत्रता सेनानी कर्मचारियों ने इस प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक सरकार को कितने आवेदन-पत्र भेजे हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) तक : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

ज्वार भाटीय तरंगों से बिजली बनाना

3778. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी फर्मों ने सरकार को जवार भाटीय तरगों से बिजली बनाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं?

(ख) यदि हां तो उनकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है; और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या का 921 दिनांक 26-2-1974 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ NO. 921 DATED 26-2-1974

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 26-2-1974 को सभा-पटल पर अतारांकित प्रश्न संख्या 921 का उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) के उत्तर में मैंने कहा था कि असम सरकार ने अपने राज्य में उत्पादित कच्चे तेल की रायल्टी में वृद्धि के लिए मांग नहीं की। उसके बाद मैंने पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री को असम के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में लिखे गये एक पत्र को देखा है जिसमें अनुरोध किया गया था अतः इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित सुधार किया जाए :—

(क) तथा (ख) : इस समय कच्चे तेल के लिए 15 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से दी जाने वाली रायल्टी को तत्काल 30 रुपए प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ाने के संबंध में असम के मुख्यमंत्री से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

(ग) इस समय पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्त सीमा तक सभा-पटल पर दिए गए उत्तर में संशोधित करने का आग्रह करता हूं। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : हमने पटना में गोली चलने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया ऐसे प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात् लिये जाते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : नियम तो यह कहता है कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद यह उठाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु हम यह परम्परा का पालन काफी समय से करते आ रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If you so desire, we may first take up call attention and then adjournment motion.

Mr. Speaker : It should be settled once for all whether adjourment motion should be taken up before call attention.

Some Hon. Members : First take up call attention, please.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में गन्ना उत्पादकों के लिए निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य का भुगतान न किये जाने का कथित समाचार

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : श्रीमान्, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में गन्ना उत्पादकों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य का भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप उनकी करोड़ों रुपये की राशि बकाया हो जाने तथा सोसाइटी क्षेत्र में गन्ने की खड़ी फसल की खरीद बन्द हो जाने के समाचार।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : श्रीमन्, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मौसम में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। इस आदेश में गन्ना उत्पादकों को गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान करने की व्यवस्था है।

2. 15 फरवरी, 1974 जिस तारीख तक के पूरे आंकड़े मंत्रालय में उपलब्ध हैं, को देश में कारखानों द्वारा 1973-74 के दौरान खरीदे गए गन्ने का कुल मूल्य 245.76 करोड़ रुपये बैठता है। इसके प्रति कारखानों ने 193.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और 52.52 करोड़ रुपये का भुगतान करना शेष था। इसमें से 15 फरवरी, 1974 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के दौरान कारखानों को सप्लाई किए गए गन्ने का मूल्य लगभग 46.29 करोड़ रुपये बैठता है। अतः 31 जनवरी, 1974 तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य की

बकाया राशि उक्त तारीख को 6.23 करोड़ रुपये बैठेगी । यह राशि खरीदे गए गन्ने की कुल कीमत का 3.1 प्रतिशत बैठती है। 1971-72 के दौरान 31 जनवरी तक सप्लाई किए गए गन्ने की बकाया राशि 4.3 प्रतिशत थी जबकि 1972-73 के दौरान वास्तव में वह शून्य थी। पिछले वर्ष स्थिति में सुधार हुआ था अधिकांशत: इसलिए कि हमारे कहने पर भारत के रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए थे कि वे कारखानों को दिए गए अग्रिमों को दो खातों में चलाए, उनमें से एक को केवल गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए अलग रखा जाए।

3. राजस्व बकाया होने की दिशा में गन्ने के मूल्यों का समय पर भुगतान कराने के लिए कुछेक राज्य सरकारों, विशेषतया उत्तर प्रदेश और बिहार के पास पहले ही आवश्यक विधायी शक्तियां हैं। उन्हें कानून के अधीन कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा है। जिन अन्य राज्य सरकारों ने इसी प्रकार के अपने कानून नहीं बनाए हैं, उनसे समय-समय पर कहा जाता है कि वे ऐसा कानून बनाएं।

4. मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कारखानों में निर्धारित जोनों में गन्ने की खरीदारी बन्द कर दी है।

Shri Jagannath Mishra : Sir, Agriculture is the backbone of our economy. The progress of the country depends on the progress of the farmers. Our Government has paid more attention to the development of urban areas than the development of agriculture. As regards the sugarcane crop, and Sugar industry it comes after textile industry. There are about 216 sugar mills and an amount of Rs. 700 crores is invested in it. If more attention is paid to this industry it can prove more beneficial and more foreign exchange earner.

The condition of cane growers in U. P., Bihar and other States is very deplorable. Payment of cane dues are not made in time. Though government gave an assurance in the reply given on 13-11-72 to question No. 83 that the expeditious payment of cane dues will be made to the cane growers and the State Governments have also been advised to do so. Inspite of it, payment is not made to them and it resulted in arrears to the tune time of crores of rupees. In Uttar Pradesh alone this amount was Rs. 35 crores in 1969-70 and Rs. 20 crores in 1970. Even the sugar factories being run by the cooperatives are not making payment to the cane growers in time. For instance a co-operative sugar factory in Darbhanga district is in arrears of Rs. 17 lakhs. The private owners of the sugar mills utilize the money, advanced by the banks against sugar stocks for disbursment to the cane growers, for starting some other new business or for expending existing one. Even the money collected on account of the development cess is not spent by them for development of roads etc. These days sugar cane seed and fertilizers are not being supplied by the Centre. I would like to know whether all these things will be set right ; and whether all the sugar mills will be nationalised so that they may be run efficiently and the farmers may not be subjected to injustice. May I also know whether the duel pricing policy in respect of sugar will have adverse effect on sugarcane production, which is falling down even now.

Shri B. P. Maurya : Sir, it is not correct to say that the Central Government and the State Governments are indifferent to the development of sugar industry. Despite of failure of winter monsoon the production of sugar will be 4·3 million tonnes, which is more than last year's production. The dual price system of sugar in proportion of 70 : 30 will have good inpact on the production of sugarcane.

As regards the payment of cane price to the growers, some States have already enacted legislations in this respect and according to the existing provision growers must be paid within 14 days of the supply of sugar cane to the mill. Our Ministry is giving thought to the issue of reducing this period to 7 days. We always advise the State Governments to properly implement the concerned rules. We received no report that any mill is refusing to take supply of the zones ear marked for it. As regards the nationalisation of the sugar industry, the report of the commission appointed on this point has been received and it is being studied by Government.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, the amount of arrear has been given in lump sum and not factorywise, so that one may not understand the actual position. May I know the steps being taken by Government to improve the lot of Cane growers. i.e. to make expeditious payment for their cane supply, to make good seeds and fertilizers available to them; to introduce good marketing system, to appoint a Chemist to decide the percentage of recovery in private mills and to fix the date by which the standing crop of sugarcane will be crushed ?

Shri B. P. Maurya : We fix the support price with the intention to give benefit to the growers and in most of the cases growers get more price than the support price. As regards the question of recovery, there is a provision of Inspector appointed by government, who decides the percentage of recovery. I assure the hon. Member that this provision will be enforced more strictly in the future.

Shri Hari Kishore Singh (Pupri) : Sir, I would like to know the basis on which the support price for sugarcane is fixed ; whether the increase in the prices of fertilizers and diesel was taken into consideration while fixing the support price; and the reasons why different support prices were fixed for Uttar Pradesh, Bihar and Haryana States. The old and out dated machinery in sugar mills of Uttar Pradesh and Bihar shows less recovery in sugarcane, and one this account cane growers have to suffer. May I know the steps government is going to take in this respect? Whenever, there is more average of sugarcane the sugar mills are not in a position to lift the whole of sugarcane production and on this account also the farmers suffer. What steps are being taken to improve this situation?

Shri B. P. Maurya : As I have already stated, the farmers got more than the support price last year as well as this year. While fixing the support price, it is seen that growers are not put to loss. As regards the less recovery on account of old machinery in sugar mills, the government is equally worried about it and decision in this respect will be taken soon.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : The Minister has stated that the government has received no reports about the refusal by sugar mills to purchase the sugarcane from the farmers. But I would like to give some positive information to the Minister in this connection. The sugar mills in Amritsar, Gurdaspur of Punjab and mills located in Gorakhpur and Deoria of U.P. have stopped purchasing sugarcane. The Batala co-operative Sugar Factory is purchasing the sugarcane at less than fixed price. The mills situated in farrukhabad district of U. P. are also paying less than fixed price to the growers. Even the Dimond Sugar Factory, which is a government controlled factory, is in arrear of Rs. 40 lakhs. Such factories have been waiting for a change in the credit squeeze policy of Reserve Bank. I want to know whether the mill owners are puting pressure on the government to have the change in its policy by taking the decision of stopping to take sugarcane supplies. May I know whether government will take steps to increase the ex-port of the sugar and the same will be sold in international free market after the existing agreement with U. K. or U.S.A. expires in December, 1974; and whether an association of sugar producing countries will be formed on the pattern of the association of oil producing countries. Will government lay down a definite policy in rpesect of production, control and

proper distribution of khandsari, gur and sugar? May I know the reasons why the report of the Bhargava commission is not being laid on the Table of the House ?

Shri B. P. Maurya : The Diamond sugar Mill of Uttar Pradesh stopped taking sugarcane on 2nd of February. The sugarcane of this area is being diverted to other mills so that the growers are not put to loss. An amount of Rs. 46·74 lakhs was outstanding against this Mill. U. P. government has given guarantee for Rs. 16 lakhs to this mill for re-starting the work. As regards the export of sugar, we will export as much as can easily be exported and we will see that our Country does not suffer in sugar trade with others countries in view of the fact that the price of sugar has been increasing in international market. As regards the report of Bhargava Commission, it was submitted on 27th of February and it is being studied in details. We will try to place it on the Table of the House soon.

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दिया जाना

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिहार की स्थिति बिगड़ती जा रही है । वहां 20 व्यक्ति गोली से मार दिये गये हैं और लगभग 200 व्यक्ति जख्मी हो गये हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The central government is responsible for all this. (Interruptions)

Mr. Speaker : Order, Order please. you all sit down. I have not been able to make out anything of what you all are speaking.

Shri Jyotirmoy Bosu : Statement should have been given yesterday.

Mr. Speaker : How can it be done unless situation is ascertained. The Notice of the adjournment motion was given yesterday and the Minister of Home Affairs is in Bihar .....

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, if you want to accept it, please accept or hear us before taking the decision on this question.

Mr. Speaker : Now, I have no objection in allowing it, as the budget discussion is going to conclude today. The motions were received from Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri G. P. Yadav, Shri Ramavtar Shastri, Shri H. N. Mukherjee, Shri C. K. Chandrappan, Shri Samar Guha, Shri S. M. Banerjee, Shri Madhu Dandvate.....First of all, the motion of Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri G. P. Yadav was received. So now I ask Shri Vajpayee to move for leave of the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, I move for leave of the House for my adjournment motion :

"That the debate in the House be adjourned to discuss the deteriorating situation in Bihar."

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सरकार की ओर से मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे खड़े हो जाएं....

चूंकि इसके पक्ष में 50 सदस्य से कम हैं इसलिए इसे अनुमति नहीं मिली ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Seats to C. P. M. members may be provided on the other side. They are with the government.

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या आप समझते हैं कि बिहार पर चर्चा न करा कर बिहार में होने वाली क्रान्ति को आप रोक सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाइये ।
(व्यवधान)

पटना में गोली चलना
FIRING IN PATNA

Shri Madhu Limaye (Banre) : I sire an a point of order. Please allcw discussion on the situation of Patna under Rule, 197.

अध्यक्ष महोदय : सभा के कार्य का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है ।

Shri Madhu Limaye : Will you allow discussion on it?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के मामलों पर अविलम्ब चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : यह मामला अत्यन्त गम्भीर है अतएव इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए (अन्तर्बाधाएं) ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री ए० के० गोपालन : यह मामला शासक दल अथवा विरोधी दलों का नहीं है अपितु असामाजिक तत्वों का है । उनका कहना है कि मूल्य बढ़ गये हैं । अतएव इस पर चर्चा की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा पर किसी प्रकार से रोक लगाना नहीं चाहता । जब स्थगन प्रस्ताव पर राय ली गई थी तब सम्भवत: बहुत से लोग अनुपस्थित थे ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : तब आप नियमों में परिवर्तन कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी दशा में सभा में गणपूर्ति का क्या करेंगे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यदि विरोधी पक्ष की संख्या कम है तो क्या महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मेरी शक्ति में है वह मैं मानने को तैयार हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : गृह मंत्री पटना गए हुए हैं । उनके आने पर हम मामला आप के समक्ष रख देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल तो आपने कहा था सरकार को वक्तव्य देना चाहिए । अब बताया गया है कि गृह मंत्री पटना गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं थी ।

श्री एस० एम० बैनर्जी (कानपुर) : उप-मंत्री यहां पर हैं । उन्हें वक्तव्य देने दें ।

श्री के० रघुरामैया : मेरे सहयोगी श्री मोहिसन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक वक्तव्य देंगे ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : As I belong to that constituency I may be allcwed to speek on the matter.

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस पर भाषणों की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

Shri Shanker Dyal Singh : We are very much perturbed at the happenings of Patna. The lawlessness being committed by them should be condemned.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि श्री मोहिसन वक्तव्य दें ।

Shri Atal Bihari Vajapayee : We are perpered for that. But would a discussion be allowed in the matter ?

अध्यक्ष महोदय : ये चाहते हैं कि यदि चर्चा की अनुमति दी जाये तो वक्तव्य को सुनेगे ।

श्री के० रघुरामैया : गृह मंत्री को आने दीजिए । ऐसी जल्दी क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री को आने दीजिए ।

Shri Atal Bihari Vajapayee : Please decide the time of discussion right now. You can do it under Rule 193.

अध्यक्ष महोदय : जब कल गृह मंत्री वक्तव्य दे देते हैं तो हम इस पर ध्यान देंगे ।

Shri Atal Bihar. Vajapayee : Cannot you decide it today ; that after the Minister's, statement there shall be a discussion.

अध्यक्ष महोदय : हमें उनसे समय लेना होगा । मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात के बारे में परिसीमत आयोग का आदेश संख्या 10

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं भारत के राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 1974 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 118(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 10 दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6458/74]

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मनाली का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा मालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6459/74]

जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जल तथा विद्युत् विकास परामर्शदात्री सेवा (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6460/74]

(2) (एक) ग्राम विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्राम विद्युतिकरण निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6461/74]

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड के कार्यकर्ण का वार्षिक समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, महालेखा परीक्षक का टिप्पणियों सहित लेखे

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गन्जम) का वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गन्जम) का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गन्जम) का वर्ष 1971-72 का निदेशकों का प्रतिवेदन, ले खा विवरण तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां :

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6462/74]

नियम 377 के अधीन मामला

Matter under Rule 377

महाराष्ट्र सरकार द्वारा समुद्री-भराव की भूमि को बेचने का कथित समाचार

Shri Madhu Limaye (Barka) : Article 297 of Constitution provides that all lands and other things of value under laying the oceans within the territorial waters of the continental shelf of India shall vest in the union and shall be used for the purpose of the union.

In spite of that the Maharashtra government has taken over the ownerships of land under ocean. Under a reclamation scheme 161 acres of land has been reclaimed. The rate of land per acre is 1 crore 70 lakh rupees. A plot of land has been sold @ Rs. 5000 rupees per yard.

May I know with whom the ownership of the land under oceans vests? I understand that in to sale transaction of 166 acres of land a large amount has been taken under the table. It is possible that Centre might have received some funds out of that amount for congress election fund.

The hon. Minister may please enlighten on the encroachment on Centre, ownership by the state.

Mr. Speaker : This would be communicated to the Minister.

सामान्य बजट 1974–75—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1974-75—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर 3·30 बजे देगें । तब तक दोनों ओर के एक एक सदस्य को कुछ समय दिया जा सकता है । श्री विद्यालंकार ।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : Yesterday, I was saying that many of our problems cannot be solved until and unless some radical changes are brought in our social structure. It is a matter of pleasure that yesterday it was stated by finance Minister in Rajya Sabha that steps will be taken to check black money. We will have to think about some effective measures to check black money.

The failure of social control does not mean that we should give up our efforts rather we should adopt social measures more vigorously. Yesterday, it was stated by the Finance Minister that Government is contemplating to transfer the wheat trade in private sector. I do not support this measure. I do not think that we can check the rising prices through such measures. We must understand one thing quite clearly that mixed economy is not our ultimate goal but socialism is our ultimate end.

The Government must put an end to all sorts of unproductive expenditure. The Government officers should also change their line of thinking and attitude. For instance, I would like to quote that 10 thousand houses are required for Chandigarh but for their construction there is no money with the Government but at the same time a ply-over is' being constructed at the cost of rupees 21 lakhs which is not very essential as there is not much traffic at that place. The priority should be given to those who have no houses to live. For this purpose Government should fix priorities.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मेरे विचार से वर्तमान बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य बजटों की तुलना में अधिक यथार्थवादी है परन्तु इसे विकास प्रधान या मुद्रा स्फीति विधेयक बजट

कहना ठीक नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । वित्त मंत्री द्वारा विकास छूट को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का निर्णय किया गया है । 1 दिसम्बर, 73 से पहले जिन उपकरणों या मशीनरी के आदेश दिये गये हैं और जो 31 मई, 1975 तक आ जायेंगे उन पर ये छूट लागू होगी । यह ठीक है कि आदेश देने के लिए तिथि का सुनिश्चित करना आवश्यक है परन्तु इसके साथ ही उसकी क्रियान्विति के लिए भी तिथि सुनिश्चित करना ठीक नहीं है क्योंकि क्रियान्विति का कार्य तो आदेश को पूरा करने वाली फर्म या देश की सुविधानुसार होता है । अतः इस मामले में मंत्री महोदय को कुछ नर्म रवैया अपनाना चाहिये । तभी यह बजट विकास प्रधान हो सकता है ।

अब बजट के मुद्रा स्फीति विरोधक पहलू को ही लीजिये । वित्त विधेयक में अनेक ऐसी साधारण वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है जिस का सीधा प्रभाव साधारण व्यक्ति पर पड़ता है । वास्तविकता तो यह है कि ऐश्वर्य से सम्बद्ध जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव भी साधारण व्यक्ति पर ही पड़ेगा । डाक-तार विभाग की सेवाओं पर जो अधिक कर लगाये गये हैं; उसका असर भी तो साधारण व्यक्ति पर ही पड़ेगा, उससे भी स्फीतिकरण ही होगा ।

यह ठीक है कि हम किसी भी बजट से यह आशा नहीं कर सकते कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर देगा । परन्तु हां, उससे इतनी आशा तो की जा सकती है कि उसमें कुछ विशिष्ट समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है चोर-बाजारी तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए कुछ निदेश दिए जाने चाहिए थे । भ्रष्टाचार से स्फितिकरण होता है । भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष कारण नियत्रण है । मैं समझता हूं कि यदि बहुत सी चीजों से नियंत्रण समाप्त कर दिया जाय तो उसके कारण होने वाला भ्रष्टाचार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा । मैं कुछ वस्तुओं पर नियंत्रंण बनाए रखने के पक्ष में हूं । नियंत्रण यदि केवल कुछ एक वस्तुओं पर ही रह जाएगा तो उसका पालन भी कड़ाई से किया जा सकेगा ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह खाद्यान्न तंत्र अथवा कर वसूल करने वाले तंत्र की कार्यकुशलता से पूरी तरह संतुष्ट हैं । क्या उन्होंने इससे सम्बद्ध लोक लेखा प्रतिवेदनों आदि को पढ़ लिया है । यदि नहीं, तो मेरा यही अनुरोध है कि वह उन्हें कृपया पूरे गौर से पढ़ने का प्रयत्न करें ताकि इस तन्त्र के कार्यकरण में सुधार किया जा सके । उदाहरणार्थ आयकर अधिकारियों का मामला ही लीजिये । उनकी भर्ती, उनकी योग्यतायें, उनके वेतनमान आदि के बारे में निर्णय करने में वर्षों लग जाते हैं । जब उन लोगों को आप ने बहुत अधिक शक्तियां दे रखी हैं, वह लाखों रुपये का कर सरकार को वसूल करके दे सकते हैं तो फिर आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सेवा में अच्छी से अच्छी योग्यता के लोग आयें । इसके लिए आपको उनकी सेवा-शर्तों में सुधार करना होगा ।

अब दूसरी ओर उन मामलों को भी देखिये जहां क्रियान्विति में विलम्ब होता है, वसूली में विलम्ब होता है, मूल्यांकन में विलम्ब होता है, और इन सब का प्रभाव सरकार की कर वसूली पर पड़ता है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर पूरा ध्यान देकर इसमें सुधार करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

Dr. Gobind Dass Richhariya (Jhansi) : In the context of present circumstances, the Finance Minister has presented the most balanced budget for which he deserves congratulations. The greatest problem before the country is that of price rise and the success of this budget his upon it. Two things are essential to check the price rise first being the increase in production and second the distribution. It is being observed in our country that the mode and policy of distribution is

defective, and is responsible for much of the present corruption. We will have to come forward with some new modes so that essential commodities can reach the exploited people.

The Production has got two aspects. First is the production from land and second is from factory. The land production is mainly concerned with agricultural production. In this connections special attention should be paid to the implementation of all the land Reform laws which have been enacted so far. I will request the Finance Minister to fix a final date for the country as a whole by which all land reforms Act should be implemented. Special attention should be given to it.

Irrigation is vital for increasing agricultural production. Sufficient provision for irrigation has not been made in our Five Year Plans. The difficulties in the way of proper irrigation should be removed. Many of our irrigation plans are not implemented before river water disputes. This must be avoided as far as possible. Similarly, special attention should be given for making the different agricultural inputs to the farmers.

Regarding the factories, I am to state that all the factories which were taken over by the Government are running in loss. The labourers should be given due representation and ownership rights so as to promote their interest in their prosperity.

The Third Pay Commission Report has not been implemented in all the departments. The people of defferent categories have not been benefited by it. Immediate attention should be given to their early implementation in case of class I employees. Attention should also be given to solve many problems of employees connected with their allowances. At the same time every sort of wastage should be avoided.

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें तथ्यों तथा असफलताओं का वर्णन सच्चाई के साथ किया गया है। वर्तमान बजट की मुख्य बात यह है कि इसमें पूंजी निवेश के लिए नये प्रयत्न किये जा रहे हैं। आयकर की दर 97.75 प्रतिशत से घटाकर 77 प्रतिशत कर दी गई है। परन्तु फिर भी मुझे इसके बारे में संदेह है कि वह इस प्रयत्न में कामयाब होंगे या नहीं क्योंकि वास्तविकता यह है कि अनेक प्रकार अप्रत्यक्ष कर लगा दिये गये हैं। गरीबी हटाने और बेरोजगारी दूर करने के लिए मंत्री महोदय को और अधिक साधन जुटाने पड़ेंगे।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Sir, just now we have received a news from Patna.

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : * *

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं किसी भी सदस्य पर दवाब डालना नहीं चाहता। परन्तु इस सदन की कार्यवाही चलाने के कुछ इस प्रकार अचानक किसी चर्चा के दौरान उठकर अपनी बात कह देना, नियमों का उल्लंघन है। हमें संसदीय मानदण्डों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। अतः आप इस समय बैठ जाइये।

**कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं पूंजी जुटाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आए दिन कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है । इसी मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप ही कई अन्य समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। बढ़ते हुए मूल्यों के परिणाम स्वरूप ही हम उतना उत्पादन नहीं कर पाये हैं जितना हम करना चाहते थे। कृषि उत्पादन के क्षेत्र पर इसका प्रभाव सब से अधिक पड़ा है ; उर्वरक उत्पादन में वृद्धि होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे । आज स्थिति यह है कि हमारे पास 50 लाख टन उर्वरकों का अभाव है जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कृषि उत्पादन में 50 शाख टन की कमी हो जायेगी। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हो रही।

कच्चे माल का भारी अभाव है, आयातित वस्तुओं के मूल्यों में भी भारी वृद्धि हो रही है । अतः इन परिस्थितियों में हम यह जानना चाहते हैं कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होगी और जब तक हम इन दोनों क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने में सफल नहीं होते, तब तक देश की गरीब जनता के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है ;

आज स्थिति यह है कि घर और बाहर दोनों ही जगह हमारी आलोचना हो रही है। मूल्यों में 100 से 300 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। अब मूल्यों को नीचे लाने की बात तो एक तरफ अब तो हम उनमें स्थिरता लाने में भी कामयाब नहीं हो रहे, अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि उनमें स्थिरता किस प्रकार लाई जाये ? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

अब मैं मुद्रास्फीति के बारे में भी एक दो बातें कहना चाहता हूं । इस समस्या के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा भी कोई हल नहीं सुझाया जा सकता, क्योंकि मंत्रालय ने अधिक नोट छापने की नीति जो गत वर्ष अपनाई उससे भी हम भली-भांति अवगत हैं। इस वर्ष राहत कार्यों के लिए हमें 100 करोड़ रुपये के स्थान पर 220 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। परन्तु फिर भी सूखे और बाढ़ जैसे राहत कार्यों पर, तो सरकार को रुपया लगाना ही पड़ेगा। परन्तु हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोकने में असफल रहे हैं।

मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है परन्तु मेरी समझ में बह यह बात नहीं आती कि आखिर उनकी इस जानकारी का आधार क्या है। वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में ही गिरावट आई है।

गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये भी वित्त मंत्री महोदय द्वारा किया गया है। परन्तु मुझे समझ नहीं आता कि वह उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। आज वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्येक बात के लिए कोई न कोई इधर-उधर का बहाना प्रस्तुत कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि इसे करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के तैयार नहीं है। मैं समझता हू कि हमें प्रत्येक कार्य के लिए लोगों को या उनके द्वारा चुने गये विधान सभा या संसद सदस्यों को अपने विश्वास में लेना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं

कि योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के शिए उन्हें अपेक्षित योगदान देना चाहिये ;

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : बढ़ते हुए मूल्यों के परिणाम स्वरूप देश के समक्ष उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में जो संतुलित बजट वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मूल्यवृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रास्फीति है। अब हमें देखना यह है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या किया गया है । मैं समझता हूं कि जब तक हम इसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है।

आज हम सार्वजनिक क्षेत्र में करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं परन्तु हम उन्हें कच्चे माल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं देते। इतना ही नहीं, हम राज्य व्यापार निगम को भी विदेशी मुद्रा नहीं कमाने देते। उदाहरणार्थ कागज के मामले को ही लीजिये। कागज के लिए हमारा करार हुआ था और कागज उपलब्ध भी था परन्तु हमारे सम्बद्ध व्यक्ति के पास उसे खरीदने का अधिकार नहीं था। यही बात गेहूं और चावल पर भी लागू होती है। यह सब कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम विदेशी मुद्रा कमा सकते थे और 125 करोड रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था को कम किया जा सकता था।

वित्त मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि वर्ष 1974-75 बहुत कठिन वर्ष होगा। आज देश की स्थिति यह है कि न देश में चीनी मिलती है, न सीमेंट या स्टील। आज हर तरफ अभाव ही अभाव है। आज समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में संसद सदस्यों अथवा विधायकों का भविष्य क्या होगा।

जो सात मिनट का समय मुझे दिया गया है उसमें सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों में सुधार करना चाहिये ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक राजनीतिक प्रश्न है। हमारे श्रमिक बहुत ही शील, अच्छे और देशभक्त हैं। आज देश में संकट राजनीतिक नेताओं के कारण ही उत्पन्न हो रहा है न कि श्रमिकों के कारण। श्रमिकों को तो वे अपने हथियार के रूप में काम में ला रहे हैं।

प्रशासनिक व्यय को कम किया जाना चाहिये और कार्यालयों तथा प्रबन्ध व्यवस्था में अनुशासन होना चाहिए। कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते के बारे में किसी प्रकार का नियंत्रण रखना चाहिए। एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स को अधिक धन दिया जाना चाहिए ताकि वे अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। हमें उन लोगों को अवश्य ही प्रोत्साहन देना चाहिये जो पर्यटक के रूप में भारत आना चाहते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शुल्क से मुक्त दुकानों पर विदेशियों के लिए बडी मात्रा में भारतीय वस्तुएं उपलब्ध की जायें।

विकास छूट तक एक वर्ष की बजाय दो वर्ष के लिये दी जानी चाहिए इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों को पूंजी-निवेश करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अतः एक वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है। आयकर छूट की सीमा 6,000 रुपये से बढ़ा कर 7,500 रुपये की जानी चाहिये।

इसके पश्चात् ऋण पर नियंत्रण की बात आती है। वास्तविक रूप में एक युक्तियुक्त ऋण योजना बनायी जानी चाहिये। किन्तु दुर्भाग्यवश ऋणों पर नियंत्रण लगा दिया गया है। लोगों के मस्तिष्क से इस गलत धारणा को दूर किया जाना चाहिये।

100 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाना चाहिये। करोड़ों रुपये के मूल्य के बैंक ड्राफ्ट बेनामी नामों से चल रहे हैं और भेजने वाला जानता है कि जिसके नाम इसे भेजा जाता है उसे यह मिल ही जाता है। इस तरह करोड़ों रुपये का काला धन एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि राष्ट्रीयकृत, विदेशी एवं अन्य सभी बैंकों पर छापा मारा जाये, तो इस काले धन की बुराई को समाप्त किया जा सकता है।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Mr. Speaker, Sir, what have you decided regarding the matter raised by me under rule 340?

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस प्रश्न पर काफ़ी समय ले चुके हैं। मैंने आपकी सूचना को देखा है। मेरे विचार में पहले यह निर्णय किया गया था कि गृह मंत्री कल वक्तव्य देंगे और मेरा यह भी विचार है कि अध्यक्ष महोदय ने इस बात का संकेत दिया था कि उन्हें उस के पश्चात् चर्चा किये जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

Shri G. P. Yadav : I want to say that Gaffoor Government is totally incapable of tackling the problems, so it should resign. The Government is not accepting the ordinary demands of the students. When they asked for the fulfilment of their demands, they were fired at (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : मैं इस बात की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के अन्तिम वाक्य में यह कहा है कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को, जिनका सामना इस समय हम कर रहे हैं, समाजवादी उद्देश्यों को समक्ष रखते हुए तीव्र गति से विस्तारशील अर्थव्यवस्था से ही हल किया जा सकता है। किन्तु हमारी अर्थ व्यवस्था समाजवादी दिशा में नहीं चल रही है। गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकारों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय कृत बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं पहले की ही तरह से एकाधिकारियों को वित्तीय सहायता दे रही हैं। हमारी सूमची राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था 75 एकाधिकार गृहों के साथ में है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार ये एकाधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण प्राप्त कर रहे हैं। जब तक हम इन एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना कठिन है।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता बढ़ती जा रही है। वेतन भोगी वर्ग में भी असमानता पाई जाती है। कराधान की अधिकतम सीमान्तक सीमा को 97.75 कम करके 77 प्रतिशत कर दिया गया है। तर्क यह दिया गया है कि इससे कर अपवंचन कम हो जायेगा। किन्तु इससे ऐसा लगता है कि हम कर अपवंचन पर नियंत्रण नहीं कर पाये हैं और इस तरह हम उन्हें राहत दे रहे हैं। इस देश में राजस्व स्त्रोत के मामले में हमें पूर्णतया करों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और इसके लिये हम पूंजीवादी दिशा की ओर जा रहे हैं। मूल्य वृद्धि जनसाधारण की एक मुख्य समस्या है। जब भी मूल्यों में वृद्धि होती है, तो साथ ही लाभ में भी वृद्धि होती है। गत वर्ष वित्त मंत्री ने बहुत जोर-शोर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहा था, परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक तरह से काम नहीं कर रही है।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुये
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

इस संबंध में मैं आसाम का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां सरकार ने चावल के व्यापार का सरकारीकरण किया । सरकार वहां चावल और आवश्यक वस्तुओं का वितरण सहकारी समितियों द्वारा कर रही है । यदि हम वास्तव में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को कम करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिये । वसूली और वितरण कार्य केवल सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने चाहियें । वसूली और वितरण दोनों कार्यों के मामले में निजी व्यापारियों को बीच में से हटा दिया जाना चाहिये ।

आसाम को आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई के कारण सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण में बाधा पड़ गई । सभी उपभोक्ता वस्तुओं वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । समूची वितरण प्रणाली को जन-सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को विशेषकर आसाम के लिये आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई अवश्य ही सुनिश्चित करनी चाहिये जहां हमने पहले ही चावल, धान आदि की वसूली तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये सहकारी समितियों का जाल बिछाया हुआ है ।

Shrimati Sabodrabai Rai (Sagar) : I welcome the Budget which has been presented by the Finance Ministry: He has presented a very good Budget. But today the main problem is this that even essential commodities are not easily available. The farmers are not getting seeds, fertilizers and such other things. Harijan Adivasis in Madhya Pradesh have not been given lands. Not only that, even some of their leases have been terminated.

It is not a good thing that commodities are not available in the country. The fact is that Government officers are dishonest persons and they divert the goods and thus they are sold in the blackmarket. When these things are not available in the open market, they are easily available in the black market. We have not enough food grains in the country, but they are not available to the public in the market. Therefore, some steps should be taken to see that foodgrains and other essential commodities are not sold in black market. The Government should fix their prices and they should also see that the prices are not allowed to go up and thus the difficulties of the public are removed. Moreover, the restriction on the movement of foodgrains should be removed. In the end, I again welcome this Budget.

Shri Chiranjib Jha (Sahanga) : Today, the discontentment is prevailing in the country due to the constant rise in prices. The Finance Minister has stated that inspite of the measures adopted by the Government, the prices have been constantly increasing.

The hon. Minister has also admitted in his Budget-Speech that the prices could not be brought down despite better kharif crop in 1973 because of other forces of raising prices being active in our economy. I, therefore, want to know from his as to what does he mean by changing the ways according to the circumstances? Does he think that the existing administrative-setup which we got in heritage from Britishers has to be changed? If so, I would insist on a very quick improvement therein on reorganisation thereof so as to suit our democratic set-up and socialistic pattern of society.

The prices increased despite very good Kharif Crop in 1973 because of certain vested interests, then why does he not take action against such interests? The entire country is with us and our people would support us although they are sore that we have not proved our worth despite the power and mandate given to us and hopes pinned in us by our masses.

Mr. Chairman : Let the hon. members be brief and not exceed five minutes since, the hon. Finance Minister has to reply today itself. I have to give opportunity to others also.

Shri Chiranjib Jha : I will conclude soon.

Whereas we are upset by the unemployment problem of both educated and uneducated people, we are equally harassed by the already employed Government Servants in various departments on account of their frequent strikes which are causing a great damage to the economy of the country. They are demanding a raise in their pay on account of rise in prices.

The Saint-leader Acharya Vinoba Bhave has time and again appealed to the Government to arrange for recovery of revenues from farmers in kind instead of in cash by giving them adequate rebates. This would not only pacify them but would help administrative machinery too.

Mahatma Gandhi always pleaded for the decentralisation of power and economy and for that he had insisted on Gram-Panchayats and for giving adequate powers to them.

Maximum attention should be paid to the development of backward areas. The opposition is wrong if they say that nothing has been done in this direction. Many developmental programmes have been undertaken. But it is also true that they need much more attention. The Mahatma had asked the Administration to start uplighting the most down trodden and most backward people.

With these words, I support the Budget and thank you, Sir.

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal) : Although I congratulate the hon. Finance Minister on the presentation of such a Budget, yet I do not agree with the view that it is a socialistic Budget. It does not confirm to the declarations made by the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, about the objective of socialism.

I belong to that area which has the privilege of giving birth to Bharat after whom the country was named 'BHARAT. But it is a pity that nothing has been done for the development and upliftment of that great land.

Everybody here is crying about the dearth of Foreign Exchange but none speaks of the most beautiful and attractive places in my area which, if developed and made accessible to the Foreign tourists can fetch a lot of Foreign Exchange for the nation. A 200 kilometer spot Dudhatoli, at a height of about 4500 ft. to 9000 ft. is as good as Switzerland and Kashmir when there is snowfall there and you can enjoy snowfall there. as you do in Switzerland or Kashmir.

The Britishers had conducted a survey for a railway line in 1920-21 and also marked the route therefor, but I am grieved to point out that Garhwal is having only half a kilometre long railway line despite the fact that lakhs of people visit Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Jamnotri and other places there every year. A railway line is that area would not be uneconomic as well. Hemkund the lower valley where Guru Govind Singh meditated is also situated there.

We all think of national security, since we are facing a danger from China, and our area is quite adjacent to Tibet, which is now under Chinese control and there are many hill-paths through which China can attack us. It is, therefore, quite imperative that we should take effective steps for the development of that area. We cannot have more patience and therefore demand justice immediately, which we have not got till now. For instance, we have a population of 38 lakhs and an area of 51,000 sq. kilometers as compared to the population of 34 lakhs and an area of 55,000 sq. kilometers of Himachal Pradesh, but despite that our area is not represented in Rajya Sabha. though Himachal Pradesh is represented. We have now only 19 Members in U. P. Legislative Assembly of 425. This is a grave injustice to us. You should keep in view for the area also when you fix the limits.

We have no roads and no means of transport. Our ladies are supposed to travel 3 miles down the hills and fetch water from the rivers. How long can we hear that?

It is not a matter of pity that in the land of Ram Ganga, Alaknanda, Yamuna and Bhagirathi, people are not getting enough water to drink.

My area is a land of great heroes and freedom fighters. 28 thousand Garhwalis were the brave soldiers of I.N.A. and now also we have 3000 soldiers in our Indian Army.

I, therefore, appeal to the Finance Minister to please attend to the development and upliftment of our area where you would find ample resources of wealth, minerals and mountains of cement. The precious waters there are also not being exploited for want of necessary facilities. The life-saver shrubs, which brought Lakshmanji back to life was brought by Hanumanji from this area itself, I mean to say that this area has plenty of life-saving shrubs and herbs and they need only to be exploited. I hope my suggestions would be given due consideration.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मुझे कुछ सुझाव देने हैं जिनमें से एक तो यह है कि देश की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए विदेशों के साथ हमारी व्यापार-पद्धति अधिक उदार होनी चाहिए। तेल के मूल्यों में वृद्धि की दृष्टि से सरकार उपभोक्ता तथा उत्पादक देशों के साथ सहयोग करे तथा स्थायी प्रबंध करे। उद्योगों, रेलवे तथा कृषि क्षेत्र में पूरा उत्पादन किया जाये मूल्यों में वृद्धि द्वारा उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को हल करने के कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये। इसके लिये प्रमुख वस्तुओं के विक्रय के लिये उचित दर की दुकानें खोली जायें तथा राज सहायता प्रदान की जाये। जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों एवं मुनाफाखोरों को दण्ड दिया जाये। चीजों पर विक्रय मूल्य लिखे जायें।

मंत्री तथा सरकारी अधिकारी सामाजिक न्याय के लिये कार्य करें तथा असहाय लोगों की इस कठिन समय में सहायता करें।

बच्चों तथा विशेषकर अपंग बच्चों को सविधायें देने तथा देश में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये। देश में क्रांति को रोकने के लिये मूल्यों में कमी की जाये। देशभर में सरकारी परिवहन की व्यवस्था की जाये।

चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये राजनैतिक दलों को वित्तीय सहायता दी जाये ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से निपटा सकें। मताधिकार की आयु को घटा कर 18 वर्ष कर दिया जाये। लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव देश भर में एक साथ हों। इससे देश के करोड़ों रुपये बचेंगे। या तो हम विधान सभाओं के चुनाव पहले करा लें या फिर लोक सभा का कार्यकाल बढ़ा दें। न्याय के लिये कानूनों तथा प्रशासन में सुधार किया जाये।

राष्ट्रीय हित में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक जमापूंजी वाले बैंकों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। देश में विश्वकर्मा जाति के पांच-छः करोड़ लोग हैं, उन्हें भी रोजगार के लिये प्राथमिकता दी जाये। छोटे शीतल-पेय निर्माताओं पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये। तथा उन्हें अधिक स्वास्थ्यकर पेय बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विदेशी ह्विस्की, ब्रांडी तथा जिन पर उत्पादनशुल्क 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाये ताकि छोटे शीत-पेय उत्पादकों को राहत मिले, मेरे इस सुझाव पर अवश्य ध्यान दिया जाये।

उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्यान्नों की वसूली के मामले में किसानों को आयातित खाद्यान्नों के समान दरें दी जाये। आयकर सीमा 6000 रुपये सही है। परन्तु पोस्ट कार्ड के दाम बढ़ाना उचित नहीं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से आम निर्धन जनता का पत्र व्यवहार के लिये यही माध्यम है।

जब स्पेन अपने जहाजों का मूल्य अधिक मांग सकता है तो भारत सरकार भी यूगोस्लाविया से अपने वैगनों के अधिक मूल्य मांगे या फिर क़रार को समाप्त करके 27 करोड़ रुपये बचाये। वित्त मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करे। विपक्षी दलों को चाहिये कि वे भड़काऊ रवैया अपनाने की बजाय बंध, हड़ताल आदि रोकने में सरकार के साथ सहयोग करें। विमुद्रीकरण वर्तमान स्थिति में सहायक होने की बजाये इससे समस्यायें पैदा हो जायेंगी, इसलिये मैं इसके विरुद्ध हूं।

अन्तर्जाति विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाये तथा ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहिये जैसे कि पंजाब में हुई जहां कि अन्तर्जाति विवाह करने पर नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाये।

सभापति महोदय : इसका कराधान से क्या संबंध है।

श्री मधु लिमये : बजट पर चर्चा के दौरान कोई सीमा नहीं होती है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : पंचवर्षीय योजनाओं की जगह दो वर्षीय योजनायें होनी चाहियें, ताकि परियोजनाओं की क्रियान्विति तुरन्त हो और मूल्य वृद्धि का उन पर प्रभाव न पड़ने पाये। लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता के लिए सदा प्राकृति प्रकोपों को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिये। जैसा प्रशासनिक अकुशलता के कारण भी होता है।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिये।

मुहानों पर कोयला बड़ी मात्रा में पड़ा रहता है। उसकी ढुलाई की समस्या बनी हुई है। इसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाए।

हिन्द महासागर में किसी भी देश को अपने अड्डे बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। आधुनिक विमानों तथा परमाणु अस्त्रों की होड़ में हमारे देश को भी पीछे नहीं रहना चाहिये और हर स्रोत से उन्हें प्राप्त करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Finance Minister has presented a very balanced budget at a time the country is facing a grave economic crisis. The Finance Minister has not put any burden on the weaker section. Exemption limit in Income-tax should be raised from Rs. 6000 to Rs. 10,000. Also, there should be no increase in the price of post-card.

Rise in population is one of the reasons for rise in prices. Efforts should be made to check the growth of population.

Approximately, seven to ten thousand crores of rupees of black money is in circulation in our country which has assumed the place of parrallel economy. Check on its circulation is essential.

Nearly 130 prominent economists of the country presented a report to the Prime Minister demanding partial demonetisation of currency. They have given some other valuable suggestions also. The present inflationary trends can be checked by implementing the suggestions of the economists.

The provision for defence is quite in order. Second priority should be given to the agriculture and third to the exploration and production of petroleum products.

A solution needs to be evolved under which there could be no possibility of strike for five years. 60 lakh man-days were lost during 1971, 1972 and 1973 in the Public Sector Undertakings due to strikes.

The Government should check the expenditure incurred for unproductive purposes.

30 percent people in our country are living below poverty line. Hilly region of Uttar Pradesh is still below this line. Development of this area should be taken up according to the local conditions prevailing there.

The number of land-less labourers is increasing with the passage of time. Government of India should make a provision for providing land to all the landless labourers.

Shri Tula Ram (Ghatampur) : The Finance Minister has presented a balanced budget. Today, country is facing poverty, shortages and rising prices.

Corruption in public life is assuming high dimensions. Beside providing improved equipments and seeds, Government should also ensure irrigational facilities to the farmers.

So far as procurement of foodgrains is concerned, Government should see to it that reasonable prices of foodgrain are provided to the farmers.

Government is discriminating between rural and urban people by way of giving more ration quota of sugar and foodgrains to urban people. This is against democratic principles. Government should see to it also that poor people are not harrassed by the police. The hon. Minister should also pay necessary attention towards constructing overbridge at Kanchausi Station.

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी): यह बजट देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था का प्रतिविम्ब है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

दो समय का भोजन प्रदान करने पर देश के करोड़ों लोगों को खुश किया जा सकता है। अन्त के मामले में हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं और न हैं। आवश्यक वस्तुओं के आयात पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। आमोद की वस्तुओं, पैट्रोल आदि पर हम प्रतिबन्ध लगायें तो कोई हानि नहीं है। लेकिन गरीब आदमी की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण घाटे की अर्थ-व्यवस्था है। दूसरा कारण कालाधन है। तीसरा कारण है विमुद्रीकरण की अफवाह जिसके भय से धनवान लोग अपने काले धन से वस्तुओं का क्रय करके जमाखोरी करते हैं और अभाव की स्थिति पैदा करते हैं।

हमें रक्षा व्यय में कमी करनी चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं तो कम से कम रक्षा सम्बन्धी व्यर्थ के व्यय को बन्द करना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी करूंगा कि 5 होर्स पावर तक के वातित जल एककों को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाय।

Shri Madhu Limaye (Bankı) : This budget is an expression of bankrupty by the Government. Taxation and deficit financing has been increasing after launching the slogan of g.ribi hatao Additional taxes worth Rs 244 crores were imposed during first three year of the Fourth Five Year Plan. There was deficit financing worth Rs. 2110 crores during the last 4 years of this Plan.

The Planning Commission has no utility now. The wheat take over was definitely a step in the wrong direction. Different yardsticks for different persons were adopted in the matter of wheat procurement. The wheat procured at the rate of Rs. 76/- per quintal were sold in the markets at Bombay at the rate of Rs. 350/- to 400/- per quintal. It can not be denied that Maharashtra Government adopted a policy for the procurement of raw cotton and cotton.*

श्री धामनकर (भिवण्डी) : ये मुख्य मंत्री का नाम ले रहे हैं ..... (**व्यवधान**)

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

Expunged as ordered by the Chair.

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइये। श्री लिमये आप एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं और जो अपना बचाव नहीं कर सकता। इसे नियमों के अनुसार अनुमति नहीं दी जा सकती। यह उचित नहीं है।

Shri Madhu Limaye :

सभापति महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा क्योंकि यह संसदीय प्रक्रिया के प्रतिकूल है। कृपया किसी के विरुद्ध व्यक्तिक आरोप न लगायें **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye : I am speaking the truth. You had also been a trade unionist. I am not given to flattery.

I was referring to the distribution of foodgrains. The food policy adopted by the Government proved to be a total failure.

Money earned by the Indians abroad has been increasing for the last ten years which is being used for smuggling. Who will dare to check smuggling is high ups hold meetings with the smugglers king. The smuggler's king donated one crore rupees and wanted his photo with the dignatory in return. (*Interruptions*)

What is the reason behind Bihar happening. Main reason is the poverty of Bihar where 25 percent peasants are landless. Bihar Government had demanded 17·40 lakh tonnes of foodgrains whereas only 4·40 lakh tonnes of foodgrains were actually supplied to them.

The Government cannot crush the mass resentment with bullets and army.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. DREPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The target of public outlay has not been fulfilled in the first year of Fifth Five Year Plan and no return is expected from the investments due to price rise.

Keeping in view the recent performance of the Planning Commission, I suggest that it will be better if this body is wound up.

It is stated in the Five Year Plan that revenues will be augmented through direct taxes but this budget has decreased the amount of direct taxes. The Government has argued that tax evasion will decline in case taxes are reduced.

There is no national income policy with the Government. There is no social justice in the income policy of the Government. There is no scheme to augment the income of a common man.

Diesel oil, Kerosene oil, mobil oil or fertilizers are selling at double the rates in the rural areas in the absence of controlled rates.

The Government has not so far adopted some integrated policy regarding cloth. Course and medium varieties of cloth should be sold on controlled rates to the people during Fifth Five Year Plan and fine or superfine cloth should be kept for export only.

America imports one lakh bales of long stable cotton and Japan has been importing two lakhs bales per year. This country has been spending Rs. 800 crores of foreign exchange per year for 4 lakh long stable cotton bales. For the last 9 years ....(*Interruptions*) you could import fertilizer etc. with this huge sum of Rs. 800 crores. We have been importing tear gas shells from America. Should we not instead import articles which increase our production? You have been importing all articles of suppression from America.

Government has not been taking the parliament into confidence. All those who speak the truth are termed as anti-Indians. We should try to bring about some change.

***अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया**

*Expunged as ordered by the Chair.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : बजट की, सभा के कुछ वर्गों ने आलोचना की है जब कि अन्य ने बजट के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है तथा कुछ सदस्यों ने उसका समर्थन करने के साथ-साथ आलोचना भी की है।

सदस्यों ने यह प्रश्न उचित किया है कि वे इस बजट की परीक्षा करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या यह देश की मुख्य आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम है, हमें यह देखना है कि यह बजट मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि घाटे की अर्थ व्यवस्था और देश की आर्थिक उन्नति की समस्या को किस सीमा तक हल कर सकेगा।

गत चार वर्षों में पर्याप्त घाटे की वित्त व्यवस्था हुई है इससे अधिक की घाटे की वित्त व्यवस्था होती यदि हमने गत चार वर्षों में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम न उठाए होते। जनता से रुपया लेने और संसाधन खोजने के बावजूद हमें घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। यद्यपि हम इसे कम से कम करना चाहते हैं। 1971-72 में घाटे की वित्त व्यवस्था 521 करोड़ रु० थी, 1972-73 में 88 करोड़ रुपए तथा 1973-74 में यह 650 करोड़ रुपए थी, इस प्रकार गत तीन वर्षों में 1752 करोड़ रु० की घाटे की अर्थ व्यवस्था हुई। परन्तु यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? इसका सबसे प्रमुख कारण शरणार्थियों को सहायता देना, रक्षा, प्राकृतिक विपत्तियों, वेतन पुनरीक्षण, महंगाई भत्ता और खाद्य-राज सहायता देना है।

क्या बजट में कुछ कम राशि देकर हम शरणार्थियों की सहायता अथवा रक्षा अथवा प्राकृतिक विपत्तियों या वेतन पुनरीक्षण अथवा महंगाई भत्ता देने से मना कर सकते थे? अन्ततः सरकार को देश की समस्याओं का सामना करना ही है। हम वास्तविक जीवन को बजट के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कुछ स्थिति पैदा होती है और हमें उनका सामना करना है इसलिए हमें घाटे की वित्त व्यवस्था को उस दृष्टि से देखना चाहिए।

उत्पादन और देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति किए बिना हम घाटे की अर्थ व्यवस्था और मुद्रा सप्लाई की समस्या का सामना नहीं कर सकते। समस्या का मुख्य पहलू यह पता करना है कि किस क्षेत्र को सहायता दी जानी चाहिए और शक्ति समपन्न बनाया जाना चाहिए और यह सर्वविदित है इस बजट में हमने सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ ऐसा किया है। हमने कृषि, इस्पात, बिजली, सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। बजट में देश की उत्पादन और प्रगतिशील शक्तियों को बल देने का प्रयत्न किया गया है। बजट उत्पादन प्रधान और प्रगति अभिमुख है। इस प्रकार यह बजट और घाटे की मुद्रा स्फीति और घाटे की वित्त व्यवस्था के मुख्य प्रश्न और समस्या को हल करने का प्रयत्न करता है।

कर प्रस्ताव करते हुए निर्धारित सिद्धान्तों का पालन किया गया है। 1971 में दिये गए भाषण के एक भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा।

मैंने कुछ मोटे सिद्धान्तों की ओर संकेत किया था इनमें से प्रथम तो यह है कि कर ढ़ांचे को सरल बनाया जाए ताकि कर दाता तथा कर लगाने वाले दोनों को ही उससे लाभ हो सके। करों की चोरी की संभावना को कम किया जा सके। दूसरी बात यह है कि करों का विभाजन कुछ इस ढंग से किया जाए कि उसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े। और उससे आय के क्षेत्र में विद्यमान असमानता को दूर किया जा सके। इस संबंध में मेरा

तीसरा सिद्धांत यह था कि नये कर कुछ ढंग से लगे कि उनका मूल्य वृद्धि पर अधिक प्रभाव न पड़े। अतः यही प्रमुख असूल थे जिनके आधार पर वर्तमान कराधान प्रस्ताव बनाये गये हैं।

कर दो प्रकार के हैं अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष। हमने निवेष प्रधान उद्योगों को कुछ रियायतें देने का प्रयत्न किया है श्री मधु लिमये ने प्रश्न उठाया है कि इस देश का कर दाता क्या ईमानदार है कि वह इस रियायत का लाभ उठाना चाहेगा उनका विचार है कि कर देने वाले बड़े-बड़े लोग ईमानदार नहीं हैं और उनकी मनोवृत्ति में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता मेरा दृष्टि कोण इस मामले में इतना निराशावादी नहीं है मेरा विचार है कि हमारी नई संतति के लोक इस प्रकार के नहीं हैं उन्हें भी हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उतनी ही चिंता है जितनी कि हमें। अतः मैं यह फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूंजी निवेष के लिए प्रत्यक्ष करों में जो रियायतें दी गयी हैं वह व मुद्रास्फीति विरोधी हैं। मेरी यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कानूनी ढंग से लाभ कमाएगा वह अपनी एकत्रित पूजी का निवेष किसी न किसी अन्य उद्योग में करना चाहेगा या बैंकों में उसे लम्बी अवधि के लिए जमा करवाना चाहेगा अतः यह एक प्रकार की बचत ही होगी जिसका हम लाभ उठा सकेंगे। मैं माननीय सदस्यों के इस मत से सहमत नहीं हूं कि वह ऐसे धन का उपयोग खाद्यान्नों आदि का स्टाक करने के लिए ही करेंगे।

अप्रत्यक्ष करों का भी अधिकांश सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया है क्योंकि उन्हें केवल कुछ गिनी चुनी वस्तुओं पर ही लगाया गया है। यह कर जनसाधारण के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर नहीं लगाया गया । इसलिए मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान कराधान प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि उनसे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो हमने बजट में सभी ऐसी समस्याओं से जूझने का प्रयत्न किया है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या हमारा योजना परिव्यय उत्पादन में सहायता करने के अनुरूप है मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि निश्चय ही इसे उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।

श्री समर गुह : टूथ पेस्ट और पोस्टकार्ड के दाम बढ़ाने का क्या औचित्य है, इन पर उत्पादन शुल्क क्यों बढ़ाया गया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो यह सोच रहा था कि इसे आप ने समाचार पत्र में पढ़ लिया होगा । खैर फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं इस सदन में इस विषय पर कई बार चर्चा की जा चुकी है। यही एक ऐसा उद्योग है जिसमें लाभ हो रहा है। इस क्षेत्र के लोगों के लाभ को सीमित करने के लिए ही उत्पाद शुल्क लगाया गया है। सदस्यों का यह कहना भी ठीक है कि अन्ततः इस वृद्धि का असर उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। परन्तु फिर भी उनके लाभ को दृष्टि गत रखते हुए उन पर कर लगाना उपयुक्त ही है।

श्री समर गुह निरन्तर पोस्टकार्ड के मूल्य की बात करते आ रहे हैं। डाक तथा तार विभाग की अपनी समस्याएं हैं। आये वर्ष इस विभाग को हानि उठानी पड़ रही है किसी भी वाणिज्यिक विभाग के लिए आत्मनिर्भर होना अच्छा होता है और इसके लिए उसे अपने संसाधनों का विस्तार करने के योग्य होना चाहिए। डाक मूल्यों के बारे में मैंने संचार मंत्री से बातचीत की थी। उस समय कई प्रकार के

सुझाव भी सामने आए थे यदि हम डाक से संबद्ध अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं तो हमारे लिए पोस्टकार्ड के मूल्य में वृद्धि करना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो अन्य वस्तुओं यथा लिफाफे या अन्तर्देशीय पत्र की तुलना में कार्ड का प्रचलन काफी बढ़ जायेगा।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रसंगों के संबंध में तथा बजट संबंधी चर्चा के संदर्भ में बार-बार यह बात कही गयी है कि मैंने कालेधन की समस्या से निबटने के लिए कुछ नहीं किया यह ठीक है कि बजट में मैंने 'ब्लैकमनी' शब्द का प्रयोग नहीं किया है "ब्लैकमनी" का तात्पर्य उस धन से है जो बिना हिसाब किताब के होता है दूसरे शब्दों में यह करों की चोरी से बनाया गया धन होता है। हमारा विचार यह है कि "ब्लैकमनी" की समस्या से निबटने के लिए करों की चोरी को रोकना अनिवार्य है। इससे रोकने का दूसरा साधन यह है कि जन साधारण के उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो उनका किसी प्रकार का अभाव न हो। उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा काफी विचार किया गया है। आयोग द्वारा एक ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है जिससे आम इस्तेमाल की वस्तुओं को उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। ऐसा करने से मूल्यों में हो रही वृद्धि को भी किसी सीमा तक रोका जा सकेगा।

टैक्सों की चोरी को रोकने के भी दो तीन तरीके हो सकते हैं। प्रथम यह है कि कृषिउत्पादन से होने वाली टैक्सों की चोरी को रोका जाए। कुछ लोगों द्वारा सुझाया गया था कि सम्पत्ति के ऊपर लगाए जाने वाले काले धन को रोकने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। कम मूल्य पर सम्पत्ति का हस्तान्तरण रोकने के लिए हमने 1972 में कानून पास किया था। 1972 में इसके बारे में विधेयक पुरस्थापित किया गया था और अब यह विधेयक कई चरणों में से गुजर चुका है। जब यह विधेयक पारित हो जायगा तो प्रत्येक हस्तान्तरित की जाने वाली या खरीदी बेची जाने वाली सम्पत्ति से संबद्ध कागजातों का निरीक्षण आयकर विभाग द्वारा किया जायगा। इस विधेयक के अन्तर्गत यदि आयकर विभाग यह समझे कि किसी सम्पत्ति को कम मूल्य पर बेचा या हस्तान्तरित किया जा रहा है तो वह उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। गत कुछ महिनों में इस प्रकार के मामलों में 3669 व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये थे। यद्यपि इनमें से अभी 20 मामलों में ही आदेश जारी किये गये हैं फिर भी उन सब का संबंध 20 लाख रु० से भी अधिक सम्पत्ति से है। मुझे आशा है कि कुछ समय बाद ऐसे कई और मामले सामने आएंगे।

कृषि उत्पादन से होने वाली आय के ऊपर कर लगाने के बारे में हमने क्या किया है, इस बारे में अक्सर लोगों ने शिकायत की है। राज समिति द्वारा इस संबंध में कुछ सिफारिशें की गयी थीं और केन्द्रीय सरकार से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को हमने स्वीकार कर लिया है। कृषि के अरतिक्ति अगर लोगों की आय का कोई अन्य साधन होता है तो दोनों साधनों से होने वाली आय को जोड़ कर उस पर कर लगाया जाना चाहिए। हमने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है हमें आशा है कि इससे करों की चोरी को रोकने में काफी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त विधेयक के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में करों की चोरी बहुत कठिन हो जायगी। इसके लिये लोगों को कड़ी सजाएं दी जायेंगीं। अतः हमने 'कालेधन' के प्रसार को रोकने के लिए हर प्रकार से सम्भव कार्यवाही की है।

अब हमारे समक्ष 'विमुद्रीकरण' का प्रश्न आता है। मैं इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का विमुद्रीकरण करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह समस्या का स्थायी हल नहीं है।

आयकर की बकाया धनराशि की वसूली के लिए हमने काफी प्रयत्न किये हैं 31 मार्च, 1972 को यह धनराशि 805 करोड़ रुपए थी जब कि 31 दिसम्बर. 1973 को यह घटकर केवल 714 करोड़ रुपए रह गयी है। अतः इस अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपए की बकाया धन राशि की वसूली की गयी। अतः इस दिशा में हमारा प्रयास काफी संतोषजनक चल रहा है।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने परिलिब्धयों के प्रश्न को उठाया है। जहां तक परिलिब्धयों के मूल्यांकन का संबंध है उसके बारे में कुछ सुधार किये जा चुके हैं। कर्मचारियों को अब तक उनके वेतन का 10 प्रतिशत रिहायश के लिए दिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों को मोटरकार की सुविधा दी जाती थी उसे 150 रु० से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। छोटी मोटर कार के लिए इसे 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार जहां तक परिलिब्धयों के दूसरे पहलू का संबंध है उसमें भी कई सुधार किये गये हैं। इस दिशा में कुछ अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनियम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए हमें कम्पनियों के तथा निदेशकों और वरिष्ठ कार्यकारियों के मूल्यांकन में परस्परिक संबंध स्थापित करना होगा। अतः अब हमने कम्पनियों, निदेशकों, और उनके वरिष्ठ कार्यकारियों के मामले का फैसला करने के लिए एक विशेष सैल बना दिया है। इस संबंध में जुलाई 1973 में आयकर आयुक्त के अपेक्षित निदेश जारी किये गये थे।

अब यह प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है कि बजट में जो 125 करोड़ रु० की घाटे की व्यवस्था की गयी है, क्या वह वास्तविक है। मुझे इस संबंध में तो यही कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में तो वह ठीक ही है। इसके साथ ही मैं इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि चालू वर्ष में हमें कुछ अतिरिक्त खर्चे की मांगों को भी पूरा करना पड़े या नहीं परन्तु फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि वर्तमान अन्तर ही बना रहे उसमें कोई वृद्धि न करनी पड़े।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा दो तीन बाते उठायी गयी हैं। उनका प्रथम प्रश्न उस धन के बारे में था जो रूस से आने वाली गेहूं को बेचने पर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्राप्त होने वाले धन को हम छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसका उल्लेख मैंने विस्तृत रूप से मैं अपने बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 58 के अनुच्छेद 46 में कर दिया है। इससे होने वाले 200 करोड़ रुपए की आय को अगले बजट में शामिल किया जायेगा।

दूसरा प्रश्न श्री बाजपेयी जी ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए की गयी धन की व्यवस्था के बारे में उठाया है। उनका विचार है कि इस कार्य के लिए 6.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है, जो कि कम है। इसके बारे में उन्हें कुछ गलत सूचना मिली है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए वर्ष 1974-75 के दौरान 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

वर्ष 1974-75 की राज्य योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इस कार्यक्रम से संबद्ध कुछ सेवाओं को राज्यों को हस्तान्तरित करने के बाद यह आंकड़े गत वर्षों की तुलना में अच्छे हो जायेंगे।

श्री दिनेश सिंह द्वारा 'सरकारी क्षेत्र' के कार्यकरण की बात उठायी गयी है। मुझे इस संबंध में यही कहना है कि अब इसमें भी कुछ प्रगति हो रही है, इसके कार्यकरण में परिवर्तन आ रहा है। हाल ही में इसके कार्यकरण की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक दल नियुक्त किया गया था। यह दल बहुत संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इसने कुछ कारगर सुझाव दिये हैं जिनके परिणास्वरूप इस क्षेत्र के कार्यकरण में काफी प्रगति होने की संभावना है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि 'सरकारी क्षेत्र' की दृष्टि से वर्ष 1974-75 काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सम्पूर्ण राष्ट्र इसी प्रगति का इच्छुक है।

माननीय मिश्र, श्री पीलू मोदी द्वारा जो चार सुझाव दिये गये हैं उनमें से एक तो यह है कि 'सरकारी क्षेत्र' समाप्त ही कर दिया जाए और टैक्स कम कर दिये जायें। उनका दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए। वास्तव में हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम कृषि के क्षेत्र पर काफी खर्चा कर रहे हैं। निश्चय ही यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को काफी शक्ति प्रदान कर सकता है।

जहां तक निर्यात का संबंध है गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष हमने इसपर अधिक ध्यान दिया है। इस वर्ष हमारे सभी प्रयत्नों का मुख्य केन्द्र निर्यात ही रहेगा हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि कच्चे तेल तथा उर्वरक आदि की कीमतों में जो वृद्धि हुयी है उसे पूरा करने के लिए हमें अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी पड़ेगी इसलिए इस संबंध में वाणिज्यिक मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

मैं जानता हूं कि हमारा रास्ता कठिनाइयों से भरपूर है। आज देश की स्थिति हमारे सामने अनेक चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। वास्तव में तो पिछले चारों ही वर्ष चुनौतियों से भरपूर रहे हैं परन्तु फिर भी हम अपने तथा अपने राष्ट्र में विश्वास रखते हुए उनका सामना करने में सफल हुए हैं और आगे भी होंगे।

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS (GENERAL) 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Grants on Account for the year 1974-75 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि विभाग . . .	27,20,000	..
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग .	1,30,000	..
3.	कृषि	13,04,65,000	61,32,08,000
4.	मछली पालन . .	1,23,59,000	21,30,000
5.	पशु पालन और डेरी विकास	5,28,22,000	48,07,000
6.	वन	1,49,80,000	9,17,000
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगी .	5,82,36,000	..
8	खाद्य विभाग .	20,02,46,000	2,19,97,000
9	सामुदायिक विकास विभाग . .	4,93,08,000	..

1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
10	सहकारिता विभाग . . .	1,10,73,000	3,51,87,000
11	विदेश व्यापार विभाग .	18,10,000	..
12	विदेश व्यापार . . .	28,07,02,000	32,50,58,000
13	संचार मंत्रालय . . .	13,35,000	45,83,000
14	समुद्रपारीय संचार सेवा . .	1,14,15,000	63,33,000
15	डाक व तार (कार्यचालन व्यय) .	62,44,34,000	...
16	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग तथा सामान्य राजस्व से दिए जाने वाले ऋणों की वापसी अदायगी .	13,89,10,000	...
17	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	—	24,73,83,000
18	रक्षा मंत्रालय . . .	24,88,000	4,18,87,000
19	रक्षा सेवाएं—थल सेना . .	206,40,44,000	...
20	रक्षा सेवाएं—जल सेना . .	18,23,40,000	..
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना . .	63,81,66,000	..
22	रक्षा सेवाएं पेंशन आदि . .	12,75,17,000	..
23	रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय . .	..	39,47,88,000
24	शिक्षा विभाग . . .	19,73,000	..
25	शिक्षा . . .	17,89,52,000	10,99,000
26	समाज कल्याण विभाग . .	3,46,79,000	..
27	विदेश मंत्रालय . . .	12,52,61,000	5,20,00,000
28	वित्त मंत्रालय . . .	4,10,56,000	...
29	सीमा-शुल्क . . .	2,94,23,000	..
30	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क . .	4,72,31,000	..
31	आय आदि पर कर . . .	5,23,89,000	..
32	स्टाम्प	1,03,75,000	11,94,000
33	लेखा परीक्षा . . .	8,70,83,000	..
34	मुद्रा, सिक्का और टकसाल . .	5,15,86,000	2,82,22,000
35	पेंशन	5,00,90,000	..
36	अफीम के कारखाने और एल्कलायड के कारखाने	10,33,45,000	10,75,000

1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
37	राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	41,73,97,000	..
38	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय . .	32,48,73,000	40,94,55,000
39	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण .	..	10,48,65,000
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय .	9,19,000	..
41	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . .	9,66,52,000	3,91,85,000
42	परिवार नियोजन . .	9,67,88,000	3,33,000
43	भारी उद्योग मंत्रालय .	4,80,000	..
44	भारी उद्योग .	86,16,000	5,35,81,000
45	गृह मंत्रालय .	34,59,000	..
46	मंत्रिमंडल . . .	17,69,000	..
47	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग .	92,69,000	..
48	पुलिस . .	26,69,06,000	45,83,000
49	जनगणना . .	57,70,000	..
50	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय . .	12,98,38,000	2,83,27,000
51	दिल्ली	14,40,88,000	5,66,12,000
52	चण्डीगढ़ . . .	1,78,76,000	73,93,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह .	2,79,76,000	1,19,12,000
54	अरुणाचल प्रदेश . .	3,30,19,000	1,40,66,000
55	दादरा और नागर हवेली .	16,48,000	21,58,000
56	लक्षद्वीप . .	43,12,000	13,31,000
57	औद्योगिक विकास मंत्रालय . .	38,85,000	..
58	उद्योग	81,51,000	7,05,47,000
59	खादी और ग्रामोद्योग . .	4,70,57,000	8,81,78,000
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	5,33,000	..
61	सूचना और प्रचार . . .	1,99,77,000	34,58,000
62	प्रसारण . . .	3,39,94,000	2,93,67,000
63	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . .	75,61,000	1,19,33,000
64	सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण योजनाएं .	1,93,69,000	30,75,000
65	विद्युत योजनाएं . .	1,85,99,000	11,70,29,000
66	श्रम मंत्रालय . . .	9,20,000	..

1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
67	श्रम और रोजगार . .	4,90,42,000	17,000
68	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	1,20,87,000	. .
69	न्याय प्रशासन . .	3,81,000	
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	11,72,000	. .
71	योजना मंत्रालय	1,92,000	. .
72	सांख्यिकी	1,44,85,000	. .
73	योजना आयोग .	52,58,000	. .
74	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	31,62,000	. .
75	सड़कें . . .	10,29,35,000	11,23,72,000
76	बन्दरगाह, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन	2,27,30,000	30,27,51,000
77	सड़क और अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन	17,23,000	2,54,02,000
78	इस्पात विभाग	4,17,03,000	26,78,14,000
79	खान विभाग	5,52,000	. .
80	खान और खनिज	5,54,62,000	48,11,93,000
81	पूर्ति विभाग .	3,46,000	. .
82	पूर्ति और निपटान	1,25,11,000	. .
83	पुनर्वास विभाग . .	5,59,45,000	88,67,000
84	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	5,46,000	. .
85	मौसम विज्ञान	1,41,45,000	25,10,000
86	विमानन	2,43,03,000	3,95,98,000
87	पर्यटन . .	49,93,000	1,05,33,000
88	निर्माण और आवास मंत्रालय . .	7,09,000	. .
89	सरकारी निर्माण कार्य	8,47,87,000	1,98,61,000
90	जल पूर्ति तथा जल निकासी . .	12,68,000	. .
91	आवास तथा नगर विकास .	1,35,49,000	1,63,74,000
92	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	3,17,82,000	. .
93	परमाणु ऊर्जा विभाग .	6,09,000	. .
94	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास .	6,09,39,000	9,89,41,000
95	माभिकीय विद्युत योजनाएं . .	5,09,99,000	7,75,70,000,

1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
96	संस्कृति विभाग	1,12,56,000	..
97	पुरातत्व .	86,26,000	..
98	इल्क्ट्रानिक्स विभाग .	1,56,14,000	66,80,000
99	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	99,39,000	22,08,000
100	भारतीय सर्वेक्षण . .	2,08,92,000	..
101	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान .	5,02,01,000	..
102	अन्तरिक्ष विभाग .	3,49,78,000	1,18,47,000
103	लोक सभा	52,89,000	..
104	राज्य सभा . . .	22,90,000	..
105	संसदीय कार्य विभाग .	2,79,000	..
106	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . .	74,000	..

अनुदानों की मांगें (रेलवें) 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1974-75 के लिए बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 15 मिनट के अन्दर अपने कटौती प्रस्तावों की पर्चियां क्रमांक सहित प्रस्तुत कर दें।

मांगें अब सभा के समक्ष हैं।

रेल मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1.	श्री रामावतार शास्त्री	: रेलवे में चरमसीमा तक पहुंचें भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	2.	,,	रेलवे बोर्ड को साप्त करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
,,	3.	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे बोर्ड के स्थान पर एक स्वायत्त निगम स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
,,	4.	,,	आल इण्डिया रेलवे इम्पलाइज कनफैडरेशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	5.	,,	रेल में काम करने वाले गैर-मान्यताप्राप्त यूनियन एवं संगठनों के साथ वार्ता करने की आवश्यकता	,,
,,	6.	,,	रेल मजदूरों के लिए अन्य सरकारी कारखानों के मजदूरों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन निश्चित करने में असफलता ।	,, ,,
,,	7.	,,	रेल वैगनों की कमी को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	8.	,,	रेल में काम करने वाले कैजुअल मजदूरों को स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
,,	9.	,,	रेल मजदूरों को ट्रेड यूनियन कार्यों में भाग लेने के कारण विभिन्न प्रकार की सजा देने की नीति का अन्त करने में असफलता ।	,,
,,	10.	,,	रेलवे में मजदूरों का एक ही संगठन बनाने में असफलता ।	,,
,,	11.	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा लड़ाकू मजदूर यूनियनों को दबाने की नीति को बदलने की आवश्यकता ।	,,
,,	12.	,,	रेल मजदूरों के लिए आवश्यकता के आधार पर निम्नतम वेतन 314 रुपए निर्धारित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	13.	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता	,,
,,	14.	,,	रेलवे के प्रबन्ध में ऊपर से नीचे तक श्रमिकों की भागीदारी नीति को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	15.	,,	रेलवे कर्मचारियों को सस्ते अनाज तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की आवश्यकता।	,,
,,	16.	,,	सम्पूर्ण देश में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में, समय अनुसार रेल-गाड़ियां चलाने में असफलता।	,,
,,	17.	,,	यात्रियों को विशेष रूप से तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को, सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	18.	श्री रामावतार शास्त्री :	परिचालक कर्मचारियों, लोको मेकेनिकल कर्मचारियों, सिग-नल और दूर-संचार कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों को हड़ताल के समय तथा नियमानुसार कार्य के आन्दो-लन के समय दिए गए आश्वा-सनों को क्रियान्वित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	19.	,,	विभिन्न वर्गों में यूनियनों /संघों को मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	20.	,,	विभिन्न रेलवों में मजदूर संघों को जो ए०आई०टी०यू०सी० से सम्बन्धित हैं, मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	21.	,,	रेलवे में प्रादेशिक सेना का हड़-तालों को तोड़ने और सरकारी एजेंट के रूप दुरुपयोग।	,,

1	2	3	4	5
1	22.	श्री रामावतार शास्त्री :	रेलवे में ऊपरी श्रेणियों के प्रशासनकों की छटनी करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	23.	,,	रेलवे में हुई चोरियों को रोकने में असफलता।	,,
,,	24.	,,	वैगन की उत्पादकता को बढ़ाने तथा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वैगन कारखानों को हाथ में लेने में असफलता।	,,
,,	25.	,,	रेलों के विकास का सन्तुलित कार्यक्रम बनाने में असफलता।	,,
,,	26.	,,	रेलवे बोर्ड उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करने के लिए एक जांच समिति बनाने में असफलता।	,,
,,	27.	,,	रेलवे में चोरी और कोयले का देरुपयोग रोकने में असफलता।	,,
,,	28.	,,	भारतीय रेलों में का कर रहे अनुसूचित कर्मचारियों के 96 प्रतिशत कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाये जाने के के लिए विभिन्न रेल मंत्रियों द्वारा बार-बार दिए गए वचनों को लागू करने में असफलता।	,,
,,	29.	,,	भारतीय रेलों में अधिकारियों को सैलून तथा सैलून जैसी दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	30.	,,	भारतीय रेलों में गेट-मैनों के के लिए 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
1	31.	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेलों में लगातार कई वर्षों तक कार्य करने के पश्चात् भी एवजी कर्मचारियों को नियमित स्थायी बनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	32.	,,	अखिल भारतीय रेल कर्मचारी सम्मेलन में दिल्ली में 27-2-74 को गठित की गई संयुक्त समन्वय समिति के साथ जिसमें अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महा संघ, ए०आई०टी०यू०सी०के मजदूर संघों, आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन, बी०एम० एस० एण्ड केटेगोरिकल संघों ने सम्मेलन की छः सूत्री मांगों के आधार पर भाग लिया था, बातचीत करके हल निकाल लिए जाने की आवश्यकता।	,,
,,	57.	**डा० लक्ष्मीनरायन पाण्डये**	रेलवे बोर्ड में प्रशासनिक अनियमितताएं रोकने तथा अकुशलता को दूर करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
,,	58.	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा समय पर घोषित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	59.	,,	विभिन्न जंकशनों पर गाड़ियों की समय सूची में बहुत कम अन्तर होने के कारण उनका मिलान करने में असफलता के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने असफलता।	,,

1	2	3	4	5
1	60.	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डये	रेलवे में रेल सुरक्षा बल द्वारा छुट-पुट चोरियों को रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाए
,,	61.	,,	रतलाम डिवीजन में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर निमित खोमचे वालों द्वारा यात्रियों को चाय और अल्पाहार सप्लाई करने का प्रबन्ध करने में असफलता।	,,
,,	62.	,,	रतलाम डिवीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए अलाट, गरोथ, सुवासरा स्टेशनों पर प्रतिक्षालयों का नवीकरण करने में असमर्थता।	,,
2	75.	,,	रतलाम, जाओरा तथा मन्दसौर स्टेशनों के निकट रेलवे फाटकों के स्थान पर रेल पुलों के निर्माण में विलम्ब।	,,
,,	76.	,,	बरवाडीह (बिहार) तथा रामानुजगंज (मध्य प्रदेश) के बीच रेलवे लाइन के अधूरे कार्य को पूरा करने में विफलता	,,
4	105.	,,	विभिन्न रेलवे कर्मचारियों की मांगों को व्यक्त करने वाले रेल कर्मचारियों के प्रति प्रशासकीय व्यवहार में दमनकारी नीति का त्याग करने में असफलता।	,,
,,	106.	,,	लोको कर्मचारियों की उचित मांगों की पूर्ति में असफलता	,,
,,	107.	,,	रेलवे सिगनेलर्स (टेलीग्राफिस्ट्स) की मांगों की पूर्ति में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
4	108.	डा० लक्ष्मीनरायण पाण्डये	देहरादून एक्सप्रैस में रतलाम-दिल्ली कोच लागाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
,,	109.	,	राजधानी एक्सप्रैस को जनता की मांग होते हुए भी रतलाम पर यात्रियों के लिए ठहराने में असफलता।	,,
,,	110.	,,	रतलाम डिवीजन के अनेक कर्मचारियों की सिनीयारिटी तथा ग्रेडेशन सम्बन्धी मामलों के निपटारे में जानबूझ कर विलम्ब।	,,
,,	111.	,,	रेलवे बोर्ड की प्रशासनिक अनियमितता एवं क्षमता को दूर करने में असफलता	,,
,,	112.	,,	रतलाम डिवीजन के गरोठ, बडायला, नौगांवा तथा अनेक अन्य स्टेशनों पर बिजली की सुविधा का अभाव।	,,
,,	113.	,,	मंदसोर (रतलाम डिवीजन) स्टेशन पर (निर्गम आगम के लिए प्लेटफार्म की ओर) दो बड़े फाटकों की व्यवस्था का अभाव।	,,
,,	114.	,,	((रतलाम डिवीजन) कचनारा फ्लैग स्टेशन को पूर्णरूपेण स्टेशन में बदलने में विलम्ब।	,,
,,	115.	,,	रतलाम डिवीजन के नागदा (बिरलाग्राम) में ग्वालियर रेयन द्वारा डेमरेज देते हुए जानबूझ कर वैगनों को समय पर खाली न करने की प्रवृत्ति को रोकने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
4	116.	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डये	दिग्विजय इण्डस्ट्रीज बांगरोद (रतलामडिवीजन) द्वारा लोड किए जाने वाले माल को लोड के पहले न तोलना, भुगतान करने की वृत्ति को रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	117.	,,	मध्य प्रदेश के रतलाम डिवीजन में बिजली पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी रेलगाड़ियों का विद्युतिकरण करने में असफलता।	,,
,,	118.	,,	रतलाम डिवीजन में अजमेर-खण्डवा मीटर गेज लाइन के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कंडक्टरों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	119.	,,	रेल सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी भाषी उम्मीदवारों की अवहेलना।	,,
,,	120.	,,	रेल सेवा आयोग के क्षेत्रीय आधार पर गठन तथा कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता।	,,
,,	121.	,,	जनता की मांग के बावजूद देहरादून एक्सप्रैस को बांगरोद स्टेशन (रतलाम डिवीजन) पर रोकने में असफलता।	,,
,,	122.	,,	मध्य प्रदेश के झाबुआ, बस्तर और सटगुजा जैसे आदिक्षेत्रों में रेल सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	123.	,,	यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा वृद्धि न देते हुए यात्री किराए मे वृद्धि।	,,

1	2	3	4	5
4	124.	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :	छोटे स्टेशनों पर पर्याप्त मात्रा में वैगन सप्लाई करने में असफलता।	
,,	125.	,,	एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल पहुंचाने की अवधि निर्धारित होते हुए भी उसका पालन न करना तथा कई बार महीनों पश्चात् भी माल न पहुँचने की प्रवृत्ति को रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
,,	126.	,,	वर्क लोड होते हुए रतलाम डिवीजन के मंदसौर, जाओरा, रतलाम तथा अन्य स्टेशनों पर कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाना तथा ओवर टाइम में काम करवाना ?	,,
,,	127.	,,	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की मांगों पर उपेक्षापूर्ण कार्यवाही तथा उनके साथ दमनात्मक नीति।	,,
,,	128.	,,	अजमेर-खण्डवा मार्ग पर यात्रियों के लिए नई किस्म के यात्री-शयन-यान चलाने में विलम्ब तथा उपेक्षा।	,,
5	144.	,,	रतलाम-नीमच के बीच एक शटल ट्रेन चलाने में असफलता।	,,
,,	145.	,,	अजमेर-खण्डवा के मध्य एक मेल ट्रेन चलाने में असफलता।	,,
10	153.	,,	नीमच, रतलाम, तथा महू स्थित रेलवे कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी समस्या हल करने में असफलता।	,,
,,	154.	,,	रतलाम डिवीजन के मंदसौर, नीमच, जावरा, शामगढ़ नागदा तथा अन्य स्थानों के लिए	,,

1	2	3	4	5
			रेल कर्मचारियों को समय पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने में विलम्ब।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाय।
14	173	,,	चित्तौड़-कोटा रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा करने में असफलता।	,,
,,	174.	,,	दोहद-खण्डवा रेल लाइन की जनता की मांग को पूरा करने में असफलता।	,,
22	181.	,,	रतलाम डिवीजन में गत दो वर्षों में हुए अनेक दुर्घटनाग्रस्त लोगों को उचित मुआवजा देने में विलम्ब।	,,
,,	182.	,,	विभिन्न रेलों में बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को टालने में असफलता।	,,
1	183.	श्री डी० के० पेडा :	रेल कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	184.	,,	औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों के पक्ष में नीति अपनाने में असफलता।	,,
,,	185.	,,	रेल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों तथा प्रबन्धकों के बीच हुए विभिन्न समझौतों को निर्धारित अवधि के अन्दर क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	186.	,,	वैगनों का उचित उपयोग करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप भारी हानि हुई है।	,,
,,	187.	,,	देश के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल रेलों सम्बधी नीति का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	188.	**श्री डी० के० पण्डा :**	दक्षिण-पूर्व रेलवे के गैंगमैनों के वेतन में संशोधन करने तथा नैमितिक श्रमिकों को स्थायी बनाने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपए कर दी जाए
,,	189.	**डा० लमीनारायण पाण्डेय :**	मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों से प्रोफैशनल टैक्स लेने की त्रुटिपूर्ण कार्य-वाही को रोकने में बोर्ड की असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाए।
,,	190.	,,	रेल कर्मचारियों को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में असफलता।	,,
,,	205.	**श्री डी० के० पण्डा :**	दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय उड़ीसा की नई राजधानी भुवनेश्वर में बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	206.	,,	उड़ीसा में बांसपानी-जाखापुरा, टालचेर-बिमलगढ़ और ताल-चेर-सम्बलपुर रेलवे लाइनों का अप्रैल, 1974 रेल निर्माण कार्य आरम्भ करने की आ-वश्यकता।	,,
,,	207.	,,	उड़ीसा में खुर्दा रोड़-फलबनी ओर जाजापुर होते हुए जाजा-पुर रोड से चंदावलीपत्तन रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य अप्रैल, 1974 तक आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	208.	,,	उड़ीसा में भद्रक-चंदावली पोर्ट, जहयापुर रोड-कियोंझारबर्जा-मिंदा रेलवे लाइनों पर अप्रैल, 1974 तक निर्माण-कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	209.	**श्री डी० के० पण्डा :**	गोपालपुर-पोर्ट-बरहानपुर-अस्का-भंजननगर-फुलबनी-बालागीर रेलवे लाइन पर, जिसका 1946 में सर्वेक्षण हो चुका था, इस वर्ष निर्माण कार्य आरंभ करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें
,,	210.	,,	उत्कल एक्सप्रैस को सप्ताह में दो बार चलाने की बजाय रोज चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	211.	,,	पारलाकिमड़ी-गुनुपुर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में तुरंत बदलने की आवश्यकता।	,,
,,	212.	,,	उड़ीसा में पलासा-खर्दा रोड शटल गाड़ी को भद्रक तक (319 अप/820/डाउन) बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	213.	,,	उड़ीसा में कटक में मालगोडाउन और शिखरपुर गेट पर उपरी पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	214.	,,	उड़ीसा में कटक रेलवे स्टेशन का सभी आधुनिक सुविधाओं सहित-पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	215.	,,	उड़ीसा में हावड़ा-हैदराबाद एक्सप्रैस गाड़ी पर डाक डिब्बे लगाने की आवश्यकता।	,,
,,	216.	,,	उड़ीसा में कटक और बरहानपुर रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं देने की आवश्यकता।	,,
2	217.	**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**	मध्यप्रदेश में नई रेल लाइनों की संभावनाओं को परीक्षित करने मे विलम्ब।	,,

1	2	3	4	5
2	218.	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :	रतलाम के डीजलशेड के विस्तार कार्य को अधिक त्वरित गति से पूरा करने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
1	219.	,,	उदयपुर-शादड़ी लाइन को नीमच तक विस्तार करने के बारे में सर्वेक्षण करने तथा आगे कार्य-वाही करने में विलम्ब ।	,,
,,	220.	,,	उज्जैन-इन्दौर ब्राडगेज लाइन को महु तक विस्तार करने में असफलता ।	
4	221.	,,	विभिन्न मालगाड़ियों में गार्ड केबिनों की बुरी दशा में सुधार करने में असफलता ।	,,
,,	222.	,,	रतलाम डिवीजन के गार्डों को आवश्यक सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
7	238.	,,	कोयले की चोरी को रोकने में विफलता ।	,,
,,	239.	,,	कोयले की कमी के बहाने से रतलाम डिवीजन की कई गाड़ियों के बार-बार रद्द किए जाने के कारण जनता को हुई असुविधा ।	
10	240.	,,	रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हितों के संरक्षण हेतु बनाए गए संघों को मान्यता न देकर कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा ।	,,
,,	241.	,,	टी०टी०ई०, गार्डों तथा सिगनलरों की आवास, काम के घंटे तथा मूल्य वृद्धि के अनुरूप वेतन निर्धारण जैसी उचित मांगों के प्रति उपेक्षा ।	,,
13	242.	,,	नीमच के लोको शेड का विस्तार करने में विलम्ब ।	,,

1	2	3	4	5
13	243.	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :	अजमेर खण्डवा रेल लाइन को मेल गाड़ियां चलाने के लायक बनाने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
13	244.	,,	रतलाम-बांसवाँड़ा-डौंगापुर रेल लाइन के निर्माण की संभावना के प्रति उदासीनता ।	,,
1	262.	श्री रानेन सेन :	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में डमडम जंकशन और बान-गांव के बीच दोहरी लाइन बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1रु० कर दी जाये ।
,,	263.	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में बानगांव-हसनाबाद और रानाधार--बानगांव सैक्शनों में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में असफलता ।	,,
,,	264.	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में यात्रियों के अपराधों को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	265.	,,	भारतीय रेलों में वैगनों की तोड़फोड़, चोरी तथा सार्व-जनिक सम्पत्ति की हानि को रोकने में असफलता ।	,,
,,	266.	,,	पूर्व रेलवे में रेलवे के कुछ कर्म-चारियों तथा रेल सुरक्षा दल के बीच सांठगांठ ।	,,
,,	267.	,,	हावड़ा--सियालदह सैक्शनों में पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवों पर रेल डिब्बों में भीड़भाड़ कम करने में असफलता ।	,,
,,	268.	,,	हावड़ा तथा सियालदह स्टेशनों पर भीड़ कम करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	269.	**श्री रानेन सेन :**	गाड़ियों के गंतव्य स्थानों पर विलम्ब से पहुंचने को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।
4	270.	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**	मानसा आउटर एजेंसी के कांट्रेक्टर की अनियमितताओं तथा गलत कार्यों की जांच कराने तथा स्थिति को ठीक करने में सरकार की असफलता ।	,,
,,	271.	,,	अजमेर–खण्डवा लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं जैसे पानी, सफाई, बिजली आदि की समुचित व्यवस्था प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	272	,,	यात्री रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले भोजन के स्तर में निरन्तर गिरावट ।	,,
,,	273.	,,	अजमेर–खण्डवा लाइन पर यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए पर्याप्त गाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
,,	274.	,,	रतलाम–दिल्ली तथा रतलाम-बम्बई के मध्य यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त यात्री ट्रेन चलाने की मांग पूरी करने में असफलता ।	,,
1	275.	**श्री रामावतार शास्त्री :**	आल इण्डिया रेलवे ऐम्पलाइज कंफैडरेशन का रल कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	
,,	276.	,,	आल इण्डिया स्टेशन मास्टरज् एसोसिएशन को भारतीय रेल में कार्य करने वाले स्टेशन	,,

1	2	3	4	5
			मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाए ।
1	277.	**श्री रामावतार शास्त्री :**	इण्डियन रेलवे लोको मिकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन को भारतीय रेल में कार्य कर रहे लोको मिकेनिकल स्टाफ के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में असफलता ।	,,
,,	278.	,,	आल इण्डिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	279.	,,	आल इण्डिया कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	280.	,,	आल इण्डिया मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन को भारतीय रेलों के मन्त्रालयों कर्मचारियों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	281.	,,	आल इण्डिया सिगनल एण्ड टैलिकम्यूनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	282.	,,	आल इण्डिया ट्रेन एक्जामिनर वैल्फेयर कमेटी को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	283.	,,	आल इण्डिया रेलवे कर्मशियल क्लर्कस् एसोशिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	284.	श्री रामावतार शास्त्री	इण्डियन रेलवे चेंकिंग स्टाफ एसोशिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।
,,	285.	,	आल इण्डिया गार्ड कोंसिल को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	286.	,,	इण्डियन रेलवे पर्मानेन्ट वे स्टाफ एसोसियेशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	287.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में पूर्वोत्तर रेल मजदूर संगठन को कर्मचारियों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	288.	,,	उत्तर रेलवे में उत्तर रेलवे वर्कर्स यूनियन को कर्मचारियों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	289.	,,	ईस्टर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	290.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	291.	,,	दक्षिण मध्य रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	292.	,,	पश्चिम रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	293.	,,	दक्षिण रेलवे लेबर यूनियन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	294.	,,	रेल कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करने और रेलवे में औद्योगिक शान्ति रखने के	,,

1	2	3	4	5
			लिये उपाय सुझाने के विषय पर चर्चा करने के लिये मान्यता प्राप्त दो फैडरेशनों, आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कन्फेडरेशन तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की यूनियनों और एसोसिएशनों की एक औपचारिक बैठक बुलाने की आवश्यकता ।	
4	295.	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय रेलों में प्रतीक्षा गृहों में बैरों को वर्दियों देने में असफलता ।	राशिमे से 100 रुपए घटा दिये जायें ।
,,	296.	,,	गरहरा–बरौनी और उससे 20 किलोमोटर की दूरी के बीच कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को प्रायोजना भत्ता देने के लिये मंजूरी देने में असफलता ।	,,
,,	297.	,,	रेल दावे निवारण समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय रेलों में ट्रैनशिपमेंट रोड के कर्मचारियों को भत्ता देने में असफलता ।	,,
,,	298.	,,	टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के समय उनके जीवन की रक्षा करने में असफलता ।	,,
,,	299.	,,	डकैतों और समाज विरोधी तत्वों के आक्रमणों से बचाव के लिये जांच करने वाले कर्मचारियों को जीवन की सुरक्षा के लिये उन्हें रिवाल्वर देने में असफलता ।	,,
,,	300.	,,	भारतीय रेलों के सभी मेकेनिकल, कैरिज सिगनल, यार्ड और	,,

1	2	3	4	5
			केन कर्मचारियों को ठण्डी और गर्म वर्दियां देने की आवश्यकता ।	
4	301.	**श्री रामावतार शास्त्री**	खलासियों की ड्यूटी का समय नियम करने की आवश्यकता ताकि वे ट्रेड टैस्ट दे सकें ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	302.	,,	भारतीय रेलों में रनिंग स्टाफ के लिये 10 घंटे की ड्यूटी को पूरी तरह लागू करने में आसफलता ।	,,
,,	303.	,,	चीनी आक्रमण के पश्चात् रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी में की गई कमी को पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	304.	,,	भारतीय रेलों में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों को रनिंग स्टाफ घोषित करने में असफलता ।	,,
,,	305.	,,	पटना अथवा दानापुर में रेल सेवा आयोग का पूरा कार्यालय खोलने में अफसलता ।	,,
,,	306.	,,	दानापुर में दावे सम्बन्धी कार्यालय खोलने में असफलता ।	,,
,,	307.	,,	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में रेल सेवा आयोग के मुख्यालय को कटिहार में स्थापित करने में असफलता ।	,,
,,	308.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर, नरकटिया गंज, इज्जत नगर और वाराणसी में रेलवे हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
4	309.	**श्री रामावतार शास्त्री**	भारतीय रेलों में चलने वाले टिकट निरीक्षकों को रनिंग रूम सुविधायें देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	310.	,,	भारतीय रेलों में महाप्रबन्धकों और अन्य अधिकारियों को, अमान्यताप्राप्त यूनियनों/ऐसोसियेशनों से ज्ञापन प्राप्त करने और उनके प्रतिनिधियों से मिलने के बारे में हिदायतें देने में असफलता ।	,,
,,	311.	,,	माल और पार्सल चढ़ाने और उतारने के लिये ठेके की वर्तमान पद्धति को समाप्त करने और इस कार्य के लिये नियमित कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	312.	,,	रेलों में कार्य के लिये ठेके की वर्तमान व्यवस्था समाप्त करने और विभाग द्वारा ही अनुरक्षण और निर्माण कार्य किये जाने की आवश्यकता ।	,,
1	313.	,,	भारतीय रेलों में गैर-सरकारी ठेका पद्धति को समाप्त करने तथा विभागीय खान-पान व्यवस्था चालू करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी दी जाये ।
,,	314.	,,	शत-प्रतिशत रेल कर्मचारियों को आवास प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	315.	,,	भारतीय रेलों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्त्ती पर लगे प्रतिबंध हटाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	316.	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय रेलों की वर्कशापों में कर्मचारियों की भर्त्ती पर लगे प्रतिबंध हटाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	317.	,,	गाड़ियों में सफाई, रोशनी और पीने के पानी का अभाव ।	,,
,,	318.	,,	रेलवे में अपव्यय को रोकने में असफलता ।	,,
,,	319.	,,	मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही रेलों का राष्ट्रीय-करण करने में असफलता ।	,,
,,	320.	,,	बिहार में फतूहा–इस्लामपुर और आरा–सहसराम लाइट रेलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
,,	321.	,,	कर्मचारियों के वेतनमान निर्धा-रित करने और उनके स्थाना-न्तरण करने की त्रुटिपूर्ण पद्धति ।	,,
,,	322.	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	322.	,,	मीटर लाइनों को वड़ी लाइनों में बदलने में असफलता ।	,,
,,	324.	,,	रेलों के समुचित विकास के लिए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक योजना बनाने में असफलता ।	,,
,,	325.	,,	रेलवे बोर्ड के नौकरशाही ढंग को बदलने में असफलता ।	,,
,,	326.	,,	रेलों में उच्च बोझिल प्रशासन को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	327.	,,	आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कन्फेडेरेशन और पी० एन० एम० में कैटेगोरिकल यूनियन/	,,

1	2	3	4	5
			एसोसिएशनों को प्रतिनिधित्व देने में असफलता ।	
1	328.	**श्री रामावतार शास्त्री**	आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कन्फेरेडेशन और कैटेगोरिकल यूनियन/एसोसिएशनों को रेल प्रशासन के साथ सभी स्तरों पर बात-चीत करने की सुविधाएं देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	329.	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक स्थान देने के लिए वातानुकूल और पहले दर्जे को समाप्त करने तथा केवल तीसरे दर्जा बनाये रखने में असफलता ।	,,
,,	330.	,,	भारतीय रेलों में भोजन यानों को बनाये रखने और सामान्य यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य गाड़ियों में ऐसी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
,,	331.	,,	भारतीय रेलों में आकस्मिक और एवेजी कर्मचारियों को नियमित बनाने में असफलता ।	,,
,,	332.	,,	भारतीय रेलों में संविदा श्रम पद्धति को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	333.	,,	विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारियों को वर्दी देने में असफलता ।	,,
,,	334.	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों के किरायों में 5 पैसे से 8 रुपए तक की वृद्धि ।	,,
,,	335.	,,	भाड़ा प्रभारों के सम्बन्ध में भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारियों को दी गई रियायतों को सीमित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	336.	**श्री रामावतार शास्त्री :**	भारतीय रेलों के स्टोरों में अनुपयोगी वस्तुओं का रखा जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	337.	,,	रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी मानकर उन्हें बातचीत के अधिकार सहित सभी कार्मिक संघ अधिकार देने में असफलता ।	B
,,	338.	,,	सभी रेल कर्मचारियों का पुनर्वर्गीकरण करके और सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी के वेतन को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतनमान कार उनका दर्जा पुन: निर्धारित करके एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से उनके कार्य का मूल्यांकन करने में असफलता ।	C
,,	339.	,,	रेल कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन होने तथा उनका पुनर्वर्गीकरण होने तक उनको केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों, अर्थात् हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भोपाल हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन के बराबर वेतन देने की आवश्यकता ।	D
,,	340.	,,	6 महीने की अवधि में प्रति चार अंकों की वृद्धि के कारण मूल्यों में हुई वृद्धि को पूर्णतया निष्प्रभावी करने हेतु जीवनयापन मूल्य सूचकांक में मंहगाई भत्ते को जोड़ने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	341.	श्री रामावतार शास्त्री	वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए एक महीने के वेतन की दर से बोनस देने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	342.	,,	सभी आकस्मिक रेल कर्मचारियों को नियमित बनाकर तथा सेवा में स्थायी बनाकर उन्हें भूत-लक्षी प्रभाव से सभी लाभ देने की आवश्यकता ।	,,
,,	343.	,,	विभागीय दुकानों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की आवश्यकता ।	,,
,,	344.	,,	भारतीय रेलों में उत्पीड़न के सभी मामलों की वापस लेने की आवश्यकता ।	,,
,,	345.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में लोको रनिंग कर्मचारियों की गिरफ्तारी और उनके उत्पीड़न को रोकने में असफलता ।	,,
,,	346.	,,	आल इन्डिया स्टेशन मास्टरस् एसोसिएशन तथा डिविजनल रेलवे इम्पलाईस कोआर्डनेशन कमेटी, धनबाद के नेताओं की कार्मिक संघ गतिविधियों के कारण उनके अन्तमंडलीय स्थानान्तरण को रद्द करने में असफलता ।	,,
,,	347.	,,	इण्डियन रेलवे लोको मकैनिकल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा चलाये गये नियमानुसार कार्य-आन्दोलन के सम्बन्ध में लोको मकैनिकल कर्मचारियों के	,,

1	2	3	4	5
			विरुद्ध निलम्बन, स्थानान्तरण तथा उत्पीड़न सम्बन्धी अन्य सभी आदेशों को वापस लेने की आवश्यकता ।	
4	348.	**श्री रामावतार शास्त्री**	भारतीय रक्षा नियमों तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन न्यायालय मामलों को वापस लेने तथा इन्डियन रेलवे लोको मकैनिकल स्टाफ एसोसिएशन, वेस्टर्न जोन, के पदाधिकारियों सहित सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने की आवश्यकता ।	**राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।**
1	363.	**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**	लोको शेडों में पुराने औजारों और संयंत्रों के स्थान पर आधुनिक औजार और संयंत्र प्रतिस्थापित करने में असफलता ।	,,
,,	364.	,,	रेला कर्मचारियों के लिए अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	365.	,,	ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त करने में असफलता ।	
,,	366.	,,	अमान्यता प्राप्त संघों के साथ सामूहिक सौदाबाजी करने से इन्कार ।	,,
,,	367.	,,	रद्दी लोहे का निलाम करने के बजाय उसे लाने के लिए ढलाई घर खोदने में असफलता	,,
,,	368.	,,	पेंशन योजना के लिए विकल्प देने के लिए कर्मचारियों को एक और अवसर प्रदान करने के आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	369. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**	संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए गुप्त मतदान का तरीका अपनाने की आवश्यकता ।		राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	370.	रेलवे बोर्ड तथा उच्च बोझिल प्रशासन को समाप्त करने में असफलता ।		,,
,,	371. ,,	उन आकस्मिक श्रमिकों को, जो लम्बी अवधि तक की सेवा करने के पश्चात् नियमित होने के समय चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य पाये गये, वैकल्पिक नौकरियां देने में असफलता ।		,,
,,	372. ,,	ब्रिटिश राज के दौरान स्वतंत्रता सांग्राम में भाग लेने के कारण उत्पीड़ित रेलवे कर्मचारियों की बहाली करने में असफलता ।		,,
,,	373. ,,	वर्ष 1947, 1948 और 1949 में कार्मिक संघ गतिविधियों के कारण उत्पीड़ित कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने में असफलता ।		,,
,,	374. ,,	देश में वैगनों की मांग की पूर्ति के लिए रेलवे वैगन निर्माण कर्मशालाओं का विस्तार करने और नई कर्मशालाएं खोलने में असफलता ।		,,
,,	375. ,,	विभिन्न रेल कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करनें में असफलता ।		,,
,,	376. ,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता ।		,,
,,	377. ,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।		,,

1	2	3	4	5
1	378.	**श्री एस० ए० मुरुगनतम**	सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार रेलों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया करदी जाये ।
,,	379.	,,	लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे की ड्यूटी लागू कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	380.	,,	हड़ताल के समय रनिंग कर्मचारियों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	381.	,,	हड़ताल समाप्त करने के लिए रेलों में प्रादेशिक सेना के प्रयोग को रोकने में असफलता ।	,,
,,	382.	,,	रेल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन के बराबर लाने में असफलता ।	,,
,,	385.	,,	रेलवे वैगन अलाट करने में चल रहे भारी भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
4	398.	**श्री रामावतार शास्त्री**	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में उचित तथा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाये जाने की आवश्यकता ताकि गलत व्यक्तियों की भर्ती को रोका जा सके जैसा कि इस समय हो रहा है ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।
,,	399.	,,	स्थानांतरण और पदोन्नति के लिए एक सुनिश्चित और उचित नीति तैयार करने तथा पक्षपात पूर्ण और भ्रष्ट ढंग से की गई सभी स्थानापन्न पदोन्नतियों को रोकने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
4	400.	**श्री रामावतार शास्त्री**	भ्राष्ट और साम्प्रदायिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, कम से कम सेवा से बर्खास्तगी की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	401.	,,	रेल कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों के सहयोग से कर्मचारियों को उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों, और कर्तव्यों सम्बन्धी जानकारी देने के-लिए कारगर व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
14	402.		पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की आवश्यकता ।	,,
,,	403.	,,	पटना में रेलगाड़ियों के गतिरोध को रोकने के लिए मीठापुर रेल क्रांसिंग पर पक्का ऊपरी पुल बनाने में विफलता ।	,,
,,	404.	,,	गाड़ियों के विलम्ब से चलने को रोकने के लिए पूर्व रेलवे में पटना से गया तक दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
,,	405.	,,	फर्रका के रास्ते किऊल से कलकत्ता तक दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	
,,	406.	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल को चौड़ा करने में असफलता ।	,,
,,	407.	,,	भीड़-भाड़ को रोकने के लिये दानापुर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान ऊपरी पुल के पूर्व में एक नया पैदल ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
14	408.	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्व रेलवे के दानापुर (खगौल) स्टेशन पर विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रू० घटा दिये जायें ।
,,	409.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के थाना बीहपुर स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	410.	,,	पूर्व रेलवे के निग्रौरा स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	411.	,,	पटना जंक्शन स्टेशन के विकास के लिए तुरन्त कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
,,	412.	,,	पूर्व रेलवे के निग्रौरा स्टेशन पर लकड़ी का ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	413.	,,	पूर्व रेलवे में निग्रौरा स्टेशन पर पार्सल कार्यालय खोलने में विफलता ।	,,
,,	414.	,,	पूर्व रेलवे के बीहटा स्टेशन से बिक्रम, पालीगंज, अरवाल और कुर्था के रास्ते जहांनाबाद तक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	,,
,,	415.	,,	पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन पर मुगलसराय से आसनसोल तक विद्युतीकरण करने में विफलता ।	,,
,,	416.	,,	पटना जंक्शन स्टेशन के उन प्लेटफार्मों पर, जहां से गया और रांची के लिए गाड़ियां चलती हैं, शेड बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	417.	,,	पटना आर० एम० एस० के सामने स्टेशन पर रोड बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
14	418.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन स्टेशन पर गंदी बस्तियों की सफाई की आवश्यकता ।	राशी में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
,,	419.	,,	पटना के राजेन्द्र नगर स्टेशन पर यात्री गाड़ियों के रूकने की आवश्यकता ।	,,
,,	420.	,,	विहटा स्टेशन से डाल्टनगंज तक औरंगाबाद होते हुए एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	421.	,,	पूर्व रेलवे के जहांनाबाद स्टेशन से राजगीर तक एकनगर सराय होते हुए नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	422.	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन से डेहरी-आन-सोन तक नहर के साथ एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता जिसका वहुत पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका था ।	,,
,,	423.	,,	पूर्व रेलवे पर वांका घाट स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	424.	,,	पूर्व रेलवे पर फुलवारी शरीफ स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	425.	,,	पूर्व रेलवे पर परसा, पोठही, नदवां, नदौल, लारेगना स्टेशनों पर शेड और पीने के पानी की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	426.	,,	पूर्व रेलवे के गुलजारबाग स्टेशन के दोनों ओर शेड बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
14	427.	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्व रेलवे पर सदाशिवपुर स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।
,,	428.	,,	पूर्व रेलवे पर सदाशिवपुर स्टेशन में शेडों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	429.	,,	मध्य प्रदेश में रीवा जिले को रेल लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता ।	,,
,,	430.	,,	पूर्व रेलवे पर विहटा स्टेशन में यातायात की कठिनाई समाप्त करने के लिए एक पक्के ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	431.	,,	पूर्व रेलवे पर पटना-गया लाइन पर नदौल हाल्ट स्टेशन का दर्जा बढ़ा कर पूर्ण स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	432.	**श्री दीनेन भट्टाचार्य**	रेलों में उच्च बोझिल प्रशासन पर व्यय को कम करने में सरकार की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	433.	,,	रेल कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन लागू करने में असफलता ।	,,
,,	434.	,,	पूर्व रेलवे में रेल यात्रियों के जन तथा धन की सुरक्षा की गारंटी देने में असफलता ।	,,
,,	435.	,,	पूर्व रेलवे में ई० एम० यू० कोचों के समुचित रख-रखाव में असफलता ।	,,
,,	448.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पुराना बाजार (सदरथाना के निकट) सिलिगुड़ी में एक ऊपरी पुल	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
			का निर्माण करने में असफलता ।	
1	449.	श्री रामावतार शास्त्री	डी० एच० रेलवे में दार्जिलिंग में मालगोदाम क्षेत्र की नियमित रूप से सफाई रखने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	450.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में विशेषकर मांशी-सहरसा, कटिहार-मांसा और कटिहार-सिलीगुड़ी सेक्शनों पर यात्रियों के माल असबाब की चोरी को रोकने में विफलता ।	
,,	451.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवेमें रनिंग स्टाफ के लिए 10 घंटे की ड्यूटी को लागू करने में विफलता ।	,,
,,	452.	,,	बरौनी से मुगलसराय और वापसी के लिए सीधी यात्री गाड़ी अथवा शटल गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	453.	,,	वर्ष भर गया से पटना तक रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकने वाली और सुबह 6 बजे पटना पहुंचने वाली गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	454.	,,	पटना से जहांनाबाद और वहां से वापसी के लिए उस शटल गाड़ी को पुनः चलाने की आवश्यकता जिसे लोको रनिंग स्टाफ के पिछले आन्दोलन के दौरान बन्द कर दिया गया था ।	,,
,,	455.	,,	आल इण्डिया टीचर्स एसोसिएशन और इण्डियन पीपल्स थियेटर एसोसिएशन सहित सभी	,,

1	2	3	4	5
			सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों को यात्रा किराये में छूट देने की आवश्यकता।	
1	456.	श्री रामावतार शास्त्री	भारत साधु समाज और भारत सेवक समाज को दी गई पास सम्बन्धी सुविधाओं को वापस लेने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	457.	,,	नियमों के अन्तर्गत की गई व्यवस्थानुसार रेलों को कोयले की सप्लाई करने में विफलता।	,,
,,	458.	,,	सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को पेंशन की अदायगी में अनियमितताओं और असाधारण विलम्ब को रोकने में असफलता।	,,
,,	459.	,,	जमालपुर रेलवे वर्कशाप से पीतल और अन्य वस्तुओं की चोरी और उठायीगीरी को रोकने में असफलता।	,,
,,	460.	,,	जमालपुर रेलवे वर्कशाप में चोरी और उठायीगीरी की घटनाओं में रेल अधिकारियों की सांठ-गांठ।	,,
,,	461.	,,	अमान्य प्राप्त यूनियनों के साथ सामूहिक समझौते करने की आवश्यकता।	,,
,,	462.	,,	गुप्त मताधिकार के आधार पर कर्मचारियों के प्रतिनाधयों की भागीदारी के साथ रेलवे प्रबन्ध तथा प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने में असफलता।	,,
,,	463.	,,	उन सभी मजदूरों को जो 5 से लेकर 20 वर्षों से ठेकेदारों के	,,

1	2	3	4	5
			अधीन कोयले का काम कर रहे हैं, स्थायी घोषित करने में असफलता ।	
1·	464.	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में कोयला तथा राख के काम ठेकेदारी की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	465	,,	नैमन्तिक तथा एवजी रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
,,	466.	,,	मजदूर वर्ग विरोधी रुख अपनाने तथा रेल अस्पताल, धनबाद के कुप्रबन्ध के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाही करने में में असफलता ।	,,
,,	467.	,,	भारतीय रेलों में उच्च अधिकारियों के वेतन को कम करने में असफलता ।	,,
,,	468.	,,	तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को पर्याप्त तथा कीमती दवाइयां सप्लाई करने और अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	469.	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	470.	,,	रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध एक संसद सदस्य द्वारा गत वर्ष लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	471.	श्री रामावतार शास्त्री	रेल अधिकारियों द्वारा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से घरों में काम लेकर उनका दुरुपयोग करना ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
4	472.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	शेवरफूली-तारकेश्वर और बन्देल-कटवा खण्ड में दोहरी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
4	473.	,,	हावड़ा स्टेशन को उचित रूप से साफ रखने तथा यात्री गाइडों की अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	474.	,,	पूर्व रेलवे में हावड़ा और बान्डैल के बीच उपमार्ग को चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	475.	,,	पूर्व रेलवे के सेरामपुर और शेवड़ा-फुली सेक्शनों के बीच रेल-गाड़ियों के पहुंचने और रवाना होने की घोषणा करने के लिए लाउडस्पीकरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	476.	,,	पूर्व रेलवे के सियाल्दह-बोगांव, सियाल्दह-नैहाटी और हावड़ा-बान्डेल सैक्शनों में अधिक शटल रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	477.	,,	जी० टी० रोड को पार करने के लिए सेरामपुर फाटक के दक्षिणी भाग पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
1	478.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	रेलवे बोर्ड के नौकरशाही और तानाशाही ढंग को समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1	479.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन	लोको रनिंग कर्मचारियों को दिये गये वचन के अनुसार उनके लिए 10 घंटे की ड्यूटी का दिवस लागू करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	480.	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	481.	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता।	,,
,,	482.	,,	रेलों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	483.	,,	रेलों में बढ़ती हुई चोरी को रोकने में असफलता।	,,
,,	484.	,,	कार्मिक संघों को लोक तंत्रीय ढंग से मान्यता प्रदान करने में असफलता।	,,
,,	485.	,,	पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई लाईनों के निर्माण के मामले में एक नया दृष्टिकोण अपनाने में असफलता।	,,
,,	486.	,,	कतिपय क्षेत्रों के असन्तुलित आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर तथा ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने के लिए नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	487.	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों के रेल किरायों में भारी वृद्धि को कम करने की आवश्यकता।	,,
,,	488.	,,	रेलवे के उच्चाधिकारियों द्वारा स्पेशल सैलूनों के इस्तेमाल को रोकने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	489.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	केरल में रेलों का विद्युतीकरण करने के लिए केरल में सस्ती दर पर उपलब्ध बिजली का उपयोग करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
,,	490.	,,	देश में विभिन्न खानों के मुहानों से कोयले की ढुलाई के लिए वैगन सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	491.	,,	रेल कर्मचारियों के बच्चों को पर्याप्त और बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	,,
,,	492.	,,	तीसरे दजे के यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
,,	493.	,,	रेल कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित वेतन देने में असफलता ।	,,
,,	494.	,,	रेल कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में असफलता ।	,,
,,	495.	,,	रेलों में आकस्मिक श्रमिकों की सेवा की शर्तों को बेहतर बनाने में असफलता ।	,,
,,	496.	,,	गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता ।	,,
,,	497.	,,	वैगन सप्लाई के संकट को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	498.	,,	रेल कर्मचारियों द्वारा जनता से ली जा रही रिश्वत को रोकने में असफलता ।	,,
2	499.	,,	केरल में वैगन निर्माण कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।

1	2	3	4	5
2	500.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	एक नया रेलवे डिविजन स्थापित करने की आवश्यकता, जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में हो ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	501	,,	रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवासीय क्वार्टर प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
,,	502.	,,	बलियापट्टम, केरल में -रेल-एवं सड़क पुल के क्षतिग्रस्त लकड़ी के तख्तों की, मरम्मत करने की आवश्यकता ।	,,
,,	503.	,,	केरल में बारिशी मौसम के कारण वहां पर मुख्य रेलवे स्टेशनों पर उनकी समूची लम्बाई तक छत डालने की आवश्यकता ।	,,
,,	504.	,,	ओलवक्कोट और कोचीन के बीच दोहरी लाइन बिछाने के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	505.	,,	एर्णाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच बड़ी लाइन विछाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने की आव-श्यकता ।	,,
,,	506.	,,	तेल्लीचेरी स्टेशन पर जयन्ती जनता को रोकने की आव-श्यकता ।	,,
,,	507.	,,	दिल्ली से मंगलौर और कोचीन तक चलने वाली जयन्ती जनता की गति बढाने की आवश्यकता ।	,,
14	508.	,,	एर्णाकुलम और कायमकुलम बरास्ता एलेप्पी के बीच एक रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
14	509.	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	तेल्लीचेरी और मैसुर वरास्ता कुर्ग के बीच एक नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	510.	,,	कोटाय्यम और मदुरै वरास्ता साबरीमाला के बीच एक नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	511.	,,	कुट्टीपुरम और गुरुवायूर के बीच एक नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
				,,
,,	512.	,,	मंगलूर और बम्बई को मिलाते हुए एक नई लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	513.	,,	कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच एक नई लाइन का निर्माण-कार्य को तेज करने की आवश्यकता ।	,,
1	514.	श्री पी० जी० मावलंकर	रेलों के कार्यों को राष्ट्रीय दृष्टि से लोको उपयोगी बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	515.	,,	गुप्त मतदान द्वारा सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की एक तथा न्याय यूनियन बनाने में असफलता ।	,,
,,	516.	,,	रेलों को पक्षपात और राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित कार्मिक संघों से मुक्त रखने में असफलता ।	,,
,,	517.	,,	रेलों को शक्ति की राजनीति और ग्रुप अथवा स्वार्थों या लाभों से मुक्त रखने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	518.	श्री पी० जी० मावलंकर	तत्परता से और उचित ढंग से रेलों का आधुनिकीकरण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	519.	,,	तेजी से विकास कर रहे तकनीकी विश्व में रेलों का विकास करने में असफलता ।	,,
,,	520.	,,	रेलों में कुशल और सुचारु संचालन स्तर बनाये रखने में असफलता ।	,,
,,	521.	,,	रेलों में सभी ओर लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को पर्याप्त मात्रा में कम करने में असफलता ।	,,
,,	522.	,,	रेलों में समस्त प्रशासनिक और संचालक एककों के ढांचे में परिवर्तन करने में असफलता ।	,,
	523.	,,	रेलवे बोर्ड के स्थान पर एक अधिक गतिशील निकाय बनाने में असफलता ।	,,
,,	524.	,,	रेलवे प्रशासन में नौकरशाही और गतिरोध को जो अपनी जड़ें पक्की जमा चुका है रोकने में और उसको बिल्कुल समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	525.	,,	कुशलता को बढ़ाने वाले और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए (सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों के) कार्य के घंटे नियत करने में असफलता ।	,,
,,	526.	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता ।	,,
,,	527.	,,	सेवा निवृत्त सभी रेल कर्मचारियों को कम से कम 40 रुपये प्रति मास पेंशन देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	528.	श्री पी० जी० मावलंकर	ऐसे रेल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने में असफलता जोकि समकक्ष पदों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे कार्य के समान ही कार्य कर रह हैं ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
,,	529.	,,	तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
,,	530.	,,	रेल गाड़ियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करने में असफलता ।	,,
,,	531.	,,	रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदेह बनाने में असफलता ।	,,
,,	532.	,,	रेलों को समय पर चलाने में असफलता ।	,,
,,	533.	,,	कर्मचारियों के दिमागों में यह बहुमूल्य बात बिठाने में असफलता कि वे भी प्रशासन में भागीदार हैं और उनके पदों का भी महत्व है ।	,,
,,	534.	,,	रेलों में अपव्यय को रोकने में असफलता ।	,,
,,	535.	,,	देश भर में माल, विशेषकर कोयला और खाद्यान्न ले जाने के लिए कारगर और मितव्ययी ढंग से माल डिब्बों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	536.	,,	रेलों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं को रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	537.	**श्री पी० जी० मावलंकर**	स्थायी ढंग के कार्यों को करने के लिए अस्थाई श्रमिकों को नियुक्त करने की प्रथा को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	538.	,,	उन अनेक स्थानों पर जहां इस समय बिना चौकीदारों के फाटक हैं, वहां चौकीदारों की व्यवस्था वाले फाटकों का निर्माण करने के लिए क्रमवद्ध योजना लागू करने में असफलता ।	,,
,,	539.	,,	रेल सम्बन्धी कार्यों में नागरिकों और यात्रियों से स्वैच्छिक और सक्रिय सहयोग लेने में असफलता ।	,,
,,	540.	,,	उन दैनिक यात्रियों को जो अपने घरों से 'ए' ग्रेड वाले नगरों और उनके उपनगरों में कार्य के लिये आते हैं और वापिस जाते हैं, टिकटों के किराये में छूट देने की आवश्यकता जैसी कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इस समय है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	541.	,,	नर्सों को ड्यूटी पर जाते समय किराये में उसी प्रकार छूट देने की आवश्यकता जैसे कि विद्यार्थियों को उनके शिक्षा संस्थानों में जाने के लिए दी जाती है ।	,,
,,	542.	,,	तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
1	543.	**श्री पी० जी० मावलंकर**	गुजरात के सावरकांठा जिले में नाडियाड और मुदांसा के बीच शीघ्र ही बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
,,	544.	,,	गुजरात में भावनगर-तारापुर लाइन का निर्माण-कार्य तत्काल आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
,,	545.	,,	बड़ौदा-छोटा उदयपुर की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
,,	546.	,,	अहमदाबाद और बम्बई के बीच विद्युतीकरण कार्य को तत्काल पूरा करने की आवश्यकता ताकि उस रास्ते पर शीघ्र ही विद्युत् चालित गाड़ियों को चलाया जा सके ।	,,
,,	547.	,,	अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण-कार्य को पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	548.	,,	रेल कर्मचारी प्रशिक्षण कालिजों को अधिक धन और सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता ताकि रेलों के संचालन में कुशलता और सुचारिता लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके ।	,,
,,	549.	,,	सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को सुचारु और स्वच्छ रखने की आवश्यकता ।	,,
,,	550.	,,	अधिक फासले वाली एक्सप्रैस गाड़ियों में खान-पान की	,,

1	2	3	4	5
			व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
1	551.	श्री पी० जी० मावलंकर	तीसरी श्रेणी के डिब्बों में अधिक जगह और आराम की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
2	552.	,,	अहमदाबाद के स्टेशन पर वर्तमान रेल प्लेटफार्मों (मुख्य और बड़ी लाइन) का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	553.	,,	अहमदाबाद के निकट साबरमती की रेलवे बस्ती में लोगों के रहने की स्थिति सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
,,	554.	,,	इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की जिन यात्रियों ने अपनी सीटें सुरक्षित की हुई हों, वे इस सुविधा का लाभ बिना किसी रोक-टोक के उठा सकें ।	,,
,,	555.	,,	साबरमती रेलवे बस्ती में पेय जल और शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	556.	,,	अहमदाबाद से कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद के रास्ते वाराणसी तक सीधी रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
,,	557.	,,	अहमदाबाद के निकट बाटवा रेलवे स्टेशन पर शैडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
2	558.	श्री पी० जी० मावलंकर	"नैनपुर" फ्लैग स्टेशन (पश्चिम रेलवे में माहेमदाबाद) का नाम बदलकर "इन्दुलाल याज्ञनिक नगर" करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
,,	559.	,,	कुलियों के लिए रैन बसेरों और रेलवे कैन्टीनों में सस्ते भोजन की व्यवस्था करके उनकी हालत में सुधार करने की आवश्यकता।	,,
,,	560.	,,	कुलियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करने और माल उठाने की वर्तमान दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
,,	561.	,,	अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली एक्सप्रैस गाड़ियों में एक-एक अतिरिक्त कोच लगाने की आवश्यकता।	,,
1	569.	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वोत्तर रेलवे डिपार्टमेन्टल कैटरिंग एण्ड वेंडिंग एसोसिएशन (खानपान तथा खोमचा संघ) को मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	570.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा आयोजित बसंत मेले में धन का दुरुपयोग रोकने में असफलता।	,,
,,	571.	,,	बरौनी जंकशन से बारसोई जंकशन तक कटिहार होते हुए बड़ी लाइन बनाने में असफलता।	,,
,,	572.	,,	कटिहार से कलकत्ता तक एक सीधी एक्सप्रैस गाड़ी चलाने में असफलता।	,,
,,	573.	,,	कर्मचारियों से रेल के नामे पड़ी रकम की वसूली के सम्बन्ध में	,,

1	2	3	4	5
			अनुशासन तथा अपील नियमों का पालन करने में असफलता ।	
1	574.	श्री रामावतार शास्त्री	कटिहार स्टेशन को नये सिरे से बनाने तथा कटिहार स्टेशन में पर्याप्त रेलवे क्वाटरों का निर्माण करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिऐ जाएं ।
,,	575.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में छोटी और बड़ी लाइनों के सेक्शनों में महत्वपूर्ण स्टेशनों तथा डाइनिंग कारों में अन्य रेलों की तरह विभागीय खानपान पद्धति अपनाने में असफलता ।	,,
,,	576.	,,	जनरल मैनेजर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को सम्बोधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 18-1-74 के पत्र के अनुसार कटिहार स्टेशन पर एक विस्तृत खान-पान एकक बनाने में असफलता ।	,,
	577.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में खान-पान की ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	578.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में प्रबन्धक (खान-पान) के पद का दर्जा ऊंचा करने में असफलता ।	,,
,,	579.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सी० एण्ड डब्ल्यू कर्मचारियों, एस० एण्ड टी० कर्मचारियों, खान-पान कर्मचारियों और यातायात कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	580.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सी० एण्ड डब्ल्यू० कर्मचारियों का 40 प्रतिशत तथा एस० एण्ड टी०	,,

1	2	3	4	5
			कर्मचारियों का 60 प्रतिशत दर्जा बढ़ाने में असफलता ।	
1	585.	श्री रामावतार शास्त्री	कटिहार रेलवे अस्पताल में एक पूर्णकालिक दन्तचिकित्सक नियुक्त करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।
,,	586.	,,	प्रत्यावर्तन और निलम्बन के सम्बन्ध में रेल अधिकारियों के गलत निर्णयों के कारण उनसे धन वसूल करने में असफलता ।	,,
,,	587.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में बड़ी लाइन के सैक्शन पर गोहाटी मेल और कामरूप एक्सप्रेस गाड़ियों में विभागीय भोजन-यान लगाने में असफलता ।	,,
,,	588.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 20 प्रतिशत की टी.एक्स.आर. 'सी' की 205-280 रुपये के वेतन मान में पदोन्नति तीन साल की सेवा पूरी करने के पश्चात् कुशल श्रेणी के कर्मचारियों में से करने में असफलता ।	,,
,,	589.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में एक अनुभवी सहायक वाणिज्यिक अधिकारी (सामान्य), जो वाणिज्यिक और खानपान सम्बन्धी जानकारी रखता हो, की नियुक्ति करने में असफलता ।	,,
,,	612.	,,	श्रेणी I और II के लिपिकों के वेतनमानों को मिलाकर एक	,,

1	2	3	4	5
			वेतनमान बनाने में असफलता क्योंकि उन दोनों की एक सी ड्यूटियां हैं ।	
1	613.	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे में सभी रिक्त पदों को भरने तथा उन पदों पर अस्थायी और स्थानापन्न कर्मचारियों को स्थायी करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	614.	,,	रेल प्रशासन की निर्णीत नीतियों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	
,,	615.	,,	लोको शैडों में मिकेनिकल कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में शंकर शरण न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	616.	,,	दुर्घटनाओं को टालने के लिए लोको शैडों में काम करने वाले मिकेनिकल कर्मचारियों के 25 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	617.	,,	चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार उन चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को जिन्होंने भारतीय रेलवे में 5 साल से अधिक सेवा की है, तीसरी श्रेणी में पदोन्नति करने में असफलता ।	,,
,,	618.	,,	रेल सुरक्षा बल की डिब्बे तोड़ने वालों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के साथ, जो रेल संपत्ति की चोरी करते हैं, सांठ-गांठ को रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
,,	619.	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों की रेल के डिब्बे तोड़ने तथा रेल संपत्ति की चोरी में सांठ-गांठ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	620.	,,	मुगल सराय, गया, पटना, धनबाद, जमालपुर, हावड़ा, बरौनी, गरहरा, कटिहार, सिलीगुडी, गोरखपुर, सोनपुर, फुलवारी, शरीफ और नेवरा में दिन दिहाड़े डिब्बों को तोड़े जाने से रोकने में असफलता।	,,
,,	621.	,,	उत्तर पूर्व रेलवे में सोनपुर में उस क्षेत्र के विकास के लिए मंडल अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
,,	622.	,,	भारतीय रेलवे के कोच-परिचरों की उचित मांगों को पूरा करने में असफलता।	,,
,,	623.	,,	भारतीय रेलवे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	624.	,,	रेल कर्मचारियों की लगातार 18 महीने की सेवा के बाद बिना डी० ए० आर० कार्यवाही के उनकी पदोन्नति रोकने के बारे में रेलवे बोर्ड के परिपत्र की क्षेत्रीय रेलवे द्वारा क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	625.	,,	जमालपुर में वचन दिये जाने के बावजूद भी मण्डल अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने में असफलता।	,,
,,	626.	,,	पूर्व रेलवे में दानापुर खगौल में काम करने तथा रहने वाले	,,

1	2	3	4	5
			रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता फिर से देने में असफलता ।	
1	627.	,,	रेल कर्मचारियों से निर्धारित माप-दंड के अनुसार काम देने तथा उनसे 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लेने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	628.	,,	अवर्गीकृत रेल कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	629.	,,	लोको कोयला खालासियों को रेल कर्मचारियों के रूप में मानने की आवश्यकता ।	,,
1	655.	**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**	दक्षिण रेलवे में तूतीकोरिन से नमक भेजने के लिए पर्याप्त संख्या में डिब्बे अलाट करने में असफलता ।	,,
14	656.	,,	दक्षिण रेलवे में तूतीकोरिन से अरुमुगानेरी तक मुत्तियापुरम-मुल्लाकाडु - मुक्कानी - औत्तर होते हुए एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	657.	**श्री रामावतार शास्त्री**	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए नियत किए गए कोटे के अनुसार उन्हें नौकरियां और पदोन्नतियां देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	658.	**श्री रामावतार शास्त्री**	भारतीय रेलों में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य की शर्तों की पूरी जांच करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
1	659.	,,	रेलवे स्टेशनों के फाटकों पर कर्मचारियों के लिए 14 दिन तक लगातार 24 घंटे की ड्यूटी को समाप्त करने में असफलता।	,,
1	660.	,,	रेलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना किराए क्वार्टर देने की आवश्यकता।	,,
1	661.	,,	पश्चिम रेलवे की पटना-गया रेल लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियों में जल, बिजली और सफाई की कमी।	,,
1	662.	,,	समस्तीपुर कालेज को, जिसमें अनेक रेल कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
1	663.	,,	बी० एम० सी० और एफ० आई० सी० के लिए जाब राइटर की आवश्यकता।	,,
1	664.	,,	रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण केंद्रों पर जाते समय अग्रिम यात्रा भत्ता देने की आवश्यकता।	,,
1	665.	,,	प्रत्येक लोको शेड में टूल्ज रूम की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
1	666.	,,	रेलों में गेंगमैनों, कीमैनों और मिस्त्रियों के, कार्यभार को कम करने में असफलता।	,,
1	667.	,,	रेलवे स्टेशनों के सभी फाटकों और लाजेज पर कर्मचारियों के लिए स्टूल अथवा कुर्सियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	668.	**श्री रामावतार शास्त्री**	न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार रेलवे वर्कशापों में कारीगरों को आकस्मिक छुट्टी की सुविधा देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
1	669.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार डिवीजन में प्रतीक्षा गृहों के बैरों को वर्दियां सप्लाई करने में असफलता ।	
1	670.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली, खंड 2, अध्याय 28, पृष्ठ 2833 में निहित नियमों का पालन करने में असफलता ।	,,
1	671.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में खान-पान सम्बन्धी लोक सेवा को सुधारने हेतु उपाय करने के लिए केटरिंग एण्ड वैंडिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ परामर्श करने की आवश्यकता ।	,,
1	672.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की न्यू बानगांव वर्कशाप में उन बी० टी० कर्मचारियों की पदोन्नति करके नियुक्ति करने में असफलता जिन्होंने 1970 में ट्रेड टैस्ट पास कर लिया था ।	,,
1	673.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार में रेलवे हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	674.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लोअर हाफलाँग रेलवे स्टेशन पर खान-पान की व्यवस्था करने वाले विभाग को पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	,,
1	675.	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में दस से बारह वर्ष तक की सेवा पूरी करने के पश्चात् भी खान-पान व्यवस्था से सम्बंधित	,,

1	2	3	4	5
			कर्मचारियों को स्थाई बनाने में असफलता ।	
1	676.	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार न्यू बोनगांव रेलवे स्टेशन पर ठेके की खान-पान व्यवस्था को समाप्त करके विभागीय खानपान व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
1	677.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार स्टेशन पर सार्वजनिक सुविधा के लिए आर० एम० एस० को स्टेशन के बीच से हटा कर एक कोने में करने की आवश्यकता ।	,,
1	678.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों की पदावनति रोकने के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा 9-6-65, 15-1-66 और 22-11-66 को जारी किए गए परिपत्र का पालन करने में असफलता ।	,,
1	679.	,,	रेलवे सतर्कता संगठन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	,,
1	680.	,,	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में इकलाखीम और बलूरघाट के बीच नई रेल लाइन बिछाने में असफलता ।	,,
1	687.	,,	लोको शेडों में कारखाना अधिनियम लागू करने में असफलता ।	,,
1	688.	,,	उत्तर रेलवे के नई दिल्ली मण्डल कार्यालय में स्टेनोग्राफरों के लिए लीव रिजर्व रखने की आवश्यकता ।	,,
1	689.	,,	मकानों के अलाटमेंट के प्रयोजन के लिए स्टेनोग्राफरों को आवश्यक कर्मचारी मानने में असफलता ।	,,
1	690.	,,	दिल्ली में रेल कार्यालयों में जुलाई, 1947 से पहले से काम कर रहे	,,

1	2	3	4	5
			कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर देने में असफलता ।	
1	691.	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों और भूमिहीन कृषि कर्मकारों को रेलवे भूमि देने में असफलता ।	,,
1	692.	,,	रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार डीजल और स्टीम सुपरवाइजरों की संयुक्त वरिष्ठता को बनाए रखने की आवश्यकता, जैसाकि लोको रनिंग कर्मचारियों के मामले में किया जाता है ।	,,
1	693.	,,	गर्मी के मौसम में भारतीय रेलों में सभी लोको शेडों में पीने का ठंडा पानी उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
1	694.	,,	राज्याध्यक्ष पंचाट की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित ड्यूटी करने के पश्चात् समयोपरि भत्ता देने में असफलता ।	,,
1	695.	,,	निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, जिसका संशोधन होना आवश्यक हो गया है, लोको शेडों में सुपरवाइजरी स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने में असफलता ।	,,
1	696.	,,	लोको शेडों में पुराने औजारों और संयंत्रों को आधुनिक औजारों और संयंत्रों द्वारा बदलने में असफलता ।	,,
1	697.	,,	लोको मैकेनिकल कर्मचारियों को वर्दी देने में असफलता ।	,,
1	698.	,,	लोको शेडों में इंजन की मरम्मत के लिए लोको मैकेनिकल कर्मचारियों को आवश्यक सामान सप्लाई करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	699.	**श्री रामावतार शास्त्री**	भारतीय रेलों के लोको शेडों में डकों की सफाई करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
1	700.	,,	भारतीय रेलों के लोको शेडों में साइकिल स्टेण्ड बनाने में असफलता ।	,,
1	701.	,,	उत्तर रेलवे के मुगलसराय, दानापुर, झाझा, बनारस लोको शेडों तथा अन्य कुछ शेडों में कार्य कर रहे लोको मैकेनिकल कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता ।	,,
1	702.	,,	पूर्व रेलवे के तरेगना स्टेशन पर मसौरही वाटर टैंक सेपी ने का पानी सप्लाई करने की आवश्यकता ।	,,
1	703.	,,	पूर्व रेलवे में पटना-गया लाइन पर बिना टिकट यात्रा को रोकने में असफलता ।	,,
1	704.	,,	पूर्व रेलवे में पटना-गया लाइन पर अपराधों को रोकने में असफलता ।	,,
1	705.	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के एवजी रेल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
1	706.	,,	दानापुर में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में जातिवाद और भाई-भतीजावाद ।	,,
1	707.	,,	रेल कर्मचारियों के बच्चों की नियुक्ति के लिए कुछ प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
1	708.	,,	पटना से गया होकर धनबाद तक एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यक्ता ।	,,

1	2	3	4	5
1	709.	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में रांची और जमशेदपुर तक दिन में एक तेज रफ्तार की गाड़ी चालू करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
1	710.	,,	जमशेदपुर से समस्तीपुर तक और समस्तीपुर से जमशेदपुर तक एक तेज रफ्तार की गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	711.	,,	पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर साउथ बिहार एक्स-प्रेस और पाटलीपुत्र एक्सप्रेस को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	712.	,,	पटना सिटी स्टेशन का नाम बदल कर पटना साहिब रखने में असफलता ।	,,
1	713.	,,	पटना जंकशन का नाम बदलकर पाटलीपुत्र जंकशन रखने में असफलता ।	,,
1	714.	,,	पटना जंकशन स्टेशन पर तीसरे दर्जे के टिकटघर के निकट लगातार कई घंटों तक मृत शरीरों को रखने की प्रथा को रोकने में असफलता ।	,,
1	715.	,,	पटना जंकशन के पूछताछ काउंटर पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	716.	,,	पटना जंकशन पूछताछ काउंटर पर रेल यात्रियों की टेलीफोन कालों का उत्तर देने में असफलता ।	,,
1	717.	,,	गाड़ियों में भीड़-भाड़ को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	718.	,,	गाड़ियों में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए अधिक बोगियां लगाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	719.	**श्री रामावतार शास्त्री**	दानापुर (खगौल) में रेलवे हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे कालिज बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
1	720.	,,	रेलवे द्वारा खगौल नगरपालिका को दिए जा रहे अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	721.	,,	लोको स्टेटिक स्टाफ के वेतनमानों को कार्यभार और उत्तरदायित्व के अनुसार निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
1	722.	,,	सभी स्टेटिक स्टाफ को वर्दी देने की आवश्यकता ।	,,
1	723.	,,	स्टेटिक स्टाफ के लिए समुचित प्रशिक्षण प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	,,
1	724.	,,	स्टीम शेडों के अन्दर धूमिल तथा गन्दले वातावरण में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
1	725.	,,	तीन साल की लगातार सेवा करने के पश्चात् कर्मचारियों को स्थाई बनाने और 6 महीने की अवधि तक आकस्मिक रूप से कार्य करने के पश्चात् कर्मचारियों को नियमित बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	726.	,,	अवरूद्ध श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की आवश्यकता ।	,,
1	727.	,,	डीजल शेडों की तरह स्टीम लोको शेडों में कारीगर कर्मचारियों के लिए ए० एल० एफ० पदों का सृजन करने की आवश्यकता ।	,,
1	728.	,,	बी० टी० एम० के पद को समाप्त करने और सभी वर्तमान बी० टी०	,,

1	2	3	4	5
			एम० की पदोन्नति करने की आवश्यकता ।	
1	735.	**श्री रामावतार शास्त्री**	उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में रेलवे में कार्य कर रहे लिपिकों को फैक्ट्री अधिनियम के अधीन मजदूरों के रूप में मानने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
1	736.	,,	सभी रेलों में रात की गस्ती ड्यूटी पर एक गैंगमैन के स्थान पर दो गैंगमैन नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
1	737.	,,	न्यायालय के मामलों में कमी करने तथा इसमें करोड़ों रुपए के हो रहे अपव्यय को कम करने में असफलता ।	,,
1	738.	,,	भारतीय रेलवे में वर्कशाप केंटीन कर्मचारियों को अधिकृत वेतनमान देने में असफलता ।	,,
1	739.	,,	रेल पटरियों के रख-रखाव के पर्याप्त व्यावहारिक अनुभवयुक्त इंजीनियरों को रेल पटरी-प्रभारी इंजीनियर नियुक्त करने में असफलता ।	,,
1	740.	,,	आल इण्डिया रेलवे परमानेन्ट वे स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	741.	,,	खुले स्थान में तितर-बितर पड़े रेल-पथ सामान की चोरी न होने देने के सम्बन्ध में चौकीदारी करने में असफलता ।	,,
1	742.	,,	रेल पटरियों के रख-रखाव में लगे रेल-पथ गैंगों के सम्बन्ध में सिद्धांत निश्चित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	743.	**श्री रामावतार शास्त्री**	इंजीनियरों द्वारा रेल पटरियों के निरीक्षण के बारे निर्देश देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें।
1	744.	,,	सहायक तथा डिवीजनल इंजीनियरों द्वारा रेल पटरियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में निश्चित जिम्मेदारी निर्धारित करने में असफलता।	,,
1	745.	,,	रेल बस्तियों में अधिक औषधालय खोलने तथा उन औषधालयों से कर्मचारियों को लिखी गई दवाइयां सप्लाई करने में असफलता।	,,
1	746.	,,	कीमैन और मेट के पदों का दर्जा बढ़ाने में असफलता।	,,
1	747.	,,	गैंगमैन को 314 रुपए का न्यूनतम वेतन देने में असफलता।	,,
1	748.	,,	गैंगमैनों को अर्द्ध कुशल मजदूरों के रूप में वर्गीकृत करने में असफलता।	,,
1	749.	,,	रेल पथ मजदूर की प्रत्येक श्रेणी के काम का वैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण करने तथा कठिन ड्यूटी के प्रकार पर तथा निभाई गई जिम्मेदारी की मात्रा के आधार पर वेतन निश्चित करने की आवश्यकता।	,,
1	750.	,,	रेल कर्मचारियों को राजपत्रित छुट्टी तथा सार्वजनिक छुट्टी, रविवार, दूसरा शनिवार और अन्तिम शनिवार को काम करने के बदले में अवकाश तथा दुगुना वेतन देने की आवश्यकता।	,,
1	791.	,,	समयानुसार दुर्घटना अनुदान तथा ब्रेक डाउन भत्ता देने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
1	792.	श्री रामावतार शास्त्री	पी० डब्ल्यू० आई० से भण्डारों का उत्तरदायित्व वापिस लेने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
1	793.	,,	पी० वे० श्रमिकों को सिविल सुविधाओं सहित क्वार्टर देने की आवश्यकता।	,,
1	794.	,,	पी० वे० श्रमिकों को वर्दियां देने की आवश्यकता।	,,
1	795.	,,	रेलों में गोपनीय रिपोर्टें देने की पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
1	796.	,,	समान कार्य के लिए समान वेतन देने का फार्मूला लागू करने की आवश्यकता।	,,
1	797.	,,	आठ घंटे से अधिक कार्य के पश्चात् समयोपरिभत्ता देने की आवश्यकता।	,,
1	798.	,,	डीलक्स और अधिक दूरी तक जाने वाली सभी गाड़ियों में खान-पान सम्बन्धी सुविधाएं जारी रखने की आवश्यकता।	,,
1	799.	,,	गोहाटी मेल और जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ियों में खान-पान की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता।	,,
1	800.	,,	संसद् सदस्यों की सुविधा के लिए संसद् भवन के बुकिंग कार्यालय में कर्मचारी बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
1	801.	,,	डीलक्स और गोहाटी मेल में वस्टिब्यूल वाले प्रथम श्रेणी के कोच लगाए जाने की आवश्यकता।	
1	802.	,,	नई दिल्ली स्टेशन से जयन्ती जनता और गोहाटी मेल को शाम के	,,

1	2	3	4	5
			7.25 के स्थान पर शाम के 6 बजे चलाने की आवश्यकता।	,,
1	803.	**श्री रामावतार शास्त्री:**	उपभोक्ताओं की सलाहकार समितियों में केलव ऐसे संसद् सदस्यों को जो बैठकों में भाग लेते हैं, नामनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जायें।
1	804.	,,	उपभोक्ताओं की सलाहकार समितियों के प्रत्येक स्तर पर, केवल ऐसे सदस्यों को, जो बैठकों और कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, नामनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता।	,,
1	805.	,,	पूर्व रेलवे में गोमोह के स्थान पर 11-3-74 को रेलवे के एक ट्रेड यूनियन नेता की हत्या के मामले में रेल अधिकारियों का हाथ होना।	,,
1	806.	,,	गोमोह के स्थान पर 11-4-74 को रेलवे के एक ट्रेड यूनियन नेता की हत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता।	,,
1	813.	**श्री गदाधर साहा :**	पूर्व रेलवे की अहमदपुर-कटवा (नेरोगेज) रेल लाइन को कम्पनी से लेकर उसका राष्ट्रीयकरण करने और उसे आधुनिक बनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
1	814.	,,	अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) रेल लाइन पर कर्माड़ांगा हाल्ट को स्टेशन के रूप में बदलने में विलम्ब।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जायें
1	815.	,,	कटवा स्टेशन पर प्लेटफार्म को साफ रखने की आवश्यकता।	,,
1	816.	,,	कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइन) रेल लाइन पर गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
1	817.	**श्री गदाधर साहा :**	गाड़ियों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
1	818.	,,	अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) रेल लाइन पर गाड़ियों में भीड़-भाड़ को कम करने में असफलता।	,,
1	819	,,	अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) के बीच स्टेशनों को क्रासिंग स्टेशनों म बदलने के लिए वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करने और रेल पथ को सुदृढ़ बनाने तथा भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने में असफलता।	,,
5	828.	,,	पूर्व रेलवे की छोटी लाइन के अहमदपुर और कटवा स्टेशनों के बीच रेल पथ की मरम्मत तथा उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	,,
5	829.	,,	पूर्व रेलवे में कटवा-अहमदपुर रेल लाइन की समुचित मरम्मत और रख-रखाव की आवश्यकता।	,,
1	856.	**श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रानाघाट-गेडे लाइन को उपनगरीय लाइन घोषित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए।
1	857.	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रानाघाट जंकशन और सीमावर्दी स्टेशन गेडे के बीच की इस दोहरी लाइन का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी जनता की मांग पूरी करने में असफलता।	,,
1	858.	,,	मजदीआ रेलवे स्टेशन पर, जो पूर्व रेलवे के सियालदह-गेडे लाइन पर पटसन के व्यापार का बड़ा केन्द्र है एक उपयुक्त ऊपरी पुल और स्टेशन तक पहुंच सड़क के निर्माण की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।

1	2	3	4	5
1	859.	**श्रीमती बीभा घोष गोस्वामी :**	पूर्व रेलवे के कटवा उपनगरीय सैक्शन पर चलने वाली गाड़िया में प्रतिदिन होने वाले विलम्ब और यात्रियों को न्यूनतम सुविधाएं देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
1	897.	**श्री पी० के० देव :**	दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को उड़ीसा में किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण करने की वांछनीयता	,,
1	898.	,,	दण्डकारण्य से विजाग पत्तन तक यातायात की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे में आमगुडा-केसिंगा रेल लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	899.	,,	केसिंगा रेलवे स्टेशन के निकट एक ऊपरी पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	900.	,,	पुरी-वाल्टेयर एक्सप्रैस को कटबन्जी या रायपुर तक बढ़ाने की वांछनीयता ।	,,
1	901.	,,	दादर-नागपुर लाइन को विशाखा-पत्तनम् तक बढ़ाने की वांछनीयता ।	,,
1	902.	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे में तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन का निर्माण तुरन्त आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
1	903.	,,	हावड़ा-डोंगरगढ़ प्रथम श्रेणी की बोगी को 30 अप और 29 डाऊन एक्सप्रैस में नागपुर तक बढ़ाने की वांछनीयता ।	,,
1	904.	,,	उत्कल एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाने तथा उसे एक दिन छोड़कर बरास्ता रायपुर और विजयनगरम् चलाने की वांछनीयता ।	,,

1	2	3	4	5
1	905.	**श्री पी० के० देव**	रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारियों को तुरन्त स्थाई बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाये।
1	906.	,,	रेलवे प्लेटफार्मों पर भीख पर रोक लगाने की वांछनीयता।	,,
1	907.	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे में टाटा-मद्रास एक्सप्रैस को नारला रोड़ पर खड़ी करने की वांछनीयता।	,,
	908.	,,	दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायपुर-विजाग सैक्शन पर स्टेशनों से आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों का उपलब्ध न होना।	,,
1	911.	**श्री रामावतार शास्त्री**	इण्डियन रेलवे वर्क्स फैडरेशन को मान्यता देने की आवश्यकता।	
1	912.	,,	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए नये स्थापित किए जा रहे कारखानों में रेल कर्मचारियों को प्रयोजन भत्ता देने की आवश्यकता।	,,
13	913.	**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**	पूर्व-रेलवे में हावड़ा-बन्देल, हावड़ा-तारकेश्वर और हावड़ा-चन्दनपुर सेक्शन में स्थानीय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
13	914.	,,	सेवमपुर रेलवे स्टेशन के उत्तरी सिरे पर एक उप-मार्ग बनाने की आवश्यकता।	,,
13	915.	,,	पूर्व रेलवे के बन्देल और कटवा सैक्शन को जाने और वहां से आने के लिए अधिक गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
13	916	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सियालदह से डानकुनी तथा डानकुनी से सियालदह तक अधिक गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपदे घटा दिये जाएं।
13	917	,,	पूर्व रेलवे के हिन्द मोटर रेलवे स्टेशन के अप प्लेटफार्म से टिकट घर तक के रास्ते को चौड़ा करने की आवश्यकता।	,,
13	918	,,	हावड़ा-बर्दवान, हावड़ा-तारकेश्वर, और रानाघाट-सियालदह सेक्शन में खोमचे वालों को अधिक लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता।	,,

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जो स्थगत प्रस्ताव मैंने तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने रखा था, वह रेलवे के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित था।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए]

[Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair]

रेलवे प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्चाधिकारियों पर किए जा रहे अनावश्यक व्यय को कम किया जाना चाहिए तथा इसका उपयोग यात्री सुविधाएं देने और रेलवे कर्मचारियों की आर्थिक मांगों को पूरा करने में किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए।

रेलवे में लम्बी दूरी की गाड़ियों में भोजन व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है। कालका मेल में डाइनिंग कार में भोजन परोसना बन्द कर दिया गया है। भोजन किसी रास्ते के स्टेशन पर परोसा जाता है और वहां भी उसका मूल्य बढ़ गया है परन्तु उसकी किस्म गिरती जा रही है। रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

आरक्षण में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। हावड़ा बम्बई और मद्रास के तीसरे दर्जे के यात्रियों को तीन टायर में सोने की सीट बिना कुछ दिए पाना नितांत असम्भव है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक नए तरीके के अनुसार हम अपनी सीट एक साल पहले बुक करा सकते हैं जो निरर्थक है। एक सामान्य तीसरे दर्जे के यात्री के लिए एक साल पहले आरक्षण कराना किस प्रकार सम्भव है? इस प्रकार की आरक्षण प्रणाली की क्या उपयोगिता है? इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

जी० टी० रोड पर सीरमपुर क्षेत्र में एक रेल फाटक है। इस लाइन पर गाड़ियाँ बहुत अधिक चलती हैं। इस लिए पैदल यात्रियों के लिए एक ऊपरी पुल की मांग की गई है। इतना ही नहीं, गाड़ियों के यातायात के लिए भी एक पुल बनाया जाए जिससे वह बिना रोक पार हो सकें। मंत्री महोदय ने कहा है कि 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकार को वहन करनी चाहिए। परन्तु राज्य सरकार इसे कभी भी वहन नहीं कर सकेगी। अतः रेल मंत्री कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत भार वहन किए बिना कुछ व्यवस्था की जा सके।

देश में अनेकों बिना चौकीदार वाले रेल फाटक हैं। इन पर चौकीदारों को लगाने के लिए रेलवे क्या कदम उठा रही है?

हावड़ा सियालदह क्षेत्र में यात्रियों के लिए अधिक लोकल गाड़ियों की आवश्यकता है। लाखों आदमी इन गाड़ियों से यात्रा करते हैं तथा भीड़ के समय में इन गाड़ियों में चढ़ना असम्भव है। अतः सियालदह और हावड़ा डिवीजन में कुछ और गाड़ियां चलाई जाएं।

कटवा-बन्देल लाइन अभी भी ब्रिटिश काल की स्थिति में ही है। पिछले कुछ वर्षों में वहां फैक्टरियां स्थापित हो गई हैं और उनमें काम पर जाने के लिए कर्मचारियों को जाना पड़ता है। परन्तु एक अकेली लाइन होने और गाड़ियों के अनियमित रूप से चलने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है। इस सैक्शन में गाड़ियों का चलना सुधारा जाना चाहिए।

सियालदह सैक्शन की स्थिति बहुत खराब है। वहां गाड़ियां कभी ही समय पर चलती हैं। वहां इकहरी लाइन है और डिब्बों में बहुत भीड़ रहती है। यहां दुहरी लाइनें बिछाई जानी चाहिएं। गत दो वर्षों के दौरान सियालदह-बौंगा, सियालदह-राणाघाट तथा सियालदह-दक्षिण सैक्शनों पर चोरी आदि की अनेक घटनाएं हुई हैं। उस सैक्शन पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

अन्तिम बात, जो मैं कहना चाहता हूं, वह पहले कई बार कही गई है किन्तु रेलवे विभाग द्वारा से अभी तक उस बारे में कोई स्पष्ट प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। हावड़ा-आमता, हावड़ा-सीकाला लाइट रेलवे के संबंध में क्या हुआ है। रेल मंत्री ने बार बार कहा है कि इसे बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा और इसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मैं प्रार्थना करता हूं कि रेल मंत्री महोदय एक स्पष्ट उत्तर दें कि क्या रेलवे विभाग उस क्षेत्र में बड़ी लाइन को चालू करने के लिए तैयार है जिसे पहले मार्टिन बर्न रेलवे कहा जाता था। स्वयं प्रधान मंत्री ने 1972 के चुनावों से पूर्व बचन दे चुकी हैं कि यदि कांग्रेस दल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ हो गया, तो मार्टिन बर्न रेलवे को पुनः चालू कर दिया जाएगा। किन्तु अभी तक इस वचन को पूरा नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि हावड़ा-आमता और हावड़ा-सीकाला लाइनों के संबंध में कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए।

श्री एस० आर० रामाणी (शोलापुर) : मैं केवल मांग संख्या 1, 4, 5 और 6 के बारे में कहूंगा।

अनुशासन, अव्यवस्था, अभाव आदि के बारे में शिकायतें की गई हैं। किन्तु श्रमिकों में अनुशासन बनाए रखने में ये शिकायतें कहां तक सहायक रही हैं जिससे रेल-गाड़ियां

ठीक तरह चलती रहें और रेलों में बड़े पैमाने पर होने वाली उठाईगीरी को रोकने में जिससे रेलवे को बहुत हानि हो रही है, यह कहां तक सहायक रही हैं।

बजट पेश करते समय तथा बजट के संबंध में उत्तर देते हुए रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि वह व्यय में अधिकतम मितव्ययता बरतने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि क्षमता के उपयोग में सुधार करने का पूरा प्रयास किया गया है ताकि राजस्व में वृद्धि हो। किन्तु व्यय में मितव्ययता बरतने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है ।

रेलवे बोर्ड में प्रति वर्ष व्यय बढ़ रहा है। अधिकारियों की संख्या भी बढ़ रही है। 1973-74 में आप द्वारा 1,033 स्थायी कर्मचारी और 33 अस्थाई कर्मचारी बताए गए थे। व्यय में मितव्ययता बरतने और व्यय को कम करने के नाम पर स्थाई कर्मचारियों की संख्या को कम करके 885 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 33 से बढ़ा कर 287 कर दी गई है। कर्मचारियों की कुल संख्या को 1,066 से बढ़ाकर श्रेणी चार में 390 सहित 1,172 कर दी गई है। क्या व्यय को इसी प्रकार कम किया जा सकता है।

1972-73 में मरम्मत और रख रखाव के लिए 334 करोड़ रुपए की मांग की गई थी जो 1973-74 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में 18 करोड़ रुपए और बढ़ गई है। किन्तु 1974-75 में यह 77.46 और बढ गई और 1972-73 से यह 125.21 करोड़ रुपए अथवा 40 प्रतिशत अधिक है यह वृद्धि दो वर्ष में ही दुगुनी से भी अधिक हो गई है। क्या परिव्यय में यह वृद्धि राजस्व में हुई वृद्धि के अनुसार हुई है? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमें यह सूचना देंगे कि गाड़ियों द्वारा कितना माल उठाया गया और इनके द्वारा कितने यात्रियों ने यात्रा की ताकि हम निर्णय कर सकें कि क्या व्यय में वृद्धि अनुपात के अनुसार हुई है या अधिक हुई है।

जहां तक संचालन कर्मचारियों संबंधी मांग संख्या 6 का संबंध है, इस शीर्ष के अन्तर्गत 1972-73 में हुए वास्तविक व्यय में इस वर्ष के अनुमान की तुलना की जाए, तो पता चलता है कि इसमें 70 करोड़ रुपए अथवा 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हम इसकी तुलना 1973-74 के पुनरीक्षित अनुपानों के साथ भी करें, तो इसमें 45 करोड़ की वृद्धि हुई है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि रिक्त स्थानों को भरा नहीं जा रहा है। किन्तु साथ ही व्यय भी बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय को इस समस्या की गहराई तक पहुंच कर यह पता लगाना चाहिए कि व्यय इतना क्यों बढ़ा है और इसे बढ़ाया क्यों जा रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान कि रेलों में कोई न कोई हड़ताल होती रहती है। ऐसा लगता है कि रेलवे प्रशासन में कोई न कोई त्रुटि अवश्य है।

मुझे आशा है कि रेल मंत्री महोदय मेरे द्वारा कही गई बातों की ओर ध्यान देंगे और हमें वास्तविक अच्छा प्रशासन देने का प्रयास करेंगे।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I want to draw the attention of the Railway Minister to the demands of Madhya Pradesh regarding railways.

The State of Madhya Pradesh is a big and highly populated state. Justice should be done to Madhya Pradesh and more railway trains should be provided there, only then the development of the State would be possible.

The deposits of copper have been found in Balaghat. It is very good that the copper has been found in Khetri area also. I would request you to correct Chhuimine with Rajnathgaon. When this is done, Bombay would be connected with Calcutta railway line.

The railway line between Gwalior and Shivpuri should be connected into broad gauge line. The narrow-gauge line of Chindwara should also be connected into broad-guage line. Similarly the area of 65 miles between Ujjain and Agur should also be connected into broad gauge line.

Iron ore are available in Dalli Rajhora in Rajnathgaon area. The survey has been completed for the construction of a railway line between Dalli Rajbara and Bailadilla. The construction work regarding this line should be started. A railway line should be constructed to connect Dalli-Rajbara, Rajnandgaon-Khairgarh Tehsil, Gandia, Lohara, Khaura and Jabalpur.

Raipur is a very big city, but no amenity is provided to trand between Raipur and Bhopal. A line should be provided to connect Raipur, Rajnandgaon, Chhuimine, Khaharda. Mandla and Jabalpur. Only then it would be possible to reach Bhopal by catching a train from Jabalpr.

I would request the Hon'ble Railway Minister to do something so that the proposed railway strike should be averted so that the people may not be forced to face the inconveniences. I hope that you would do everything possible to effect improvement in the railways.

In Fifth Five Year Plan only 10 crores of rupees have been allocated for providing the railway amenities in the Central Railway.

The survey has been conducted for the construction of a line between Satna and Rewa. This line should be constructed. The survey of a line to connect Lalitpur, Tikamgarh, Chattarpur, Panna and Satna has also been conducted. But so far no provision has been made for the construction of this line. The Railway Minister should look into the matter and he should get this line constructed.

I hope that the Railway Minister would do justice and provide new lines to Madhya Pradesh which has remained neglected so far.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I want to draw the attention of the Railway Minister to North Bihar which is one of the most backward state in the country. Adequate facilities of communications and transport should be provided for the development of that area.

A broad gauge line should be provided from Samastipur to Narakatiaganj via Darbhanga, Sitamarhi and Raxaul. Dining cars should be attached to the Delhi-Howrah delux, Assam Mail and Jayanti Janta. Moreover an Express Train should be introduced from Narkatiaganj to Pahlejaghat via Samastipur.

The proposal for increasing the railway fare for III class passengers should be withdrawn.

The improvement should be made in the passenger amenities at Sitamarhi Station. The waiting room, bath rooms and platforms, at the station are always found very dirty. A retiring room should also be provided there.

Now I want to draw the attention of the Railway Minister towards A. H. Wheeler & Co which has got stalls on a large number of railway stations and they sublet these stalls on the basis of monthly rent. This type of monopoly must be ended. These stalls should be given to the local educated unemployed youngmen..... (*Interruptions*) I want to ask the leaders of opposition who are responsible for the strike. If you want that there should be improvement in the railways and the prices should be brought down, there should be no strike.

I want to say about the reservation of berths also. There is a lot of corruption in the staff, who are responsible for reservation of these berths. They must be strictly dealt with. A proper indication board should be displayed at all important stations showing the position of reservation of berths & seats in different trains.

In the end I would request the Railway Minister to provide gatemen at all the railway crossings at Narkatiaganj, Samastipur line, so that railway property may be protected.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम): मैं माननीय रेल मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह बांकुरा-दामोदर छोटी लाइन की स्थिति में सुधार करें। वर्दवान-आसनसोल सैक्शन पर और गाड़ियां चलाई जानी चाहिएं और इसे उपनगरीय सैक्शन घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वी रेलवे के बर्दवान-साहिबगंज लूप सैक्शन को दोहरी लाइन में बदला जाना चाहिए और इस सैक्शन पर अधिक गाड़ियों को चलाया जाना चाहिए, ताकि उत्तर बिहार तथा कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र के साथ और अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

दुर्गापुर से टाटानगर बरास्ता बांकुरा तक एक लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए।

सियालदहगेडे लाइन को उपनगर लाइन में बदला जाना चाहिए। यह पहले ही दोहरी लाइन है और यह उपनगरीय लाइन के रूप में विचार किए जाने के लिए सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I want to support these demands and also give some suggestions.

Adequate means of transport should be provided in Madhya Pradesh, so that the State can be developed economically. A railway line for Bailladila in Bastar district is very necessary. Huge deposits of copper have been found in Balaghat and if a railway line is provided there, it would be helpful in the development of that area.

Madhya Bharat and Bundel Khand have remained as dacoit infected areas. As a result of efforts made by the Government of Madhya Pradesh, the dacoits surrendered themselves before the Government there. If development of that area is not made, the dacoit problem would not be solved in that area. Railway lines are also required in Bundelkhand., so that it can be economically and industrially developed. Sheopuri-Gwalior narrow gauge line should be converted into broad gauge.

About 5 thousand dacoits have surrendered in Bundel Khand area. A railway line should be constructed between Balaghat and Chhuimine connecting Lalitpur with Tikamgarh and Panna with Satna via Rajnandgaon so that Bombay and Calcutta may be connected with this line.

Another railway line should be provided from Damoh to Tikamgarh and Chattarpur should be connected with Mohoba via Kajuraho so that it may be connected with Calcutta-Lucknow line.

I want that the Goverment should conduct survey or the development of Bundel Khand. You should also be careful about the damages caused to the railways by your departmental employees.

सभापति महोदय : श्री अहिरवार, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोकसभा बुधवार, 20 फरवरी 1974/29 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, March 20, 1974/Phalguna 29, 1895 (Saka).

199LSS/74—G.I.P.F.

PLS. 48. XXXVI. 20.74 (N)
490

© 1974 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पाचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।

© 1974 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the Manager, Government of India Press, Faridabad